

सातवाँ वर्ष



310.58
Ind/M.I.B.

GOVERNMENT OF INDIA
 ARCHÆOLOGICAL SURVEY OF INDIA
 ARCHÆOLOGICAL
 LIBRARY

ACCESSION NO. 3651
 CALL No. 310.58/Ind/M.I.B.

D.G.A. 79

‘प्रसारिका’ साहित्य, कला, इतिहास, यात्रा, दर्शन, धर्म, विज्ञान, मनोविज्ञान आदि विषयों पर देश भर के प्रख्यात व्यक्तियों के चुने हुए भाषणों का संग्रह है। उच्चकोटि की बौद्धिक सामग्री के अलावा इस संग्रह में कहानी, कविता, नाटक, हास्य-रस के लेख आदि भी होते हैं। ऐसी उत्कृष्ट सामग्री सभी को सुलभ करने के लिए इस सचित्र, लगभग सौ पृष्ठ की पत्रिका का मूल्य केवल आठ आने रखा गया है।

नोट : प्रसारिका के पहले दो अंक ‘रेडियो संग्रह’ नाम से प्रकाशित हुए हैं।

पब्लिकेशन्स डिवीजन, ओल्ड सेक्रेटेरियट,
 दिल्ली-८

सातवाँ वर्ष

310.58
(100)

3051



310.58
Ind / M.I.B.

मूल्य—

१॥), ३ शि० ६ पेन्स, ५० सेंट

डाइरेक्टर, पब्लिकेशन्स डिबोर्ज, द्वारा प्रकाशित और एलबियन प्रेस,
कश्मीरी गेट दिल्ली द्वारा मुद्रित ।

CENTRAL ARCHAEOLOGICAL
LIBRARY, NEW DELHI.

Acc. No. 3651

Date 21. 10. 55

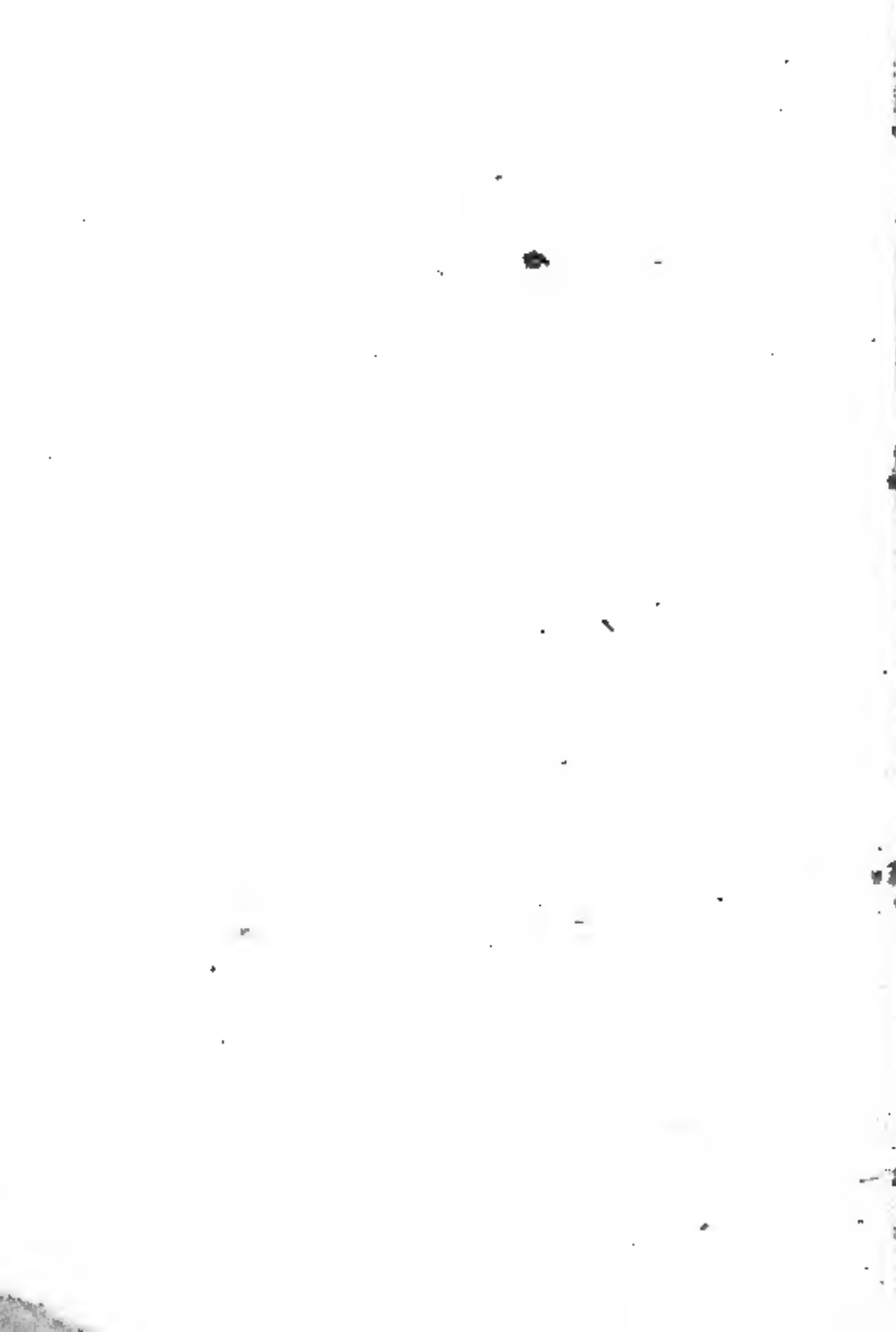
Call No. 1058/2nd/M.9.B.

आमुख

'सातवाँ वर्ष' में केन्द्रीय और राज्य सरकारों की अप्रैल १९५३ और
मार्च १९५४ में हो चुके वाली विशेष सफलताओं और कार्यों का विवरण
प्रस्तुत किया गया है। पहले भाग में केन्द्र के कार्यों और दूसरे भाग में राज्यों
के कार्यों का विवरण दिया गया है।

पञ्चवर्षीय योजना के अन्तर्गत अनेक स्कीमों और कार्य सफल होने लगे
हैं और उनकी पूर्ति सन्निकट है।

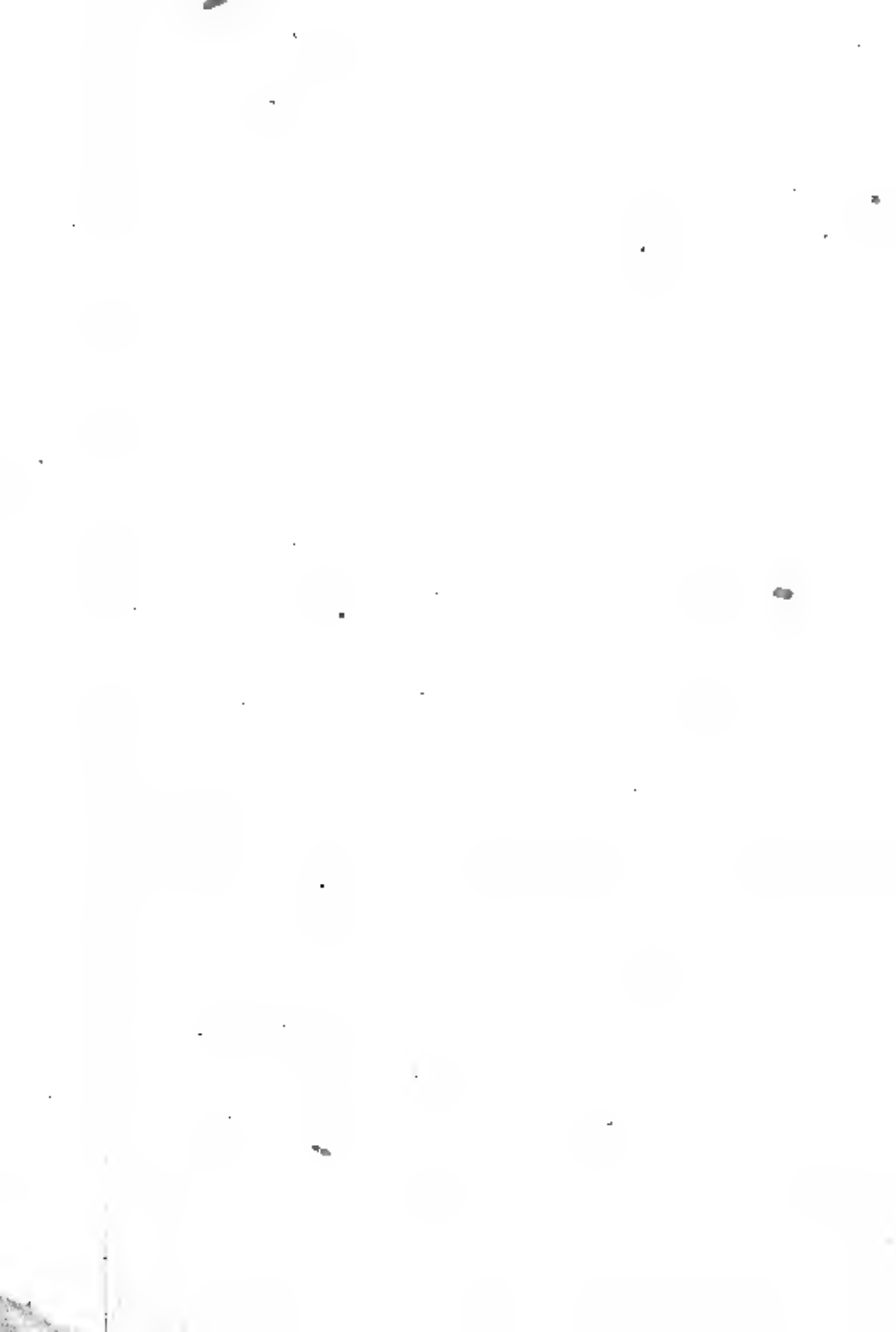
केन्द्र के कार्यों को चार शीर्षकों के अन्तर्गत रखा गया है: सामाजिक,
आर्थिक, आन्तरिक और वैदेशिक। इस प्रकाशन का रूप व्यापक होने के कारण
अनिवार्यतः विभिन्न विषयों को संक्षेप में ही दिया जा सका है।



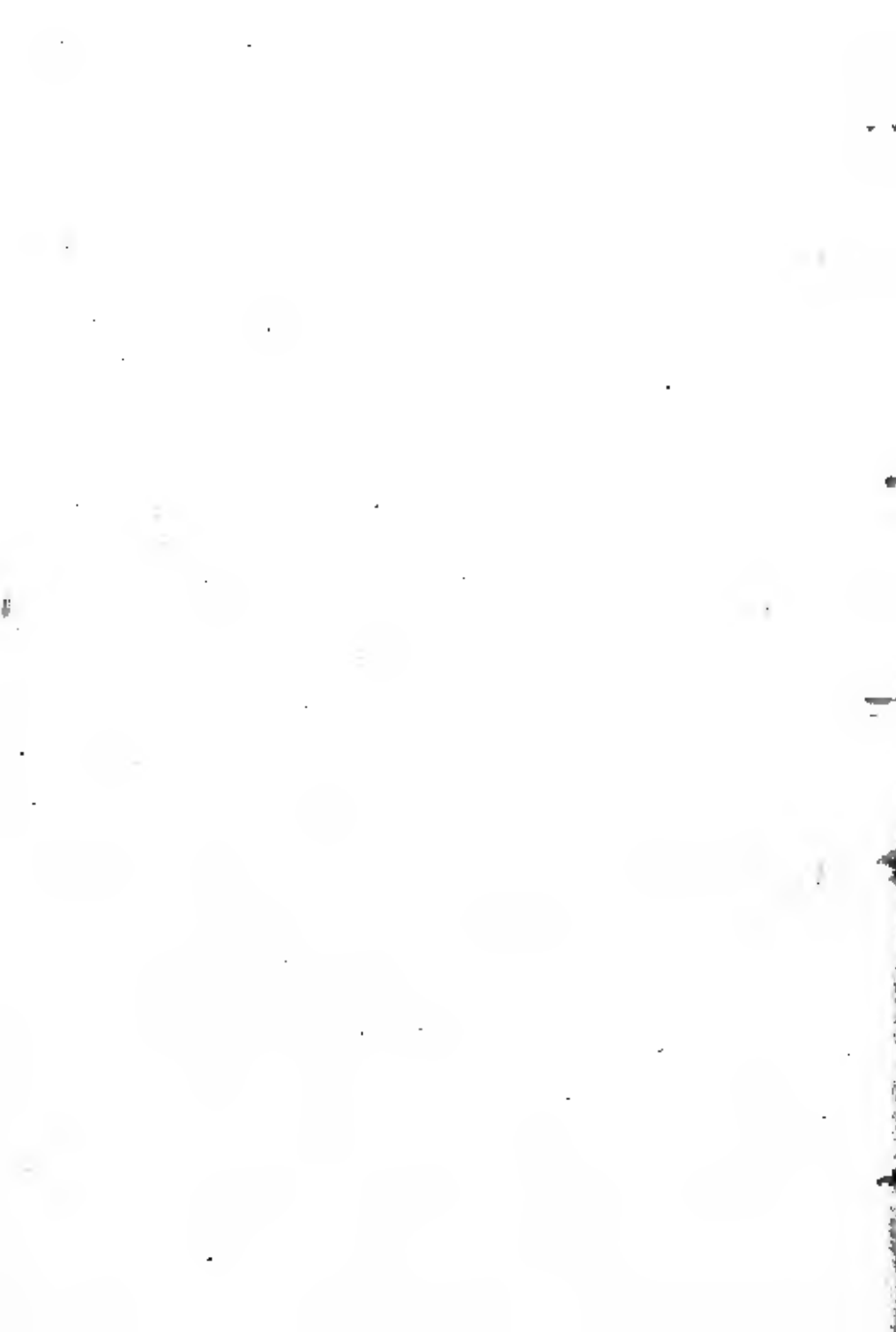
विषय-सूची

केन्द्र

	पृष्ठ
सामाजिक	
शिक्षा	३
स्वास्थ्य	६
पुनर्वास	१५
श्रम	१६
आर्थिक	
वित्त	२७
सिंचाई और विद्युत	३७
साप्ताहिक योजना प्रशासन	४३
साध और कृषि	४८
बाणिज्य और उद्योग	५२
प्राकृतिक साधन और वैज्ञानिक अनुसन्धान	५६
उत्पादन	६१
कार्य, गृह-निर्माण और सम्पत्ति	६७
आन्तरिक	
गृह मन्त्रालय	७४
राज्य मन्त्रालय	७८
संचार	८४
परिवहन	९१
रेल्वे	९५
वैदेशिक	
अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन	९९
प्रतिरक्षा मन्त्रालय	१०७
सूचना एवं प्रसार मन्त्रालय	११२
राज्य	
'क' भाग	१२३
'ख' भाग	१६१
'ग' भाग	१८४



केन्द्र



शिक्षा

हिन्दी का विकास

भारत सरकार ने २६ सितम्बर १९५३ को हुई हिन्दी शिक्षा समिति की तीसरी बैठक की सिफारिश पर भारतीय यूनियन के पूर्वी राज्यों में, जिनमें आसाम, असिपुर, उड़ीसा, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल सम्मिलित हैं, हिन्दी प्रचार की योजना स्वीकार कर ली है। प्राथमिक संघर्ष-हिन्दी शब्दकोष तैयार करने के लिए इलाहाबाद की हिन्दुस्तानी कल्चर सोसाइटी को ६०,००० रुपये की आर्थिक सहायता देना स्वीकृत हो चुका है। हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में सामान्य रूप से प्रचलित शब्दों का भी एक शब्दकोष तैयार किया जा रहा है।

अगले वर्ष में ऐसे केंद्रों की संख्या तीन से बढ़कर आठ हो गई जहाँ कक्षाओं में हिन्दी के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। इन कक्षाओं में लगभग ६०० विद्यार्थी हैं। माध्यमिक स्कूलों में कास आने वाले गणित शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र तथा समाज विज्ञान के हिन्दी पारिभाषिक शब्दों की कार्यनिर्वाहक सूचियां प्रकाशित की गईं और राज्य सरकारों तथा विश्वविद्यालयों आदि को भेज दी गईं। हिन्दी के प्रचार के लिए, विशेषकर अहिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्रों में, पंचवर्षीय योजना में निविष्ट पांच लाख रुपये के अलावा ३,६६,००० रुपये की और व्यवस्था रखी गई है।

विश्वविद्यालय तथा प्रौद्योगिक शिक्षा

आ० एस० एस० भटनगर की अध्यक्षता में नवम्बर १९५३ में विश्व-

विद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना हुई। आयोग एक विशेषज्ञ समिति के रूप में केन्द्रीय सरकार की विश्वविद्यालयों में सुविधाओं के समन्वय तथा स्तर कायम रखने से सम्बन्धित समस्याओं के विषय में परामर्श देगा। इसका एक महत्वपूर्ण कार्य विश्वविद्यालयों की वित्तीय आवश्यकताओं की जाँच-पड़ताल करना तथा अनुदानों के लिए राशियों के निर्धारण में केन्द्रीय सरकार को सलाह-महिवरा देना होगा।

विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिशों पर क्रमशः किये जाने की प्रगति के पुनर्विलोकन के लिए केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की एक समिति नियुक्त की गयी। समिति ने प्राथमिकताओं की एक सूची तैयार की। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने फरवरी १९५४ को अपनी बैठक में इस सूची को अपनी स्वीकृति दी। मानव विद्याओं (ह्यूमैनिटीज़) के अध्ययन सम्बन्धी अनुसन्धान-छात्रवृत्तियों की योजना वाली संस्था का विशेष उल्लेख भी किया जा सकता है।

प्रौद्योगिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रसिद्ध भारत प्रौद्योगिक शिक्षा परिषद् के चुनाव पर १९४७-४८ में आरम्भ किया गया विकास-कार्यक्रम अब प्रगति पुर होने की अवस्था में है। सात व्यक्तियों की समिति की सिफारिश पर परिषद् ने प्रौद्योगिक शिक्षा की सभी दृष्टि से उन्नति करने तथा उसके विस्तार की एक योजना तैयार की है। इस योजना के फलस्वरूप (क) स्नातकोत्तर अध्ययन की सुविधाओं, उच्च प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान का विकास होगा, (ख) पूर्व-स्नातक स्तर पर इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के शिक्षण की सुविधाओं में वृद्धि होगी, (ग) आंशिक समय के पाठ्यक्रमों, प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रमों, उद्योग-बंधों के साथ-साथ अध्ययन तथा अन्य प्रकार के शिक्षणों की सुविधाओं की व्यवस्था हो सकेगी तथा (घ) मुद्रण प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिक प्रशासन, व्यवसाय-प्रबंध आदि के प्रशिक्षण की पर्याप्त सुविधाएं मिल सकेंगी।

छद्दपुर की भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था में १९५३-५४ में ७५० छात्र थे। १९५४-५५ में छात्रों की संख्या १,१०० हो जाने की आशा है। बंगलोर की भारतीय विज्ञान संस्था के विस्तार का कार्यक्रम, जिसमें पौने दो करोड़ रुपये व्यय होंगे, करोड़-करोड़ पूरा हो चुका है।

कला और संस्कृति

सरकार कला और संस्कृति के विकास की ओर बराबर ध्यान देती आ रही है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक ट्रस्ट स्थापित करने के निर्णय के सम्बन्ध में राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी और राष्ट्रीय साहित्य अकादमी स्थापित की जा चुकी है। सरकार राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की स्थापना के लिए एक ऽस्ताव भी स्वीकार कर चुकी है। राष्ट्रीय कला भवन के लिए जयपुर हाउस प्राप्त कर लिया गया है।

बालकों द्वारा बनाये गये चित्रों और शाल कला-कृतियों की जनवरी १९५४ में नई दिल्ली में बुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के लिए 'शंकरल बोकली' को १२,००० रुपये दिये गये।

सरकार विभिन्न भारतीय भाषाओं के उच्चकोटि के ऐसे शिक्षकों तथा विद्वानों को विलीय सहायता देने का कार्यक्रम भी स्वीकार कर चुकी है, जिसको सहायता की आवश्यकता है।

अन्तर्सांस्कृतिक सम्बन्ध

भारत वर्ष में सांस्कृतिक सम्बन्ध के लिए व्यवस्था दो भिन्न-भिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत की गई थी : (१) सामान्य सांस्कृतिक कार्य, तथा (२) प्रधान शंभो के अनुरोध पर वर्तमान आन्तरिक और बाह्य सांस्कृतिक कार्यों में वृद्धि करने के लिए व्यवस्था।

अमेरिका को भेजी गयी प्रदर्शनी कनाडा भी जा चुकी है। हमारे देश में रूस और अफगानिस्तान से सांस्कृतिक प्रतिनिधिमण्डल आये। भारतीय और जापानी बालकों द्वारा बनाये गये चित्रों का परस्पर विनिमय करने का विचार किया जा रहा है। चित्रों की एक प्रदर्शनी रूस और अन्य यूरोपीय देशों को भेजी गयी। भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् विदेशों के साथ विश्वविद्यालय के अध्यक्षों के विनिमय का कार्यक्रम तथा विदेशों में कलाकार मण्डल भेजने का कार्यक्रम भी चालू रहलगा।

संशोधित छात्रवृत्ति योजना

संशोधित समुद्रपार छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत १९५३-५४ में २४ व्यक्ति चुने गये। १९५४-५५ में विश्वविद्यालयों तथा अन्य संस्थाओं से २५ अभ्यापक और भोजन का विचार है। १९५४-५५ में इस सम्बन्ध में होने वाले व्यय के लिए १९५४-५५ के बजट में २,४५,७०० रुपये की व्यवस्था की गई है।

भारत-जर्मनी सहयोग योजना

१९५२-५३ में भारत सरकार ने भारत-जर्मनी औद्योगिक सहयोग योजना के अन्तर्गत जर्मन विश्वविद्यालयों तथा संस्थाओं में स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए ५० छात्र तथा जर्मन उद्योगों में प्रत्यक्ष प्रशिक्षण के लिए १०० छात्र भेजना स्वीकार किया। पहले ५० छात्रों को फीस माफ रहेगी, और अन्य १०० छात्र एग्नेटिस के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इसके बदले में भारत सरकार ने भारतीय विश्वविद्यालयों तथा संस्थाओं में भारतीय भाषाओं, धर्म तथा दर्शन के अध्ययन के लिए दस जर्मन छात्रों को वृत्ति दी।

छात्रवृत्तियाँ

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और पिछड़ी जातियों के छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए १९५३-५४ के बजट में ४० लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। छात्रवृत्तियों के लिए बहुत अधिक संख्या में माये हुए प्रार्थना-पत्रों की दृष्टि से यह राशि अपर्याप्त पायी गयी और इसके अतिरिक्त २२ लाख रुपये की और व्यवस्था की गयी है।

फ्रांसीसी छात्रों की वृत्तियाँ

विदेशों में भारतीय छात्रों को अध्ययन के लिए कई विदेशी सरकारों द्वारा छात्रवृत्तियाँ दिए जाने की सम्भावना के बदले में भारत सरकार ने एक छात्रवृत्ति योजना बनाई है। तदनुसार भारत सरकार ने फ्रांसीसी छात्रों को छात्रवृत्तियाँ देने की एतदर्थ योजना को, जो १९४६-५० में स्वीकार की गयी थी, १९५३-५४ में फिर से लागू करने का निर्णय किया। इस योजना के अन्तर्गत भारतीय विश्वविद्यालयों में अभ्यापन तथा अनुसन्धान के लिए फ्रांसीसी

नागरिकों को दो-दो वर्षों की छात्रवृत्तियाँ दी गईं हैं। १९५३-५४ के लिए २८,५०० रुपये की व्यवस्था की गई थी और १९५४-५५ में २०,००० रुपये की व्यवस्था की गई है।

विचार-गोष्ठियाँ और सम्मेलन

संयुक्त राष्ट्रीय शिक्षा, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) के स्थायी भारतीय राष्ट्रीय आयोग का सर्वप्रथम सम्मेलन ६ जनवरी १९५४ से १४ जनवरी १९५४ तक नई दिल्ली में हुआ। सम्मेलन में अफगानिस्तान, निम्न, दण्डोनेशिया, ईरान, जापान तथा अन्य देशों के राष्ट्रीय आयोगों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और यूनेस्को के कार्यक्रमों और नीतियों पर पुनर्विचार किया गया। सम्मेलन में यूनेस्को के कार्यक्रमों का पूर्वीकरण करने की महत्वपूर्ण सिफारिशें की गईं जिससे एशियाई और अफ्रीकी देशों की आवश्यकताएँ पूरी हो सकें।

यूनेस्को के सम्मेलन को १९५३ में हुई असाधारण बैठक में भारत की ओर से भाग लेने वाले प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व भारत के उपराष्ट्रपति डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णण ने किया। भारत सरकार ने जुलाई १९५३ में जेनेवा में हुए १६ वें अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक शिक्षा सम्मेलन में भी भाग लिया। इस सम्मेलन में संसार के विभिन्न देशों की शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति पर विचार किया गया। सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों की शिक्षा-पद्धतियों की रचना, उनके पाठ्यक्रमों आदि पर विचार विनिमय हुआ।

सामान्य विकास

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अनिवार्य (बैलक) तथा सामाजिक शिक्षा योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए १,६८,७५,००० रुपये की व्यवस्था की गई है। सामाजिक शिक्षा के क्षेत्र में कई नई योजनाओं पर भी काम आरम्भ किया गया।

पाठ्यपुस्तक अनुसन्धान समूह तथा शैक्षणिक और व्यावसायिक पर-प्रदर्शन समूहों की केन्द्र और राज्यों में स्थापना भी नई योजना का अंग है।

श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख को अध्यक्षता में समाजकल्याण बोर्ड को स्थापना हुई। इसका काम है समाज कल्याण का काम करने वाली विभिन्न संस्थाओं के कार्यों में सन्तुल्य करना और उन्हें संगठित करना तथा ग्राम्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता देना। शारीरिक उन्नति की शिक्षा तथा नवयुवक कल्याण के लिये भी एक विस्तृत कार्यक्रम बनाया गया है, जो राज्य सरकारों, विद्वद्विज्ञान-समर्थों तथा स्वयंसेवक संगठनों की सहयोगिता से कार्यान्वित किया जायेगा।

माध्यमिक शिक्षा आयोग की रिपोर्ट सितम्बर १९५३ में प्रकाशित हुई। बताया है कि कुछ और महत्वपूर्ण सुझावों को आगामी शिक्षा-वर्ष में कार्यान्वित किया जायेगा।

फोर्ड प्रतिष्ठान के सहयोग से चार विदेशी और चार भारतीय शिक्षा-शास्त्रियों की एक मण्डली को भारत, यूरोप और अमेरिका की माध्यमिक शिक्षा प्रणालियों का विस्तृत और तुलनात्मक अध्ययन करने का काम सौंपा गया। इनके अध्ययन में विशेष ध्यान शिक्षकों के प्रशिक्षण की पद्धतियों और पाठ्यक्रमों के पुनर्गठन पर दिया जाना था।

माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में दूसरा महत्वपूर्ण कार्य हेडमास्टरों के निष्कारगोष्ठी अवकाश शिविर का लगाना था। इस शिविर में २५ राज्यों के ५० हेडमास्टरों ने भाग लिया और अपने अपने स्कूलों के सुधार का कार्यक्रम बनाया। ट्रेनिंग कालेजों को विशिष्ट समस्याओं पर अनुसन्धान कार्य करने के लिये प्रोत्साहन देने का कार्यक्रम भी पूरा कर लिया गया है। इस कार्यक्रम को आगामी वर्ष में कार्यान्वित किया जायेगा।

शिक्षा मन्त्रालय द्वारा अनेक महत्वपूर्ण पुस्तकें प्रकाशित हुईं। माध्यमिक स्कूलों के लिए हिन्दी में पारिभाषिक शब्दों की कार्य-निर्वाहक सूचियों का भी उल्लेख किया जा सकता है।

शिक्षा संस्थाओं में दिया मुनाफ़ा कर सिलाने की प्रणाली के अधिक से अधिक उपयोग को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से शिक्षा मन्त्रालय ने यूनेस्को के सहयोग से शिक्षण लेने वाले छात्रों के लिये तीन महीने के वर्ष मेंसूच में भाग

से बर्दे १९५३ तक लगाये । १९५३-५४ के बजट में शिक्षा मन्त्रालय के बजट मुना कर सिखाने वाले विभाग के कार्यों के लिए ६५,००० रुपये की व्यवस्था की गयी थी ।

भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार ने अभिलेख प्राप्त करने, छात्रों को अनुसन्धान की सुविधाएं देने तथा अभिलेखों के प्रशिक्षण की सुविधाओं की व्यवस्था करने में अच्छी प्रगति की । इस विभाग के लिये १९५३-५४ में ७,९३,७०० रुपये निर्धारित किये गये ।

पुरातत्व विभाग ने इस वर्ष अपने कार्यों के लिये ४४,२६,००० रुपये की स्वीकृति दी । भाग 'ख' राज्यों के राष्ट्रीय महत्व के सभी स्मारक इस विभाग द्वारा प्राप्त कर लिये गये हैं और इसके लिये ६,९६,००० रुपये की लागत पर दो नये केन्द्र खोले गये हैं ।

शरीर रचना शास्त्र विभाग ने दक्षिण बंगाल में अपने दो केन्द्रों में सामूहिक जीवन पर अपनी अभिलेख रिपोर्ट पूरी कर ली है । इस विभाग के लिए ७,१३,००० रुपये रखे गये हैं ।

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य सेवाओं के डायरेक्टर जनरल का कार्यालय चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यों पर अपना नियन्त्रण रखता तथा इनके सम्बन्ध में स्वास्थ्य मन्त्रालय को आवश्यक परामर्श देता है ।

केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद्

अगस्त १९५२ में एक केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् की स्थापना की गई । इस परिषद् में केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री और राज्यों के स्वास्थ्य मन्त्री होते हैं । केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री इस परिषद् का अध्यक्ष होता है । यह परिषद् स्वास्थ्य, चारों ओर के स्वस्थ वातावरण, पोषिकता, स्वास्थ्य शिक्षा के सभी पहलुओं से

सम्बन्धित विषयों पर विचार और सिफारिश करती तथा प्रशिक्षण और अनुसन्धान आदि को सुविधाओं को प्रोत्साहन देती है।

स्वास्थ्य मन्त्री का विवेकानुदान

अनुसन्धान कार्यों में संलग्न तथा चिकित्सा सम्बन्धी सहायता की व्यवस्था करने वाली संस्थाओं की सहायता के लिये प्रति वर्ष ३ लाख रुपये की व्यवस्था की जाती है। धानु वर्ष में कोढ़ के अनुसन्धान कार्य, तपेदिक की चिकित्सा, अन्वों की सहायता, बालकल्याण, प्राइवेट चिकित्सा-संस्थाओं के लिये अस्पताल के उपकरणों तथा दवाओं की खरीद, प्राइवेट चिकित्सा संस्थाओं तथा कल्याण-केन्द्रों के लिये भवन निर्माण तथा चलते-फिरते दवाखानों की व्यवस्था आदि कार्यों के लिए सहायता दी गई।

स्वास्थ्य मन्त्री का कल्याण-कोष

इस कोष में से चिकित्सा तथा स्वास्थ्य संस्थाओं की स्थापना, वर्तमान चिकित्सा तथा स्वास्थ्य-संस्थाओं की सहायता देने तथा समाज-कल्याण के कार्यों को प्रोत्साहन देने में व्यय किया जाता है।

सरकारी नौकरों के लिए स्वास्थ्य-सेवा

सरकारी नौकरों के लिए अनुदायी स्वास्थ्य सेवा की एक योजना बनाई गयी है जिससे केन्द्रीय सरकार के सभी वर्गों के कर्मचारियों को चिकित्सा सम्बन्धी उचित सुविधाएँ दी जा सकें।

अस्पतालों का पुनर्गठन

राज्य स्थित मानसिक रोग का अस्पताल अब से सीधे केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण और प्रबन्ध में रहेगा और १९५४-५५ के बजट में इसके लिए १५,१६,४०० रुपये की व्यवस्था रखी गयी है। अस्पताल के पुनर्गठन की योजना पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत रखी गयी है।

नई दिल्ली स्थित विंसेगडन अस्पताल तथा नर्सिंग होम १ जनवरी, १९५४ को नई दिल्ली म्युनिसिपल कमिटी से भारत सरकार द्वारा अपने अधिकार में ले लिए गये। दोनों का विस्तार किये जाने की सम्भावना है।

१ मार्च, १९५४ को भारत सरकार ने सऊथरजंग अस्पताल भी अपनी रेल रेल में ले लिया। इसके पहले यह अस्पताल दिल्ली राज्य सरकार के नियन्त्रण में इलिन अस्पताल के एक भाग के रूप में चल रहा था। इस अस्पताल में एक गुप्त रोग-प्रशिक्षण केंद्र तथा एक शरीर चिकित्सा प्रणाली विभाग (फीजियोथेरेपी) खोले जा रहे हैं।

बम्बई स्थित टाटा मेमोरियल अस्पताल के ले लिये जाने के प्रश्न का निर्णय होने तक भारत सरकार ने अस्पताल को १९५३-५४ से तीन वर्षों के लिए १,००,००० रुपये की सहायता देने का निर्णय किया है। अस्पताल की व्यवस्था एक ऐसी समिति करेगी जिस में भारत सरकार के दो प्रतिनिधि होंगे।

अखिल भारत मानसिक स्वास्थ्य संस्था

भारत सरकार ने १,५०,००० रुपये के अनुवर्तक व्यय तथा १,२६,५०० रुपये के आवर्तक व्यय पर बंगलोर में एक अखिल भारत मानसिक स्वास्थ्य संस्था स्थापित करने का निर्णय किया है। संसद सरकार वर्तमान अस्पताल के भवनों के विस्तार तथा उपकरणों की खरीद में योग्य होंगे। आशा है कि संस्था का कार्य शीघ्र ही आरम्भ हो जायगा।

अन्तर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस को अनुदाय

अन्तर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति के अनुदान पर भारत का वार्षिक अनुदाय बढ़ाकर ७५,००० रुपये वार्षिक करने का निर्णय किया गया है। जेनेवा स्थित लीग ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटीज द्वारा किये गये कार्य की प्रशंसा में भारत सरकार ने १९५२-५३ में ५०,००० रुपये का अनुदाय दिया।

स्वास्थ्य शिक्षा

सिनेमाओं, पथों तथा पुस्तिकाओं को सहायता से स्वास्थ्य शिक्षा को योजना द्वारा नागरिकों में सार्वजनिक और व्यक्तिगत सफाई की भावना पैदा करने का विचार किया जा रहा है।

स्थायी रूप से एक केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा व्यूरो की स्थापना करके स्वास्थ्य शिक्षा के कार्यक्रम का विस्तार करने का विचार है।

प्रशिक्षण और अनुसन्धान

विस्थापित लड़कियों और महिलाओं को उपयोगी धर्मों में लगाने के लिए उनके प्रशिक्षण की दृष्टि से पुनर्वास मन्त्रालय ने उन्हें वाइयों का प्रशिक्षण देने की एक योजना चालू की है। यह प्रशिक्षण करोवाबाद तथा राजपुरा स्थित सहायता-शिविरों से सम्बन्धित अस्पतालों में तथा बिल्ली के लंबी हाड़िंग अस्पताल और सेंट स्टीफेंस अस्पताल में दिया जायेगा।

वल्लभभाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट

बिल्ली विद्वद्विद्यालय के अस्थापित वल्लभभाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट में तपेदिक की बीमारी की चिकित्सा सम्बन्धी डिप्लोमा-कोर्स प्रारम्भ किया गया है। आर्थिक दृष्टि से इस संस्था की व्यवस्था भारत सरकार के ही नियन्त्रण में है।

नसिग कालेज

१९५३ में कालेज में बी. एस. सी. (मानस) के लिए १९ छात्राएं और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए १५ छात्राएं भरती की गईं। यह कालेज अन्ततः अखिल भारत चिकित्सा विज्ञान संस्था का ही एक अंग बन जायेगा।

भारत की मलेरिया निवारक संस्था

इस संस्था का एक मुख्य कार्य मलेरिया की रोक-थाम के निम्नलिखित पहलुओं पर अनुसन्धान करना है। चिकित्सा अधिकारियों का अध्ययन काल, जो पहले छः सप्ताह का था, अब १२ सप्ताह का कर दिया गया है। राज्य सरकारों द्वारा भेजे गये छात्र ही इस में अध्ययन करते हैं। विचारधीन वर्ष में २२ चिकित्सा अधिकारियों (इनमें दो शिलार्यों विद्वत् स्वास्थ्य-संगठन की ओर से अफगानिस्तान के थे) तथा १३५ मलेरिया इन्स्पेक्टरों (नेपास के १९ इन्स्पेक्टरों सहित) को प्रशिक्षण दिया गया।

भारतीय औषधि संस्कार ग्रंथ

भारतीय औषधि संस्कार ग्रंथ समिति का काम, जो २३ नवम्बर १९५३ तक का था, एक वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। कलकत्ता स्थित भार.

जी. कार मेडिकल कालेज के शैवचि विज्ञान के अध्यापक डा. बी. एन. घोष इस समिति के नये अध्यक्ष नियुक्त किये गये ।

विश्व-स्वास्थ्य संगठन

भारत १९४८ में विश्व-स्वास्थ्य संगठन की स्थापना के समय से, उसका सदस्य रहा है । दक्षिण पूर्वी एशिया के लिये इसका प्रादेशिक कार्यालय नई दिल्ली में स्थापित किया गया है ।

१९५३ में विश्व-स्वास्थ्य संगठन ने इसके अथवा भारत सरकार द्वारा चालू की गई विभिन्न योजनाओं में लगे २८ भारतीय कर्मचारियों को वृत्तियाँ दीं ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ का अन्तर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष (यूनिसेफ)

यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र संघ का एक संगठन है । यह गर्भवती माताओं तथा बालकों के लिए स्वास्थ्य कार्यक्रमों को व्यवस्था करता है । सहायता साबारूपता साधनों के रूप में दी जाती है । भारत सरकार ने १९५३ में इस कोष में १५ लाख रुपये दिए और इतने ही रुपये वह चालू वर्ष में देना चाहती है ।

परिवार आयोजन

परिवार आयोजन के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक अध्ययन किया जा रहा है । इसके दो केन्द्र दिल्ली में तथा एक केन्द्र मैसूर राज्य में है । अध्ययन का परिणाम १९५४ में मिलने की आशा है ।

तपेदिक निरोध कार्य

डॉ. सी. डी. के डीके लगाने का कार्यक्रम, जो अन्तर्राष्ट्रीय तपेदिक निरोध आन्दोलन, विश्व-स्वास्थ्य संगठन और संयुक्तराष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष की सहायता से १९४८ में आरम्भ किया गया था, और अधिक विस्तृत कर दिया गया है । यह आन्दोलन २१ राज्यों तक फैला दिया गया है और ऐसी आशा है कि शीघ्र ही शेष राज्यों में भी पशुंच जायगा । दिसम्बर १९५३ के अन्त तक २ करोड़ ५६ लाख व्यक्तियों की परीक्षा की गयी और लगभग

८० लाख व्यक्तियों को बी. सी. जी. के टीके लगाये गये। इस आन्दोलन के विस्तार के साथ-साथ गृहणी स्थित प्रयोगशाला से विभिन्न राज्यों को टीके अधिक मात्रा में भेजने को कहा गया है। प्रयोगशाला से टीके मलाया, सिंगापुर, बर्मा और लंका भी भेजे जाते हैं। गृहणी में बी. सी. जी. को टीका प्रयोगशाला के लिए नये भवन का निर्माण किया जा रहा है। जुलाई १९५३ में मेहरोली में एक तपेविक अस्पताल स्थापित किया गया और दूसरा अस्पताल स्थापित किया जाने वाला था।

आवश्यक कानून

धात्री शिक्षा, वनत चिकित्सा और औषधि तैयार करने के व्यवसायों पर नियंत्रण रखने के लिए कानून बना दिया गया है। केन्द्रीय धात्री शिक्षा परिषद्, वनत चिकित्सा परिषद् और औषधि शिक्षा परिषद् स्थापित की जा चुकी हैं।

१९५३ का औषधि और चामत्कारिक चिकित्सा विधेयक (आपत्तिजनक विज्ञापन) राज्य परिषद् में दिसम्बर १९५३ में प्रस्तुत किया गया और परिषद् द्वारा फरवरी १९५४ में पास किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य है औषधियों के विज्ञापनों पर नियन्त्रण तथा चामत्कारिक चिकित्सा उपायों के विज्ञापनों को रोकना।

संसद में प्रस्तुत १९५२ का खाद्य मिलावट विधेयक प्रवर समिति के सामने आ चुका है। इसमें निम्नलिखित ध्येयस्थाएँ हैं—(१) एक केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला की स्थापना जिसके पास खाद्यों के नमूने विशेषज्ञों की सम्मति के लिए भेजे जायेंगे, (२) एक केन्द्रीय खाद्य स्तर समिति की स्थापना जिसमें केन्द्रीय और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे और ये प्रतिनिधि कानून के प्रशासन सम्बन्धी विषयों पर सलाह-मदिवरा देंगे और (३) खाद्य वस्तुओं तथा अन्य वस्तुओं के स्तर को नियन्त्रित करने से सम्बन्धित कानून बनाने का अधिकार केन्द्रीय सरकार को देना।

पुनर्वास

१९५१ की अखिल भारतीय जनगणना के अनुसार पश्चिम तथा पूर्व पाकिस्तान से भारत आने वाले कुल विस्थापित व्यक्तियों की संख्या ७२ लाख २५ हजार है। तब से अब तक पूर्वी पाकिस्तान से ६ लाख ५५ हजार व्यक्ति भारत आ चुके हैं। इस प्रकार विस्थापित व्यक्तियों की संख्या ७८ लाख ५० हजार तक पहुँच गई है।

• देहातों में पुनर्वास

पश्चिम पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों में से किसान विस्थापित फिर से पूरे तौर पर बसाये जा चुके हैं। भूमि दिए जाने के अलावा जिन व्यक्तियों की आवश्यकता थी उन्हें बीज, बेल, औजार आदि खरीदने के लिए ऋण भी दिए गये हैं। १९५३-५४ के अन्त तक इस प्रकार ६ करोड़ १० लाख रुपये के ऋण वितरित किये जा चुके होंगे।

पूर्व पाकिस्तान से आये विस्थापित खेतिहर और सामान्य परिवारों की कुल संख्या २ लाख ६२ हजार है। ये सब परिवार पूर्वी प्रदेश के बेहारी क्षेत्रों में बसाये जा चुके हैं। अनुमान है कि १९५३-५४ के अन्त तक मकानों के लिए ऋण, खेतों के औजारों की खरीद आदि के लिए ६ करोड़ ६२ लाख रुपये उन्हें दिये जा चुकेंगे।

शहरी बस्ती

पश्चिम पाकिस्तान ■ आये लगभग २४,७०,००० विस्थापित व्यक्ति ३,७६,००० घरों में बसाये जा चुके हैं। उन्हें २७,००० निष्क्रमणार्थी ठूकानें तथा २,००० औद्योगिक संस्थान भी आवंटित किये जा चुके हैं और विभिन्न कस्बों में ३२,००० नयी ठूकाने बनायीं जा चुकी हैं।

पूर्व पाकिस्तान ■ आये विस्थापित व्यक्तियों को मकान बनाने के लिए सरकार की ओर से जमीन और ऋण दिये गये हैं। अक्टूबर १९५३ के अन्त तक २,५६,००० मकान या तीस बनकर तैयार हो चुके थे या बनाये जा रहे थे।

अनुमान है कि १९५३-५४ के अन्त तक विभिन्न गृहनिर्माण योजनाओं पर सहायता और ऋण के रूप में १३ करोड़ ३४ लाख रुपये व्यय किये जा चुकेंगे।

ऋण

विस्थापित व्यक्तियों को तीन प्रकार के ऋण दिये गये : (१) उन विस्थापित व्यक्तियों को राज्य सरकारों द्वारा दिये गये ऋण जो अपने निजी कारोबार स्थापित करना चाहते हैं; ये ऋण केवल नयी बस्तियों के निवासियों को ही दिये गये, (२) पुनर्वास-वित्त-प्रशासन द्वारा दिए गये ऋण, (३) नयी बस्तियों में नये उद्योगों की स्थापना के लिये उद्योगपतियों को दिये गये ऋण। इसके अतिरिक्त लाभदायक नौकरियाँ प्राप्त करने में सहायता देने के सम्बन्ध में उनमें से कुछ को सरकारी नौकरियाँ बिलवार्ड गयीं और कुछ को प्राइवेट नौकरियाँ, और शेष लोगों को सरकार द्वारा संगठित औद्योगिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण की योजनाओं से लाभ पहुँचा।

शिक्षा

विस्थापित छात्रों की रियायतों और अनुदानों के रूप में सहायता दी गयी। नयी संस्थाओं की स्थापना द्वारा तथा वर्तमान संस्थाओं को सहायता देकर शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं का भी विस्तार किया गया। १९५३-५४ में पश्चिम पाकिस्तान से आये विस्थापित छात्रों की शिक्षा पर १ करोड़ रुपये और पूर्व पाकिस्तान से आये विस्थापित छात्रों की शिक्षा पर २८ लाख रुपये व्यय किये गये।

सहायता

पश्चिम पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्ति

१९५०-५१ में सभी सहायता-शिविरों के बंद किये जाने के समय से केवल उन्हीं महिलाओं और बच्चों, नुर्द्दों और अशक्त व्यक्तियों को सहायता दी जा रही है जिनकी देख भाल करने वाला कोई नहीं है। तपेदिक के रोगियों को आर्थिक सहायता दी जा रही है। कुछ बस्तियों में चिकित्सा सम्बन्धी सहायता की सुविधाएँ भी दी गई हैं।

निराश्रित महिलाओं, बच्चों, बुढ़ों और अशक्त व्यक्तियों को जो अशक्त-गृहों में रह रहे हैं और जिनकी क्षतिपूर्ति की मरगों को जांच हो चुकी है, क्षति-पूर्ति के मामले में प्राथमिकता दी जा रही है। उनसे कह दिया गया है कि वे अशक्त गृह में रह सकते हैं और उनके जीवन निर्वाह पर जो व्यय आवेगा, वह उनको ही जाने वाली क्षतिपूर्ति की राशि में से काट लिया जायेगा। १९५३-५४ के अन्त तक क्षतिपूर्ति के रूप में ३ करोड़ रुपये दिये जा चुकेंगे।

पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्ति

पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापितों के लिये शिविर अभी भी चलाये जा रहे हैं। १९५३-५४ के प्रारम्भ में इन शिविरों में स्थायी रूप से रहने वालों के अतिरिक्त लगभग ८६,००० व्यक्ति थे। जनवरी १९५४ तक यह संख्या घट कर ७६,०७५ रह गई। ४०,००० निराश्रित महिलाओं, बच्चों, बुढ़ों और अशक्तों को भी सहायता दी जा रही है। १९५३-५४ में सहायता काव्य पर २ करोड़ ६० लाख रुपये व्यय किये जायेंगे।

जीवन-निर्वाह भत्ता

पश्चिम पाकिस्तान से आये लगभग १४,००० विस्थापित व्यक्तियों को जीवन-निर्वाह भत्ता दिया जा रहा है क्योंकि वे वृद्धावस्था, अशक्तता, बीमारी आदि के कारण रोजी नहीं कमा सकते और अब तक वे पश्चिम पाकिस्तान में स्थित शहरी चल सम्पत्ति से होने वाली आय पर आश्रित थे।

दिसम्बर १९५३ तक उनके जीवन-निर्वाह पर करीब १ करोड़ २० लाख रुपये व्यय हो चुके थे। ये व्यक्ति उस धेड़ी में आते हैं जिसे अन्तरिम क्षति-पूर्ति योजना के अन्तर्गत उच्च प्राथमिकता मिली हुई है। इनमें से कुछ सौ व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति का धन दिया जा चुका है और उनका भत्ता बन्द कर दिया गया है। जब शेष व्यक्तियों को भी क्षतिपूर्ति दी जा चुकेगी तो भत्ता देना समाप्त कर दिया जायगा।

क्षतिपूर्ति का भुगतान

पश्चिम पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों को, जिनके दावों की जांच की जा चुकी है, क्षतिपूर्ति की योजना को अन्तिम रूप तक नहीं दिया जा सकता अब तक यह माजूम न हो जाये कि निष्कमलाधी सम्पत्ति के मामले में

पाकिस्तान के साथ समझौता हो भी सकता है या नहीं ।

तबतक के लिए, कुछ विशेष प्रकार के विस्थापित व्यक्तियों के सम्बन्ध में एक अन्तरिम योजना स्वीकृत की जा चुकी है ।

भतिपूर्ति के भुगतान के लिए एक विशेष व्यवस्था की गयी है । अन्तरिम भतिपूर्ति योजना के अन्तर्गत कुछ वर्गों के दावेदारों को अधिक प्राथमिकता दी गई है । योजना में उन लोगों को जो जीवन-निर्वाह खर्च पाते हैं, जो अशक्त-गृहों में रहते हैं और जो अशक्त-गृहों के बाहर निःशुल्क सहायता पाते हैं, १६५३-५४ में नकद रुपये दिये जाने की व्यवस्था की गई है । १,३०० से अधिक ऐसे व्यक्तियों को कुल ४२ लाख ५० हजार रुपये दिये जा चुके हैं । अन्तरिम भतिपूर्ति योजना के अन्तर्गत नकद रुपये दिये जाने के बदले में ६,००० मिट्टी के भोपड़ों का स्वामित्व उन भोपड़ों में रहने वालों को दे दिया गया है । इन भोपड़ों की लागत १८ लाख रुपये है । प्राथमिकता वाले १,५००० से अधिक दावेदार योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा बनायी गयी २७ नयी बस्तियों में रह रहे हैं । निवास स्थानों के षट्-स्थायी प्रायंटन सम्बन्धी पहली कार्रवाई के रूप में सम्पत्तियों का मूल्यांकन किया गया है । निष्क्रमणार्थियों के सकारों या सरकार द्वारा बनेबाए गये घरों में रहने वाले प्राथमिकता वाले दावेदारों को १ नवम्बर १९५३ से किराया देने से मुक्त कर दिया गया है ।

पाकिस्तान के साथ समझौता-वार्ताएँ

कराची में जुलाई और अगस्त १९५३ में हुए विचार विनिमय के फल-स्वरूप चल सम्पत्ति समझौता की कई मर्कों को कार्यान्वित किये जाने का निर्णय हो चुका है । इस समझौते का सम्बन्ध है निष्क्रमणार्थियों के उन गृह तथा सम्पत्तियों के बेचने या हटाने से, जो या तो कस्टोडियन के अधिकार में हैं, या मित्रों के पास हैं या पुनर्वस के लिए ले ली गई हैं, अधिकार में की गई चल-सम्पत्ति को फिर से प्राप्त करने से, गाढ़े हुए वन को हटाये जाने से, कस्टोडियन के पास रहित भित्री की रकम तथा चल-सम्पत्ति के हस्ताभरण से तथा पोस्ट आफिस सेविंग बैंक एकाउन्टों तथा पोस्टल पासबुक्स के हस्ताभरण से ।

श्रम

कानून

इस वर्ष की महत्वपूर्ण कानून पास हुए—औद्योगिक विभाग (संशोधन) कानून १९५३ और एम्प्लाइज प्राविडेन्ट फंड (संशोधन) कानून १९५३। पहले कानून में कारखाने के बन्द होने या छुटनी की प्रवस्था में मजदूरों को सतिपूर्ति देने की व्यवस्था है। कारखाने के बन्द होने के सम्बन्ध में कानून में जो व्यवस्थाएँ हैं, वे १ अप्रैल १९५४ से लागू उद्योग के लिए भी लागू कर दी गईं। एम्प्लाइज प्राविडेन्ट फंड (संशोधन) कानून १९५३ इसलिये बनाया गया कि जिससे उक्त कानून के कुछ दोषों और प्रशासन सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर किया जा सके।

श्रम कानूनों का कार्यान्वित किया जाना

एम्प्लाइज प्राविडेन्ट फंड योजना

एम्प्लाइज प्राविडेन्ट फंड कानून उन मजदूरों पर लागू होता है जो सीमेंट, सिगरेट, निजली के सामान तथा यांत्रिक और सामान्य इंजीनियरिंग का सामान बनाने वाले उद्योगों, ध्वार्ड, कागज, वस्त्र उद्योग तथा लोहा एवं इस्पात उद्योग में लगे हों। कानून तभी लागू होगा जब किसी कारखाने में लगे मजदूरों की संख्या ५० या उससे अधिक हो। यह सरकारी कारखानों या स्वाधीन संस्थाओं और उन संस्थाओं पर लागू नहीं होगा जिन्हें स्थापित तीन वर्ष से कम समय हुआ है। विसम्बर १९५३ के अन्त तक उन कारखानों से, जिन पर यह कानून लागू होता है, कुल प्राविडेन्ट फंड ६ करोड़ ४६ लाख रुपये संग्रहीत हुआ। यह धन औद्योगिक गृह-निर्माण योजना के लिये व्यय किया जायेगा।

योजना को कार्यान्वित किए जाने के सम्बन्ध में पर्याप्त अनुभव प्राप्त कर लेने पर, इसे अन्य उद्योगों पर भी लागू किया जायेगा।

इस समय कोयला खान प्राविडेन्ट फंड और मोनस योजना में भाग लेने

वालों की संख्या ६,६३,३३९ है। ३१ अक्टूबर १९५३ तक १२,२८७ को ११,७८,४४१ रुपये प्राविडेन्ट फंड दिया गया।

७ मई, १९५३ को इम्प्लाइड स्टेट इन्सुरेन्स योजना, १९४६, पंजाब के कई औद्योगिक क्षेत्रों में भी लागू की गई—अमृतसर, बटाला, लुधियाना, जालंधर, भिवानी, भम्बुल्लापुर—जगाधरी और भम्बाला। इस योजना के कलकत्ता शहर और हवड़ा जिले में कार्यान्वित किये जाने की तैयारियाँ की गई हैं। इसे नागपुर, कोयम्बटूर तथा मध्य भारत के कुछ कस्बों में भी लागू करने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

खेतों में काम करने वाले मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरें निर्धारित की गयीं हैं जो बिहार राज्य के पटना डिबोखन, उत्तर प्रदेश के मुल्तानपुर, प्रतापगढ़, आजमगढ़, बाना, बारानांकी, जौनपुर, रामगरेली, फंजाबाद, हमीरपुर, बलिया, गाजीपुर तथा जालौन जिलों के ५० या उससे अधिक एकड़ के फार्मों में काम करने वाले मजदूरों, अजमेर, बिलासपुर, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, पेप्सू, पंजाब, राजस्थान, मंसूर और त्रिपुरा के दूरे दूरे राज्यों, तथा बिस्म्य प्रदेश में सीपी जिले, पश्चिम बंगाल में बार्जीलिंग और जलपाईगुड़ी जिले, और आसाम में कछार जिले के लिये लागू होती हैं।

मद्रास गोदी कर्मचारी (भौकरी के नियम) योजना १९५२ के प्रयासनाथ मद्रास गोदी श्रम बोर्ड जुलाई १९५३ में स्थापित किया गया।

औद्योगिक सम्बन्ध

जनवरी १९५३ से अक्टूबर १९५३ तक श्रम सम्बन्धी झगड़ों और काम-बिनों की हानि की संख्या क्रमशः ८१८ और २५,५३,५२६ की।

कुल मिलाकर ज्ञान, बड़े मन्दरगाह, रेलवे, बैंकिंग तथा शीमा कम्पनी सम्बन्धी १८ औद्योगिक झगड़े धनबाद और कलकत्ता स्थित स्थायी ट्रिब्यूनलों के सामने रखे गये। इनके अलावा अन्य १२ झगड़े राज्य सरकारों के ट्रिब्यूनलों को तथा एक झगड़ा एतदर्थ ट्रिब्यूनल को सौंपा गया।

सामाजिक-

आसाम तथा पश्चिम बंगाल में कुछ चाय बागानों के बंद किये जाने से जो मजदूर बेकार हो गये थे, वे या तो नये बागों में लगा लिए गये या उन्हें कुछ दूसरा काम दिया गया ।

श्रम कल्याण

कोयला खान

कोयला खान श्रम कल्याण कीष के १९५३-५४ के बजट में सामान्य कल्याण के लिए ७८,००,००० रुपये के और गृह निर्माण के लिए २२,००,००० रुपये के व्यय की व्यवस्था है । सामान्य कल्याण के अन्तर्गत अधिकांश व्यय सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्रोत्साहन देने और शिक्षा पर होगा । इसके अतिरिक्त कोयले की खानों में काम करने वाले मजदूरों के कल्याण के लिए निम्नलिखित योजनाएँ स्वीकृत की गई हैं :—

(१) ३,०२,००० रुपये के अनुमानित व्यय पर शिक्षा, मनोरंजन सम्बन्धी तथा अन्य सुविधाएँ देने वाले बहुद्देशीय केन्द्र ।

(२) बिहार के कोयला खान क्षेत्र में चार महिला कल्याण केन्द्र और हैदराबाद के कोयला खान क्षेत्र में एक संयुक्त मातृमंगल शिक्षा कल्याण केन्द्र ।

(३) जाँदा तथा तलचर के कोयला खान क्षेत्रों में से प्रत्येक में एक-एक शिक्षा केन्द्र तथा बिहार के कोयला खान क्षेत्र के लिए छः शिक्षा केन्द्र ।

(४) भरिया, रानीगंज, तलचर तथा सम्बलपुर के कोयला खान क्षेत्रों की बहु-उद्देशीय संस्थाओं में ७०० रुपये प्रति सेट वाले दस रेडियो लगाये जायेंगे । इनके साथ-साथ लाउड स्पीकरों की भी व्यवस्था होगी । इसके अलावा जाँदा के कोयला खान क्षेत्रों के मजदूरों के लिए तीन रेडियो लगाये जायेंगे ।

(५) हैदराबाद की सट्टी कोयला खानों में काम करने वाले मजदूरों के मातापिता के लिये ३,००० रुपये के व्यय पर एक खुली हुई मोटर जरीबी आयगी ।

(६) जगज्जान स्थित केन्द्रीय अस्पताल के पुनर्वासि केन्द्र तथा पालना विभाग के ५० कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए दूसरा पाठ्यक्रम जिससे अशक्त मजदूरों को सहायता दी जा सके और उन्हें दूसरा काम मिलीया जा सके।

एक संशोधित गृह निर्माण योजना भी तैयार की गयी है जिसके अन्तर्गत कोयला खान के उन मालिकों को अरुण तथा सहायता दी जायगी जो मजदूरों के लिए मकान बनायेंगे।

अन्नक की खानें

अन्नक खान अन्न कल्याण कोष के कार्य-क्षेत्र में बिहार, आन्ध्र, राजस्थान और अजमेर के अन्नक खान क्षेत्र आते हैं। इस कोष के वार्षिक बजट में इन राज्यों में कल्याण-कार्य के लिये क्रमशः १३,६०,००० रुपये, ४,३३,००० रुपये, १,२६,००० रुपये तथा ४४,००० रुपये के अर्थ की व्यवस्था है। बम्बई, मेसूर, तिरुवांकुर-कोचीन, मध्य भारत तथा मध्यप्रदेश के अन्नक खान क्षेत्रों में कल्याण कार्य आरम्भ करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। कोयला-खान के मजदूरों की भाँति अन्नक खान के मजदूरों को भी चिकित्सा, शिक्षा, मनोरंजन तथा भक्षण सम्बन्धी सौख्य ही सुविधाएँ दी गई हैं।

सामान्य कल्याण-कार्य

१९४३-४४ में कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा संचालित अल्पकालीन समाज कल्याण कार्य के पाठ्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय और राज्य सरकारों के तीस अन्न-अधिकारियों को सामाजिक कार्य का प्रशिक्षण दिया गया। केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों के अन्तर्गत काम करने वाले सभी अन्न-अधिकारी एक केन्द्रीय समूह के अन्तर्गत आते हैं।

वर्तमान भारत में बागानों में मजदूरों के भरती-किय जाने की कानूनी प्रथा उन्मूलन सम्बन्धी सर्व प्रथम उपाय के रूप में भद्रात, तिरुवांकुर-कोचीन, मेसूर और कुछ सरकारों से इस प्रथा की मुरादियों की रोकथाम के लिये कुछ उपाय करने की प्रार्थना की गयी है।

खान विधि, १९४२ की व्यवस्थाओं को लागू करने की कार्रवाहियों तथा

वेखभान के परिणाम स्वरूप हैदराबाद के कोयला खान क्षेत्रों तथा कोत्तार के स्वर्ण-खान क्षेत्रों में घुघटनाएं काफी कम हो गयीं।

खानों में ऐसी घुघटनाओं को जिनके फलस्वरूप मृत्यु हो जाए, रोकने के लिए प्रभावकारी उपाय किये गये। खान विधि, १९५२ के अन्तर्गत सभी प्रकार की खानों के लिए एक से नियमों को नियामाबली तैयार की गयी है।

कारखानों का निरीक्षण

विस्तृत टेक्निकल सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार ने चुने हुए उद्योगों में उत्पादन-क्षमता के और भुगतान को सुधरी हुई प्रणालियों के जामू किये जाने के लिए एक विशेषज्ञ मण्डली की सेवाएं प्राप्त की हैं। पहले छः महीनों में विशेषज्ञ प्रबंधकों तथा मजदूर सभाओं के सामने यह सिद्ध कर सके कि थोड़े समय के प्रशिक्षण से भी कारखानों के कार्य तथा उत्पादन क्षेत्रों में काफी प्रगति हो सकती है।

बम्बई में एक केन्द्रीय भ्रम-संस्था स्थापित की जाने वाली है। संस्था में एक सामाजिक-आर्थिक प्रयोगशाला के रूप में कार्य होगा और इसमें भ्रम संबंधी समस्याओं के विषय में विशेष प्रशिक्षण दिया जायगा। इसके अतिरिक्त इस संस्था में उद्योग से सम्बन्धित सभी लोगों के लिये कल्याण-कार्य करने वाले प्रत्येक वर्ष की स्थान प्राप्त होगा।

कृषि-भ्रम सम्बन्धी जांच

कृषि-भ्रम सम्बन्धी जांच के प्रथम सोपान अर्थात् गांव के सामान्य पर्यवेक्षण को रिपोर्ट 'एग्रोकल्चरल वेजेंज इन इण्डिया' शीर्षक खंड में प्रकाशित हुई है।

इसी सम्बन्ध में दूसरे और तीसरे सोपान अर्थात् परिवार सम्बन्धी सामान्य पर्यवेक्षण और परिवार सम्बन्धी विस्तृत पर्यवेक्षण को रिपोर्टें और राज्यों पर और आवश्यक ग्राफिकल-रिपोर्टें भी प्रकाशित की जाने वाली हैं।

श्रम-सम्बन्धी जाँच

इस वर्ष 'भारत के जीवन निर्वाह-ध्वज के सूचनार्थक' शीर्षक विषय पर एक विशेष लेख तैयार किया गया। काजू उद्योग में काम करने वाले मजदूरों की स्थिति, भारत में महिला-मजदूरों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति, तथा भवन और निर्माण उद्योग आदि की भी जाँच की गयी।

श्रम सम्मेलन

भारत सरकार अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-संगठन के कार्य में पूरी गति से भाग लेती रही। भारत सरकार ने जिन महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और बैठकों में अपने प्रतिनिधि भण्डस भेजे, उनमें से जून १९५३ में जेनेवा में हुए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन ■ ३६ में अधिवेशन; दिसम्बर १९५३ में टोकियो में हुए दूसरे एशियाई प्रादेशिक सम्मेलन; तथा अक्टूबर १९५३ में संका में हुए एशियायी सामुग्रिक सम्मेलन का उल्लेख किया जा सकता है।

१९५३-५४ में हुए राष्ट्रीय श्रम-सम्मेलनों और श्रम समिति की बैठकों में जुलाई १९५३ में नई दिल्ली में हुआ स्थायी श्रम समिति का १३ वाँ अधिवेशन; जनवरी १९५४ में मैसूर में हुआ भारतीय श्रम सम्मेलन का १३ वाँ अधिवेशन; तथा फरवरी १९५४ में नई दिल्ली में हुई संयुक्त उद्योग एवं श्रम सलाहकारी बोर्ड की पाँचवीं बैठक सम्मिलित हैं।

टैक्निकल सहायता

इस वर्ष जो टैक्निकल सहायता मिली, उसमें विशेषज्ञों से मिला परामर्श, बुनियादी तथा अनुसन्धान सम्बन्धी उपकरण सम्मिलित हैं।

विशेषज्ञों की सहायता

विभिन्न टैक्निकल सहायता कार्यक्रमों के अन्तर्गत श्रम मन्त्रालय की सहायता के लिए बस विदेशी विशेषज्ञ नियुक्त किये गये हैं। ये विशेषज्ञ औद्योगिक स्वच्छता, समाज-सुरक्षा तथा उत्पादन क्षमता सम्बन्धी अध्ययन आदि के विषय में कार्यक्रम तैयार करते हैं। इसके अलावा श्रम मन्त्रालय को दो विशेषज्ञ और भिजे गये हैं जो अगामी के क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण को प्रोत्साहन देने

सम्बन्धी तथा उद्योग सम्बन्धी प्रशिक्षण की योजनाओं से सम्बन्धित हैं।

वृत्तियाँ

केन्द्रीय और राज्य सरकारों तथा उद्योग-मालिकों तथा मजदूरों ■ संघ-
ठनों के ३१ अधिकारों निम्न विषयों के प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजे गये :
कम लागत के गृह-निर्माण, प्रौद्योगिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण, श्रम-सम्बन्ध,
प्रौद्योगिक स्वच्छता, श्रम सम्बन्धी श्रैकडों का संकलन आदि।

उपकरण

चतुर्थ सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त १,६५,००० रुपये के उपकरण,
विशेषज्ञों की सहायता के ही एक शृंग हैं।

प्रशिक्षण और नौकरी

पुनर्वास और नौकरी के डायरेक्टरेट जनरल के भविष्य के सम्बन्ध में
शिवराव समिति की रिपोर्ट सरकार को बी जा धुकी है। इस वर्ष बिजनौर,
बुलन्द शहर, इटावा, फतेहगढ़, लखीमपुर-खैरी, मथुरा, मिर्जापुर, मुजफ्फर
नगर तथा सीतापुर के नौ कामदिलाऊ केन्द्र बन्द किये गये। इण्डनगंज,
सहरियासराय, बिलिगुन द्वीप तथा धाना में चार नये कामदिलाऊ केन्द्र खोले
गये। १९५३ के अन्त तक कुल मिलाकर १२६ कामदिलाऊ केन्द्र काम कर रहे
थे। दिसम्बर १९५३ के अन्त में केन्द्रों के रजिस्ट्रों में ५,२२,३६० लोगों के
नाम दर्ज थे जबकि १९५२ के अन्त में यह संख्या ४,३७,५७१ थी। १९५३ में
लगभग ११,२१८ विस्थापित व्यक्तियों को नौकरी दिलाई गयी। छुट्टी किये
गये ८,१०० सरकारी नौकरों को भी कामदिलाऊ दफ्तरों द्वारा काम दिलाया
गया। इनमें से ४,१३७ व्यक्ति केन्द्रीय सरकार के भूतपूर्व नौकर थे और
३,९६३ राज्य सरकारों के भूतपूर्व नौकर थे। कामदिलाऊ दफ्तरों के द्वारा
२८,०४० अनुसूचित जाति के तथा ३,२०३ अनुसूचित उपजातियों के आर्थियों
को नौकरी दिलाई गयी और वर्ष के अन्त में ४७,४२८ अनुसूचित जाति के
तथा ३,५६३ अनुसूचित उपजातियों के आर्थियों के नाम रजिस्टर में दर्ज थे
जो काम की खोज में थे।

पुनर्वास और नौकरी के डायरेक्टरेट जनरल के कार्यालय में एम्प्लायमेंट

अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी। १६ अधिकारियों ने प्रारम्भिक प्रशिक्षण प्राप्त किया।

प्रशिक्षण केन्द्र

इण्डस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, बिस्ली; कलकत्ता का रोजर्स शोर्टहैंड स्कूल और महिलाओं के लिए मद्रास स्थित इण्डस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर १९५३ में बन्द कर दिये गये। दिसम्बर १९५३ के अन्त में कुल प्रशिक्षण केन्द्रों व संस्थाओं की संख्या ५६ थी; ३२ औद्योगिक तथा २३ व्यावसायिक विषयों का प्रशिक्षण दिया गया।

विस्थापित व्यक्तियों को 'एग्रिमेंट्सशिप' के रूप में प्रशिक्षण दिये जानें के कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में ५२ विस्थापित व्यक्तियों ने और पश्चिम बंगाल में ४८८ विस्थापित व्यक्तियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।

कोनो-बिलासपुर स्थित सेन्ट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में लगभग २०० व्यक्तियों ने इन्स्ट्रक्टरों का प्रशिक्षण प्राप्त किया।

२. आर्थिक

वित्त

वित्त-मन्त्रालय केन्द्रीय सरकार के वित्त को तथा देश के समस्त वित्तीय मामलों की व्यवस्था करता है। यह केन्द्रीय राजस्व की भी व्यवस्था करता है। केन्द्रीय सरकार के सभी प्रकार के व्यय का निमन्त्रण भी वित्त-मन्त्रालय ही करता है। इसके अलावा यह सरकार की कर तथा ऋण सम्बन्धी नीतियों का भी संचालन करता है। साथ ही साथ बैंकिंग तथा मुद्रा सम्बन्धी समस्याओं को देखभाल भी यही मन्त्रालय करता है और इससे यह आशा की जाती है कि यह देश के विदेशी विनिमय के उचित उपयोग को भी व्यवस्था करेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि केन्द्रीय मन्त्रालयों से निकट सम्पर्क होने के कारण इसका कार्य क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है।

वित्त-मन्त्रालय में दो विभाग हैं। एक विभाग राजस्व और व्यय की देखभाल करता है; दूसरा विभाग बजट और आर्थिक मामलों की व्यवस्था करता है।

राजस्व तथा व्यय विभाग तीन भागों में बँटा हुआ है : राजस्व विभाग जो 'सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू' के नाम से विदित है, प्रसैनिक-व्यय विभाग और प्रतिरक्षा-व्यय विभाग।

राजस्व-विभाग

■ विभाग परीक्ष तथा अपरीक्ष कर सम्बन्धी नीतियों की रचना करता

है और यही उनके प्रशासन के लिए उत्तरदायी है। एक कानून द्वारा, सीमा शुल्क और उत्पादन कर कानूनों के अन्तर्गत इसे अपील सुनने का भी अधिकार प्राप्त है। यह आयकर के उचित प्रशासन के लिए आवेश भी जारी करता है और इस क्षेत्र में इसका कार्य अधिकांशतया सभन्वय करने का है। आयकर-कानून के अन्तर्गत इसे कुछ मौलिक और अपील सुनने के अधिकार प्राप्त हैं। भू-सम्पत्ति-कर कानून के प्रशासन का भार जो १५ अक्टूबर १८५३ से लागू हुआ है, आयकर विभाग पर है। भू-सम्पत्ति कर कानून, १९५३ के अन्तर्गत सेन्ट्रल बोर्ड आफ रेवेन्यू को अपील सुनने का भी अधिकार होगा और यह सम्पत्ति के मूल्यांकन और जिम्मेदारियों के निर्धारण सम्बन्धी अपीलों भी सुन सकेगा। बोर्ड के अपील सम्बन्धी आवेशों के फलस्वरूप उत्पन्न किसी भी कानूनी तबाल को यह हाईकोर्ट के पास भी भेज सकेगा।

आयकर विभाग के अधिकारियों को भू-सम्पत्ति कानून की व्यवस्थाएँ समझाने के लिए दिल्ली में एक कर्मचारी प्रशिक्षण-वर्ग चालू किया गया था। इसमें भारत के सभी क्षेत्रों से आये ४५ चुने हुए अधिकारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। क्योंकि हमारा भू-सम्पत्ति कर कानून ब्रिटेन के भू-सम्पत्ति कर कानून पर आधारित और करीब-करीब उस जैसा ही है, इसलिए भू-सम्पत्ति कर कानून के प्रशासन सम्बन्धी प्रशिक्षण के लिए कोलम्बो योजना के अन्तर्गत ६ अधिकारियों को ब्रिटेन भेजने का निर्णय किया गया है।

इस विभाग के मुख्य कार्यों का उत्सेख निम्नलिखित रूप से किया जा सकता है :—

आयकर

आयकर जांच कमीशन का कार्य ३१ दिसम्बर, १९५५ तक बढ़ा दिया गया है। ३१ दिसम्बर १९५३ तक कमीशन के सामने १,६६८ मामले पेश हुए। इनमें १,०३१ मामलों का निबटारा हो चुका है और शेष मामलों की जांच पूरी की जा रही है। जिन मामलों का फैसला हो चुका है उनका सम्बन्ध आय के छिपाये जाने से था और इस प्रकार ४५ करोड़ रुपये की आय छिपाई गयी थी। इन आयों का कर निर्धारण और उन पर कर लेने का कार्य जारी है।

द्विपार्श्व हुई आय स्वयं अपनी इच्छा से स्वीकार किये जाने का कार्यक्रम जिसकी घोषणा मई १९५१ को की गयी थी, २२ अक्टूबर १९५१ तक जारी रहा। इसके फलस्वरूप अब तक ८० करोड़ रुपये की आय का पता लग चुका है। इससे राजस्व प्राप्त होने के अलावा, कस्बाता और आयकर विभाग के बीच अच्छे सम्बन्ध स्थापित हुए हैं।

केन्द्रीय उत्पादकर

जनवरी १९५३ से नवम्बर १९५३ तक सीमा शुल्क सम्बन्धी नियमों के भंग किये जाने के २१,०८२ मामलों का पता लगा। इस प्रकार इन मामलों में ६७,३६,३७१ रुपये का माल डूबर-डूबर किया गया।

चोरी से माल लाने-ले जाने पर रोक

स्थलीय और जलयान सीमाओं पर चोरी से माल लाने-ले जाने के काम को रोकने के उपाय किये गये और जहाँ आवश्यक हुआ, वहाँ ऐसे उपाय लागू किये गये। इस योजना के अन्तर्गत समुद्र में चलने वाले जहाजों और जोप गाड़ियों की सेवाएं और ही उपलब्ध की जायेंगी। इनमें हथियारों और रेडियो की व्यवस्था रहेगी।

नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में 'स्वर्ण सोवक' नामक एक विशुद्ध यंत्र का प्राविष्कार किया गया है जिससे सोना चुराकर ले जाने वाले व्यक्तियों के पास से सोने का पता लगाया जा सकेगा। ऐसे यंत्रों का परीक्षण बम्बई तथा कलकत्ता के सीमा शुल्क कार्यालयों में किया जा रहा है।

आर्थिक विषय विभाग

इस विभाग को चार भागों में विभक्त किया गया है जो क्रमशः वयट, आंतरिक वित्त, योजना तथा बाह्य वित्त सम्बन्धी व्यवस्था करते हैं।

वयट विभाग

यह विभाग केन्द्रीय वयट तैयार करता है, पर इसमें रेलवे वयट सम्मिलित नहीं होता। प्रतिरक्षा सेवाओं के प्रावक्तनों की जीप और उनका संग्रह प्रतिरक्षा विभाग करता है। वयट विभाग ऋण तथा छोटी वयटें

जारी करने, सरकारी ऋण के (सरकार की ओर से जिसकी व्यवस्था रिजर्व बैंक करता है) प्रशासन तथा हिसाब और आय-व्यय निरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था के लिए उत्तरदायी है। वजेट विभाग संसद् के सामने आय-व्यय निरीक्षण की रिपोर्ट और विनियोग खाता भी प्रस्तुत करता है।

कर-जानि कमिशन की स्थापना अप्रैल १९५५ में हुई। आशा है कि यह प्रयोग अपनी रिपोर्ट १९५४ में अन्त तक ले देगा।

आंतरिक वित्त विभाग

इस विभाग का सम्बन्ध भुक्त और सिकों, रिजर्व बैंक और बैंकिंग, ऋणालय के प्रशासन, बहुमूल्य धातुओं की जाँच करने वाली संस्थाओं और इण्डिया सिन्थोरेटो प्रेस, पुनर्वासित वित्त प्रशासन, औद्योगिक वित्त कारपोरेशन तथा राज्य-वित्तीय कारपोरेशनों से है। यह विभाग हिसाब किताब, कम्पनी कानून तथा बोमा सम्बन्धी समस्याओं का भी निपटारा करता है। इसके अतिरिक्त इसके और भी कई कार्य हैं।

(१) यह विभाग सारी सम्बन्धी कार्यों, कुवोर तथा छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए वित्त की व्यवस्था करता है।

(२) अधिक मूल्य के नोटों के न होने से वाणिज्य और उद्योग के क्षेत्र में होने वाली असुविधा को दूर करने की दृष्टि से इस विभाग ने शीघ्र ही १,००० रुपये, ५,००० रुपये और १०,००० रुपये के नोट फिर से चालू करने का निर्णय किया है। पुराने नोटों को जिनका मूल्य घटा दिया गया था, फिर से जारी नहीं किया जायगा और नये नोट जारी किये जायेंगे।

बैंकिंग कम्पनियों के ऋण-निस्तार सम्बन्धी कार्रवाइयों की जाँच-पड़ताल के लिए १९५२ में एक समिति नियुक्त की गयी थी। समिति के सुझाव पर बैंकिंग कम्पनी कानून संशोधित किया गया था। आशा है कि कानून द्वारा संशोधित प्रक्रिया के फलस्वरूप उन लोगों को जिन्हें भूतकाल में बैंकों के खेल होने से घाटा सहना पड़ा, कुछ सहायता मिल सकेगी।

देहाती क्षेत्रों में बैंकों की शाखाएँ

२० जून १९५३ को समाप्त होने वाले दो वर्षों में भारतीय इम्पीरियल बैंक ने विभिन्न देहाती क्षेत्रों में २७ शाखाएँ खोलों और नौ छोटे सखानों को शाखाओं में परिवर्तित कर दिया गया।

पुनर्वास वित्त प्रशासन

पुनर्वास वित्त प्रशासन द्वारा परोक्ष रूप से दिए जाने वाले ऋण का अधिकतम परिमाण ७ करोड़ रुपये से साढ़े बारह करोड़ रुपये कर दिया गया है। ज्वॉइंट स्टॉक बैंकों के माध्यम से विस्थापित व्यक्तियों में ऋण के रूप में वितरित किये जाने के लिए २ करोड़ रुपये सुरक्षित रखे गए हैं। पर यदि सब रुपये वितरित न किये जा सकें तो शेष राशि ऋण के इच्छुक लोगों को सीधे प्रशासन द्वारा दे दी जायेगी। ऋणों की प्रदायगी की अवधि १० वर्ष से बढ़ाकर १५ वर्ष कर दी गई है। ३१ जनवरी १९५४ तक प्रशासन के लिए ६५,७३२ प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए थे। इनमें से ६१,५५८ प्रार्थनापत्रों पर विचार किया जा चुका है और शेष प्रार्थनापत्रों की परीक्षा की जा रही है। कुल मिलाकर १५,५५४ व्यक्तियों को लगभग १२ करोड़ ५ लाख रुपये दिया जाना स्वीकृत हो चुका था, किन्तु इसमें से अभी तक केवल ७ करोड़ ५७ लाख रुपये ही वितरित किये गये हैं। अनुमान है कि स्वीकृत ऋणों से एक लाख विस्थापित व्यक्तियों को परोक्ष रूप से फिर से जताया जा सकेगा और करीब २ लाख विस्थापितों को ऋण लेने वाले व्यक्तियों द्वारा आरम्भ किये गये औद्योगिक तथा वाणिज्य-व्यवसायों में काम बिलाकर अपरोक्ष रूप से जताया जायगा।

पूँजी सम्बन्धी नियंत्रण

१९५३ में २७२ प्रार्थियों ने ८६ करोड़ ८० लाख रुपये की पूँजी लड़ी करने की अनुमति माँगी। इनमें से औद्योगिक कम्पनियों की ओर से आये १२४ प्रार्थनापत्र स्वीकार कर लिए गये जिनमें ७१ करोड़ ४० लाख रुपये की पूँजी लड़ी करने की व्यवस्था है और सात प्रार्थनापत्र जिनमें ४६ लाख ७० हजार रुपये की पूँजी लड़ी करने की व्यवस्था थी, अस्वीकार कर दिए गए। इन सातों प्रार्थनापत्रों में बोलस छोड़ जारी करने की अनुमति माँगी गयी थी। इसके

मालाका १० करोड़ रुपये की पूंजी लड़ी करने के गैर-आर्थिक कम्पनियों से साथ प्रार्थनापत्र स्वीकृत हुए और ७ करोड़ ६० लाख रुपये की पूंजी सम्बन्धी ३३ प्रार्थनापत्र स्वीकृत हुए थे।

इस वर्ष विदेशी व्यक्तियों और कम्पनियों के १२१ प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए। इन प्रार्थनापत्रों में कुल मिला कर साढ़े २० करोड़ रुपये की पूंजी लगाने की अनुमति मांगी गयी थी। इनमें से १०१ प्रार्थियों को इस देश में १७३ करोड़ रुपये की पूंजी लगाने की अनुमति दी गई और शेष प्रार्थियों को आवश्यक अनुमति नहीं दी गयी।

योजना विभाग

इस वर्ष इस मन्त्रालय के योजना विभाग ने जिन बड़े-बड़े आर्थिक प्रश्नों पर विचार किया, उनमें से सबसे अधिक महत्वपूर्ण समस्या थी नई नौकरियों के लिए प्रवर्तन का अभाव। यह महसूस किया गया कि प्रत्येक व्यवस्था में अपर्याप्त विनियोग ही बेरोजगारी का मुख्य कारण है। इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र में विकास-अध्ययन की दर बढ़ाने का तथा पंचवर्षीय योजना में उचित रूप से संशोधन करने का निर्णय किया गया। इस प्रकार समय में वृद्धि होने से अधिक से अधिक लोग रोजगार से लग सकेंगे।

अभाव-ग्रस्त क्षेत्रों के स्थायी सुधार के लिए अंतिम योजना में ४० करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है और इस राशि को उन विभिन्न राज्यों में बाँट दिया गया है, जिन पर ऐसी अपेक्षाएँ आईं। प्रारूप योजना में अकाल सम्बन्धी आपत्तिकालीन सहायता-कार्य के लिए १५ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। ४० करोड़ रुपये की व्यवस्था इससे अलग है। ये सहायताएँ केन्द्रीय बजट का ही स्थायी अंग बन जाएँगी।

बाह्य-वित्त-विभाग

यह विभाग विदेशों के साथ भारत के वित्तीय और आर्थिक सम्बन्धों की देखरेख करता है। यह विभाग विनियम-निष्पन्न, वित्तीय सम्झौतों के कार्यान्वित किये जाने तथा विदेशों से लिये गये और विदेशों को दिए गये ऋणों के लिए भी उत्तरदायी है। आयात और निर्यात सम्बन्धी नीतियों के निर्धारण में

आर्थिक

यह विभाग वाणिज्य एवं उद्योग, खाद्य एवं कृषि और कार्य, गृह-निर्माण तथा पूर्ति मंत्रालयों से निकट सहयोग पूर्वक कार्य करता है।

इस विभाग का अन्तर्राष्ट्रीय सहायता समन्वय विभाग पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित किये जाने में विदेशों तथा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से भारत को प्राप्त होनेवाली आर्थिक सहायता से सम्बन्धित मामलों की देखभाल करता है।

भारत में विदेशों पूंजी के प्रवाह को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से सरकार ने अपनी नीति अधिक उदार कर दी है पहले यह निर्णय किया गया था कि यदि भारत में पूंजी लगाने वाले विदेशी व्यक्ति चाहें तो उन्हें वह पूंजी वापस लेने की अनुमति दे दी जायेगी जो इस देश में जनवरी १९५० के बाद लगायी गयी है। किन्तु अब निर्णय यह किया गया है कि इन सुविधाओं का विस्तार इस प्रकार किया जाये कि पूंजी के मूल्य में होने वाली कोई भी वृद्धि इनके अन्तर्गत आ जाए।

१९५२ के अन्त में मिस्र में पौड के भारी अभाव के कारण पौड के क्षेत्र के बिकट आयात सम्बन्धी कड़ी रोक लगायी गयी थी। इससे मिस्र को होने वाले भारतीय निर्यात के मूल्य पर बुरा प्रभाव पड़ा। देश के निर्यात की रक्षा के लिए ८ जुलाई १९५३ को एक व्यापार और भुगतान सम्बन्धी करार किया गया।

भुगतान पर रोक

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के समझौते के अनुच्छेद १४ के अन्तर्गत, जो भी सदस्य राष्ट्र १ मार्च १९५२ के बाद वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय लेनदेन के भुगतान पर रोक जारी रखना चाहे, उसे इस रोक को जारी रखने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के साथ समझौता करना पड़ेगा। यदि कोई भी देश इस रोक को एक साल से अधिक जारी रखना चाहे तो ऐसे समझौतों का मक्कराण कराना पड़ेगा। इस व्यवस्था के अनुसार १९५३ के उत्तरार्द्ध में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के साथ परामर्श किया गया। भारत सरकार ने यह आवश्यक समझा कि पंचवर्षीय योजना के उचित रूप से कार्यान्वित किये जाने की दृष्टि से वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय लेनदेन के भुगतान पर विनिश्चय-नियन्त्रण सम्बन्धी रोक अभी और

जारी रखी जाये। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष ने, बात चीन के बाद नवम्बर १९५३ में रोक एक वर्ष के लिए और जारी रखना स्वीकार कर लिया।

राष्ट्रमंडल के वित्त मन्त्रियों का एक सम्मेलन १९५४ में ८ जनवरी से १५ जनवरी तक सिडनी में हुआ। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व भारत के वित्त मन्त्री, कैम्बेरा स्थित भारतीय हाई कमिश्नर तथा एक अधिकारी-मंडल में किया। सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों ने विश्व-व्यापार और बहुमापी भुगतानों ■ स्वतन्त्र प्रवाह की स्थिति पैदा करने के निश्चय को फिर दोहराया। पौंड मुद्रा को दृढ़ बनाना तथा इसकी परिवर्तनशीलता इस उद्देश्य की सबसे पहली आवश्यकताएँ हैं। इसी दृष्टि से सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों ने ऐसी नीतियों पर चलने का निश्चय किया जिससे ये उद्देश्य प्राप्त किये जा सकें। इसके परिणाम स्वरूप पौंड मुद्रा के क्षेत्र के देशों को अपने साधनों के शीघ्र विकास के लिए दृढ़ प्रयत्न-नीतियाँ बनानी और साननी पड़ेंगी और इनसे पौंड के सम्पूर्ण क्षेत्र के भुगतानों की स्थिति में सुधार हो सकेगा। भारत की पंचवर्षीय योजना का पौंड क्षेत्र के उद्योगित उद्देश्यों के साथ पूरा सामंजस्य है।

बामोदर घाटी कारपोरेशन के उपयोग के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से गत वर्ष लिया गया १ करोड़ ६५ लाख डालर का ऋण घट कर १ करोड़ ५ लाख डालर रह गया है। अन्य योजनाओं में जिनके लिए बैंक से और ऋण मिलने की प्राप्ति है, दाम्बे में विद्युत-उत्पादन-केन्द्र तथा बम्बई राज्य में कोयना में जल-विद्युत-केन्द्र के निर्माण की व्यवस्था है। इन दो योजनाओं के विषय में बैंक को आवश्यक जानकारी करा दी गई है।

भारत-अमेरिका टेक्निकल सहयोग करार १९५२ के अन्तर्गत अमेरिकन सरकार ने ७ करोड़ ७१ लाख डालर की सहायता और देने का निर्णय किया है। इस में ■ १०० रेलइंजनों, ५००० मालगाड़ी के डिब्बों, २ लाख टन लोहा और इस्पात तथा सिंघाई तथा विद्युत योजनाओं के लिए उपकरणों के आयात के लिए ६ करोड़ ५ लाख रुपये सुरक्षित रखे गये हैं।

कोलम्बो योजना में भाग लेने वाली सरकारों ने भारत को इसके विकास-

आर्थिक

कार्यक्रम के लिए और अधिक सहायता देने का निर्णय किया। प्राप्त किया तथा म्यूजीलैंड से मिलने वाली सहायताओं पर अभी भी विचार-विमर्श चल रहा है। कनाडा से मिली सहायता का उपयोग रेल-इंजिनों, तार-उद्योग ■ लिए कच्चे माल का आयात तथा मयूराक्षी और ऊष्ण भोजनाओं के लिए उपकरणों आदि के लिए किया जायगा।

फोर्ड-प्रतिष्ठान में चालू वर्ष में १० लाख डॉलर देने का निर्णय किया है। यह धन अधिकांशतः समाज-शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा ग्राम-सफाई के, प्रशिक्षण पर व्यय किया जायेगा।

भारत ने नेपाल को २ करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देने का निर्णय किया है। इसका उपयोग सड़क सुधारने तथा छोटे सिंचाई कार्यों आदि के लिए किया जाएगा।

टेक्निकल सहायता की योजनाएँ धीरे-धीरे महत्वपूर्ण हो गई हैं। अब तक भारत को विदेशी सरकारों अथवा संस्थाओं से २७७ विशेषज्ञों की सेवाएँ मिल चुकी हैं। इसी के साथ साथ ७२० भारतीय विशेष प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजे गये हैं।

कोलम्बो योजना के अन्तर्गत भारत ने सबसे भे, दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों को टेक्निकल सहायता दी है। इन देशों को ६ भारतीय विशेषज्ञ भेजे गये और इन देशों के २०७ व्यक्ति भारत में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं।

इस वर्ष भारत सरकार ने दक्षिणी जर्मनी की सरकार का टेक्निकल सहायता का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है।

राष्ट्रीय बचत संगठन

इस संगठन के अन्तर्गत भंडार को छोड़ कर समस्त भारत आ जाता है। भंडार राज्य की अपनी भ्रमण बचत योजना है। छोटी बचत योजना के अन्तर्गत २६५२-५३ में ४० करोड़ १० लाख रुपये का शुद्ध संग्रह हुआ जबकि गत वर्ष

सातवाँ वर्ष

साढ़े अठतीस करोड़ रुपये का ही संग्रह हुआ था। संग्रह करने में कुल व्यय ०.८ प्रतिशत हुआ। इसमें कर्मचारियों का वेतन, प्रचार-व्यय तथा अधिकृत एजेन्टों का कमीशन सम्मिलित है।

योजना कमीशन की सिफारिश पर महिला समाज कार्यकर्तों तथा महिला-संगठनों की सेवाओं से व्यापक विस्तार का संग्रह-आन्दोलन आरम्भ किया गया। इस आन्दोलन का परिणाम उत्साहवर्धक रहा। १०० महिला तथा अन्य समाज सेवा संगठनों को एक कर्ष के लिए अधिकृत अभिकर्त्रियों के रूप में नियुक्त किया जायगा।

मध्य प्रदेश में ग्राम-पंचायतों के द्वारा देहली क्षेत्रों में छोटी-बचत आन्दोलन को लोकप्रिय बनाने को एक योजना चालू की जा रही है। अन्ततः यह योजना भारत के सभी राज्यों में चालू की जायगी।

विभिन्न राष्ट्रीय पर्यवेक्षण

इस योजना के अन्तर्गत देश की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति के अंकड़ों का संग्रह किया जा रहा है। निम्न पर्यवेक्षण किये जा रहे हैं : (१) दिल्ली और अन्य स्थानों में आरम्भिक रोजगार सम्बन्धी पर्यवेक्षण, (२) बम्बई में विस्थापित व्यक्तियों सम्बन्धी पर्यवेक्षण, (३) फरीदाबाद का सामाजिक और आर्थिक पर्यवेक्षण, (४) जालुवर्ष १९५२ और वित्तीय वर्ष १९५२-५३ के लिए उत्पादन करने वाले उद्योगों का पर्यवेक्षण तथा (५) कर-जोख कमीशन और प्रेस कमीशन की ओर से जांच पड़ताल का कार्य।

सिंचाई और विद्युत

१९५२ में स्थापित इस मन्त्रालय का काम तेजो से आगे बढ़ा। हीराकुड बांध योजना सीधे इसके नियन्त्रण में कर दी गई है। भाग 'ख' और 'ग' के राज्यों की सिंचाई और विद्युत योजनाएँ, जो पहले राज्य-मन्त्रालय के अधीन थीं, अब इस मन्त्रालय के अन्तर्गत आ गई हैं। यह मन्त्रालय नदी घाटी योजनाओं के बहुद्देशीय विकास, पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सभी योजनाओं, राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं की जाँच पड़ताल, राज्य सरकारों को वित्तीय-सहायता देने तथा सिंचाई और विद्युत सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय अगड़ों के निपटारे के लिए उत्तरदायी है। विद्युत सम्बन्धी कानून बनाने तथा अन्तर्राष्ट्रीय नदियों तथा नदी घाटियों के लिये भी यही मन्त्रालय उत्तरदायी है। इस मन्त्रालय का कार्य सुचारु रूप से चलाये जाने की दृष्टि से, इसे एक उच्च प्रशासन अधिकारी के नियन्त्रण में रखा गया है जो सचिव कहलाता है।

अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनादि

भू-यान्त्रिकी तथा भौम सम्बन्धी इंजीनियरिंग का तीसरा अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन अगस्त १९५३ में स्विट्जरलैंड में हुआ था। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व हीराकुड अनुसन्धान केन्द्र के डिप्टी डायरेक्टर ने किया। उन्होंने बड़े-बौध सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय आयोग की कार्यकारिणी समिति और उपसमिति की बैठकों में भी भाग लिया जो सितम्बर १९५३ में पेरिस में हुई। मन्त्रालय से सम्बद्ध मुख्य यान्त्रिक ने अगस्त १९५३ में मिनियापोलिस में हुई अन्तर्राष्ट्रीय जल-शक्ति अनुसन्धान संस्थान बैठकों में भाग लिया।

केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग

जल-विभाग

इस विभाग के सभी कार्यालयों का पुनर्संगठन किया गया है। प्रौद्योगिक सामान्य-शक्ति तथा विभिन्न नदी घाटी योजनाओं की अगले १०-१५ वर्ष की आवश्यकताओं के समन्वय की स्थिति का उचित रूप से अनुमान लगाने के लिए

सभी राज्य सरकारों से ठीक-ठीक आंकड़ों का संग्रह किया जा रहा है।

नदी घाटी योजनाओं के नमूनों तथा इन योजनाओं के कार्यों के विवरण वाले पोस्टरों की वेंच की विभिन्न प्रदर्शनियों में प्रदर्शित किया गया।

पूना-स्थित केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसन्धान केन्द्र ने विभिन्न योजनाओं के सम्बन्ध में कई उपयोगी प्रयोग किये हैं।

विद्युत विभाग

यह विभाग चतुर्मुखी समन्वय स्थापित करने की दृष्टि से विकास योजनाओं की जांच करता है। यह विभाग कोयला योजना, दम्बई के विद्युत्-तोकरण-ट्राम्वे के विद्युत्-तोकरण की योजना, दामोदर घाटी कारपोरेशन की विद्युत-व्यवस्था का कलकत्ता तथा पटना तक विस्तार करने जैसी बड़ी-बड़ी योजनाओं के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार और योजना कमिशन को परामर्श भी देता है। कमिशन विस्तृत जांच कर चुका है, डिजाइनें तैयार कर चुका है, कच्छ, बिन्ध्य प्रदेश, सौराष्ट्र आदि की विद्युत योजनाओं का कार्यक्रम तैयार कर चुका है तथा दामोदर घाटी कारपोरेशन, भाखरा-नांगल और हीराकुड योजनाओं के सम्बन्ध में परामर्श दे चुका है। पेप्सु, राजस्थान, हैदराबाद तथा अन्य क्षेत्रों में बिजली का भार सम्बन्धी पर्यवेक्षण किया गया जिससे इसके विकास-कार्य का अनुमान लगाया जा सके। कमिशन के विद्युत-उत्पादन-केन्द्र-निर्माण विभाग ने इंदौर, नांगल, पोर्ट ब्लेयर, भावनगर, गोरखपुर, मुरादनगर, राजमंगपुर और दिल्ली में विद्युत-उत्पादक यन्त्र लगाने तथा उनको सफाई आदि का कार्य किया।

दामोदर घाटी कारपोरेशन

दामोदर घाटी कारपोरेशन ने विभिन्न योजनाओं के सम्बन्ध में अच्छी प्रगति की है। तिलैया योजना का कार्य, जिसके अन्तर्गत पक्का बांध और जल विद्युत केन्द्र का निर्माण होना था, पूरा हो चुका है।

कोनार बांध में पानी इकट्ठा करना आरम्भ हो चुका है जिसका उपयोग बोकारो थर्मल केन्द्र में ठंडा करने की प्रक्रिया के लिए किया जायेगा। सिचाई

के लिए पानी के उपयोग पर विचार किया जा रहा है। आशा है कि बाँध-निर्माण सम्बन्धी कंकरीड का काम १९५४ के मागसूम के पूर्व ही पूरा हो जायगा। केवल कुछ छुटपुट काम को छोड़ कर नोकरो थर्मल केन्द्र का काम करीब-करीब पूरा ही हो चुका है। ५०,००० किलोवाट के प्रत्येक एकक के हिसाब से तीन एककों का काम चालू हो चुका है।

विजली के प्रसार और वितरण के कार्य प्रोग्राम के अनुसार चल रहे हैं। २६८ मील की लम्बाई में विजली के तारों के बिछाये जाने का कार्य तथा १३ प्रिड सब-स्टेशनों तथा रिस्त्रिबुट केन्द्रों का निर्माण भी हो चुका है। मैनन योजना में पानी का बहाव बदलने वाली सुरंग और गलियों का निर्माण हो चुका है और बांध का काम १९५४ के मध्य तक पूरा हो जाने की आशा है। आशा है बांध १९५४-५५ तक और जल विद्युत केन्द्र १९५५-५६ तक बन कर तैयार हो जायेंगे।

पांचेत पहाड़ी योजना के कार्य के सम्बन्ध में बहाव का रास्ता बदलने वाली नालियों की खुदाई और बांध का काम तेजी से चल रहा है। तिब्बत के बांध तथा नहर योजना सम्बन्धी प्रारम्भिक कार्य पूरा हो चुका है। बाँध-निर्माण के सम्बन्ध में कंकरीड का काम और रेत भरने का काम तेजी से चल रहा है। आशा है योजना सम्बन्धी कार्य १९५७ तक पूरा हो जायेंगे।

वित्थापित व्यक्तियों को फिर से बसाने की दृष्टि ■ कारपोरेशन ने १९५३ में १०,७८७ एकड़ भूमि खरीदी। भूमि अधिकार कानून के अन्तर्गत ७,६२३ एकड़ भूमि के लिए नोटिस जारी कर दी गयी है और शेष कार्रवाई आगामी वर्ष में पूरी हो जायगी। नामोदर घाटी कारपोरेशन के विभिन्न कार्यों द्वारा वित्थापित व्यक्तियों को कुल मिलाकर २२,६१,८०० रुपये का नकद मुआविका दिया गया है। ४,३१४ एकड़ भूमि मुआविके के रूप में वित्थापित व्यक्तियों को दी गयी। अब तक विभिन्न योजनाओं द्वारा ३,६६५ परिवारों को फिर से बसाया जा चुका है।

हीराकुड बाँध योजना

हीराकुड बाँध योजना के कार्य का पहला भाग पूरा होने वाला है। इसमें

मुख्य बाँध का निर्माण, छोटे बाँध, चार एकड़ों का एक विद्युत उत्पादक केन्द्र, ४०० मील की लम्बाई में बिजली के तार बिछाना तथा सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण आदि आते हैं। बाढ़ को रोकने के अलावा इस योजना की सहायता से सम्मलपुर, बोलनगिर तथा पटना जिलों में कुल मिलाकर ४,४८,६०० एकड़ भूमि को सिंचाई हो सकेगी और २,०८,५०० किलोवाट बिजली पैदा की जा सकेगी। जुलाई १९५५ तक बिजली और सिंचाई के लिए पानी की सुविधाएँ उपलब्ध होने लगेंगी।

भाखड़ा-नंगल योजना

भाखड़ा-नंगल योजना भारत की सबसे बड़ी बहु-उद्देशीय योजना है। इस योजना के अन्तर्गत बनने वाला ६८० फुट ऊँचा बाँध संसार का सबसे ऊँचा बाँध है। इसके अतिरिक्त इस योजना के अन्तर्गत ६५० मील लम्बी नहरें तथा २,००० मील से अधिक लम्बी सहायक नहरें आ जाती हैं। नंगल हाइडल गहर से सिंचाई और बिजली का निर्माण ये दोनों काम होंगे। इस नहर द्वारा भाखड़ा सिंचाई प्रणाली में पानी पहुँचाया जायगा तथा जल-विद्युत पैदा की जायेगी। भाखड़ा नहर और उसकी छोटी-बड़ी बालिका कुल मिलाकर २,८६० मील की लम्बाई में पौलो होंगी और साथ ही दो विद्युत-उत्पादक केन्द्र भी होंगे।

तुंगभद्रा योजना

आंध्र राज्य की स्थापना के साथ-साथ आंध्र और मद्रास राज्यों के एक समान हितों की दृष्टि से तुंगभद्रा बोर्ड स्थापित किया गया। बोर्ड की स्थापना किसी भी एक राज्य से सम्बन्धित मामलों को देखभाल के लिए हुई थी; किन्तु बाद की एक ओर आंध्र और मद्रास सरकारों और दूसरी ओर हैदराबाद की सरकार के बीच हुए समझौते के फलस्वरूप बोर्ड को आंध्र, मद्रास और हैदराबाद-तीनों राज्यों के लिये एक से कायों या एक सी योजनाओं सम्बन्धी कार्यों के सम्बन्ध में सभी मामलों पर नियन्त्रण का अधिकार मिला। किन्तु हैदराबाद सरकार हैदराबाद राज्य में पड़ने या आने वाली योजनाओं के सम्बन्ध में निर्माण तथा संचालन कार्य, बोर्ड के नियंत्रण में स्थगित करती रहेगी। बोर्ड ने नित्य प्रति के कामकाज की देखभाल के लिए दो उपसमितियाँ बनाई गई हैं।

काकरापार बाँध-महर योजना

इस योजना के कार्य में सन्तोषजनक प्रगति हो रही है। ४०,००० एकड़ भूमि की सिंचाई की सुविधाएँ हो गई हैं। दिसम्बर १९५३ के अन्त तक इस योजना पर कुल ३ करोड़ ३४ लाख रुपये व्यय हुए।

कोसी योजना

जल-अन्तरिक्ष विद्या सम्बन्धी आँकड़ों के संकलन ■ लिये किए जाने वाले निरीक्षण के अलावा बेल्टा बाँध सम्बन्धी जाँच-पड़ताल का कार्य जून १९५३ में पूरा हुआ। जाँच-पड़ताल के आधार पर तैयार किये गये नक्शों और आवश्यकताओं पर सलाहकार समिति के साथ विचार-विमर्श हुआ और बाद को उनके सुझावों की केन्द्रीय जल एवं विद्युत आयोग द्वारा जाँच भी हुई। नवम्बर १९५३ में आयोग ने एक योजना-कार्यक्रम तैयार किया जिसमें तीन एकड़ सम्मिलित थे।

इस योजना पर एतदर्थ टेक्निकल सलाहकार समिति ने विचार किया। समिति में इस योजना के कार्यान्वित किये जाने की सिफारिश की। यह कार्य बिहार सरकार के नियंत्रण में होगा और आवश्यक टेक्निकल सहायता केन्द्रीय सरकार देगी।

उकाई बाँध योजना

विस्तृत जाँच पड़ताल के लिये एक विभाग खोला गया है जिसका प्रधान कार्यालय सूरत में है।

उड़ीसा राज्य योजनाएँ

दिकारपारा और नरज बाँधों के लिये जो महानदी पर बनाये जायेंगे, जल विज्ञान तथा अन्तरिक्ष विज्ञान सम्बन्धी निरीक्षण किये जा रहे हैं।

नर्मदा घाटी योजना

बर्गी, तवा, पुनासा तथा भड़ौच योजनाओं के लिए जल-अन्तरिक्ष विज्ञान सम्बन्धी आँकड़ों का संकलन किया जा चुका है। तवा तथा पुनासा योजनाओं से

सम्बन्धित रिपोर्टों तथा प्राक्कलनों का परीक्षण किया जा रहा है।

साबरमती योजना

जांच-कार्य पूरा हो चुका है और योजना सम्बन्धी रिपोर्टें विचाराधीन हैं।

आसाम की योजनाएँ

कुछ महत्वपूर्ण भवियों के सम्बन्ध में जल विज्ञान और आन्तरिक विज्ञान सम्बन्धी आकड़ों का संकलन किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश की योजनाएँ

ऊपरी महानदी (सटियारा) योजना सम्बन्धी रिपोर्टें का परीक्षण किया जा रहा है।

दिल्ली-राज्य बिजली बोर्ड

बोर्ड के बिजली उत्पादन यंत्र की स्थापित क्षमता ५४,००० किलोवाट है। इस यंत्र से ३८,००० किलोवाट बिजली से आसानी से पैदा की जा सकती है। अभी तक अधिकतम ३६,३५० किलोवाट बिजली पैदा की जा सकी है। इस प्रकार १,६५० किलोवाट बिजली कम पैदा हुई। आशा है कि १९५४ के अन्त तक नंगल से १०,००० किलोवाट बिजली मिलने से दिल्ली में बिजली की पूर्ति को स्थिति काफी सुधर जायेगी।

कात्काजी, मालवीय नगर, किलोकी और ओलसा में बिजली लगाई जा रही है।

कृष्णनगर, गौधी नगर, आशाब नगर, मोती नगर, तिलक नगर, रमेश्वर नगर, राजौरी गार्डन्स में बिजली लगाने का प्रश्न विचाराधीन है।

१९५३ में ६,३४८ नये स्थानों को बिजली पहुँचाई गयी।

सामूहिक योजना प्रशासन

सामूहिक विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा का उद्देश्य लोगों को अपना रहन-सहन उन्नत करने की प्रेरणा देना है। उन्हें योजना-कार्यों में भाग लेने तथा अपने-अपने क्षेत्रों में विकास-कार्यक्रम कार्यान्वित करने में प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इस उद्देश्य से योजना सलाहकार समितियाँ नियुक्त की गई हैं। इन समितियों के सदस्यों में राज्य विधान तथा जिला बोर्डों के सरकारी सदस्यों के अतिरिक्त पंचायतों तथा सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि भी हैं। राष्ट्रीय विस्तार सेवा-खंडों में भी ऐसी ही सलाहकार समितियाँ बनाई गई हैं। सामूहिक विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा को सहायता प्राप्त स्वयं-सहायता कार्यक्रम कहा जाता है। सामूहिक-योजना के क्षेत्रों में विकास सम्बन्धी कार्यों में जनता का सहयोग एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है। ग्रामीणों द्वारा सहयोग स्वयं अपनी इच्छा से भ्रम के रूप में दिया गया जब कि उन्होंने धन, सामान तथा भूमि के रूप में सहयोग दिया ही था। सितम्बर १९५३ को समाप्त होने वाले वर्ष में १९५२-५३ में आरम्भ की गयी सभी सामूहिक विकास योजनाओं में ग्रामीणों ने ७२ लाख ४० हजार रुपये के मूल्य की भ्रम-सेवाएं दीं और ७४ लाख ६० हजार रुपये के मूल्य की भूमि, सामान, धन आदि दिया। इस प्रकार ग्रामीणों ने स्वयं अपनी इच्छा से १ करोड़ ४७ लाख रुपये के मूल्य की सहायता दी जब कि सरकार ने २ करोड़ ४५ लाख रुपये व्यय किए।

गत वर्ष प्रधान मन्त्री के जन्म दिन पर ग्रामीणों ने कुल मिला कर ४५ लाख रुपये के मूल्य की स्कूलों के लिए भूमि देने, पुस्तकालयों ■ लिए धन देने, खेल-कूद का सामान आदि देने के वचन दिए थे। उन्होंने ३३० स्कूल खोलने का वचन दिया। इसके लिए उन्होंने २,४६० एकड़ भूमि दी और ४ लाख रुपये मकद दिए।

गांवों में लोगों को सामूहिक योजना कार्यक्रम में सहयोग देने के लिए पंचायतों, सहकारी संस्थाओं, युनियन बोर्डों जैसी स्थानीय संस्थाओं द्वारा

प्रोत्साहन दिया जाता है। कुछ क्षेत्रों में लोगों के सहयोग का संगठन एतदर्थ तब आननुविहित आदि संस्थाओं जैसे मध्यप्रदेश में ग्राम विकास मंडलों, उड़ीसा में ग्राम-मंगल समितियों, मद्रास में ग्राम सेवा संघों तथा पश्चिमी बंगाल में पत्नी-उन्नयन समितियों ने किया। इन कार्यों में छात्रों तथा नेशनल केडेट फोर के छात्रों ने भी भाग लिया।

खंडों का आबंधन

१९५२-५३ के लिए विभिन्न राज्यों में कई पूर्ण सामूहिक योजनाएं और व्यक्तिगत विकास खंड आबंधित किये गये जो लगभग ५५ सामूहिक विकास योजनाओं के बराबर थे। ऐसे प्रत्येक पूर्ण सामूहिक योजना में तीन विकास खंड आते हैं जिसके अन्तर्गत ३०० गांव, २ लाख ६० हजार व्यक्तियों की जनसंख्या और ४५० से ५०० वर्गमील क्षेत्र आता है। एक विकास खंड में ६७,००० व्यक्तियों की जनसंख्या के १०० गांव आते हैं; और ऐसे तीन विकास खंडों को मिलाकर एक पूर्ण सामूहिक विकास योजना बनती है।

अक्तूबर १९५३ तक १६७ विकास खंडों में काम आरम्भ हो चुका था, जिनमें भारत-अमेरिका कार्य समझौता के अन्तर्गत १९५२-५३ के लिये आबंधित सभी सामूहिक योजनाएं और विकासखंड, उत्तर पूर्वी सीमान्त एजेंसी के लिए एक विकास खंड और समझौते के बाहर आबंधित जम्मू तथा काश्मीर के लिए तीन खंड सम्मिलित हैं।

जनवरी १९५३ में सामूहिक योजना प्रशासन ने राज्य सरकारों से अनुरोध किया था कि वे प्राथमिकता की दृष्टि से यह बतायें कि १९५३-५४ में विकास कार्य के लिए कौन-कौन से क्षेत्र लेना चाहेंगे। राज्य सरकारों से प्रस्ताव मिसने पर केन्द्रीय समिति द्वारा मैसूर, अजमेर, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर और त्रिपुरा राज्यों को छोड़ कर अन्य सभी राज्यों के लिए ५२ अतिरिक्त सामूहिक विकास खंड निर्धारित किये गये थे। कार्य समझौता के पूरक के अलावा देहरी-गढ़वाल जिले का भिलंगना का एक विकासखंड उत्तर प्रदेश को आबंधित किया गया। इस समय ५१ खंडों में कार्य हो रहा है। राष्ट्रीय विस्तार सेवा का आरम्भ २ अक्तूबर, १९५३ को हुआ और १७२ राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों में काम शुरू हुआ। तब से २७ खंडों में काम और शुरू

किया जा चुका है। इस प्रकार, इस समय २१८ सामूहिक योजना खंडों के अतिरिक्त कुल मिलाकर १६६ राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों में काम हो रहा है। इनके अन्तर्गत ४३,३५० गाँव आते हैं जिनकी कुल जनसंख्या ३ करोड़ ४५ लाख २० हजार है। दो सामूहिक योजना खंडों और ५३ राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों में अभी काम शुरू किया जाता शेष है जो १६५३-५४ के लिए आवंटित किये गये हैं।

आशा की जाती है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना काल (१९५१-५६) में सामूहिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के अन्तर्गत समस्त ग्रामीण जनसंख्या का चौथा भाग अथवा १,२०,००० गाँव ले आये जायेंगे। जनसंख्या की दृष्टि से इन कार्यक्रमों के फलस्वरूप २६½ करोड़ की समस्त ग्रामीण जनसंख्या में से लगभग ७ करोड़ ४० लाख लोगों को लाभ पहुँचेगा।

कार्य की प्रगति

सामूहिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि-विकास को प्राथमिकता दी गयी है। बेकार और ऊसर पड़ी हुई भूमि को खेती योग्य बनाकर; कुओं को खुदाई, नलकूप लगाना, तालाबों का निर्माण आदि जैसी छोटी-छोटी योजनाओं की व्यवस्था करके; अच्छे बीजों की व्यवस्था करके; उर्वरकों की व्यवस्था तथा प्राकृतिक और गढ़ों की खाद के उपयोग को लोकप्रिय बनाकर तथा परिष्कृत कृषि-विधियों के प्रचार द्वारा यह कार्य किया जा रहा है। इस प्रकार, समस्त देश के योजना क्षेत्रों में खाद के १,५०,४६४ गड्डे खोले गये हैं, ७,०६,४७४ मन उर्वरक, २,२१,६६२ मन बीज तथा खेती के १०,००० औजार वितरित किये गये हैं और ५०८ प्रदर्शन-खेत बने हुए हैं। १६,५१० एकड़ भूमि में फलों के वृक्ष लगाये गये हैं और १७,४२३ एकड़ भूमि में सब्जियाँ बोई गई हैं। इसके अलावा ६१,५४७ एकड़ भूमि को खेती-योग्य बनाया गया।

कुएँ तथा तालाब भी पर्याप्त संख्या में बनवाए गये या उनकी मरम्मत कराई गई। सितम्बर १९५३ में समाप्त होने वाले वर्ष में १,३१,३२३ एकड़ भूमि की सिंचाई के लिए पम्पिंग सेट लगवाए गये तथा कई अन्य उपाय भी किए गये।

कृषि का पशुपालन तथा मछली उद्योग से निकट का सम्बन्ध है। पशुओं की नस्ल अच्छी न होने की दृष्टि से उनकी नस्ल सुधारने तथा बीमारियों से रक्षा करने के विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं। सितम्बर १९५३ को सम्पादित होने वाले वर्ष में २५६ प्रजनन और कृत्रिम रेतन केन्द्र खोले गये, ६६,८०५ भैंसों को बधिया किया गया और ४४५ सतंड बिये गये। १२,२३,३८७ पशुओं को टीके लगाये गये और ३,२५,७६१ पशुओं की विभिन्न रोगों के लिए चिकित्सा की गई। मुर्गियों की किस्म सुधारने के लिए ७,२०१ प्रच्छी मुर्गियाँ भी गई। तालाबों में छोटी मछलियों को छोड़कर मछली-पालन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। साल भर में विभिन्न सामूहिक योजना क्षेत्रों में लगभग २२ लाख छोटी मछलियाँ बांटी गयीं।

सामूहिक योजना कार्यक्रम में वर्तमान ग्राम-उद्योगों का विकास तथा नये उद्योगों की स्थापना सम्मिलित है, जिससे बेरोजगार व्यक्तियों को काम दिया जा सके और उन लोगों को पूरा काम दिया जा सके जिन्हें विभिन्न कारणों से वर्ष में काफी समय तक बेकार रहना पड़ता है। अर्थों तथा सुधरे तरीकों के प्रतिकरण की सुविधाओं के द्वारा वर्तमान कुटीर-उद्योगों की उन्नति की जा रही है। कई स्थानों में नये कुटीर-उद्योग स्थापित किये गये।

सामूहिक विकास कार्यक्रम में ग्रामायात के विकास को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अब तक ३,५३३ मील लम्बी कच्ची सड़कें और १५५ मील लम्बी पक्की सड़कें बनवाई जा चुकी हैं।

उद्योगों को बढ़ावा देकर तथा यातायात विकास द्वारा ग्रामों में जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने का विचार किया जा रहा है। यह स्वीकार किया जा चुका है कि ग्राम-जीवन को बढ़ाने में ठोस प्रगति तब तक नहीं हो सकती जब तक ग्रामीणों की अन्य आवश्यकताओं की व्यवस्था नहीं की जाती। इसलिए चिकित्सा सम्बन्धी व्यवस्था, गृहनिर्माण सम्बन्धी पर्याप्त सुविधाओं तथा शिक्षा और समाज-कल्याण को प्रोत्साहन देने पर जोर दिया गया है। स्वास्थ्य और सफाई के क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण कार्य किये गये हैं और १५,१७४ पानी सुखाने के गड्ढे, २,१७५ बेहाती टट्टियाँ तथा १,४४,७०१ गज नालियाँ बनाई गयीं। १,३५४ कुओं का निर्माण कराया गया और ८,८४३ कुओं का पुनरुद्धार किया गया।

प्रशिक्षण

शिक्षा तथा समाज शिक्षा के क्षेत्र में १,४६४ नये स्कूल खोले गये तथा २६१ वर्तमान स्कूलों को दुनियादी स्कूलों में परिवर्तित किया गया, ३,७०७ ग्रामीण शिक्षा केन्द्र तथा ३,०१६ समाज-अभ्युत्थान केन्द्र स्थापित किये गये।

लगभग २,७४६ नये मकान बनवाए गये और १५,१२५ मकानों की मरम्मत आदि की गयी। सामूहिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहकारी संस्थाओं के विकास पर बल दिया गया है और इस और १,०१६ सहकारी संस्थाओं की स्थापना और ग्राम-संस्थाओं को बहुउद्देशीय संस्थाओं में परिवर्तित करके कुछ प्रगति की गयी।

प्रशिक्षण

सामूहिक योजना कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए अधिकाधिक प्रशिक्षण-प्राप्त व्यक्तियों, जैसे प्रशासन अधिकारियों, ग्राम सेवकों, कृषि-विस्तार निरीक्षकों, पशुचिकित्सकों, सहकारी और पंचायत अधिकारियों, स्कूल अभ्यापकों, समाज शिक्षा के व्यवस्थापकों, डाक्टरों, कन्सल्टण्टों, सफाई इन्स्पेक्टरों, स्वास्थ्य निरीक्षकों तथा हजीनियरों आदि की आवश्यकता है। इस लिए ऐसे व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए नयी संस्थाओं की स्थापना अत्यन्त आवश्यक है और आज ३३ विस्तार सेवा प्रशिक्षण केन्द्र चालू हैं। जनवरी १९५४ तक ३,१७० ग्राम सेवक तथा ५५४ निरीक्षण-कर्मचारी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके थे, जब कि १,५८२ ग्राम-सेवक और १६४ निरीक्षण कर्मचारी अभी भी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। १ अप्रैल १९५३ को नीसोखेड़ी, हैदराबाद, गांधीग्राम, शांतिनिकेतन तथा इलाहाबाद में समाज शिक्षा तथा मुख्य शिक्षा व्यवस्थापकों के प्रशिक्षण के लिए पाँच केन्द्र स्थापित किये गये। पहले चार केन्द्रों में समाज शिक्षा व्यवस्थापकों को तथा इलाहाबाद स्थित केन्द्र में मुख्य समाज शिक्षा व्यवस्थापकों को प्रशिक्षण दिया जायगा।

केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालय ने विस्तार सेवा प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए स्वास्थ्य इन्स्पेक्टरों तथा सामूहिक योजना क्षेत्रों के लिए स्वास्थ्य कर्मचारियों के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में नये कोर्स की व्यवस्था की।

खाद्य और कृषि

१९५२-५३ में खाद्य स्थिति में सामान्य रूप से प्रगति होती रही। इसी वर्ष ४ करोड़ ७६ लाख टन अनाज पैदा हुआ। स्वतन्त्रता मिलने के बाद से यह वार्षिक उपज सबसे अधिक रही। १९५३ में कुछ क्षेत्रों में धान वसूली का कार्यक्रम समाप्त कर दिया गया और कुछ क्षेत्रों में सरस बना दिया गया। अनाज के एक राज्य से दूसरे राज्य को अनाज-आने पर प्रतिबन्ध अभी भी जारी है। गेहूँ की मिफो ■ सम्बन्ध में माथा सम्बन्धी सभी रोक उठा ली गई है।

१ जनवरी, १९५४ को केथल सोराबू, मध्यभारत तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के ग्यारह जिलों से होने वाले निर्यात को छोड़ कर देश भर में मोटे अनाज पर से कंट्रोल उठा लिया गया। जने पर से भी कंट्रोल उठा लिया गया है। १९५३ में केवल २०.०३ लाख टन खाद्यान्न के आयात का था।

१९५४ के आरम्भ से जब केन्द्रीय और राज्य सरकारों के पास १४-४ लाख टन खाद्यान्न बच रहा, हम कुछ-कुछ आत्म-निर्भर हो चले हैं और सरकार ने १९५४ में होने वाले गेहूँ के आयात की मात्रा में काफी कमी कर दी है। देश में उत्पादित चावल देश की मांग के लिए काफी होना चाहिये। आयातों की सहायता से खाद्यान्न सुरक्षित रखा जा सकेगा।

सम्मिलित फसल-उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत, जिसमें खाद्यान्न, कपास, पदसम और चीनी आती है, १९५३-५४ में प्रगति सन्तोषजनक रूप से होती रही। १९५२-१९५३ के प्रत्यक्षतन्तों से प्रकट होता है कि २० करोड़ एकड़ भूमि में अनाज बोया गया है। उत्पादन ४ करोड़ ७६ लाख टन हुआ।

१९५२-५३ में उत्पादन में वृद्धि

चावल	२७ लाख टन
गेहूँ	७ "
अन्य अन्न	१७ "
चना	५ "

‘अधिक अन्न उपजाओ’ आन्दोलन

छोटी सिचाई योजनाओं के कार्यक्रम को अधिक शीघ्रता से कार्यान्वित करने की दृष्टि से १९५५-५६ को समाप्त होने वाले तीन वर्षों के लिए १० करोड़ ९० प्रतिवर्ष की प्रतिरिक्त व्यवस्था की गयी है। सिंचि के रासायनिक खाद के कारखाने तथा अन्य कारखानों ■ अब अमोनियम सल्फेट अपेक्षित मात्रा में मिल सकेगा। गत छः वर्षों में केन्द्रीय ईंधन संयुक्त करीब १० लाख एकड़ भूमि को खेती के योग्य बना चुका है। १९५३ में २,६०,००० एकड़ भूमि से अधिक खेतों के योग्य बनाई गई। इस वर्ष आरम्भ की गयी धान की खेती की जापानी पद्धति के फलस्वरूप उत्पादनबर्धक परिणाम हुआ है। गत वर्ष चालू विधे गये जम्मू फार्म के प्रतिरिक्त १०,००० एकड़ भूमि के एक दूसरे क्षेत्र में (भोपाल में) मशानों की सहायता से खेती की जाने लगी है। १९५३-५४ के ‘अधिक अन्न उपजाओ’ कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप उत्पादन में १३,५५,००० टन की वृद्धि हो जानी चाहिए थी।

कपास

‘अधिक कपास उपजाओ’ आन्दोलन के सम्बन्ध में अरुण के रूप में १९५३ में राज्य सरकारों को लगभग ५६,४८,००० रुपये दिये गये जबकि ११,५०,००० रुपये सहायता के रूप में भी दिये गये।

पटसन

पटसन की खेती को प्रोत्साहन देने की योजनाओं के सम्बन्ध में राज्यों को ८,६५,००० रुपये सहायता के रूप में दिये गये। १९५२-५३ में ४६ लाख गांठ से अधिक पटसन पैदा हुआ। १९५३-५४ में प्रतिकूल मौसम के कारण उत्पादन ३१,३०,००० गांठ ही हुआ। इस कमो का दूसरा कारण बीने की अल्पता में पटसन के मूल्य में भारी गिरावट का आना भी था। अब अच्छी किस्म के पटसन के उत्पादन पर अधिक जोर दिया जा रहा है।

जौनी

जौनी का सबसे अधिक उत्पादन १९५१-५२ में १४,६७,००० टन रहा। १९५२-५३ में यह उत्पादन १३ लाख टन ही रहा। इसका मुख्य कारण था,

भन्ने के उत्पादन में कमी। १९५२-५३ में १६,५६,००० टन चीनी की खपत हुई जबकि १९५१-५२ में ११,६३,००० टन चीनी की ही खपत हुई थी। घाटे की पूर्ति बची हुई चीनी और आयात से की गयी।

पशुपालन

रिस्परवेस्ट रोग की रोकथाम के कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग १४,००० पशुओं के टीके लगाये गये। पशुओं के कृत्रिम रेतन के सम्बन्ध में अनुसन्धान कार्य को बढ़ाया गया। 'वाइरस वेक्सीन' के निर्माण के लिये १९५३ में भारतीय पशु रोग सम्बन्धी अनुसन्धान संस्था में एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केन्द्र खोला गया।

मछली पालन

देसी और समुद्री मछलियों के सम्बन्ध में विकास और अनुसन्धान के कार्यक्रम में १९५३ में अच्छी प्रगति हुई। नार्वे से प्राप्त होने वाले सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत तिरुवांकुर कोचीन में मछली-उद्योग के विकास के लिए एक सामूहिक योजना का कार्य आरम्भ किया गया है।

वन उद्योग

वर्ष में वन उद्योग तथा वनजन्य वस्तुओं सम्बन्धी अनुसन्धान कार्य जारी रखा गया। उत्तरी अंचलान के जंगलों के सम्बन्ध में खोज एवं शोध कार्य में संतोषजनक रूप से प्रगति हो रही है। इन जंगलों से १४,००० टन इमारती लकड़ी भारत ले आयी गई है। १९५३ के अन्त तक अंचलान में ५०० विस्फोटित परिवार बसाये जा चुके थे।

कृषि सम्बन्धी अर्थ व्यवस्था

प्राथमिक तथा आकड़ा-संकलन डायरेक्टरेट ने कृषि सम्बन्धी आंकड़ों के संकलन के लिए अपने क्षेत्र में काफी वृद्धि कर ली है। जम्मू और काश्मीर को छोड़कर भारत में आज आकड़ा-संकलन कार्य ७० करोड़ एकड़ भूमि में हो रहा है जबकि १९४६-४७ में यह कार्य ५५ करोड़ ६० लाख एकड़ भूमि में हो रहा था। इस डायरेक्टरेट की ओर से १९५३ में कई प्रकाशन हुए। विधवधिसालयों तथा अन्य अनुसन्धान संस्थाओं के सहयोग में कृषि-व्यवस्था सम्बन्धी अनुसन्धान

कार्य के लिए चार प्रादेशिक केन्द्र स्थापित करने का निर्णय किया गया है। इसके अलावा अनुसन्धान कार्य को बढ़ाने को दृष्टि से भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् ने कृषि सर्व व्यवस्था सम्बन्धी एक समिति की रचना की है।

प्रशिक्षण

सहकारी विभागों तथा अन्य संस्थाओं के कर्मचारियों को प्रशिक्षण की सुविधाएं देने के लिए श्री. बी. एल. मेहता की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गयी है। सहकारी कृषि के सम्बन्ध में प्रयोग किये जाने के लिए राश्यों को वित्तीय सहायता दिए जाने के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है।

सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सों के लिए भारतीय कृषि-अनुसन्धान परिषद् द्वारा कृषि सम्बन्धी आंकड़ों के विश्लेषण का प्रशिक्षण भी दिया गया था। भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् ने कृषि तथा तत्सम्बन्धी अभ्युदयियों के लिए १९५३-५४ में १२८ अनुसन्धान-योजनाओं का कार्य भी आरम्भ किया। एक पी० ए०९ नामक एक नये प्रकार के गेहूँ का पता लगाया गया है जिसमें तीनों प्रकार के गेहूँ को लगने वाले घुन के प्रतिरोध की क्षमता है।

इस वर्ष विस्तार प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या ३४ तक पहुँच गई और ५४६ निरीक्षण कर्मचारियों तथा २,६४३ बहुदेशीय ग्राम कार्यकर्ताओं ने इन केन्द्रों में सामूहिक विकास कार्यों का प्रशिक्षण प्राप्त किया। १५ आदर्श विकास योजनाओं का काम भी शुरू कर दिया गया है। पूर्वस्नातकों और उत्तर-स्नातकों को कृषि और विस्तार कार्य का प्रशिक्षण देने के लिए तीन कृषि-कालजों में विस्तार विभाग खोले गये हैं। २१ विस्तार अधिकारियों की एक मंडली अमरीकी और जापानी विस्तार कार्य-प्रणालियों के अध्ययन के लिये अमेरिका और जापान गई।

साथ एवं कृषि संगठन का तबस्थ होने के नाते भारत ने १९५३ में हुए सभी महत्वपूर्ण सम्मेलनों में भाग लिया। भारत-अमेरिका टेक्निकल सहयोग करार के अन्तर्गत कई कृषि-विकास योजनाओं की सहायता प्राप्त हुई। फोर्ड प्रतिष्ठान की सहायता से ग्राम-कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के एक कार्यक्रम की व्यवस्था की गयी।

वाणिज्य एवं उद्योग

सबसे अधिक औद्योगिक उत्पादन १९५२ में हुआ। इसी के परिणाम-स्वरूप सरकार के लिए कई कंट्रोल उठा लेना तथा इसके स्थान पर धीरे-धीरे विकास के कार्यक्रम पर ध्यान केन्द्रित करना संभव हो सका।

औद्योगिक उत्पादन का सामान्य सूचकांक जो १९५२ में १२८.७ था, १३४ तक बढ़ गया और बेशर्त में कपड़े तथा सीमेंट का महत्वपूर्ण उत्पादन हुआ। अल्युमिनियम कन्डक्टरों, ट्रांसफार्मरों, बाल-चेयरिंगों, पिस्टनों, लोको-मोटिव वायलरों, वाइसिकित, सीने की मशीनों, लालटेनों, गंधक के तेजाब, वाइकोमेट्स, एमोनियम सल्फेट, सोडा ऐश, क्लोराइन, तथा कास्टिक सोडा जैसी वस्तुओं के उत्पादन में भी वृद्धि हुई। औषधियों, साइकिल के फ्रीहिलों और चैन तथा बैटरियों आदि नई वस्तुओं का निर्माण हुआ।

यद्यपि कोरिया में युद्ध छिड़ने के तुरंत बाद की स्थिति के मुकाबले में आयात और निर्यात में कमी आई, पर व्यापार-सन्तुलन की स्थिति बढ़ और सन्तोषजनक रही। अनुकूल व्यापार-सन्तुलन की सहायता से १९५२ के व्यापार में हुए घाटे की पूर्ति हो गई और पौड पावने की सुरक्षित राशि में से कुछ भी निकाले बिना वर्तमान आमदनी में से विदेशी विनिमय की आवश्यकताओं को पूरा करना संभव हो सका।

इसके अलावा साल में कई नये व्यापार समझौते हुए या उनका नवकरण हुआ। इनमें जाफना सम्झौता सम्बन्धी भारत-जंका समझौते, पटसन और कोयला सम्बन्धी भारत पाकिस्तान समझौते तथा रूस के साथ हुए व्यापार सम्बन्धी समझौते का विशेष रुध से उल्लेख किया जा सकता है।

निर्यात व्यापार जमाने के लिए विभिन्न उपायों पर तथा कहीं आवश्यक हो कहीं निर्यात-कर के पुनर्निर्यात पर काफी जोर दिया गया है।

पटसन, चाय तथा सूती वस्त्र उद्योगों के सामने विदेशों में अपना मूल क्षेत्रों के सम्बन्ध में जो कठिनाइयाँ थीं, उन्हें दूर किया गया। निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए सामुद्रिक शुल्क कानून में संशोधन किया गया। निर्यात-व्यापार को प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में मन्त्रालय में एक विशेष संगठन स्थापित किया गया है।

क्योंकि ये सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व के आधार पर चलते हैं, उनके विकास के सम्बन्ध में मन्त्रालय सीधे कुछ नहीं कर सकता। तो भी, उनके विकास की गति को तेज करने की दृष्टि से मन्त्रालय को उन नीतियों के परिणामों पर निर्भर रहना पड़ता है जिनके लिए वह उत्तरदायी है। नये उद्योगों की स्थापना के लिए मन्त्रालय ने कई बड़े निर्णय किये हैं।

प्रशुल्क कमिशन की रिपोर्ट के आधार पर आटोमोबाइल उद्योग के विकास के लिए एक दीर्घ कालीन नीति की रचना की गयी है। साथ ही इंजिनियरिंग उद्योगों की क्षमता के सम्बन्ध में जांच पड़ताल करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति की भी स्थापना हुई है जिससे इन उद्योगों से भूरा-भूरा लाभ उठाया जा सके।

इसी प्रकार एक समिति ने, जिसके सदस्यों में प्रसिद्ध चिकित्सक भी हैं, फार्मसी उद्योग का अध्ययन कार्य अपने हाथ में लिया है।

उक्त कमिशन की सिफारिश पर प्रशुल्क लगाया जाकर उद्योगों को रक्षा की व्यवस्था की जा रही है। १९५३ में आयोग ने ११ उद्योगों के मामलों पर, जिन्हें संरक्षा पहले से ही प्राप्त होती आ रही है, विचार किया और संरक्षा के लिए दो नये प्रार्थनापत्रों के सम्बन्ध में जांच पड़ताल की। इसके अलावा कमिशन ने इस्पात, सीमेंट तथा टीन की खादों के उचित मूल्यों के सम्बन्ध में रिपोर्ट दी।

औद्योगिक विकास की एक मुख्य कठिनाई कोयले की कमी है। इसलिए मन्त्रालय में एक औद्योगिक विकास कारपोरेशन स्थापित करने का विचार किया है जो देश में नये उद्योगों की स्थापना के सम्बन्ध में उत्साह से काम

लेता। मन्त्रालय ने ऋणों के रूप में सरकार द्वारा सीधी वित्तीय सहायता दिये जाने के प्रश्न की भी जांच पड़ताल की है। बहुत से मामलों में ये ऋण अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुए हैं। उदाहरण के लिए घुनाई के यंत्र बनाने वाले एक उद्योग को बंद होने से बचा लिया गया और आज वह उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण यंत्र तैयार करके बैठा है।

१९५३ में संसद ने उद्योग विकास और नियन्त्रण कानून को व्यापक बनाया जिससे इसके अन्तर्गत कई नये उद्योग सम्मिलित कर दिए गये और सरकार के औद्योगिक संस्थाओं के संचालन और नियन्त्रण सम्बन्धी अधिकारों को अधिक व्यापक रूप दिया गया। कानून के अन्तर्गत स्थापित लाइसेंस देने वाली कमेटी ने नये उद्योगों की स्थापना तथा वर्तमान उद्योगों के विस्तार सम्बन्धी २५१ प्रार्थनापत्रों पर विचार किया। १५२ मामलों में आवश्यक अनुपति दी गई।

पूरी वस्त्र उद्योग का उत्पादन-स्तर अच्छा रहा। वेश और विवेश के उपभोक्ताओं की सहायताार्थ, अधिक से अधिक कपड़े का अधिक से अधिक उपयोग करने की दृष्टि से सरकार ने बढ़िया कपड़े पर उत्पादन कर कम कर दिया और मध्यम प्रकार के कपड़े पर से निर्यात कर हटा लिया है। हरण करघा-उद्योग में अब सूत का अभाव नहीं रह गया है और इस उद्योग को और अधिक प्रोत्साहन देने के लिए मिलों द्वारा धीतियों और साड़ियों के उत्पादन पर रोकें लगा दी गयीं हैं। कपड़े पर से मूल्य नियन्त्रण तथा वितरण सम्बन्धी रोक पूरी तरह से हटा दी गयी है।

मगर एक बड़े कारखाने में अम सम्बन्धी झगड़े के कारण १९५३ के पूर्वार्द्ध में इस्पात-उद्योग का उत्पादन कम रहा, पर वर्ष के अंतिम भाग में उत्पादन १९५२ के औसत से अधिक रहा। समुद्र पार देशों से इस्पात अब अधिक मात्रा में प्राप्त किया जा सकता है। लोहे की छड़ों और छोटे-छोटे सामान के अधिक मात्रा में मुलभ होने के कारण इन पर वितरण सम्बन्धी रोक कठोर-कठोर उठा-सो तो गई है। जबकि इस्पात का मूल्य तो लगभग एक सा ही कायम रहा, कुछ विभिन्न प्रकार के तारों और तारों से बनी वस्तुओं के मूल्य में कमी अवश्य आई।

आर्थिक

नियति उद्योगों में, पटसन उद्योग पर कर कम कर दिये गये। चाय उद्योग ने, जिसमें १९५२ के अंत में काफी गिरावट आई, १९५३ में महत्वपूर्ण प्रगति की और इस वर्ष हस्तगत नियति सबसे अधिक रहा।

छोटे पैमाने के उद्योगों को सहायता के लिए भी विशेष प्रयास किये गये। इनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण हाथ करघा उद्योग है। सूती वस्त्र को मिलों द्वारा उत्पादित कपड़े पर चुंगी लगाकर एक विशेष कोष का निर्माण किया गया और इस कोष का महत्वपूर्ण भाग हाथ करघा उद्योग के विकास में लगाया गया। दस्तकारियों तथा अन्य छोटे पैमाने के उद्योगों को राज्य सरकारों से मिलने वाले ऋणों और अनुदानों के द्वारा काफी सहायता प्राप्त हुई। ग्राम उद्योगों के विकास का कार्यक्रम अखिल भारतीय खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड की देखरेख में भी चलाया जा रहा है। अखिल भारतीय हस्तकला-उद्योग बोर्ड, दस्तकारियों से खनी वस्तुओं के सम्बन्ध में डिजाइन तैयार करने तथा बिक्री की व्यवस्था करने में लगा हुआ है। कुछ चुने हुए क्षेत्रों में फोर्ड प्रतिष्ठान के तत्वाधान में एक अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ-मंडली छोटे पैमाने के उद्योगों के सम्बन्ध में पर्यवेक्षण कर रही है जिससे इन उद्योगों को आर्थिक वृद्धि से अनी-भति छड़ा किया जा सके।

भारत की फर्मों द्वारा विदेशों की फर्मों को रायल्टियों और टेक्निकल शुल्क के रूप में किए जाने वाले भुगतानों के सम्बन्ध में आँकड़ों का संगठन किया जा रहा है।

चाय, कहवा तथा रखर के जैसे बागान उद्योगों को विशेष समस्याओं के अध्ययनार्थ एक विशेषज्ञ-समिति नियुक्त की जायेगी।

प्राकृतिक साधन और वैज्ञानिक अनुसन्धान

इस मन्त्रालय का सम्बन्ध वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान से है। यह मन्त्रालय वैज्ञानिक-पर्यवेक्षण का कार्य तथा खान-उद्योगों की देखभाल करता है। आणविक अनुसन्धान सम्बन्धी कार्य भी इसी का उत्तरदायित्व है।

१९५३-५४ में वैज्ञानिक अनुसन्धान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं स्थापित की जा चुकी हैं और तीन और अनुसन्धान-संस्थाओं—भावनगर स्थित केन्द्रीय नमक अनुसन्धान संस्था, पिलानी स्थित केन्द्रीय विद्युत-अनुसन्धान संस्था तथा कलकत्ता स्थित धातुिक इंजीनियरिंग अनुसन्धान संस्था—की रचना की जा रही है। उद्योग सम्बन्धी विभिन्न समस्याओं पर अनुसन्धान इन राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में किया जा रहा है। उदाहरण के लिए नई दिल्ली की राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में अम्ल-इथेनोकिनिस, ओरिडक्स, ताम्र और बिद्युतवाहन, औद्योगिक भौतिकशास्त्र, तथा निस्लेषणशक्त रसायन शास्त्र ■ क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किये जा रहे हैं। इस प्रयोगशाला में कई नये यंत्रों का आविष्कार किया गया है। मैसूर स्थित केन्द्रीय ज्ञाद्य औद्योगिकी अनुसन्धान संस्था में सखियों तथा फलों को सुरक्षित रखने की नई प्रक्रियाओं का विकास किया जा रहा है। इस संस्था में मूंगफली का दूध और बही और कुत्रिम चावल भी तैयार किया गया है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला में रीठों और जिप्सम में से रस और रही तन्माकू में से निकोटीन सल्फेट निकालने के नये आविष्कार किये गये हैं।

वैज्ञानिक अनुसन्धान के साथ लोगों के लिए उपलब्ध करने की दृष्टि से एक राष्ट्रीय अनुसन्धान विकास कार्यक्रम स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय अनुसन्धान प्रयोगशालाओं द्वारा आविष्कृत आविष्कारों और प्रक्रियाओं को औद्योगिक कार्यों के लिए तथा सामान्य जनता के लिए उपलब्ध करने का कार्य यह कार्यक्रम करेगा।

विज्ञान मंदिर

वैज्ञानिक क्षेत्र प्राचीन क्षेत्रों में भी स्थापित किये जायेंगे। ये क्षेत्र स्वास्थ्य तथा कृषि सम्बन्धी समस्याओं को हल करेंगे। ये विज्ञान मंदिर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिवर्धन के नियन्त्रण में रहेंगे। इनका मुख्य कार्य मिट्टी तथा पानी सम्बन्धी विश्लेषणात्मक कार्य करना तथा वैज्ञानिक जानकारी का प्रसार करना रहेगा। इन क्षेत्रों में रोग-निदान-प्रयोगशालाएँ भी होंगी जो रोगों के प्रतिरोधात्मक उपायों के सम्बन्ध में सार्वजनिक स्वास्थ्य-अधिकारियों को सहायता देंगी। बीमों के रोग सम्बन्धी उपचार की जानकारी भी इन्हीं क्षेत्रों द्वारा कराई जायगी। सर्वप्रथम विज्ञान मंदिर का उद्घाटन दिल्ली राज्य के कपड़ोरा गाँव के निकट १६ अगस्त, १९५३ को प्रधान मंत्री ने किया।

भारतीय खान-भूरो

खान-उद्योग को टेक्निकल शिक्षणों के सम्बन्ध में सलाह देने वाले भूरो का विस्तार करने का विचार किया जा रहा है। भारतीय उद्योग की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक विस्तृत योजना पर कार्य आरम्भ किया गया है। हमारे देश के उद्योग को ताँबे, सीसे, जस्ते आदि की सबसे अधिक आवश्यकता है। कूड़े के ढेर से मैंगनीज निकालने का प्रयास सफल रहा और मैंगनीज अलग करने का एक बड़ा कारखाना मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। भूरो द्वारा एक ऐसा उपयोगी पदार्थ तैयार किया गया है जिसकी सहायता से अधिक रेत मिश्रित मैंगनीज में से शुद्ध मैंगनीज अलग किया जा सकेगा। बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में तीसरी श्रेणी की सोने की खानों तथा उड़ीसा में बथोम्बर में ४० लाख की स्वर्ण-पट्टी का पता अभी हाल में ही लगा है।

खानों से वैज्ञानिक ढंग से खनिज पदार्थ निकालने तथा कम से कम खर्च होने देने के लिए एक विस्तृत कार्यक्रम पर प्रारम्भ किया गया है। निरोक्षरा-बोली ने विभिन्न राज्यों की मैंगनीज, इलेमनाइट, क्रोमाइट, ऐस्बेस्टोस, सोने, सीसे, ताँबे, लोहे, चीनी मिट्टी तथा फीरोज की खानों का भी पर्यवेक्षण किया गया और उनका वैज्ञानिक ढंग से विकास करने की एक विस्तृत योजना तैयार की गयी है।

घनमान स्थित खान सम्बन्धी भारतीय संस्था ■ लिए एक लाख रुपये के नये उपकरण और यंत्र खरीदे गये हैं। १९५३ में खान सम्बन्धी इंजीनियरिंग के ११ और भूगर्भशास्त्र के ६ छात्रों को "एसोसिएटशिप" का डिप्लोमा मिला।

तेल सम्बन्धी शोध-कार्य

भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों का वायु-मुम्बकीय पर्यवेक्षण करने का कार्य "दि स्टैंडर्ड बैकूथम प्रायल कम्पनी" को सौंपा था। इसके परिणामस्वरूप तेल प्राप्त करने के स्थानों का पता लगा है। भारत सरकार और उपरोक्त कम्पनी के बीच हुए एक सम्झौते में संयुक्त रूप से तेल निकालने तथा पेट्रोल और तत्सम्बन्धी द्रव्यों के निर्माण की व्यवस्था रखी गई है।

आसाम प्रायल कम्पनी लिमिटेड भी ऊपरी आसाम का वायु मुम्बकीय पर्यवेक्षण कर रही है।

भारत का भूगर्भविज्ञान सम्बन्धी पर्यवेक्षण

भूगर्भविज्ञान सम्बन्धी कारखाने में औजारों तथा अन्य उपकरणों के सम्बन्ध में उपयोगी कार्य किया गया है। इस कारखाने में कई औजारों का निर्माण हुआ है।

भारत का पर्यवेक्षण

भारत-पर्यवेक्षण विभाग एक विशेष संगठन है जो विभिन्न प्रकार के आधुनिकतम नक्शे तैयार करता है। बेहरातून और कलकत्ता में इसका अपना ग्रेस है जहाँ नागरिक प्रवासन और प्रतिरक्षा-सेवाधों दोनों के लिए नक्शे तैयार किये जाते हैं। इस विभाग के अधिकारियों को बेहरातून स्थित पर्यवेक्षण प्रशिक्षण स्कूल में प्रशिक्षण दिया जाता है।

१९५१ में पर्यवेक्षण प्राथमिकता समिति ने निर्णय किया कि केवल हिमालय प्रवेश को छोड़कर समस्त भारत का पर्यवेक्षण एक मील के पैमाने के अनुसार किया जाये। समिति ने यह भी निश्चय किया कि पर्यवेक्षण पर प्रत्येक २५ वर्षों में एक बड़ा पुनर्विचार किया जाये।

योजना कमीशन ने इस विभाग का विस्तार-कार्यक्रम स्वीकार कर लिया है जो पर्यवेक्षण प्राथमिकता समिति की सिफारिशों पर आधारित है। इस योजना को कार्यान्वित किया जाना शीघ्र ही प्रारम्भ होगा। इसके अन्तर्गत ३२ लाख रुपये के व्यय से भारत का पर्यवेक्षण सम्बन्धी प्रस्ताव सम्मिलित है। साज-सामान टेक्निकल सहयोग प्रकाशन से प्राप्त किया जायगा। तम्बों के संकलन तथा नकशों के तैयार किये जाने और छपाये जाने ■ उपयोगी कार्य के अलावा इस विभाग ने हिन्दी में भारत के चार विभिन्न राजनीतिक और प्राकृतिक नकशों

का निरूपण किया है। हिन्दी का टाइप और अधिक सुलभ होने पर अन्य नकशे भी तैयार किये जायेंगे। इन साल इस विभाग ने कुल मिलाकर ३६ पर्यवेक्षण कार्य किये। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण पर्यवेक्षण निम्नलिखित हैं—आसाम की कोपिली घाटी का पर्यवेक्षण; एबरेस्ट शिखर की जैन्वाई का पुनर्निर्धारण तथा कोसी सिंचाई योजना, चम्बल जल-विद्युत् योजना तथा भाखरा नंगल और तुंगभद्रा योजनाओं सम्बन्धी पर्यवेक्षण।

भारत का प्राणिविद्या सम्बन्धी पर्यवेक्षण

भारतीय अजायबघर के सार्वजनिक कक्षों में प्रदर्शित वस्तुओं को फिर से सजाया गया तथा उन्हें साफ किया गया और उनकी परम्पत की गयी है। इन की एक सूची भी तैयार की गयी है।

१९५३ में पर्यवेक्षण के लिए ६ टोलियां भेजी गयीं। सौराष्ट्र में समुद्री जीव जन्तुओं का; सिक्किम में पक्षियों का तथा तिरुता घाटी, मणिपुर और पंचसङ्की में पहाड़ी सोलों में पाये जाने वाले जीव-जन्तुओं का पर्यवेक्षण किया गया।

विभिन्न वर्गों के जीव-जन्तुओं के बारे में भी अनुसन्धान कार्य किया गया। टेक्निकल कर्मचारियों ने प्रकाशन के लिए अनुसन्धान कार्य सम्बन्धी ११ निबन्ध दिये। कुमि-जीवी कीड़ों के सम्बन्ध में भी काफी अनुसन्धान कार्य किया गया है। अन्य प्रकार के कीड़ों पर भी कई निबन्ध प्रकाशित किये जा रहे हैं।

राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान उद्यान

राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान उद्यानों को लगाने के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद ने सख्तमऊ स्थित सिकन्दरबाग ले लिया है। अब तक एक बीजों का अजायबगार और एक बागबानी प्रयोगशाला स्थापित किये जा चुके हैं। बागबानी सम्बन्धी विभिन्न समस्याओं पर अनुसन्धान कार्य किया जा रहा है और भूमि के छोटे-छोटे टुकड़ों में बोये जाने ■ लिए ५०० से अधिक शीतलीय पौधे छाटे जा चुके हैं।

कृषि वर्षा

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद की सहायता से हाल के वर्षों में कृषि वर्षा के सम्बन्ध में कई प्रयोग किये गये। इस सम्बन्ध में नयी दिल्ली की राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में और प्रयोग किये जा रहे हैं। कृषि-वर्षा की विधि का प्रशिक्षण लेने के लिए वैज्ञानिक अधिकारी आस्ट्रेलिया भी भेजे जायेंगे।

आणविक शक्ति आयोग

भारत में आणविक शक्ति आयोग शान्तिपूर्ण कार्यों के लिए आणविक शक्ति के उपयोग का विकास करने की दृष्टि से स्थापित किया गया था। अब तक आयोग का मुख्य कार्य रेडियो सक्रिय कनिष्ठ पदार्थों के लिए वेस के पर्यवेक्षण तथा अणु-भंजन सम्बन्धी वैज्ञानिक और ईंजिनकल समस्याओं के अनुसन्धान को प्रोत्साहन देने का रहा है।

आयोग के आणविक शक्ति के विकास सम्बन्धी कार्यक्रम में एक मध्यम शक्ति के आणविक रिएक्टर की स्थापना की व्यवस्था है। आणविक शक्ति सम्बन्धी एक संस्था ट्रिम्बे में खोली जा रही है।

अन्य देशों के रिएक्टरों के अध्ययनार्थ एक रिएक्टर की रचना की गयी है। यह देश भारत के सर्व प्रथम रिएक्टर का निर्माण करेगा।

आणविक शक्ति शायोग में दो नये विभाग खोले गये हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य सम्बन्धी विभाग रेडिएशन के सतरों से मजदूरों की रक्षा करने के लिये उत्तरदायी होगा। यह विभाग विस्फोट तथा रेडियो सक्रिय-रश्मियों के परिणामस्वरूप फैलने वाले बीमारियों की चिकित्सा और उनसे नचाव सम्बन्धी अनुसन्धान-कार्य भी करेगा। जीवविज्ञान विभाग रेडिएशन के परिणामों तथा जीवविज्ञान सम्बन्धी पहलुओं के अध्ययन के लिए मुख्यतः एक अनुसन्धान संगठन के रूप में कार्य करेगा।

अनुसन्धान सम्बन्धी योजनाएँ

विभिन्न प्रकार के अनुसन्धान-कार्यों का विकास करने के लिये वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसन्धान परिषद विश्वविद्यालयों तथा अन्य अनुसन्धान संस्थाओं को सहायताएँ दे रही है। विभिन्न स्थानों पर १०० से अधिक अनुसन्धान योजनाओं पर कार्य हो रहा है।

उत्पादन

लोहा तथा इस्पात धन

इस्पात के उत्पादन में तेज प्रगति करने के प्रश्न पर कई वर्षों से विचार किया जा रहा है। इसी तिलतिले में १५ अगस्त १९५३ को जर्मन में एक प्रसिद्ध जर्मन संस्था क्रुस डेमाग के साथ एक समझौता हुआ। इस समझौते के अन्तर्गत ५ लाख टन इस्पात इस्पात तैयार करने की क्षमता वाले एक कारखाने के निर्माण की व्यवस्था है। “क्रुस डेमाग” नामक संस्था टेक्निकल सहायता तथा भारतीय कर्मचारियों को प्रशिक्षण देगी। यह संस्था ७१ करोड़ २५ लाख रुपये की पूंजी भी लगवयेगी। आशा है यह कारखाना कार बकों में काम करने लगेगा। टेक्निकल सलाहकारों की २ करोड़ १० लाख रुपये की निश्चित फीस अथवा अनुमानित व्यय का लगभग तीन प्रतिशत मिलेगा।

एक सौ करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी के साथ हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड

नाम की एक नयी ग्राहबेट लिमिटेड कम्पनी की रचना की गयी है। गया यन्त्र इसी के नियन्त्रण में होगा तथा यही उसका संचालन करेगा। भारत सरकार तथा जर्मन संस्था के बीच शेषों का अनुपात ४:१ होगा। पूंजीगत विनियोग का, चाहे वह देश में हो अथवा विदेश में, अधिक भाग ऋणों के रूप में होगा। जर्मन विशेषज्ञों की सिफारिश के अनुसार यह कारखाना उड़ीसा में करकेला में खोला जायेगा।

विशाखापट्टनम् शिपयार्ड

शिपयार्ड के विकास के लिए १ करोड़ ८० लाख रुपये के व्यय का कार्यक्रम तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शिपयार्ड के विस्तार की योजना है जिससे साल भर में ६ से लेकर ८ जहाजों का निर्माण किया जा सके। यदि आवश्यक हुआ तो इसका इतना विस्तार भी किया जा सकेगा कि साल में १२ जहाज तैयार किये जा सकें। इस योजना पर काम किया जा रहा है। शिपयार्ड में समुद्री इंजिन, वायुशरीरों तथा अन्य सहायक यंत्रों के निर्माण के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है।

१९५३-५४ में "जल" की किस्म के साठ-साठ हजार बी० डब्ल्यू० टी० के दो जहाज तैयार करके समुद्र में उतारे गये और "मैयर" किस्म के सात-सात हजार बी० डब्ल्यू० टी० के डीजल इंजिन से चलने वाले तीन जहाजों के लिए कील बिछाई गयी। भारतीय जहाजरानी कम्पनियों, अलसेना तथा प्रकाशगुरु विभाग के साथ जहाजों के सम्बन्ध में ठेके हुए हैं। फाल्गुन अक्षरों की छंटनी के फलस्वरूप इस साल रुपये बाविक की बचत हुई।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को विशाखापट्टनम् में एक पोटी के निर्माण का कार्य सौंपा गया है। धारा है इसका निर्माण कार्य १९५४-५५ में शुरू हो जायेगा।

सिंद्री फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड

१६ जनवरी, १९५२ से ३१ मार्च, १९५३ तक इस कम्पनी को २ करोड़ ७१ लाख रुपये का सकल लाभ हुआ। १९५३ में २,६५,७०४ टन समोनियम

सालफेट का उत्पादन हुआ जब कि १९५२ में १,७२,५१६ टन असोनियम सालफेट का ही उत्पादन हुआ था।

आयरन आक्साइड केटेलिस्ट का आयात बंद करने के उद्देश्य से साढ़े तीन लाख रुपये के व्यय पर एक केटेलिस्ट कारखाना स्थापित किया जा चुका है। इसका नक्का भारतीय इंजीनियरों द्वारा तैयार किया गया था। इन्हीं के द्वारा निर्मित इस कारखाने में काम शुरू हो चुका है। सिद्दी में स्थापित केटेलिस्ट के उत्पादन पर २,५०० रुपये प्रतिटन व्यय हुए जबकि आयात किये गये केटेलिस्ट का मूल्य १०,००० रुपये प्रतिटन तक होता था।

सिद्दी के कोक-ओबेन धंधे का निर्माण कार्य जो १९५२ के मध्य में शुरू हुआ था, अब पूरा होने वाला है। इस कारखाने में उत्पादन-कार्य अगस्त १९५४ के मध्य से शुरू होने वाला है।

भारत की एंथोशिफ्टेड सीमेन्ट कंपनियों द्वारा आरम्भ किये गये सीमेन्ट के एक कारखाने का निर्माण-कार्य संतोष जनक रूप से और कार्य-प्रभाव-नुसार चल रहा है। सिद्दी के कारखाने के विस्तार का भी विचार किया जा रहा है जिससे इसमें फाल्सू गैस की सहायता से "कूरिया" और "असोनियम नाइट्रेट" जैसे नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का उत्पादन किया जा सके।

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड

डाक और तार विभाग की आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से इस कारखाने की योजना तैयार की गई है। वर्तमान समय में डाक और तार विभाग को अपनी आवश्यकताओं के लिए आयातों पर निर्भर रहना पड़ता है। इस कारखाने में प्रतिवर्ष लगभग ४७० मील लम्बे केबल तैयार करने का विचार है। यह योजना अब पूरी होने वाली ही है।

केबल इन्स के उत्पादन के लिए इमरान विमानर १९५३ के मध्य में बनकर तैयार हो चुका था और तभी से इसमें काम भी शुरू हो चुका था। इन्सुलेटिंग, ट्रिबल्लिंग तथा स्ट्रेंडिंग कारखानों में उत्पादन परीक्षण की स्थिति में शुरू हो चुका है।

तेल शोधक कारखाने

इस सम्बन्ध में पहले-पहल उत्पादन-कार्य स्टैंडर्ड वेक्युम रिफाइनरी में आरंभ

हीना और क्राशा है कि इसका कार्य कार्यक्रम से ६ मास पूर्व जुलाई १९५४ में शुरू हो जायगा। बर्मा तेल रिफाइनरी अपना उत्पादन कार्य १९५६ के आरम्भ में शुरू करने वाली थी किन्तु अब इसका कार्य १९५५ की प्रथम तिमाही में शुरू हो जाने की सम्भावना है। दोनों तेल शोधक कारखानों में प्रतिवर्ष कुल ३२ लाख टन कच्चा तेल साफ किया जा सकेगा।

भारत सरकार ने विशालापरमूम में तीसरा तेल शोधक कारखाना खोलने का कार्टेज (भारत) लिमिटेड का प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिया है। इस कारखाने में प्रतिवर्ष ५ लाख टन कच्चा तेल साफ किया जा सकेगा।

हिन्दुस्तान हाउसिंग फॅक्टरी लिमिटेड

हिन्दुस्तान हाउसिंग फॅक्टरी पुनर्व्यवस्थित की गई तथा इसे ऐसे सामान से सुसज्जित किया गया है कि इसमें छत के पटाव के लिए कंकरीट, चौखटों, कंकरीट के डबाए गये खोखटों, लकड़ी के काम तथा कुचिम इत्यादि का उत्पादन किया जा सके।

राष्ट्रीय भोजार उद्योग

कलकत्ता स्थित राष्ट्रीय भोजार उद्योग का १ करोड़ ८२ लाख रुपये के व्यय पर पुनर्संरुद्धन किया जा रहा है और नयी इमारतों, नये उपकरणों तथा यंत्रों के लिए व्यवस्था की गई है। १९५३-५४ के प्रथम ६ महीनों के लिए अनुमान लगाया गया है कि ३२ लाख ६ हजार रुपये के मूल्य का सम्मत सहित उत्पादन किया जा सकेगा। इस उद्योग में जैवार्थ तथा कोरा मापने के यंत्रों, जैव तापमान के थर्मामीटरों, क्रायि जैसी वस्तुओं का भी निर्माण किया जा रहा है। छात्रों को भोजार प्रौद्योगिकी सम्बन्धी प्रशिक्षण देने के लिए शिक्षा मन्त्रालय ने उद्योग के लिए सात छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की है।

पेनिसिलीन उद्योग

विषम स्वास्थ्य संगठन तथा "यूनिसेफ" की सहायता से एक पेनिसिलीन उद्योग स्थापित किया जा रहा है। उद्योग के लिए इमारतों का निर्माण करने तथा यंत्र और मशीनों की खरीद का कार्य शुरू हो चुका है।

हिन्दुस्तान यंत्र औजार उद्योग

कुछ विशाल टेक्निकल कठिनाइयों के कारण यंत्र औजार उद्योग का उत्पादन कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रारम्भ नहीं किया जा सका । इन कठिनाइयों पर अब विजय पा ली गई है और परिष्कृत कार्यक्रम के अनुसार उत्पादन कार्य १९५४ के मध्य में शुरू हो जाने की प्रत्याशा की ।

डी. डी. टी. उद्योग

"यूनिसेफ" तथा "उन्डा" की सहायता से भारत सरकार दिल्ली में एक डी. डी. टी. उद्योग स्थापित कर रही है जिसमें प्रतिवर्ष ७०० टन डी. डी. टी. उत्पादित की जा सकेगी । इनारतों के निर्माण, सेवाओं तथा कार्यकारी पंजी के सम्बन्ध में सरकार २२ लाख ४५ हजार रुपये देगी । "यूनिसेफ" तथा "उन्डा" धन्य तथा उपकरणों की खरीद और टेक्निकल सहायता के लिए साढ़े तीन लाख रुपये देंगे ।

उद्योग की मुख्य इमारत का निर्माण कार्य नवम्बर १९५३ के प्रारम्भ में शुरू हुआ था ।

नाहन फ़ाउन्ड्री लिमिटेड

नाहन फ़ाउन्ड्री (हिमाचल प्रदेश) एक छोटी किन्तु उपयोगी संस्था है । यह आजकल भारत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण में है । इसमें ४० लाख रुपये की पूंजी लगी हुई है । इस फ़ाउन्ड्री में गन्ने के कोल्हू, खाद पकाने के लिये कड़ाहों तथा गुरु जमान से सम्बन्धित अन्य उपकरणों का निर्माण होता है । हाल ही में सेन्ट्रीफ्यूगल पम्पों (बिजली तथा बेलों की सहायता से चलने वाले), घान कूटने की मशीनों तथा धनाज अलग करने की मशीनों का भी निर्माण शुरू हो चुका है ।

मिलावटी तेल

ब्रिटिश अकाई की लिम्बाइट की शानों के सम्बन्ध में हाल में हुई आश्चर्यचकित से मिलावटी तेल के निर्माण की सम्भावनाओं का संकेत मिलता है । बताया जाता है कि अमेरिका और जर्मनी में निर्माण विधि विषयक काफी प्रगति हुई है । सरकार लिम्बाइट की उपयोगिता के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय

सातवाँ वर्ष

रूपाति की फलों से जमी रिपोर्टें प्राप्त करने का विचार कर रही है।

कोयला

मत्सु-मिग्रन्त्रण समिति ने कोयले पर कंट्रोल जारी रखने की सिफारिश की है। १९५३ में भारत में ३ करोड़ ५८ लाख टन और ३ करोड़ ७ लाख टन कोयला क्रमशः निकाला और भेजा गया जबकि १९५२ में ये संख्याएँ क्रमशः ६ करोड़ ६२ लाख टन और ३ करोड़ ११ लाख टन थीं। १९५३ में बंगाल और बिहार की कोयले की खानों का उत्पादन कम रहा और निर्यात में कमी आने के कारण १९५३ में कोयला भेजा भी कम गया। १९५३ में १६ लाख ६० हजार टन कोयला बाहर भेजा गया जबकि १९५२ में ३३ लाख टन कोयला बाहर भेजा गया था।

कोयले की खानों में जमीन के नीचे आग लगाने की रोक-थाम के लिये रक्षात्मक कार्यों का निर्माण किया जा रहा है।

उत्पादन मन्त्रालय के निग्रन्त्रण में रहने वाली रेलवे की कोयले की खानों से १९५२-५३ में ६१ लाख रुपये का शुद्ध लाभ हुआ।

सरकार ने बाँकारो और कारगालो की रेलवे की कोयला-खानों में ठेके पर कोयला निकालने की प्रथा समाप्त कर देने का निर्णय किया है।

नमक

पञ्चवर्षीय योजना के अन्तर्गत निर्धारित ८१७ लाख मज नमक का लक्ष्य आगे बढ़ चुका है और १९५३ के लिये ८६० लाख मज नमक का लक्ष्य रखा गया था। निर्यातों को कुल ७१ लाख मज नमक भेजा गया। इस प्रकार नमक के निर्यात में वृद्धि हुई। देश में नमक के सस्य में कुछ कमी आई।

१९५३ का नमक कानून २ जनवरी १९५४ से लागू हुआ। सरकारी कारखानों में तैयार हुए नमक पर साढ़े तीन आने प्रतिमज तथा निजी रूप से उत्पादित नमक पर दो आने प्रतिमज के हिसाब से कर लगाया है। इन करों से प्राप्त होने वाले धन का उपयोग अनुसन्धान केंद्रों तथा खादों फलों की

आर्थिक

स्थापना तथा अम-कल्याण और उद्योग के विकास के लिए किया जायगा।

१९५३ में नमक में उसमें ६३.५ से ६४ प्रतिशत सोडियम क्लोराइड का होना मान्य ठहराया गया था। १९५४ में यह ६४ प्रतिशत कर दिया गया। अन्नास तथा उड़ीसा में तीन परीक्षण प्रयोगशालाएं और स्थापित की गयीं। पहाड़ से निकलने वाले ममक के विकास के लिए मण्डी योजना प्रगति कर रही है। टेक्निकल कठिनाइयों की दृष्टि से कोर ड्रिलिंग के कार्यक्रम को परिष्कृत किया गया।

लाइसेंस लिए बिना छोटे पैमाने पर नमक-उत्पादन के सम्बन्ध में सरकार ने १ मार्च, १९५५ से ऐसे क्षेत्र में और कमी कर दी है। लाइसेंस लिए बिना घस डाई एकड़ के क्षेत्र में ही नमक का उत्पादन किया जा सकेगा। १० एकड़ सम्बन्धी रिघायत एक साल के लिए और जारी रहेगी जिससे ऐसे उत्पादन क्षेत्रों में हिसाब किताब साफ किया जा सके।

नमक सम्बन्धी स्थिति सन्तोषप्रद होने की दृष्टि से यह निर्णय किया गया है कि सरकार निजी उद्योगों में २० प्रतिशत के स्थान पर १० प्रतिशत भागक ही सुरक्षित रखे।

कार्य, गृह-निर्माण एवं सम्पूर्ति

गृह-निर्माण

सरकारी सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह-निर्माण योजना के अन्तर्गत जनवरी १९५४ के अंत तक २६,००० मकानों के निर्माण के लिए ऋणों के रूप में ४०३.६८ लाख रुपये तथा सहायता के रूप में ३६६.५३ लाख रुपये की स्वीकृति दी जा चुकी थी। इनमें से २४,००० मकान राज्य सरकारों को तथा क्षेत्र ५,००० मकान व्यक्तिगत सालिकों को बनवाने थे। नवम्बर १९५३ के अंत तक ५,००० मकान बनाए जा चुके थे। योजना के अन्तर्गत औद्योगिक

मजदूरों की सहकारी-संस्थाओं को ऋणों के रूप में विये जाने वाले धन की मात्रा स्वीकृत धन्य के ३७½ प्रतिशत से बढ़ाकर ५० प्रतिशत कर दी गयी है जिससे उन्हें गृह-निर्माण के लिए अधिक प्रोत्साहन मिल सके। औद्योगिक मजदूरों की सहकारी संस्थाओं की ३५ योजनाएं विचारधीन हैं। इस वर्ष से धान के लिए व्यवस्था ऐसी की गयी है कि अधिक अनुपात में मकान दो-दो कमरे वाले होंगे।

ग्रामीण क्षेत्रों में गृह-निर्माण के सम्बन्ध में "अपनी सहायता दाय करो" का सिद्धान्त मानने का विचार किया जा रहा है। सम्भ्रालय में एक "ग्रामीण भवन-निर्माण एकक" स्थापित किया गया है ताकि देश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए आवश्यक मकानों की योजनाएं बनाई जा सकें। योजनाएं सामूहिक योजना प्रशासन को सौंप दी जायेंगी, जो ग्रामीणों को प्रोत्साहित करेगा।

योजना कमिशन के परामर्श से सम्भ्रालय स्थानीय संस्थाओं तथा राज्य सरकारों को सहायता देने के प्रबल पर विचार कर रहा है ताकि गरीब बस्तियों के सुधार या उनकी सफाई की योजनाएं कार्यान्वित की जा सकें।

बहुत बड़ी संख्या में गृह-निर्माण ■ सम्बन्ध में मुख्य कठिनाई निर्माण धन की अधिकता की है। इसीलिए सरकार की गृह-निर्माण सम्बन्धी नीति में सबसे अधिक जोर निर्माण-धन में कमी करने पर दिया गया है ताकि विशेषकर कम आय वाले लोगों के लिए गृह-निर्माण का कार्य उनके सामर्थ्य के अन्दर हो। इस कार्य को राष्ट्रीय भवन-निर्माण संगठन नामक एक विशेष संस्था को सौंप देने का निर्णय किया गया है। यह संस्था शीघ्र ही स्थापित की जायगी।

दिल्ली में कम लागत के गृह-निर्माण की अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी, गृह निर्माण और समाज-सुधार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय विचार-गोष्ठी तथा अन्तर्राष्ट्रीय गृह-निर्माण एवं नगर-योजना महासंघ (फेडरेशन) के प्रादेशिक सम्मेलन के आयोजन किये गये जिससे अनुभव के पारस्परिक विनिमय को प्रोत्साहन मिल सके और भारत के तथा विश्वों के स्थपतिओं और इंजीनियरों द्वारा निर्मित कम लागत के मकानों के नमूनों का जनता के सामने प्रदर्शन किया जा सके।

केन्द्रीय सार्वजनिक-निर्माण विभाग

यह विभाग विस्थापित व्यक्तियों के लिए अब तक ९७,५०० मकान तथा २,६०० दुकानें बनवा चुका है और २,४०० मकानों और २५० दुकानों का निर्माण हो रहा है। १९५४-५५ में और मकानों तथा दुकानों का निर्माण होगा।

१९५३-५४ में दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए ९,००० क्वार्टरों तथा हवाई अड्डों के पास ५०० क्वार्टरों का निर्माण हुआ।

पूना में पेनिसिलीन फैक्टरी, बंगलौर में घन सम्बन्धी औजारों की फैक्टरी तथा ल्पनारायणपुर में टेलीफोन केबल फैक्टरी का निर्माण-कार्य प्रायः पूरा होने को है। दिल्ली में डी० डी० टी० की फैक्टरी का निर्माण-कार्य भी आरम्भ हो चुका है। कलकत्ता में सामुद्रिक इंजीनियरिंग कालेज की इमारत बन कर तैयार हो चुकी है तथा दिल्ली स्थित टेक्निकल संस्था की इमारतें बन कर तैयार होने वाली हैं।

बम्बई तथा जालंधर में आकाशवाणी के ट्रान्समीटर की इमारतें तैयार हो चुकी हैं तथा अहमदाबाद में तत्सम्बन्धी इमारत बनाई जा रही है।

दिल्ली और बम्बई में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के लिए तथा दिल्ली अहमदाबाद और पूना में आयकर और केन्द्रीय उत्पादन कर के कार्यालयों के लिए इमारतों का निर्माण कार्य संतोषजनक रूप से प्रगति कर रहा है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय और दिल्ली राज्य के जिला न्यायालयों के लिए भी भवन-निर्माण कार्य आरम्भ हो चुका है।

कलकत्ता, सिकन्दराबाद तथा लेकाबाद के टेलीफोन एक्सचेंजों तथा जबलपुर स्थित प्रशिक्षण केंद्र के लिए इमारतें साल भर में बनकर तैयार हो जायेंगी।

नागपुर हवाई अड्डे पर टर्मिनल बिल्डिंग बन कर तैयार हो चुकी है।

बम-बम हवाई अड्डे का ७,००० फुट सम्मान्य पक्का फर्श तैयार हो चुका है। इस फर्श पर प्रायुक्तिक ढंग की प्रकाश सम्बन्धी सुविधाओं की भी व्यवस्था तेजी से की जा रही है।

उड़ड़यन सम्बन्धी प्रायुक्तिक आवश्यकताओं के अनुसार सान्ताक्रुड हवाई अड्डे के पक्के फर्श का विस्तार कर लिया गया है और हवाई अड्डे पर टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण तेजी से हो रहा है।

आगरा-बम्बई सड़क पर पड़ने वाली चम्बल नदी पर एक पुल शीघ्र ही बनाया जायगा, जब कि कलकत्ता-बम्बई सड़क पर पड़ने वाली बंतरणी और आग्रणी नदियों के पुल का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है।

स्टेशनरी तथा प्रिन्टिंग विभाग

यह विभाग प्रयासमय देश में सभी वस्तुओं की ही खरीदने का प्रयास करता है। कुटीर तथा छोटे पैमाने के उद्योगों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से सरकार के काम में आने वाली स्टेशनरी तथा स्याही तोड़ने के लिए हाथ काटने का उपयोग करने का निर्णय किया गया।

भारत सरकार के मुख्यालयों के पुनर्संगठन और विस्तार का कार्य स्वीकृत योजनाओं के अनुसार चला। शिमला स्थित भारत सरकार के मुख्यालय तथा दिल्ली के यूनाइटेड प्रेस के लिए फरीदाबाद में संबंध उपयोगी भवन-निर्माण का प्रारम्भिक कार्य पूरा हो चुका है। इन दोनों मुख्यालयों को मिलाकर एक मुख्यालय बना दिया जायगा। पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आयोजित नासिक में भारत सरकार के नये मुख्यालय के सम्बन्ध में निर्माण-कार्य संतोषजनक रूप से चल रहा है।

इस विभाग से कई महत्वपूर्ण प्रकाशनों के मुद्रण के लिए कहा गया। इस सम्बन्ध में 'गंधी-विजयली' तथा 'रेलवे शताब्दी और टेलीग्राफ शताब्दी' ग्रंथों का विशेष उल्लेख किया जा सकता है।

कोलम्बो योजना से अन्तर्गत १९५२ में ब्रिटेन से प्राप्त डेक्कन सत्याह-

कार दमिन्दार मामलों, विशेषकर भारत सरकार के मुख्यालयों के पुनर्संगठन और विस्तार संबंधित मामलों में सलाहमशविरा देता रहा ।

मजदूरों के लिए गृह-निर्माण को और भी विशेष ध्यान दिया गया । इस सम्बन्ध में नई दिल्ली स्थित भारत सरकार के मुख्यालय के कर्मचारियों के लिए ८० क्वार्टर बनाने का निर्णय किया गया ।

संपूर्ति और बिक्री

कार्य

कार्य, गृह-निर्माण एवं संपूर्ति मन्त्रालय के कार्य-संगठनों ने अप्रैल १९५३ विसम्बर १९५३ तक के समय में भारत में तथा विदेशों में कुल ६३ करोड़ ७० लाख रुपये का कार्य किया । इसमें से ३६ करोड़ ४० लाख रुपये के मूल्य का कार्य नई दिल्ली स्थित संपूर्ति और बिक्री के डायरेक्टरेट जनरल के १४ करोड़ १० लाख रुपये के मूल्य का कार्य लंदन स्थित इण्डिया स्टोर विभाग के डायरेक्टरेट जनरल के तथा १० करोड़ २० लाख रुपये के मूल्य का कार्य वाशिंगटन स्थित इण्डियन सप्लाय मिशन के माध्यम से हुआ । (१० करोड़ २० लाख रुपये की राशि में ४ करोड़ ७० लाख रुपये के मूल्य का खाद्य-कार्य सम्मिलित है ।)

अर्ध में वाणिज्य और उद्योग मन्त्रालय के टेक्सटाइल कमिशनर ने अप्रैल १९५३ से अक्टूबर १९५३ तक के समय में ३ करोड़ ५ लाख रुपये के मूल्य का सूती वस्त्र कारीदा । १ नवम्बर १९५३ को पूर्ति एवं बिक्री के डायरेक्टरेट जनरल के अन्तर्गत टेक्सटाइल कमिशनर का कार्य-संगठन कार्य, गृह-निर्माण एवं संपूर्ति मन्त्रालय के अधिकार में कर दिया गया ।

पेट्रोलियम की वस्तुओं, इस्पात, सीसा, ताँबे के केबल, ताँबे के तार तथा ढील आदि को छोड़ कर अन्य वस्तुओं का मूल्य गिरने लगा । धातुओं के मूल्य में औसतन ४० प्रतिशत तथा अन्य वस्तुओं के मूल्य में २० से २५ प्रतिशत गिरावट आई ।

कुटीर तथा छोटे पैमाने के उद्योगों को प्रोत्साहन देने तथा खादी के

अधिक उपयोग की दृष्टि से अखिल भारत खादी ग्राम-उद्योग बोर्ड की सलाह से सरकार की आवश्यकताओं के लिए खादी के प्रयोग के सम्बन्ध में विशेष उपाय किये गये हैं। मार्च १९५३ से लेकर अबतक २ लाख रुपये की खादी का आर्डर दिया जा चुका है। खादी के उत्पादन के विकास के लिए भी विभिन्न उपाय किये जा चुके हैं और आशा है कि सरकार ने आवश्यकताओं के लिए खादी का प्रयोग अधिक से अधिक होता जायेगा। यथासंभव कम भारत में ही किया जा रहा है।

वर्तमान संगठन तथा आवश्यक वस्तुओं के कम के सम्बन्ध में अपनाए जाने वाले तरीकों में सुधार करने की दृष्टि से भारत सरकार ने एक स्टोर्स-कम-समिति नियुक्त की है। इसकी सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है। यही समिति लंदन तथा वाशिंगटन की समितियों की सिफारिशों की भी जांच कर रही है।

सरकार के कम-संगठन में एक निरीक्षण-विभाग भी है जिसमें टेक्निकल कर्मचारी सरकारी काम के लिए रखे गये सामान का निरीक्षण करते हैं। मार्च १९५३ से अक्टूबर १९५३ तक ४६ करोड़ ५० लाख रुपये के मूल्य के सामान का निरीक्षण किया गया।

राष्ट्रीय सरकारी-निरीक्षण-गृह सरकारी विभागों, व्यक्तियों, फर्मों तथा सार्वजनिक संस्थाओं की ओर से सामानों का परीक्षण करता रहा। यह परीक्षण सम्बन्धी प्रमाणपत्र देता तथा टेक्निकल सहायता एवं सूचना आदि भी देता है।

बिक्री

युद्ध-काल में खरीदे गये सामान में से जो कालमू बचा हुआ था, उसे बेच दिया गया है। नवम्बर १९५३ में १६ लाख रुपये के मूल्य की सशस्त्र वाहनों, संयंत्र एवं बिक्री के बायरेट्टरेट-अभरल द्वारा देश में सब से अधिक मूल्य देने वाले को ३३ लाख रुपये में बेच दी गई।

विस्फोटक पदार्थ सम्बन्धी विभाग

१९५३ में १९४० के विस्फोटक पदार्थ नियमों के अन्तर्गत ३,२६६ लाइसेंस तथा पेट्रोलियम और केल्शियम कारबाइड नियमों तथा सिनेमेटोग्राफ फिल्म नियमों के अन्तर्गत ८,१८१ लाइसेंस दिये गये। विस्फोटक पदार्थों तथा पेट्रोलियम का कारोबार करने वाली लाइसेंस प्राप्त महत्वपूर्ण संस्थाओं में से अधिकांश का निरीक्षण किया गया और विस्फोटक पदार्थों के रखने उठाये जाने के कारण हुई कई दुर्घटनाओं की जांच पड़ताल की गयी। विभिन्न राज्य सरकारों से परीक्षण के लिए कई प्रकार के विस्फोटक पदार्थों के नमूने प्राप्त हुए। इस विभाग न स्थापित की जाने वाली एक तेल शोधक कम्पनी की विभिन्न इकाइयों सम्बन्धी विस्तृत योजनाओं की जांच-पड़ताल की और उन्हें पब्लिकार किया। यह कम्पनी बनाई जा रही है।

खानों तथा वायर की खानों में भूमि-विस्फोट के लिए इस वर्ष सिटोन से २ करोड़ रुपये के विस्फोटक पदार्थों का आयात किया गया। भूमि-विस्फोट सम्बन्धी विस्फोटक पदार्थों के निर्माण के लिए भारत में एक कारखाना खोले जाने के सम्बन्ध में सरकार ने इम्पोरियल केमिकल इन्डस्ट्रीज के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं।

पेट्रोलियम विभाग

ईरान से पेट्रोलियम की वस्तुएं प्राप्त किये जा सकने के कारण ये वस्तुएं बहुत दूर से मंगानी पड़ती हैं। इसके फलस्वरूप सभी खोजों का मूल्य बढ़ा हुआ है। सामुद्रिक भाइयों में कमी खाने तथा भारत से कम दूरी पर पेट्रोलियम की वस्तुएं सुलभ हो जाने के परिणामस्वरूप २ दिसम्बर, १९५३ से इनके मूल्य गिरने लगे हैं।

अगले वित्तीय वर्ष में ३० लाख टन की क्षमता की आयोजित तेल शोधक कम्पनियों का उत्पादन-कार्य आरम्भ हो जाने के फलस्वरूप पेट्रोलियम की वस्तुएं अधिक मात्रा में उपलब्ध हो सकेंगी। ऊपरी आसाम के नहर करहया क्षेत्र में तेल का पता लग जाने की दृष्टि से आशा है कि पेट्रोलियम की वस्तुओं का उत्पादन देश में हो जाने लगेगा और इस सम्बन्ध में स्थिति सुधर जायगी।

३. आन्तरिक

गृह-मंत्रालय

इस मंत्रालय के विभिन्न दो मुख्य कार्य हैं : सार्वजनिक सेवाएं और सार्वजनिक सुरक्षा। सेवाओं में भरती करना, अनुशासन बनाए रखना तथा सेवा सम्बन्धी नियम बनाना इसके मुख्य उत्तरदायित्व हैं। अखिल भारतीय सेवाओं का संचालन संयुक्त रूप से केन्द्रीय और राज्य सरकारें करती हैं।

सार्वजनिक सुरक्षा सम्बन्धी मामलों के विषय में १९५१ के भाग "ग" राज्य कानून के पास होने तक केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्रों में शान्ति तथा व्यवस्था बनाये रखने का उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार का था ; किन्तु भाग "ग" राज्य कानून पास हो जाने के समय से अब बहुत कुछ उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर आ गया है। भाग "क" और "ख" के राज्य अपने-अपने क्षेत्रों के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं। इस प्रकार केन्द्रीय-सरकार का काम अब मुख्य रूप से सामान्य तथा सलाह-मसिवरा देने का रह गया है।

केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्र

अंशमान और निकोबार द्वीपसमूह को बसाने की पंचवर्षीय योजना संतोषजनक रूप से कार्यान्वित की जा रही है और आशा है कि मानचून के पहले ही द्वीपसमूह में ४०० कुक्क परिवारों को बसा दिया जायेगा। पूर्वी बंगाल से आये ६७ विस्थापित कुक्क परिवारों का कार्य, जिन्हें द्वीपसमूह में १९५३ में बसाया गया था, सुचारु रूप से चल रहा है।

ग्रान्तरिक

अंबभान के जंगल गन्ना, बांस, नारियल, साड़ की पत्तियों, आदि जैसी छोटी-छोटी वन-जन्य वस्तुओं से भरे पड़े हैं। इन वस्तुओं का कुटीर उद्योगों द्वारा उपयोग किये जाने के लिए एक संगठन की रचना की जा चुकी है। १९५३-५४ के बजट में अंबभान और निकोबार द्वीपसमूह के विकास के लिए १,७५,८५,००० रुपये सुरक्षित रखे गये थे।

अनुसूचित जातियाँ तथा जन-जातियाँ

अनुसूचित जातियों तथा जन जातियों के कल्याण के लिए तथा अनुसूचित क्षेत्रों के विकास के लिए भाग "क" और "ख" के राज्यों के लिए २,४७,०२,००० रुपये और भाग "ग" के राज्यों के लिए २७,०३,००० रुपये स्वीकृत किये जा चुके हैं। १९५४-५५ के बजट प्रायकलनों में भाग "क" और "ख" ■ राज्यों के लिए ३ करोड़ ५६ लाख रुपये की तथा भाग "ग" के राज्यों के लिए साढ़े ३३ लाख ५० हजार रुपये की व्यवस्था की गयी है। अनुसूचित जन जातियों के अलावा पिछड़ी जातियों की स्थिति सुधारने के लिए पंचवर्षीय योजना में ४ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। अनुसूचित जातियों, पहले की जरायम पेशा जातियों तथा पिछड़ी जातियों की कल्याण सम्बन्धी योजनाओं के लिए १९५४-५५ के बजट में सत्रा करोड़ रुपये की सहायता देना निश्चित हुआ था।

पिछड़ी जातियों सम्बन्धी कमीशन

पिछड़ी जातियों सम्बन्धी कमीशन अब तक १२ राज्यों की छानबीन कर चुका है। इसने सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी जातियों की स्थिति की जाँच पड़ताल उनके क्षेत्रों में जाकर की। आशा है कि कमीशन का कार्य इस वर्ष के अंत तक पूरा हो जायगा।

आंध्र राज्य

१९५३ में आन्ध्र-राज्य कागून पास होने के परिणामस्वरूप नये आन्ध्र राज्य का जन्म १ अक्टूबर, १९५३ को हुआ। भाग "क" के एक राज्य के रूप में इसका शासन एक लोकप्रिय मन्त्रिमंडल करता है।

सातवीं वर्ष

राज्य-पुनर्संगठन सम्बन्धी कमीशन

राज्यों के पुनर्संगठन के लिए भारत सरकार ने श्री संयुक्त फजल अली की अध्यक्षता में एक कमीशन नियुक्त किया है। कमीशन ने लोकप्रिय संगठनों से गवाही लेना आरम्भ करके अपना कार्य शुरू कर दिया है।

नज़रबन्दी कानून

इस सम्बन्ध में विभिन्न राज्य सरकारों से मुक्तिसंगत प्रांशुओं का संकलन किया गया और उन्हें दिसम्बर १९५३ में एक रिपोर्ट के रूप में संसद में प्रस्तुत किया गया। संसद के दोनों सदनों ने इस आदेश के प्रस्ताव स्वीकार किए कि १९५० के नज़रबन्दी कानून को ३१ दिसम्बर १९५४ तक लागू रखना पूरी तरह से व्यापेक्षित है।

प्रेस (प्रापसिजनक सामग्री) कानून

१९५१ का यह कानून ३१ जनवरी १९५४ को समाप्त हो जाने वाला था किन्तु इसमें की गयी व्यवस्थाएँ अन्य किसी कानून में नहीं हैं, इसलिए १९५३ का प्रेस (प्रापसिजनक सामग्री) संशोधन विधेयक १५ दिसम्बर १९५३ को संसद में पेश किया गया। इस विधेयक द्वारा उल्लिखित कानून की अवधि दो वर्षों के लिए और बढ़ा दी गयी तथा उसमें कई अविवादास्पद संशोधन भी किए गये। अन्य कार्यों के भार के कारण विधेयक पर बहुत न की जा सकी और इसलिए संशोधन विधेयक के आधार पर एक अध्यादेश लागू कर दिया गया।

पुलिस विभाग

आसाम, कुर्ग तथा विल्ली को छोड़कर अन्य सभी राज्यों के पुलिस बलों में कुछ कमी की गई।

भारतीय अस्त्र कानून

भारतीय अस्त्र कानून तथा इसके अन्तर्गत बचाये गये नियमों के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार को कुछ अधिकार, जम्मू और काश्मीर को छोड़कर, भाग 'क' का राज्य सरकारों का दिये गये। उचित रूप से संगठित राक्षस-बलबों की

स्थापना को प्रोत्साहन दिया गया तथा राज्य सरकारों को सलाह दी गई कि वे इन सब क्लबों से अपने को प्रामुखावाय स्थित अखिल भारतीय संस्था 'नेशनल राइफल एसोसिएशन' से सम्बद्ध करने को सिफारिश करें। राइफल क्लबों को यथा संभव सरकारी फंडिंग में बनी बाबूद दिये जाने का भी निर्णय किया जा चुका है। यह बाबूद उसी दर पर दी जायगी जित दर पर प्रतिरक्षा सेवाओं के अधिकारियों को दी जाती है।

जेल तथा सुधार सम्बन्धी कार्य

बम्बई की डाटा समाज-विज्ञान संस्था में जेल अधिकारियों लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करने तथा विभिन्न राज्य सरकारों को अपराध-विज्ञान आदि विषयों के सम्बन्ध में परामर्श देने की दृष्टि से १९५२-५३ में संयुक्त राष्ट्रसंघ से अपराध विज्ञान-विशेषज्ञ डा० वाल्टर सी० रैबलेस की सेवाएं प्राप्त की गयीं। अपनी अवधि की समाप्ति पर डा० वाल्टर सी० रैबलेस ने संयुक्त राष्ट्र संघ को "भारत में जेल सम्बन्धी प्रशासन" पर अपनी रिपोर्ट दी। मन्त्रालय इस रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुसार काम करने का विचार कर रहा है।

पाकिस्तानी नागरिकों को बसाना

अनिश्चित काल के लिए भारत वापस आने के इच्छुक पाकिस्तानी नागरिकों से अपेक्षा की जाती है कि वे ऐसा दीर्घकालीन पासपोर्टों के आधार पर करें। पाकिस्तान स्थित भारतीय हाई-कमिशनर को ऐसे पासपोर्ट देने का अधिकार केन्द्रीय सरकार ने सम्बन्धित विभिन्न राज्य सरकारों की सलाह से दिया है। १९५३ में हुए भारत-पाकिस्तान सम्मेलन के बाद यह निर्णय किया गया कि विभाजित परिवारों के फिर से एक होने की सुविधाएं दी जायें।

अखिल भारतीय सेवाएं

१९५२-५३ की रिपोर्ट में यह बताया गया था कि भाग 'क' के सभी राज्यों के लिए भारतीय शासन सेवा सम्बन्धी क्रमानुसार सूची स्वीकृति के लिए 'यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन' के पास भेज दी गई है। भाग 'ख' के राज्यों के सम्बन्ध में भारतीय शासन सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा की सूचियां अंतिम रूप से तैयार किये जाने के कार्य में काफी प्रगति हुई है। अखिल भारतीय सेवा कानून के अन्तर्गत नियम बनाने का काम १९५३ में शुरू किया गया था।

केन्द्रीय सेवाएं

केन्द्रीय सचिवालय की प्रथम श्रेणी से तृतीय श्रेणी तक की सेवाओं सम्बन्धी विधान अब पूरा हो चुका है। सभी विभागों में काम करने वाले कर्मचारी इन्हीं श्रेणियों में आते हैं। वर्तमान अधिकारियों में से यूनिजन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा पर्याप्त संख्या में अधिकारी योग्य पाये गये। इस प्रकार अन्य अधिकारियों की नियुक्ति का अंशूट अब नहीं रहा। यह निर्णय किया गया है कि यूनिजन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा योग्य ठहराई गई विभागोत्तर महिलाओं को भी इन सेवाओं के लिए नियुक्ति दी जाये। तीनों श्रेणियों की सेवाओं की स्थायी नियुक्तियों के बजाया तीसरी श्रेणी की सेवाओं के लिए नियमित अस्थायी नियुक्तियों की भी व्यवस्था की गई है।

चतुर्थ श्रेणी

चतुर्थ श्रेणी की सेवाओं के लिए स्थायी नियुक्तियों के लिए १,८०० स्थान तथा नियमित अस्थायी नियुक्तियों के लिए १,२०० स्थान निर्धारित हैं। स्थायी नियुक्तियों के स्थानों में से १,७६४ स्थानों पर नियुक्ति दी चुकी है और नियमित अस्थायी नियुक्तियों के लिए १,००० नाम प्रकाशित किये जा चुके हैं।

केन्द्रीय सचिवालय-स्टेनोग्राफर सेवा

विचाराधीन वर्ष में तीसरी श्रेणी के १३८ स्टेनोग्राफरों की नियुक्तियों की सम्पुष्टि हो गयी। अब तक कुल ५२१ नियुक्तियों की सम्पुष्टि हो चुकी है। अधिकृत स्थायी नियुक्तियों की संख्या ६०४ है। प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के लिए योग्य व्यक्तियों की सूची यूनिजन पब्लिक सर्विस कमीशन के पास योग्यता-नुसार श्रेणीकरण के लिए भेजी जा चुकी है।

राज्य मन्त्रालय

राज्य मन्त्रालय ग्रन्थ मन्त्रालयों की सलाह से भाग "क" के राज्यों की प्रशासकीय, विस्तीर्ण और आर्थिक समस्याओं की देखभाल करता है। यह भाग "ग" भाग के राज्यों—हिमाचल प्रदेश, विन्ध्यप्रदेश, भोपाल, जिलापुरा, मणिपुर, कच्छ और जिलापुर—सम्बन्धी मामलों की भी देखभाल करता है।

पप्पू में राष्ट्रपति का शासन

४ मार्च १९५५ को घोषणा द्वारा राष्ट्रपति ने पड़ियाला तथा पूर्वी पंजाब राज्य संघ के प्रशासन का भार स्वयं अपने ऊपर लिया। राज्य का प्रशासन बर्ष भर केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण में रहा। इस समय में शान्ति एवं व्यवस्था पुनः स्थापित की गयी, ग्राम-मुधार किए गये, सेवाओं का पुनर्स्थापन किया गया, पैम्पू तथा पंजाब के लिए भारतीय शासन सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा की संयुक्त कर्ष व्यवस्था की गई तथा जिलों का पुनर्स्थापन किया गया। विकास सम्बन्धी सभी कार्य-क्षेत्रों में अच्छी प्रगति हुई।

१९५५ के पैम्पू विधान मंडल (अधिकार प्रदाता) कानून की धारा ३ के अन्तर्गत मिले अधिकारों के अनुसार चलते हुए राष्ट्रपति ने राज्य में कई उपयोगी विधान लागू किए।

राष्ट्रपति की घोषणा २६ मार्च, १९५४ को सभापत हुई। ७ मार्च १९५४ तक ग्राम चुनाव पूरा करने के सम्बन्ध में प्रयत्न किये गये। फरवरी १९५४ के उत्तरदाई के पहले चुनाव संभव नहीं हो सका, क्योंकि राज्य विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन सम्बन्धी परिसीमन कमीशन का आदेश सितम्बर के अन्त में प्रकाशित हुआ और इस आदेश के अनुसार मतदाताओं की सूचियाँ १५ दिसम्बर, १९५५ को ही तैयार हो पाईं। कर्नल रघुबीरसिंह के मुख्य अतिथि में गये मंत्रिमंडल ने ८ मार्च १९५४ को शपथ ग्रहण की।

तिरुवांकुर-कोचीन

२३ सितम्बर, १९५३ को तिरुवांकुर-कोचीन मंत्रिमंडल द्वारा रसे गये विधानसभा के प्रस्ताव को गिर जाने पर राज्य के राजप्रमुख ने राज्य विधान मंडल भंग करके नये चुनाव का आदेश दिया। नये चुनावों की समाप्ति तक पुराने मंत्रिमंडल से बने रहने का अनुरोध किया गया। चुनाव के परिणामस्वरूप किसी भी दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त न होने की अवस्था में राजप्रमुख ने प्रमुख-दलों ■ नेताओं के साथ परामर्श करने के बाव भी परसुम बानु पिल्लई से मंत्रिमंडल बनाने के लिए कहा। श्री पिल्लई ने १६ मार्च, १९५४ को मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली।

भाग "ग" के राज्यों का शासन (संशोधन) कानून

१९५१ का भाग "ग" राज्य शासन-कानून ६ सितम्बर, १९५१ को लागू हुआ। भाग "ग" के कुछ राज्यों में विधान सभाओं तथा मंत्रिमण्डलों की स्थापना के सम्बन्ध में कानून की व्यवस्थाएँ मार्च १९५२ में लागू हुईं। प्रजपेर, भीमाल, कुर्ग, विल्ली, हिमाचल प्रदेश तथा बिन्ध्य प्रदेश के राज्यों में प्रत्यक्ष भाग "ग" राज्य-सरकार कानून सम्बन्धी अनुभव के प्रकाश में कानून में संशोधन करना आवश्यक समझा गया जिससे उसमें निम्नलिखित विषय सम्बन्धी व्यवस्थाएँ की जा सकें।

(१) सम्बन्धित राज्य की विधान सभा में राज्य के प्राय-व्यय के लेखों पर सचिवर जनरल और कम्प्यूलर की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए;

(२) कानून की धारा ३६ को संशोधित किया जाय जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि प्रत्यक्ष राज्य विधान सभाओं में विधेयक तो हिन्दी में प्रस्तुत किये जा सकते हैं और उनके अन्धीन नियम और आदेश हिन्दी अथवा प्रादेशिक भाषा में जारी किये जा सकते हैं, पर अधिकृत लेखन कार्य भाग "क" और "ख" के राज्यों की भाँति अंग्रेजी में ही हो;

(३) कानून की धारा ३८ का संशोधन इसकी धोर संकेत करने के लिए किया जाये कि भाग "ग" राज्यों के संगठित कोष में केन्द्र द्वारा दिए गए

जहाँ भी सम्मिलित रहेंगे जिससे राज्य अपने पूँजीगत खजाने बना सकें;

(४) राष्ट्रपति की चुनाव कमीशन के परामर्श से राज्य विधान सभा के किसी भी सदस्य को अयोग्य घोषित करने के प्रश्न पर निर्णय करने के अधिकार की व्यवस्था की जाये;

(५) कानून की धारा २२ का संशोधन किया जाये जिससे राज्य विधान सभा २६ जनवरी, १९५० से १ अप्रैल, १९५२ तक के समय में राज्य तथा संसदसदस्यी सूची में सम्मिलित विधेय के सम्बन्ध में संसद द्वारा पास किये गये कानूनों में संशोधन कर सके; और

(६) प्रत्येक राज्य के लिए 'आकस्मिक कोष' की स्थापना की जाये।

इन व्यवस्थाओं से सम्बन्धित एक विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पास किया गया और भाग 'ग' राज्य शासन (संशोधन) कानून १ अप्रैल, १९५४ को लागू हुआ।

बिलासपुर

बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश में मिला देने का निर्णय किया गया है। इसलिए हिमाचल प्रदेश का लेफ्टिनेंट गवर्नर बिलासपुर का चीफ कमिश्नर भी नियुक्त किया गया। इस परिवर्तन के कलस्वरूप हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलानों के प्रधानों के अधिकार में बिलासपुर के भी तत्सम्बन्धी विभाग कर दिये गये। बिलासपुर के हिमाचल प्रदेश में पूर्ण रूप से मिला दिये जाने के पूर्व दोनों राज्यों के शासन में एक प्रकार से एकत्वता ला दी गई है।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश

१९५३ का उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (भाग "क" के राज्य) आदेश राष्ट्रपति द्वारा २६ दिसम्बर, १९५३ को जारी किया गया था। इस आदेश में जो राज्य सरकारों तथा राजप्रमुख के परामर्श से जारी किया गया था, भाग "ख" के राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की वेतन, छुट्टी, उनके भत्तों तथा भाना-भत्तों के सम्बन्ध में व्यवस्थाएँ दी गई हैं। इस आदेश के

अन्तर्गत वे न्यायाधीश भी आ जायेंगे जो एक निर्दिष्ट समय के लिए इन उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश अथवा सामान्य न्यायाधीश रहे तथा जो आदेश जारी होने की तिथि के पहले अवकाश प्राप्त कर चुके हैं।

भाग 'ख' और 'ग' राज्यों में काश्तकारी-कानून-सुधार

हैदराबाद, बिस्मय प्रदेश, भोपाल और हिमाचल प्रदेश में काश्तकारी कानून में सुधार किये गये। बिस्मय प्रदेश और भोपाल में कानून द्वारा जालीरों का उन्मूलन हो गया है जिसके अन्तर्गत वर्तमान काश्तकारों को स्वन्त्राधिकार और जागीरदारों को सुझावित्वा का भुगतान भी शामिल है। इन उपायों को योजना कमीशन के साथ परामर्श-पूर्वक किया गया है और वे पंचवर्षीय योजना की मुख्य सिफारिशों के अनुकूल हैं।

सलाहकार-परिषद

'ग' भाग शासन अधिनियम १९५१ की धारा ४२ के अनुसार त्रिपुरा और मणिपुर में सलाहकार परिषदें बनाई गईं। त्रिपुरा की सलाहकार-परिषद में तीन गैर सरकारी सदस्य हैं और मणिपुर की परिषद में पाँच।

सीमा का समन्वय

राजस्थान और बम्बई, तिरुवांकुर-कोचीन और मद्रास तथा बिहार और वड़ीसा के मध्य सीमा-समन्वय सम्बन्धी कई प्रश्न उठे, जिन पर अब राज्य-पुनर्गठन कमीशन विचार करेगा।

'ख' भाग के राज्यों को विशेष सहायता

राजस्थान, मध्यभारत, सौराष्ट्र और केम्पू के साथ किये गये संघीय वित्तीय इकीकरण सम्बन्धी समझौतों की शर्तों के अनुसार भारत सरकार ने इन चार राज्यों को १९५१-५२ में ३ करोड़ रुपये देना निश्चित किया है। यह राशि केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत राष्ट्रीय योजनाओं पर व्यय हुआ है। इन योजनाओं में सिंचाई के साधन, देहात में लाल बगवस्था, और सड़कों और पुलों का निर्माण शामिल हैं।

इन चारों राज्यों को उच्चतम समझौतों की शर्तों के अनुसार और अधिक

सहायता देने के सम्बन्ध में विचार करने के लिए भारत सरकार ने श्री० एन० श्री० गाडगिल को अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है, जो इन राज्यों की खास-खास आवश्यकताओं की जांच करेगी।

सरकार ने कमेटी की सिफारिशों को यह समझकर स्वीकार कर लिया है कि राज्य सरकारें भी उन सिफारिशों को कार्यान्वित करेंगी जो कमेटी ने प्रशासनिक और आयोगनात्मक शासन-यन्त्र के सुधार की दृष्टि से की हैं। इस निश्चय के कारण उस विशेष सहायता के अतिरिक्त जो कि इन राज्यों को दी जा चुकी है, राज्यों की पंचवर्षीय योजनाओं के लिए दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता में से ४ करोड़ २० की सहायता सीधे अनुदान के रूप में दी जायगी, ऋणों के रूप में नहीं। यह चार करोड़ रुपये की रकम राज्यों में इस प्रकार वितरित होगी :—

	लाख रुपये
सौराष्ट्र	१००
मध्यभारत	१००
राजस्थान	१५०
केन्द्रीय	५०

प्रशासनिक इमारतों, सड़कों और गांवों में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था के लिए, आगामी दो वर्षों में इन राज्यों को ४ करोड़ रुपये तदर्थ अनुदान के रूप में और दिये जाएंगे। यह तदर्थ अनुदान इस प्रकार वितरित होगा—

	लाख रुपये
सौराष्ट्र	६०
मध्यभारत	१००
राजस्थान	१५०
केन्द्रीय	६०

उपर्युक्त उद्देश्यों की सिद्धि के लिए १९५४-५५ के केन्द्रीय बजट में कमरा: २२५ लाख और १५० लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। शेष दरखा इन् राज्यों की आवश्यकतानुसार दिया जायगा।

‘ग’ भाग के राज्यों को अनुदान

मोवाल, हिमाचल प्रदेश, और विन्ध्य प्रदेश की अपनी अलग एकीकृत निधियाँ हैं, परन्तु केन्द्रीय सरकार के राजस्व से वार्षिक अनुदान भी इन निधियों को मिलता है।

कच्छ, भरिगुर और त्रिपुरा की अपनी अलग स्वीकृत निधियाँ नहीं हैं, उनका राजस्व और अन्य आय कोन्द्रीय राजस्व में जमा होती है और उनके व्यय की व्यवस्था कोन्द्रीय बजट में की जाती है।

केन्द्र और ‘ग’ भाग के राज्य

यह निश्चय हो चुका है कि भारत सरकार के मन्त्रालय ‘ग’ भाग के राज्यों के अपने प्रशासनाधीन विषयों को संभालें और राज्यमन्त्रालय वान्ति और व्यवस्था, शासकों के अधिकार और विशेषाधिकार तथा भारत सरकार अथवा राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजे गये विधेयकों की जाँच-पड़ताल, राज्य की आन्तरिक समस्याओं के मुलभूत आदि का कार्य करे। राज्य-मन्त्रालय ‘ग’ भाग के राज्यों के बजटों की जाँच-पड़ताल भी करता है।

संचार

नागरिक हवाई यात्रा

देश के वायु परिवहन उद्योग को आर्थिक दृष्टि से सुबुझ बनाने के लिये, उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और १५ जुलाई, १९५३ को दो वायु निगम बनाये गये (१) एअर इण्डिया इन्टरनेशनल और (२) इण्डियन एअरलाइन्स कारपोरेशन। इन निगमों ने १ अगस्त, १९५३ को ६ अनुसूचित वायु परिवहन कम्पनियों का काम अपने हाथ में ले लिया।

एअर इण्डिया इन्टरनेशनल ने ब्रिटेन और मैरीडी की सेवाएँ जारी रखीं।

३ जनवरी, १९५३ से नैरोबी वाली सेवा की गति बढ़ाकर पलवाड़े में ३ बार से सप्ताह में २ बार कर दी गई। ब्रिटेन वाली सेवा की गति भी बढ़ा दी गई और सप्ताह में ३ बार से ४ बार कर दी गई। इसके अलावा एयर इण्डिया इन्टरनेशनल ने १९५४ के मध्य तक बेंगलूर और मंगोला, हांगकांग होकर टोकियो को और सिंगपुर होकर अकार्ता को नई सेवा जारी करने की योजना बनाई है।

इण्डियन एयरलाइन्स कनफेरेन्स अपने उड़ोटा हवाई जहाजों के स्थान पर नये किस्म के हवाई जहाज रखना चाहता है और इसके लिये १९५४-५५ के बजट में आवश्यक व्यवस्था हो गई है।

७ नवम्बर, १९५३ को पाकिस्तान से बातचीत करने के बाद इण्डियन एयरलाइन्स ने अमृतसर-लाहौर-कामुल-कंधार मार्ग पर दिल्ली से अफगानिस्तान को नई सेवा जारी की। पहले यमई से काबुल तक एक सेवा थी, जो कराची, जहोवन, और कंधार के टेढ़े-मेढ़े मार्ग से जाती थी।

इस वर्ष वायु-सेवाओं के संचालन के लिये भूमि सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था में विशेष सुधार हुआ। समुचित वायु यातायात नियन्त्रण तथा तार-टेलीफोन संचार सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था के लिये कूजबिहार और कलकत्ता के हवाई स्टेशन पश्चिमी बंगाल की सरकार से ले लिये गये।

अमृतसर में एक दूसरा रन-वे और डबलू. टी. स्टेशन बन कर तैयार हो गया। सान्ता क्लॉज के रन-वे और बढ़ा दिये गये तथा पालन में वर्तमान टैक्सी-मार्ग चौड़ा कर दिया गया और एक नया मार्ग और बनाया गया।

इलाहाबाद में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केन्द्र ने व्यापारिक विमान-चालकों, नाविकों, भूमि-यन्त्रशास्त्रियों, वायु यातायात नियन्त्रण अफसरों और रेडियो ऑपरेटरों तथा टेक्निशियनों को प्रशिक्षण दिया। इनके अलावा वायु-संचार-संगठन के कर्मचारियों के लिये प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया। कोलम्बो योजना के अनुसार नागरिक उड्डयन के विभिन्न विषयों

सालर्वा वर्ष

के प्रशिक्षण के लिये केन्द्र में १६ स्थान बंशिए और दक्षिण पूर्वी एशिया के नागरिकों के लिये सुरक्षित रखे जाते हैं।

जयपुर में राजस्थान ग्लाइडिंग क्लब नामक एक नये उड़्डयन क्लब की सहायता भी गई। इस क्लब वहाँ पहले से ही विद्यमान थे। १९५९-५४ में इन उड़्डयन क्लबों ने कुल मिला कर १२७ "क" श्रेणी के और ३६ "ख" श्रेणी के विमान चालकों को प्रशिक्षण दिया। पुना और दिल्ली के दोनों ग्लाइडिंग क्लबों को सरकारी सहायता मिलती रहती है और उन्होंने ७१ ग्लाइडर चालकों को प्रशिक्षण दिया। उड़्डयन और ग्लाइडिंग क्लबों को कुल १४.८ लाख रुपये की सहायता भी गई।

सरकारी सहायता के बावजूब, पुना का भारतीय ग्लाइडिंग संघ प्राथमिक कठिनाइयों में फँसता जा रहा है। अब सरकार ने उसे अपने अधिकार में लेने का निश्चय कर लिया है।

मौसम सूचना

भारतीय मौसम सूचना विभाग सैनिक और असेनिक हवाई यान, नाविक और व्यापारिक जहाजरानी, अग्निगाह, कृषि, वनों, सिंचाई और विजली योजनाओं, सार्वजनिक निर्माण कार्यों, रेलों, सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याओं और जनसाधारण के लिये मौसम सम्बन्धी सूचनायें देता है।

जात तौर से किसानों के लिये आकाशवाणी के केन्द्रों से विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं में मौसम सम्बन्धी सूचनायें दी जाती हैं। ये सूचनायें अक्सरारों में भी छपती हैं और कपया मेकनेवाले लोगों को तार द्वारा भी भेजी जाती हैं। उत्तर भारत में एक बेशशास की स्थापना के लिये स्थान चुनने के लिये उज्जैन में २ साल तक निरीक्षण परिस्थितियों के देखने का प्रबन्ध किया जा चुका है।

रेडियो वायु-मान केन्द्रों की स्थापना की योजना पर विचार हो रहा है। ये केन्द्र अधिक ऊँचाई पर और वर्षा के दिनों में ऊपर की हवाओं का अध्ययन किया करेंगे। हवाई जहाजों को आँधी-तूफान की सूचना देने के लिये वेज के

अन्तर आस-बास अन्तर्राष्ट्रीय हवाईअड्डों पर रखार बन्द लगाने पर भी विचार हो रहा है।

आसाम और उत्तरपूर्वी सीमा प्रवेग में भीतम-सूचना-संगठन को पृष्ठ चलाने के उपाय किये जा रहे हैं।

समुद्रपार संचार

पञ्चवर्षीय विकास योजना के अन्तर्गत समुद्रपार संचार सेवा के लिये नयी योजनायें आरम्भ की जा रही हैं। कलकत्ता में प्रसारण चौंसू संप्रसारण केन्द्रों की स्थापना के लिये जमीन प्राप्त कर ली गई है और निर्माण कार्य शुरू हो गया है। ब्रिटेन और लन्दन से मिले हुए अन्य देशों को जानेवाले प्रत्येक विदेशी तारों के प्रवेग के लिये कलकत्ता में एक नमूने का केन्द्र मार्च १९५३ में खोला गया। जब यह केन्द्र पूर्णतया विकसित हो जायगा, तो यह अमेरिका के लिये एक सीधी टेलीफोन सेवा और पूर्व तथा सुदूरपूर्व के देशों के लिये सीधी तार और टेलीफोन सेवाओं की व्यवस्था कर सकेगा।

कलकत्ता और लन्दन के बीच एक सीधी ब्रेतार के तार की सेवा १९ मार्च, १९५३ को और भारत तथा पूर्वी अफ्रीका (नैरोबी) के बीच एक सीधी रेडियो टेलीफोन सेवा १८ अगस्त, १९५३ को स्थापित हुई। भारत और हांगकांग तथा भारत और स्विट्जरलैंड के बीच एक-एक सीधी रेडियो टेलीफोन सेवा क्रमशः २३ दिसम्बर, १९५३ और १ मार्च, १९५४ को आरम्भ हुई।

इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड

पञ्चवर्षीय योजना में इस कारखाने के लिए उत्पादन का लक्ष्य इस प्रकार निर्दिष्ट किया गया था—टेलीफोन-२५,०००, एक्सचेंज लाइनें—२०,०००। यह लक्ष्य पूरा हो चुका है। योजना-काल के लिये नये लक्ष्य इस प्रकार हैं:— टेलीफोन—६०,०००, एक्सचेंज लाइनें—४०,०००। जोशर पूंजी को २.५ करोड़ रुपये से बढ़ाकर ४ करोड़ रुपये कर देने का विचार है।

यह कारखाना कम्पेसर्स को छोड़कर टेलीफोन यन्त्र के शेष सब भाग सैयार करता है। जाता है, कम्पेसर्स भी शीघ्र ही तैयार होने लगेंगे। कारखाने

में स्वचालित एक्सचेंज सामग्री और प्रसारण सामग्री भी तैयार होती है। एक मार्ग वाले टेलीफोन का सामान तो अब भी तैयार होता है, १९५४-५५ में तीन मार्ग वाले टेलीफोन का सामान भी बनने लगेगा।

बेतार के तार के आयोजन और एकीकरण का संगठन

मह संगठन बेतार के तार के संचालन के आयोजन और एकीकरण के लिये १९५२ में स्थापित हुआ था। १९५३ में उन योजनाओं के अनुसार, जो १९५१ में जेनेवा में असाधारण प्रशासनिक रेडियो सम्मेलन में स्वीकृत हुई थीं, नाविक और वैज्ञानिक गति-सीधता में पर्याप्त वृद्धि हुई। भारत में बेतार के तार के ऐसे संचालन-कार्य, जिनसे भूमध्यसागर और दक्षिण-पूर्वी एशिया के प्रदेशों में वैज्ञानिक सेवाओं के लिए एकाग्रता पैदा हो सकती थी, व्यवहार में लिये और इस प्रकार उन प्रदेशों की गति-सीधता की योजनाओं की पूर्ति में सहायता की गई। वायरलेस आपरेटरों ■ लिए ३ परीक्षाओं की व्यवस्था की गई। संगठन की अवीनता में मानीटरिंग (monitoring) सम्बन्धी कुछ सुविधायें भी उपस्थित की गई हैं और उन बहुत सी टेक्निकल जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिये, जो अन्तर्राष्ट्रीय तार टेलीफोन संचार सम्झौता तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय करारों पर हस्ताक्षर करने के कारण भारत पर आ पड़ी है, देश-व्यापक में बहुत से मानीटरिंग केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं।

डाकखाने

अक्टूबर १९५४ में पहली भारतीय डाक टिकट की जारी हुए पर १०० वर्ष हो जायेंगे। इस अवसर पर एक अन्तर्राष्ट्रीय टिकट-संग्रह और डाक प्रदर्शनी होगी तथा कुछ विशेष प्रकार की टिकटें और उन भारतीय डाक टिकटों की जन्म रंगों की प्रतिकृतियों का एक स्मारक अवलोकन जारी किया जायगा, जो विगत १०० वर्षों में इस्तेमाल होती रही है। भारतीय डाकखानों और डाक टिकटों का इतिहास भी प्रकाशित किया जायगा। इस ज्ञानार्थी-समारोह में कई विदेशी डाक-प्रशासन भाग लेंगे।

२,००० या २,००० से अधिक आबादी वाले गांवों में डाकखाने स्थापित करने का कार्यक्रम ३१ मार्च, १९५३ तक पूरा हो गया। १ अप्रैल, १९५३ से गांवों में डाकखाने स्थापित करने की एक नई नीति पर अमल हो रहा है।

सामाजिक

इसके अनुसार ऐसे ग्राम-समूहों में डाकखाना स्थापित किया जाता है, जिसकी आबादी २,००० या २,००० से अधिक होती है। इसमें इस बात का भी ध्यान रखा जा सकता है कि डाकखाना किसी गांव से कितनी दूर है। १ अप्रैल, १९५३ से दिसम्बर, १९५३ तक १,३७२ नये डाकखाने स्थापित किये गये।

इस वर्ष तीन बार स्मारक-टिकटें जारी की गईं : (१) रेलवे-शताब्दी के अवसर पर (२) २९ मई, १९५३ को एक्स्प्रेट-विजय के उपलक्ष्य में और (३) नवम्बर, १९५३ में भारतीय तार शताब्दी के अवसर पर।

तार

दिसम्बर, १९५३ तक १५० संयुक्त तारघर खोले गये, जिससे भारत में तारघरों की कुल संख्या ८,६२० हो गई। जिले के समस्त मुख्य नगरों में तार-सुविधायें प्रदान की जायेंगी।

विभिन्न नगरों के बीच अधिक सीधा सम्पर्क हो जाने के कारण, अधिक व्यस्त शाखाओं पर भी. एक. टी. लग जाने के कारण, सभी मुख्य सर्किटों पर टेलीप्रिन्टर लग जाने के कारण तथा टेलीप्रिन्टरों की सफाई का कार्यक्रम जारी हो जाने के कारण तार-सेवा की कुशलता बहुत बढ़ गई।

आशा की जाती है कि कीर्ति-प्रणाली से तार भेजने में देरी न हुआ करेगी। इस प्रणाली के लिये सामान मंगा लिया गया है और बम्बई के केन्द्रीय तारघर में लगा दिया गया है। नई दिल्ली, कलकत्ता तथा अन्य मुख्य नगरों में भी इस एकाति को जारी करने पर विचार हो रहा है।

हिन्दी लिपि में भारतीय भाषा-तार-सेवा और भी कई जगह जारी की गई और अब ५२५ तारघरों में उपलब्ध है। बीड़ी दूरी वाले टुक टेलीफोन सर्किटों में इस सेवा को 'फोनोकम' द्वारा और भी स्थानों में जारी करने की व्यवस्था की जा रही है। भारतीय भाषाओं में इस वर्ष १८,६३६ तार भेजे गये, जबकि गत वर्ष कुल ७,८०१ ही भेजे गये थे। विभाग ने जो हिन्दी टेली-प्रिन्टर तैयार किया था, वह सफल सिद्ध हुआ है, परन्तु उसकी गति संयोजी के टेलीप्रिन्टर की अपेक्षा कम है।

टेलीफोन

जनवरी से दिसम्बर, १९५३ तक ४८ नये टेलीफोन-एक्सचेंज खोले गये और ४९ एक्सचेंज जम्मू और काश्मीर राज्य में १६ दिसम्बर, १९५३ को अवि-कार में लिये गये। २१ हजार से भी अधिक नये टेलीफोन लगाये गये। ३१ दिसम्बर, १९५३ को टेलीफोनों की कुल संख्या २,१८,००० से अधिक थी। १९५३ में ४१६ सार्वजनिक 'काल आफिस' खोले गये, जिससे ३१ दिसम्बर, १९५३ को उनकी संख्या कुल ३,२५८ हो गई। यह निश्चय किया गया है कि समस्त जिला-नगरों में टूंक-टेलीफोन की व्यवस्था की जाय।

१९५३-५४ में लगभग १२० लाख टूंक-काल हुए, जबकि अविभाजित भारत में १९३८-३९ में केवल २२,५०,००० ही टूंक-काल हुए थे। पिछले वर्ष, बड़े हुए काम को देखते हुए १४ अतिरिक्त टूंक लाइनें, १४ सिग्नल-बैन्सल कैरियर, १३ यूरोबैन्सल कैरियर और २ टर्बो-बैन्सल कैरियर विभिन्न भागों पर लगाये गये।

कलकत्ता में केंद्रीय, जोड़ारा की और एवेन्यू के स्वचालित एक्सचेंजों के स्थापित होने से भारत में पहली सीधी एक्सचेंज प्रणाली प्रारम्भ हुई। कलकत्ता में और भी एक्सचेंज योजनानुसार बन रहे हैं।

१६ नवम्बर, १९५३ को भारत सरकार ने राष्ट्रीय टेलीफोन-संचार-विकास और गवेषणा-परामर्श-समिति नाम की एक समिति बनाई, जिसमें उच्च-कोटि के वैज्ञानिक रखे गये।

डाक की वरें

१९४८-४९ से डाक विभाग में अधिक घाटा होते रहने के कारण भर्षेज और नई, १९५३ में डाक की कुछ वरें बढ़ाने पड़ीं। इस वृद्धि से १९५३-५४ के अनुमानित घाटे में काफी कमी हुई। फिर भी यह समझा जा रहा है कि गांवों में डाक-सुविधायें बढ़ाने के कार्यक्रम तथा अन्य प्रलाभजनक कार्यों के प्रारम्भ के कारण घाटा फिर बढ़ जायगा।

परिवहन

बन्दरगाह

कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और कोचीन के बड़े बन्दरगाहों को सुधारने के लिए कई योजनाएँ बनाई गई हैं और निर्माण-कार्य पर लगभग ३६२.२० लाख रुपया व्यय भी हो चुका है। इस व्यय की पूर्ति के लिये केन्द्रीय सरकार ने १६५ लाख रुपया कर्ज दिया है। कांबसा में बन्दरगाह का निर्माण सितम्बर, १९५३ में आरम्भ हुआ था। इस पर अनुमानतः ६.६५ करोड़ रुपया व्यय होगा।

बम्बई बन्दरगाह पर नये मैरीन ड्राइल टर्मिनस का निर्माण हो रहा है। इस पर लगभग ७ करोड़ रुपया व्यय होगा। इस योजना के लिए सरकार ने ३ करोड़ रुपया कर्ज दिया है।

देश के सात-सात छोटे बन्दरगाहों को सुधारने का कार्यक्रम भी बना दिया गया है और उसके अनुसार कई तटवर्ती राज्यों में काम हो रहा है। इन राज्यों को २२.६३ लाख रुपये की सहायता दी जा चुकी है, वंचनवीथ योजना की शर्तों में केन्द्र की ओर से इन्हें कुल ५० लाख रुपये की सहायता दी जायेगी।

अन्तर्राष्ट्रीय जल-परिवहन

भारत में ५,५०० मील से भी अधिक लम्बा जल-मार्ग नौकानयन के योग्य है। मुख्य जलमार्ग इस प्रकार हैं—गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियाँ, गोदावरी, कृष्णा, और तिरुवाङ्कुर-कोचीन के सामुद्रिक जलमार्ग और नहरें। मद्रास और आन्ध्र राज्यों में बर्फ़ीले नहर और पश्चिमी समुद्र तट की नहरें और उड़ीसा में महानदी की नहरें भी उत्तम जलमार्ग हैं। कई बहुदलीय नदी घाटी योजनाओं में नौकानयन योग्य जलमार्गों की भी योजनाएँ शामिल हैं। राज्य-सरकारों में प्रभावपूर्ण सामंजस्य के लिये अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता है। गंगा-ब्रह्मपुत्र-जल-परिवहन-बोर्ड ने इस विषय में कार्य भी आरम्भ कर दिया है।

सड़क-परिवहन

पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित करने से उत्पन्न होने वाली परिवहन सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयोजन के कुछ पहलुओं पर सलाह देने के लिये योजना कमिशन, परिवहन, रेलवे, उत्पादन, व्यापार और उद्योग, खाद्य और कृषि तथा श्रम मन्त्रालयों के प्रतिनिधियों का एक गवेषणा-बस बनाया गया है।

दिल्ली-परिवहन-सेवा (डी० टी० एस०)

दिल्ली-सड़क-परिवहन-प्राधिकार-आव-समिति की सिफारिशों के अनुसार कार्य करने से बस-सेवा में काफी सुधार हुआ है। वन पुरानी बसें रद्दी करार दे दी गईं, ६४ नई बसें जालू की गईं, और मार्च, १९५४ तक ७० बसें और जालू हो जायेंगी। इस प्रकार बसों की कुल संख्या ३१६ हो जायगी। बस-यात्रियों के लिये ४१ सुरक्षा-स्थान बनाने की स्वीकृति मिल गई है और २ बिघों और एक केंद्रीय कारखाना शीघ्र ही बनकर तैयार होने वाले हैं; इन पर लगभग २० लाख रु० खर्च होगा। ७० नई डीजल बसें खरीदने और कारखाना तथा बिघों बनाने के लिए प्राधिकार की ४५ लाख रुपये की राशि ब्याज दिया गया है। १९५४ में प्राधिकार की लगभग २.६७ लाख रुपये का लाभ होगा, जबकि पिछले साल ३.६६ लाख रुपये का लाभ हुआ था।

जहाजरानी

इस साल पुराने जहाजों की कीमतें गिरने लगीं और भारतीय जहाजी कंपनियों ने बाहर से पुराने जहाज खरीद कर अपने जहाजों की संख्या बढ़ा ली। १९५३ के अन्त में कुल भारतीय जहाजों का टन भार ४,३३,००० जी० ग्राम० टी० था। परन्तु जहाजों की संख्या उतनी नहीं बढ़ी, जितनी कि योजना कमिशन के कार्यक्रम में बनाई गई थी। इसलिये सरकार ने भारतीय जहाजों के कंपनियों के लिये कर्ष की शर्तों को अधिक उदार बनाना स्वीकार कर लिया है।

देश का समस्त तटीय व्यापार उन जहाजों द्वारा हुआ जो भारतीय कंपनियों के अपने थे या किराये पर लिये गये थे। साल में २५ लाख टन सात सट पर एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाया गया, जिसमें कीचला १२ लाख

आन्तरिक

सन और नमक ६ लाख टन था। तटीय जहाजों के लरीजने ■ लिये कर्ज देने के बास्ते इस वर्ष के बजट में एक करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

भारतीय जहाजी कंपनियों को १९५२-५३ में समुद्र पार के व्यापार में ८.२५ करोड़ रुपया भाड़ा प्राप्त हुआ, जबकि पिछले वर्ष ७.६२ करोड़ रुपया ही प्राप्त हुआ था।

इस वर्ष, समुद्रपार व्यापार के लिये जहाज लरीजने के बास्ते २॥ प्रति-शत व्याज पर कर्ज देने के हेतु भी २ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड में ४,००० डी० बक्यू० टी० के दो जहाज तैयार हुए और ५ तैयार हो रहे हैं।

इंस्टीट्यूट ऑफ़ शिपिंग कारपोरेशन विशाखापत्तनम् शिपयार्ड में घाट-घाट हजार टन के दो जहाज बना रहा है।

भारतीय व्यापारिक बेड़े के लिए नाविकों के प्रशिक्षण में काफी प्रगति हुई। लगभग एक हजार लड़के नाविक-प्रशिक्षण-जहाजों-‘भद्रा’ और ‘मेकला’ से पास होकर निकले। ये जहाज क्रमशः कलकत्ता और विशाखापत्तनम् में कड़े हैं। इन सब लड़कों को अब काम मिल गया है।

भारत में पहला रवार-प्रशिक्षण-केन्द्र नाविक और इंजीनियरिंग कालेज के तत्वाधान में अक्टूबर, १९५३ में खुला।

नाविक इंजीनियरिंग के प्रशिक्षण की नई योजना के अनुसार १९४६ में ४६ मौसिलुओं का जो पहला बल भर्ती किया गया था, वह १९५३ में नाविक इंजीनियरिंग कालेज से प्रशिक्षण प्राप्त करके निकला। २८ और शिक्षार्थियों ने ‘इंफरिन’ से ‘क’ भाग पास किया। इस प्रकार इस वर्ष सरकार द्वारा प्रशिक्षित कुल लड़कों की संख्या ७४ हो गई।

प्रकाश-स्तम्भ विकास

प्रकाशस्तम्भ-विभाग ग्रन्थ परिवहन-मंत्रालय के अधीन एक स्वतन्त्र एकक के रूप में कार्य कर रहा है। यह जहाजरानी के प्रधान निदेशक के कार्यालय से १ जुलाई, १९५३ को पृथक् हुआ था। प्रकाशस्तम्भों के विकास-कम्य और नाविक उपकरणों के सुधार-कम्य की पूर्ति के लिये जून, १९५३ में जहाजों पर प्रकाश-शुल्क बढ़ा दिया गया।

बेनगुरी रावत साइटहाउस और माइस्टर लाइट हाउस के लिये दो मोटरबोटें बनाई गई हैं। पैरोडन, डेलिफ़्लैन्स नीज़, कोलार्डिकोर्ट और भद्रकल में नये स्तम्भ और कर्मचारियों के लिये मकान बनाये जा रहे हैं।

भारत के समुद्रतट पर प्रकाश की देखभाल करने के लिये विभाग ने ५०,००० पौंड का एक पुराना जहाज खरीदा है।

कांडला बन्दरगाह में नौका-मार्ग के निर्माण और प्रकाशन के लिये जो योजना बनाई गई थी, उसमें काफी प्रगति हो चुकी है।

पर्यटकों का आगमन

१९५३ में विदेशों से पर्यटन के लिये आने वाले यात्रियों की संख्या २८,०६० थी। इनमें ६,२०६ अमेरिकी थे। श्रीनगर और बनारस में नये यात्री-सूचना बपतर जोले गये हैं और जब भारत में ऐसे बपतरों की संख्या सात हो गई है। एक बपतर भारत के बाहर भी है। सीमा-संबन्धी नियम, विश और सीमा-शुल्क सम्बन्धी नियम अधिक सरल बना दिये गये हैं। पर्यटकों की सुविधा के लिये बहुत-सी प्रकाशन-सामग्री तैयार की गई और विदेशों तथा भारत में वितरित की गई है। इस सामग्री में पुस्तक-पुस्तिकाएं, पोस्टर, पोस्टर, कलेंडर, चित्र-कार्ड, भांडेल और फिल्म हैं।

सड़क-विकास

दिसम्बर, १९५३ तक राष्ट्रीय राजमार्गों का २६३ मील सम्बा हिस्सा

और १६ मछे पुल बन कर तैयार हुए । वर्तमान राजमार्गों का १,५०० मील लम्बा हिस्सा सुधारा गया ।

'ग' भाग के राज्यों में तथा उत्तर-पूर्वी सीमा एजेन्सी में १,११३ मील लम्बी सड़क बनाई गई और ४०३ मील लम्बी वर्तमान सड़क सुधारी गई । इसमें आसाम को विपुरा से मिलाने वाली १३४ मील लम्बी नई अग्रतला-आसाम सीमा-सड़क भी है ।

रेलें

विकास-कार्य

भुवनेश्वर-राजद्वारा, कंडीगढ़ का वैकल्पिक मार्ग, राजकोट बाहर राजकोट अंतर्धान, पिछ्छि-नडियाव और सांगामेर बाहर-तोड़ा रायसिंह विस्तार का एक भाग पूरा हो गया है और वास्तव्यता के लिये खूब गया है ।

नीचे लिखे रेल-मार्ग, जो लोड़ दिये गये थे, १९५३-५४ में फिर बना दिये गये :— बाधिली-साजूर, शोरामूर-भीलानगर, बसाव-कथाना, बालामऊ-बाधोगंज, सतुरा-जसोलमपट्टी, नगरीडा-जोगेन्द्र नगर और भागलपुर-संगार पहाड़ी हाकायें ।

पुनर्स्थापन की गति बढ़ाने के लिये बहुत से इंजन बाहर से मंगाये जा रहे हैं । परन्तु सरकार की नीति यह है कि यथासंभव देशी साधनों का ही उपयोग किया जाय । आगामी बार वर्षों में, विस्तारजन रेल-इंजन कारखाने का वार्षिक उत्पादन-संख्या १२० से बढ़ाकर १५० और उत्पादनात् २०० मीसत इन्जनों के इंजनों का कर दिया जायगा । इसी प्रकार ठाटा लोकोमोटिव एंड इंजीनियरिंग कम्पनी भी १९५४-५५ में अपने ५० इंजन प्रतिवर्ष के उत्पादन-संख्या को प्राप्त कर लेगी, ऐसी आशा है । यह कम्पनी अब तक कुल ५० इंजन तैयार कर चुकी है ।

यात्री-गाड़ी के डिब्बे बाहर से न भेगाने की नीति पर अमल हो रहा है और हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड तथा रेल-कारखानों की क्षमता बढ़ा दी गई है ।

संचालन

१९५५-५४ में रेलों के समय-पालन में और भी सुधार हुआ । सब रेलों के साधारण प्रयाग कुम्भ मेले के प्रबन्ध के लिये एकीकृत किये गये । मेले को जाने के लिये ३७४ और ले जाने के लिये ३४४ स्वेचल गाड़ियां छोड़ी गईं । इसके अलावा मेला-क्षेत्र में ५१० शाटल गाड़ियां चलाई गईं । रेलवे-कुशलता-विभाग ने लगभग सभी रेलों की संचालन और संगठन सम्बन्धी समस्याओं पर विस्तृत अनुसन्धान किया है । माल के स्थानान्तरण की बढ़ी हुई मात्रा को पूरा करने के लिये परिवहन क्षमता बढ़ाने के उपाय किये गये जिनमें विस्कों और इंजनों की संख्या, मार्ग और गोदाम की क्षमता तथा माल के बढ़ाने-उतारने की सुविधाओं में वृद्धि शामिल है ।

यात्रियों के लिये सुविधा

छोटे स्टेशनों पर यात्री-सुविधाओं में अच्छे प्लेटफार्मों, प्रतीक्षालय, प्रकाश पुल सर्कि की व्यवस्था शामिल है । प्रथम श्रेणी के समाप्त हो जाने से निम्न श्रेणी के लिये स्थान बढ़ाना संभव हो गया है । तीसरे दर्जे के जो नये डिब्बे बने हैं, उनमें चौड़ी सीटें हैं, पंखे हैं, प्रकाश है और अच्छे शौचालय हैं । सवारी गाड़ियों में भीड़भाड़ कम करने का भी प्रयत्न किया गया । अक्टूबर से नवम्बर, १९५३ तक १६० नई गाड़ियां चालू की गईं और १२६ गाड़ियों के मार्ग बढ़ाये गये । १९४९-५० की तुलना में सवारी गाड़ी की मील-संख्या बढ़ी लाइन पर २० प्रतिशत और छोटी लाइन पर ३० प्रतिशत बढ़ी ।

यात्री-सुख-सुविधा व्यवस्था सम्बन्धी कार्य के समीकरण के लिये सब रेलों पर अफसर नियुक्त किये जायेंगे । ये अफसर प्रत्येक रेल के विभिन्न विभागों के मुख्य सामंजस्य स्थापित करेंगे जिससे कि काम में शीघ्रता की जा सके । वे वर्तमान परिस्थितियों का पता लगाने के लिये रेलों के विभिन्न खंडों का निरीक्षण करेंगे और जहाँ भी कोई जरूरी पाई जायेगी, वहाँ वे उचित कार्यवाही करेंगे ।

आन्तरिक

हिन्दी परामर्शदाता के काम के लिये रेलवे-बोर्ड के धफतर में एक हिन्दी विभाग खोला गया है और रेल-विभाग में प्रयुक्त होने वाले शब्दों के निश्चित हिन्दी पर्याय तैयार किये गये हैं। यह भी निश्चय हुआ है कि रेलवे का ग्रन्थिल भारतीय टाइमडेविल हिन्दी में प्रकाशित किया जाय। रेल-कर्मचारियों की भर्तों को आसान बनाने की दृष्टि से दो और रेलवे सेवा कमीशन बनाये गये हैं—एक हलाहवाब में और दूसरा मद्रास में।

रेलवे भ्रष्टाचार का नाश के लिय आचार्य कृपलानी की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की गई है।

यद्यपि किराया-भाड़ा घटाना सम्भव नहीं हो सका, फिर भी कई प्रकार की रियायतें दी गई हैं। इनमें ये रियायतें शामिल हैं:— १,५०० मील से अधिक दूरी के लिये तीन-चौपाई किराये पर सर्कुलर टिकटें, विद्यार्थियों के लिये ४५ मिल की राउंड टिकटें, गैर-समर्पन क्षेत्रों में विद्यार्थियों के लिये मासिक टिकटें, एक और के ब्योड़े किराये पर पहाड़ी स्थानों ■ लिये वापसी टिकटें आदि।

रेलवे कर्मचारी

रेल-कर्मचारियों के हितों का भी ध्यान रखा गया है। कुछ क्वार्टरों में आराम की चीजें बढ़ाई जा रही हैं और १९५४-५५ के अन्त तक १८,४६९ नये क्वार्टर बनकर तैयार होने वाले ह। लरेविक के रोगियों के लिये, हर सण्डल में, उपयुक्त स्वास्थ्यवर्धक स्थानों में हमारतें बनाने का निश्चय किया गया है।

इस वर्ष, अमिकों और प्रमथकों के सम्मथ अच्छे रहे। दोनों रेल फेडरेशन मिलकर एक नया संगठन बन गया है जिसका नाम नेशनल फेडरेशन ऑफ इण्डियन रेलवेमैन है।

पंचवर्षीय योजना

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत रेलों के लिये ४०० करोड़ रुपये की राशि निश्चित की गई है। १३१०४ करोड़ रुपये पहले की वर्षों में लार्च हो गये हैं

सातवीं वर्ष

और ७७.८८ करोड़ रुपये जालू वर्ष में खर्च किये जायेंगे। योजना के क्षेत्र वर्षों में कारखानों पर व्यय बढ़ाने के लिये तथा इंजन और डिब्बे प्राप्त करने के लिये प्रयत्न किया जा चुका है।

समूहीकरण

पुनः समूहीकृत रेलों का संचालन से यू-सर्जिस में सुविधा हो गई है। उपयुक्त स्थानों पर इंजन एकीकृत किये जाने लगे हैं, छोटे-छोटे ब्रेक बन्द किये जा रहे हैं और इंजनों तथा डिब्बों का अधिक प्रख्या उपयोग होने लगा है।

प्रायोगिक प्रशिक्षण

सवारी गाड़ी के डिब्बे बनाने के प्रशिक्षण के लिये वेराम्पूर में एक टेक्निकल स्कूल खोल दिया गया है। इस स्कूल में ३०० प्रशिक्षार्थी एक साथ प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

संयुक्त राष्ट्र संघीय महासभा के १५ सितम्बर, १९५३ को प्रारम्भ ■
आठवें अधिवेशन के अवसर पर भारतीय प्रतिनिधि मंडल की नेता श्रीमती
विजयलक्ष्मी महासभा की अध्यक्ष चुनी गई।

अधिवेशन-काल में कोरियाई प्रश्न यद्यपि धुल्लभूमि में रहा, पर हमारे
संरक्षक बल की सराहना संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अन्यत्र अनेक स्थानों में की
गई। दक्षिण अफ्रीका संघ में भारतीय उद्भव के लोगों के प्रति होने वाले
व्यवहार की ओर एतदर्थ राजनीतिक समिति का ध्यान गया। समिति द्वारा
स्वीकृत एक प्रस्ताव में महासभा के अगले अधिवेशन के सम्मुख रखे जाने के
हेतु प्रस्तावों की रचना के लिए स्थापित सद्भावना-समिति की जारी रखने की
स्यवस्था रखी गयी।

टोपोलंड के दूस्ड-प्रवेशों के सम्बन्ध में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने इस
बात की आवश्यकता पर जोर दिया कि इन प्रवेशों के अस्तित्व में कोई भी
परिवर्तन करने के पूर्व इनके निवासियों की इच्छाओं का पता लगा लिया जाना
चाहिये। निश्चास्त्रीकरण तथा अणुबम के उपयोग पर रोक लगाने से सम्बन्धित
प्रश्न पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्थापित आयोग ने बहुत धोड़ी प्रगति की।
इस मामले में सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों का सहयोग आवश्यक था,
इसलिये भारतीय दल ने आयोग की एक ऐसी उपसमिति बनाने तथा उसकी
निजी बैठक बुलाने का सुझाव दिया जिसमें तत्सम्बन्धी राष्ट्र हों। इन सुझावों
को महासभा द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव में स्थापित किया गया।

भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने अर्द्ध-विकसित क्षेत्रों के आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने से सम्बन्धित प्रस्तावों का भी ध्यान से समर्थन किया। मंडल ने यह स्पष्ट रूप से जता दिया कि भारत किसी भी प्रकार की बेगार को स्वीकार नहीं कर सकता।

भारत अर्थ-समाज परिषद का सदस्य बना रहा और महासभा द्वारा इसे तीन वर्षों के लिये ट्रस्टीशिप परिषद का भी सदस्य चुन लिया गया। यूनेस्को के विगत सम्मेलन में यूनेस्को द्वारा स्वीकृत एक प्रस्ताव जनवरी, १९५३ में दिल्ली में गान्धीबाबू विचारधारा और पद्धति सम्बन्धी गोष्ठी के प्रतिवेदन के आधार पर तैयार हुआ।

भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने आद्य एवं कृषि संगठन में भी एक प्रस्ताव रखा जिसमें आरम्भिककाल में अकाल सम्बन्धी सहायता की व्यवस्था रखी गयी। पक्षि बध्तिवाले देशों की आवश्यक विलस देने की अभिप्रेक्षा के कारण इस योजना को स्वीकार नहीं किया गया, पर यह सिद्धांत तो मान ही लिया गया कि आद्य एवं कृषि संगठन अन्तर्राष्ट्रीय सहायता के संगठन को दृष्टि से अन्य सदस्य-राष्ट्रों का साथ देगा।

भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र संघ के निम्नलिखित संगठनों के कार्यों में भाग लेती आ रही है : विश्व स्वास्थ्य संगठन, अन्तर्राष्ट्रीय भ्रम संगठन, अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक उद्बोधन संगठन, अन्तर्राष्ट्रीय टेली-संचार संगठन, विश्व डाक यूनियन, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और पुनर्निर्माण तथा विकास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय बैंक। १९५३ में भारत अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक उद्बोधन संगठन की परिषद और आद्य एवं कृषि संगठन का फिर से सदस्य निर्वाचित हुआ और इसे यूनेस्को, मानव अधिकार कमीशन, समाज-कमीशन, आंकड़ा-संकलन सम्बन्धी कमीशन, मार्कोटिक औषधियाँ कमीशन, परिवहन और संचार कमीशन, तथा विलस कमीशन में भी प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ।

कोलम्बो योजना

भारत को अधिक विकसित देशों जैसे कनाडा, स्विट्जरलैंड, आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड से आर्थिक तथा टेक्निकल सहायता प्राप्त हुई तथा दक्षिण एशिया

के अन्य सदस्य-राष्ट्रों को भारत ने सहायता दी। इस सहायता का एक अंग है भारत में टेकनिकल प्रशिक्षण के लिए छात्रवृत्तियाँ देना।

विदेशों से सहायता

भारत को टेकनिकल सहयोग प्रदान करने सम्बन्धी करार के अन्तर्गत अमेरिका से आर्थिक और टेकनिकल सहायता मिल रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ, भारत सरकार तथा नाटो के बीच हुए एक त्रिपक्षीय सम्झौते के अन्तर्गत भारत को नाटो भी आर्थिक और टेकनिकल सहायता मिली है।

भारत के पड़ोसी राष्ट्र

नव वर्षी भूमि राष्ट्रीयकरण विधेयक पर विचार-विमर्श के लिये एक भारतीय दल दिसम्बर, १९५३ में रंगून गया और वहाँ के अधिकारियों ने भारत सरकार के वृष्टिकोण पर विचार करने का वचन दिया है। मार्च और अप्रैल, १९५३ में भारत और बर्मा के प्रधान मंत्रियों ने भारत-बर्मा सीमा के दोनों ओर के जनजातीय क्षेत्रों का संयुक्त रूप से भ्रमण किया। बर्मा प्रवेश में चीनी राष्ट्रवादी सेना की कार्रवाइयों के सम्बन्ध में भारत सरकार ने बर्मा द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ से की गयी शिकायत का भी समर्थन किया।

भारत और लंका के प्रधान मंत्रियों ने जनवरी १९५४ में नई दिल्ली में भेंट की और लंका में भारतीयों के प्रवेश की समस्या के सम्बन्ध में एक सम्झौता हुआ।

नेपाल ■ साथ हमारे सम्बन्ध मजबूत रहे तथा भारत ने नेपाल को वित्तीय और टेकनिकल सहायता दी। एक उच्च भारतीय अधिकारी नेपाल में टेकनिकल मिशन का डायरेक्टर नियुक्त किया गया। भारत में गोरखाओं की अर्थात् करने वाले ब्रिटिश कार्यालय इस वर्ष बन्द हो गये।

भारत-पाकिस्तान के सम्बन्धों के विषय में सभी अंगों के निपटारे के साथ दोनों के एक समान हितों के लिये सहयोग की भावना पैदा करने के प्रयत्न किए गए। जुलाई और अगस्त, १९५३ में हुए सम्मेलनों के फलस्वरूप विभिन्न समस्याओं के सम्बन्ध में समझौते हुए। बल सम्पत्ति सम्बन्धी समझौतों की

सम्बुद्धि दोनों सरकारों ने की और जनवरी, १९५४ में उनको कार्यान्वित करने के आदेश जारी किये गये। दोनों देशों के बीच सहत्वपूर्ण प्रश्नों के निपटारे की दृष्टि से दोनों देशों की सरकारों ने अपने-अपने मंत्रालयों को इस सम्बन्ध में बातचीत करने के निर्देश दिये। दोनों देशों के प्रधान मंत्रियों को इन बातचीतों की प्रगति से अवगत रखने के लिये दोनों सरकारों में एक अधिकारी-समिति स्थापित की।

पूर्वी क्षेत्र से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं पर विचार-विमर्श के लिये ३० सितम्बर, १९५३ से २ अक्टूबर, १९५५ तक कलकत्ता में एक भारत-पाकिस्तान सम्मेलन हुआ। इस अवसर पर कुछ बिहार और पूर्वी बंगाल की जिल्लियों के विनिमय, सीमा निर्धारित करने तथा पूर्वी क्षेत्र के सीमा सम्बन्धी झगड़ों के निपटारे, आने जाने की स्वतंत्रता, सीमाओं पर होने वाले व्यापार तथा अग्रेज, १९५० में हुए प्रधान मंत्रियों के समझौते के फलस्वरूप उत्पन्न सहत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार विमर्श हुआ। अगस्त, १९५३ में नई दिल्ली में अपनी बातों समाप्त करने पर भारत तथा पाकिस्तान के प्रधान मंत्रियों ने एक संयुक्त विज्ञप्ति में यह बड़ा विचार व्यक्त किया कि काश्मीर का प्रश्न वहाँ के निवासियों की इच्छानुसार हल किया जायेगा।

अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को सैनिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में हुई बातचीत से एक नयी स्थिति पैदा हुई, जिसका प्रभाव काश्मीर के प्रश्न पर तो पड़ा ही, पर साथ ही साथ दोनों देशों के बीच के अन्य प्रश्नों पर भी पड़ा। बातचीत का परिणाम यह हुआ कि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच एक सैनिक-सहायता का समझौता हो गया जिसके कारण भारत-पाकिस्तान-सम्बन्धों में जटिलता आ गई।

भारत सरकार ने एक अधिकारी सिक्किम राज्य को दिया जो वहाँ योजना अधिकारी के रूप में काम करेगा। इसके प्रतिरिक्त अन्य प्रश्नों पर सलाह देने के लिए सिक्किम राज्य को समय-समय पर और भी अधिकारी दिये गये।

भारत में विदेशी उपनिवेश

फ्रांसीसी सरकार ने भारत का इस आशय का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया कि जनमत लिये बिना ही पांडिचेरी, कारीकल, माही और यनाम के भारत को हस्तांतरित किये जाने के सम्बन्ध में बातचीत आरम्भ की जाए। उनका कहना यह है कि फ्रांसीसी संविधान इस बात की अनुमति नहीं देता।

भारत स्थित पुर्तगाली बस्तियों के सम्बन्ध में पुर्तगाली सरकार द्वारा भारत सरकार के प्रस्तावों पर विचार विमर्श करना अस्वीकार किये जाने के परिणामस्वरूप विस्मय स्थित हमारा राजबूताबाद ११ जून, १९५३ को ज्ञात कर दिया गया।

दक्षिण-पूर्व एशिया

भारत और इण्डोनेशिया के बीच मित्रता की एक संधि १७ जून, १९५३ को संयुक्तराष्ट्र संघ के सचिवालय में पंजीकृत की गयी।

मलयाल हिन्दू कौन तथा इण्डियन इन्डिपेंडेंस लीग की सम्पत्ति, जो मलय के वायु-सम्पत्ति-संरक्षक के अधिकार में है, दो तथा एक के अनुपात में भारत और पाकिस्तान के बीच बाँट दी जाएगी। मलय की सरकार ने मलय में भारतीय मजदूरों को बसाने के लिये दो योजनाएँ तैयार की हैं।

मध्यपूर्व

मध्यपूर्वी देशों तथा भारत के बीच प्रतिनिधि मंडलों के विनिमय से इन देशों के साथ भारत के सम्बन्ध बृद्ध हो गये। साथ ही निम्नलिखित संधियाँ और समझौते भी हुए :

१. भारत और इराक के बीच मित्रता की संधि सम्बन्धी स्वीकृति-पत्रों का विनिमय २८ अप्रैल, १९५३ को हुआ और ६ मार्च, १९५३ की व्यापार सम्बन्धी समझौते पर हस्ताक्षर हुए।

सातवीं वर्ष

२. भारत तथा तुर्की के बीच एक व्यापार सम्बन्धी समझौते पर नवी दिल्ली में ४ जून, १९५३ को हस्ताक्षर हुए ।

३. भारत तथा मिस्र के बीच व्यापार तथा भुगतान सम्बन्धी एक समझौते पर काहिरा में २ जुलाई, १९५३ को हस्ताक्षर हुए ।

सूडान को स्वायत्त बनने तथा उसके आत्मनिर्णय से सम्बन्धित आंग्ल-मिस्री समझौते में १७ सदस्यों के मिले जुले चुनाव कमीशन की स्थापना की व्यवस्था की गयी जिसका अध्यक्ष एक भारतीय हो । ब्रिटिश और मिस्री सरकारों ■ समुदाय पर सूडान में नये चुनावों की व्यवस्था करने के लिये मुख्य चुनाव आयुक्त भी सुकुमार सेन की सेवाएं उधार दी गईं । भारत सरकार ने भारतीयों तथा भारत के व्यापारिक हितों की देखभाल करने के लिए जारजूम में एक सचिव-अधिकाधी नियुक्त करने का निर्णय किया है ।

सुरूपूर्व

भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ में चीनी गणराज्य को प्रतिनिधित्व दिलाने के अपने प्रयत्न जारी रखे । तिब्बत ■ सम्बन्ध में समान हितों के प्रश्न पर विचार-विमर्श करने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल पैकिंग गया और चीन के तिब्बती प्रवेश के सम्बन्ध में भारत और चीन के बीच एक सन्धि पर हस्ताक्षर हुए ।

भारत कोरिया में युद्ध बन्ध कराने का प्रयत्न जून १९५३ से कर रहा था । जब दोनों पक्ष युद्ध-बन्धियों की वापसी के प्रश्न पर सहमत हुए, तो युद्ध-बन्धी समझौते के अन्तर्गत कुछ विशेष शायित्व प्रहारा करने के लिये दोनों ओर की सेनाओं ने भारत को आमन्त्रित किया । तदनुसार तटस्थ-राष्ट्र युद्ध-बन्धी वापसी कमीशन के अध्यक्ष तथा कार्यकारी प्रतिनिधि (एजेन्ट) के पदों पर भारतीय नियुक्त किये गये । भारत में समझौते में निविष्ट समय के लिये युद्ध-बन्धियों की देखभाल के लिये एक संरक्षक बल भी भेजा । तटस्थ राष्ट्र युद्ध-बन्धी वापसी कमीशन में भारत का प्रतिनिधित्व सेप्टेम्बर १९५३ के ० एस० थिर्सिया ने किया । दक्षिणी सिविल के उन युद्धबन्धियों को, जिन्होंने अपने देश वापस जाना पसन्द नहीं किया, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुपुर्व कर दिया

बेडेनिक

गया और उत्तरी गिनि के युद्धबन्धु चीनो और उत्तरी कोरियाई रेडकांस द्वारा चीन और उत्तरी कोरिया के सुपुर्व कर दिये गये । तटस्थ राष्ट्रों को जाने को इच्छा प्रकट करने वाले ८८ युद्धबन्धुओं को भारत ले आया गया और उनके नामले संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिवी के पास भेज दिये गये ।

जापानी सरकार के नियन्त्रण पर तीन संसद सदस्यों का एक सम्मानना संसद जगत सितम्बर महीने में तीन सप्ताह तक जापान का भ्रमण करता रहा । भारत और जापान के बीच हुई शान्ति सन्धि के अनुसार भारत तथा जापान स्थित जापानी और भारतीय सम्पत्ति सम्बन्धी कोषों के सम्बन्ध में विचार विमर्श हुआ ।

अफ्रीका

ब्रिटिश पूर्वी अफ्रीका में संकटकालीन स्थिति के सम्बन्ध में भारत सरकार ने हिंसा की निंदा करते हुए यह विचार प्रकट किया कि केवल हमन से कोई समस्या हल नहीं होती । उसके विचार में किशुमु द्वारा हिंसात्मक कार्य किये जाने के मुख्य कारण का पता लगाकर उनकी कठिनाइयों तथा उनके कष्टों का निवारण किया जाना चाहिए । सरकार ने कनिंथा निवासी भारतीयों से जहाँ के राष्ट्रीय बलों के साथ सहयोग करने पर जोर दिया जिससे उनके तथा जहाँ के निवासियों के बीच जालिगत मित्रता की भावना पैदा हो ।

इथियोपिया

इथियोपिया की सरकार के अनुरोध पर इथियोपिया में भारतीय कृषकों के स्थायी रूप से बसाये जाने की योजना के अन्तर्गत प्रायः भारतीय कृषक परिवारों का पहला जत्था अप्रैल, १९५३ में इथियोपिया पहुँचा । प्रत्येक परिवार को १६ एकड़ भूमि दी गयी है ।

मध्य अफ्रीका

ब्रिटिश मध्य अफ्रीका के तीन प्रदेशों—न्यासलैंड, उत्तरी रोडेशिया और बल्लिणी रोडेशिया को मिलाकर एक प्रवेश बगाने की योजना के प्रति भारत सरकार को काफी दिलचस्पी थी और उसने यह विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त किया कि ऐसा उन प्रदेशों के अफ्रीकियों का इच्छानुसार ही किया जाना

चाहिये। अफ्रीकियों के विरोध के बावजूद जब नवम्बर, १९५३ में ऐसा संयुक्त प्रवेश बना दिया गया, तब भारत सरकार ने इस प्रवेश के गैर-यूरोपीय लोगों, विशेषकर भारतीयों की अयोग्यताओं के दूर किये जाने का अनुरोध किया।

पश्चिमी अफ्रीका

१९५५ के उत्तरार्द्ध में एक भारतीय राजबूतानाल की स्थापना करके भारत ने पश्चिमी अफ्रीका ■ साथ सम्बन्ध स्थापित किये। गोल्लकोस्ट तथा नाईजीरिया के लिए एक कमिश्नर नियुक्त किया गया जिसका प्रधान कार्यालय अकरा में है। इन दोनों प्रदेशों में गैरे लोगों तथा आदिवासियों के बीच जातिगत मतभेद या तनाव न होने के कारण अफ्रीकी नेताओं के लिये स्वशासन की स्थापना करने के सम्बन्ध में सहयोग से काम करना संभव हो सका।

दक्षिणी-प्रशान्त प्रदेश

कोलम्बो योजना के अन्तर्गत भारत को आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैण्ड की सरकारों से आर्थिक और टेक्निकल सहायता मिलती रही।

आस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री श्री फ्रार० जी० केसी तथा न्यूजीलैण्ड ■ स्वातन्त्र्य मंत्री श्री मार्शल ने कोलम्बो योजना की राष्ट्रमण्डलीय सलाहकार समिति के अक्तूबर, १९५३ में नई दिल्ली में ■ पांचवें अधिवेशन में भाग लिया।

भारत सरकार की सांस्कृतिक छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत फिजी के कुछ भारतीय छात्र प्रतिवर्ष भारत आते हैं।

यूरोप

शुलों का निपटारा करने के लिये इटली और नीदरलैंड की सरकारों के साथ बातचीत की गयी। रूस, बल्गेरिया तथा चेकोस्लोवाकिया के साथ व्यापारिक सम्झौते ■। पश्चिम जर्मनी, नार्वे तथा पोर्लैण्ड के साथ हुए व्यापारिक सम्झौते की अवधि बढ़ाई गयी। जिब्राल्टर स्थित भारतीय सौदागरों की कठिनाइयों के सम्बन्ध में जांच पड़ताल की गयी।

अमेरिका

भारत के उपराष्ट्रपति डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने मई, जून और जुलाई, १९५५ में यूरोप, अमेरिका तथा कनाडा की यात्रा की।

उप-विदेश मंत्री श्री अनिल कुमार खन्ना ने भी अमेरिका तथा कनाडा की यात्राएं कीं।

अमेरिका के कई कांग्रेसमेंनों तथा सेनेटर्स ने भारतयात्रा की। भारत और अमेरिका के बीच १९५६ में हुए द्विराष्ट्रीय वायुमार्ग सम्बन्धी समझौते की अवधि समाप्त होने की मोडिल १४ जनवरी, १९५४ को हो गयी। बताया है कि अमेरिका के साथ एक दूसरा समझौता होगा जिसमें भारत के हित सुरक्षित किये जायेंगे।

लैटिन अमेरिका

भारत और लैटिन अमेरिका के देशों के बीच जातिगत प्रश्नों पर संयुक्त राष्ट्र संघ में बहुत काफी सहयोग दिखाई पड़ा।

ब्रिटिश वेस्ट इण्डिया

भारत की नीति विदेशस्थित भारतीयों को बहु-जाति समुदाय बहु-उद्देशीय संस्थाओं के निर्माण के लिये प्रोत्साहन देने की है। इसी के साथ-साथ वेस्ट इण्डिया में फैले हुए भारतीय उद्भव के लोगों तथा भारत के बीच स्थापित सम्बन्ध दृढ़ किये जा रहे हैं।

प्रतिरक्षा मन्त्रालय

शान्ति का उद्देश्य

स्वतंत्रता ■ सातवें वर्ष की प्रतिरक्षा सेवाओं की गतिविधियों के सम्बन्ध

में सबसे अधिक उल्लेख कोरिया में भारत द्वारा किये गये शान्ति के प्रयासों का किया जाना चाहिए। यह उद्देश्य महत्वपूर्ण तथा विलक्षण इसलिए है कि यह पहला ही अवसर था जब शान्ति की स्थापना के लिए एक देश की सेवाएं दूसरे देश के लिये प्राप्त की गईं।

कोरिया के युद्ध-बन्धियों की समस्या हल करने ■ लिए स्थापित तटस्थ राष्ट्र (युद्धबन्धी) वापसी कमीशन का अध्यक्ष-पद ग्रहण करने का अनुरोध भारत से किया गया। अपने देशों को वापस न जाने वाले युद्धबन्धियों पर निगरानी रखने तथा उनके संरक्षण के लिए भी भारत से संरक्षक-बल भेजने का अनुरोध किया गया। तटस्थ राष्ट्र (युद्धबन्धी) वापसी कमीशन के अध्यक्ष लेफ्टिनेन्ट जनरल के० एस० बिर्म्या से सम्बद्ध कर्मचारी-मंचल ■ अलावा ६,००० अधिकारियों तथा सैनिकों का एक दल भी कोरिया भेजा गया। संरक्षक दल को कमाण्डर के पद पर मेजर जनरल एस० पी० पी० मोरट को नियुक्त किया गया।

कोरिया पहुँचने की तिथि से वापसी की तिथि तक इन लोगों ने बिकट कठिनाइयों का सामना करते हुए अपना काम लगन से तथा बिना किसी पक्षपात के किया। वे लोग कोरिया के कठोर शीत के अभ्यस्त नहीं थे। युद्धबन्धियों के व्यवहार से उनके धैर्य की परीक्षा हुई।

लोगों की सहायता

देश में प्रतिरक्षा सेवाएं दिन प्रतिदिन लोकप्रिय और शक्तिशाली होती गयीं। वर्ष में सैनिकों ने लोगों को संकट में सहायता पहुँचाई और राष्ट्रनिर्माण सम्बन्धी कार्यों में भाग लिया। इन्होंने 'अधिक अन्न उपजाओ' तथा 'बन महोत्सव' जैसे आन्दोलनों में महत्वपूर्ण योग दिया। सैनिकों ने अस्तर पड़ी हुई ६,००० एकड़ भूमि में खेती करना आरम्भ किया और २,००० टन से अधिक अन्न पैदा किया। लोगों को बिक्रिता सम्बन्धी सहायता पहुँचाने के उपाय किये गये और प्रतिरक्षा सेवाओं का फालतू सामान विभिन्न राज्यों में वितरित किया गया। कुछ केन्द्रों में लोगों को निःशुल्क उपचार की भी सुविधाएं दी गईं।

स्थल, जल तथा वायु सेना के सैनिकों ने तो लोगों की सेवाएं की हीं,

पर जनता ने भी सैनिकों तथा सशस्त्र सेनाओं के लिये जारी किये गये कोषों में बिल खोलकर सहायता पहुँचाई। उदाहरणार्थ, फोरिया स्थित सेनाओं के लिए धन तथा भेंट की वस्तुओं का संग्रह करने में जनता ने अत्यन्त उत्साह का परिचय दिया।

प्रशिक्षण

प्रशिक्षण के सम्बन्ध में स्थल-सेना पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। जल-सेना तथा वायु सेना भी इस दिशा में अच्छी प्रगति कर रही है। प्रतिरक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षण-संस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण संस्था बेहराबून स्थित राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी है जो बीघ्र ही पुना के निकट लडकवासला में लेजाई जायगी। सशस्त्र सेनाओं को इस सर्वप्रथम संस्था में प्रशिक्षण के लिए शिक्षार्थियों चुनाव में पूरा-पूरा ध्यान रखा जाता है। चुनाव का तरीका परिवर्धित किया जा चुका है। प्रशिक्षण पाने वाले शिक्षार्थियों का ठीक चुनाव करने तथा उनके गुणों का विकास करने के लिए प्रोत्साहन तथा अवसर देने के उद्देश्य से सरकार ने पंक्ति व्यवस्थापक कुंजक की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की है।

दूसरी महत्वपूर्ण संस्था, जहाँ अन्तर्सेवा के आधार पर प्रशिक्षण दिया जाता है, बेलिगटन स्थित कर्मचारियों का कालेज है। अन्तर्सेवा सहयोग को, जिसका भीगणेश राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी में हुआ था, इस संस्था में अधिक बढ़ावा जा रहा है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी, कर्मचारियों के कालेज तथा अन्य कई वायु-सेना अकादमियों को पड़ोसी राष्ट्रों से बहुत प्रशंसा प्राप्त हुई है और इन संस्थाओं में इन पड़ोसी राष्ट्रों के शिक्षार्थी भी प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं।

प्रतिरक्षा-उत्पादन

प्रशिक्षण की भांति प्रतिरक्षा सेवाओं को मिलने वाले अस्त्र-दस्त्रों तथा उपकरणों की मात्रा तथा उनकी किस्म का प्रदान भी बड़े महत्व का है। अब बहुत कुछ स्वदेशी सामान ही प्रयोग में आने लगा है जबकि पहले इनका विदेशों से आयात होता था। देश के प्रतिरक्षा-उद्योग की प्रगति के सम्बन्ध में दो महत्वपूर्ण घटनाएँ थीं। पहली तो यह कि इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की स्थापना के लिए एक प्रांतीय फर्म के साथ ठेका हुआ और १९५६-५७ से इलेक्ट्रॉनिक रेडियो तथा रडार सम्बन्धी उपकरणों का उत्पादन देश में ही शुरू होने की

आया है। दूसरी घटना यह है कि हिन्दुस्तान एअरक्राफ्ट लिमिटेड में एच० टी०-२ टुर्नर एअरक्राफ्ट का उत्पादन आरम्भ हुआ।

प्रतिरक्षा विज्ञान

प्रतिरक्षा-विज्ञान-संगठन का और अधिक विस्तार हुआ। अस्त्र-शास्त्र सम्बन्धी अध्ययनशाला तीव्रगति से प्रगति कर रही है। इसकी स्थापना पिछले साल हुई थी।

लोगों को सैनिक प्रशिक्षण

लोगों के लिए सैनिक प्रशिक्षण का क्षेत्र विस्तृत कर लिया गया है। सैनिक प्रशिक्षण देने वाले संगठन अभी तक दो ही थे—क्षेत्रीय सेना और नेशनल कैंडेट कोर। क्षेत्रीय सेना १८ से २५ वर्ष तक की आयु के नागरिकों के लिए थी और नेशनल कैंडेट कोर स्कूलों और कालेजों के छात्रों के लिए। किन्तु इन संगठनों से भारत की विशाल जनसंख्या का काम नहीं चलता। इसलिए सहायक क्षेत्रीय सेना की रचना का निर्णय किया गया जो अब सहायक क्षेत्रीय बल और सहायक कैंडेट कोर कहलाते हैं। इन दोनों का उद्देश्य स्वेच्छा से सदस्यों की भरती करना है। सहायक कैंडेट कोर उन बालक-बालिकाओं को प्रारम्भिक सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर देता है जो नेशनल कैंडेट कोर में प्रवेश न पा सके हों। इसी प्रकार सहायक क्षेत्रीय बल के परिणाम-स्वरूप देहाती और शहरी क्षेत्रों के १८ से ४० वर्ष तक की आयु के लोगों को सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर मिलता है। इन दोनों संगठनों का काम बड़े सुभद्र ङंग से आरम्भ हुआ और दोनों ही लोकप्रिय बन गये।

अपने प्रशिक्षण-कार्यक्रम में सनातन सेवा को भी सम्मिलित करने के कारण नेशनल कैंडेट कोर की प्रतिष्ठा और बढ़ गई है। देश में संगठित सभी विधियों में नेशनल कैंडेट कोर के शिक्षार्थियों ने सड़कें तथा मकान बनाए, नालियां साफ कीं, बांधों को मरम्मत की, लोगों को चिकित्सा सम्बन्धी सहायता पहुंचाई और राष्ट्रीय उत्थान में विभिन्न प्रकार से सहयोग दिया। इस सब के फलस्वरूप उन्हें धर्म के महत्त्व तथा सहयोग से किये जाने वाले कार्यों का ज्ञान हुआ।

क्षेत्रीय सेना की शक्ति में वृद्धि हुई। इसका वीर्य विकास करने की

ब्रिटिश से सरकार एक कानून बनाना चाहती है जिसके अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों तथा अन्य कर्मचारियों के लिए इस सेना में भरती होना अनिवार्य हो जायगा।

भारतीय जल-सेना

इस वर्ष में सामुद्रिक उद्योग का उद्घाटन किया गया और कोचीन में "मल्लु" नामक भारतीय समुद्री हवाई मत्तु स्थापित हुआ। वर्ष की अन्य सफलताओं में प्रशिक्षण सम्बन्धी सुविधाओं का संगठन और विकास; हैदर और "हन्ड" वर्ग के तीन विध्वंसक जहाजों का प्राप्त किया जाना तथा कुछ उच्चतम वर्गों पर भारतीयों की नियुक्ति किया जाना है। ब्रिटिश एंजिनरों से एक कूसर भी खरीदा गया।

कोचीन में छोटे जहाजों की मरम्मत की एक छोटी संस्था खोली गई है। ऐसी ही संस्था विशाखापल्लभ में खोलने तथा बम्बई की समुद्री गोदी के विस्तार की योजनाएं भी बनाई गई हैं।

जलसेना अब अपने अधिकारियों तथा सैनिकों को प्रशिक्षण दे सकती है। टेकनिकल प्रशिक्षण के सम्बन्ध में कुछ प्रशिक्षण अभी भी ब्रिटेन में लेना पड़ता है। भारत में प्रशिक्षण सम्बन्धी संस्थाओं के विकास में काफी प्रगति हुई है। १९४४ के अन्त तक कुछ स्कूलों के भी खुलने की आशा है। जहाजों पर प्रशिक्षण सम्बन्धी सुविधाओं को उन्नत करने के लिए विभिन्न प्रस्तावों पर अमल किये जाने की आशा है। जलसेना के जहाजों में प्रशिक्षण सम्बन्धी कई अभ्यास किये जिनमें नवनिर्मित जहाजों में से भी भाग लिया।

जल सेना के मुख्याध्यक्ष तथा उपसेनापति के पद पर अब एक भारतीय ही नियुक्त है। जिन अन्य पदों पर भारतीय नियुक्त हैं, वे हैं—जलसेना सचिव, कनोडोर इन्चार्ज। अन्य सभी प्रशासन सम्बन्धी कमानों के पदों पर भारतीय जलसेना के अधिकारी ही हैं। सामुद्रिक सेना विज्ञान तथा सामुद्रिक पर्यवेक्षण-कार्य के विकास में जल सेना ने अच्छी प्रगति की है।

भारतीय वायु-सेना

राष्ट्र की स्वतन्त्रता का सातवाँ वर्ष भारतीय वायु सेना के विकास, राष्ट्रीयकरण तथा प्राधुनिकीकरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

इस वर्ष पहली अप्रैल को भारतीय वायुसेना ने अपने इक्कीस वर्ष पूरे किये। उसी दिन एयर-मार्शल एस० सुकजी ने सर्वप्रथम भारतीय वायु-सेना-बलि के रूप में भारतीय वायुसेना की क्षमता सँभाली। राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्र प्रसाद ने राष्ट्र के प्रति इसकी सेवाओं की मान्यता में "प्रेसिडेन्ट का कलर" देकर वायुसेना का सम्मान किया। भारतीय वायुसेना के सभी कार्यकारी वर्गों पर अब भारतीय अधिकारी ही हैं।

विचारार्थीन वर्ष में भारतीय वायुसेना ने आसाम के दुर्गम उत्तर-पूर्व सीमान्त प्रदेश तथा शेष भारत के बीच यातायात व्यवस्था कायम रखी।

विभाजन के तुरन्त बाद प्रारम्भ हुए योजना कार्य प्रगति पर हैं। प्राधुनिक ढंग के स्थायी केन्द्रों, कारखानों तथा निवास-क्षेत्रों का निर्माण किया जा रहा है। नये प्रकार के उपकरण आदि प्राप्त किये गये। विमान-चालकों को सैनिक उद्योग के प्राधुनिक तरीकों के अनुकूल उपयोगी बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

२५ मार्च, १९५४ को इतिहास में पहली बार, भारतीय वायु सेना ने जगता के लिये सैनिक कार्यवाही के अधिकृत प्रदर्शन किये।

सूचना एवं प्रसार मन्त्रालय

आकाशवाणी

१९५३-५४ में प्रसारण के विकास के लिए जो कार्य किये गये उनमें से

उत्सवनीय थे हैं—नये ट्रांसमीटरों का लगाना जाना, अच्छे संगीत-कार्यक्रम, प्रसारण सम्बन्धी नीतियों की रचना में स्वर-परीक्षण सलाहकार समिति का अधिक सहयोग, देहात में रेडियो कार्यक्रम सुने जाने की जांच-पड़ताल, समाचार-सेवाओं में महत्वपूर्ण वृद्धि तथा एक प्रतिस्पर्धन एकक का उद्घाटन ।

नागपुर तथा गौहाटी में १० किलोवाट के मीडियम-वेव ट्रांसमीटर यंत्र लगाने जाने से इन केन्द्रों की, सम्प्रेषण-क्षमता में वृद्धि हुई । बम्बई में ५० किलोवाट का मीडियम वेव ट्रांसमीटर लगाने का कार्य करीब-करीब पूरा होने वाला है । ऐसे ही ट्रांसमीटरों के लिए ब्रह्मदाबाद और जालंधर में हमारे तैयार की जा रही हैं । २ दिसम्बर १९५३ को पुना में एक नया केन्द्र स्थापित किया गया । शास्त्रीय संगीत को लोकप्रिय बनाने की दृष्टि से हिन्दुस्तानी और कर्नाटक संगीत के प्रसिद्ध कलाकारों को राष्ट्रीय कार्यक्रम में भला लेने के लिए बुलाया गया । हुल्के-फुल्के संगीत के लिए, घाट केन्द्रों में इकाइयां स्थापित की गयीं ।

अंग्रेजी में बार्ता का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम आरम्भ किया गया और इसमें विभिन्न जीवन-क्षेत्रों के प्रसिद्ध व्यक्तियों ने बार्ताएं प्रसारित कीं । ऐसा ही एक कार्यक्रम हिन्दी में भी चालू करने का विचार है । केन्द्रीय कार्यक्रम सलाहकार समिति, संगीत-सलाहकार बोर्ड और केन्द्रीय हिन्दी सलाहकार समिति के कई सुझावों को कार्यान्वित किया जा रहा है । संगीत स्वरपरीक्षण समितियों ने विभिन्न केन्द्रों का दौरा किया और २,१०० कलाकारों का संगीत सुना । अंग्रेजी और हिन्दी के समाचार पढ़ने वालों तथा एनाउन्सरों के परीक्षण के लिए भी कई केन्द्रों में ऐसी ही समितियां बनाई गयीं ।

आकाशवाणी श्रोत-अनुसन्धान एककों ने बेहती कार्यक्रम के सुने जाने के सम्बन्ध में जांच पड़ताल की ।

समाचार-सेवा विभाग द्वारा प्रसारित किये जाने वाले समाचारों की संख्या ७३ तक पहुँच चुकी है । ये समाचार ३१ भारतीय और विदेशी भाषाओं में प्रसारित किये जाते हैं । अमेरिका के श्रोताओं के लिए स्वाहिनी भाषा में १० मिनट का एक बुलेटिन मई १९५३ में शुरू किया गया ।

सातवीं वर्ष

अनुसन्धान विभाग ने अवतरण-केन्द्रों में विविध प्रकार के अवतरणों को प्रयुक्त किये जाने के लिये एक नये प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक-डाइजिटिटी-स्विच का विकास अन्तिम रूप से तैयार कर लिया है।

अप्रैल १९५३ में नई दिल्ली के साइकास्टिंग हाउस के निकट एक प्रोसेसिंग प्लांट लगाया गया। एक प्रतिलेखन-सेवा के संगठन का प्रस्ताव प्रिचाराधीन है जो आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों तथा विदेशी केन्द्रों में वितरित किये जाने के लिए चुने हुए कार्यक्रमों के रिकार्डों के तैयार करने का कार्य करेगा।

एक व्यापारिक संस्था ने महात्मा गांधी को प्रार्थना प्रचरनों के रिकार्डों की प्रतियां का काम अपने ऊपर लिया है।

प्रेस इन्फार्मेशन ब्यूरो

प्रेस इन्फार्मेशन ब्यूरो समाचारों, चित्रों और लेखों द्वारा भारत तथा संसार के समाचार पत्रों को सरकार की गतिविधि सम्बन्धी अधिकृत जानकारी देता है। यह सरकार को जनता के बुझिकोण से भी अवगत करता रहता है। इस प्रकार ब्यूरो सरकार और समाचार पत्रों के बीच सम्बन्ध कायम करता है।

अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू, गुजराती, तमिल, बंगला और मराठी-इन सात भाषाओं की समाचार-सेवाएँ २,३०० से भी अधिक भारतीय पत्रों और पत्रिकाओं से सम्बन्धित हैं। ये ७५ भारतीय समाचार-पत्रों ३९ विदेशी समाचार-पत्रों, ६ भारतीय तथा २४ विदेशी समाचार समितियों, लेख-अभिधर्षों तथा साइकास्टिंग संस्थाओं के प्रसारित १२० भारतीय और विदेशी सम्वाददाताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करती हैं। तेलुगु तथा कन्नड़ में सूचना सेवाओं के प्रारम्भ किये जाने के प्रस्ताव इस वर्ष स्वीकार किये गये।

ब्यूरो के फोटो-विभाग की ओर से समाचारपत्रों तथा पत्रिकाओं को समाचार-चित्र दिये जाते हैं। ये फोटो नियमित रूप से ३० अंग्रेजी तथा ५५ भारतीय भाषाओं के समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं को तथा ४७ साप्ताहिक पत्रों और पत्रिकाओं को दिये जाते हैं। १९५३ में विदेशों में वितरण के लिए

भ्यूरो ने विदेश मन्त्रालय को भी ६५,४३५ फोटो दिए ।

भ्यूरो की आखाएँ कलकत्ता, बम्बई, मद्रास तथा जालंधर में हैं । जालंधर की शाखा १९५३ में खुली थी । उसी वर्ष भ्यूरो ने ८,६७० प्रेस समाचार तथा २६४ सरकारी प्रकाशन, प्रकाशन सम्बन्धी रिपोर्ट और सचित्र निबन्ध वितरित किये ।

१९५३-५४ में ईरान, आस्ट्रेलिया तथा मिला से एक-एक पत्र-प्रतिनिधि-मंडल भारत आया । भ्यूरो ने देश के विभिन्न भागों में चालू बड़ी-बड़ी विकास-योजनाओं के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने में इन प्रतिनिधि मंडलों की सहायता पहुँचाई । इन प्रतिनिधि मंडलों के अलावा, विदेशों के ८० संवाद दाताओं, संपादकों तथा प्रसारकों में भारत का दौरा किया और भ्यूरो ने उन्हें आकर्षक सुविधाएँ दीं ।

भारत में कई अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए और भ्यूरो ने उनके लिए प्रेस सम्बन्धी-सुविधाओं तथा फोटो की व्यवस्था की । क्षेत्रीय समाज कल्याण बोर्ड की प्रतिविधि जैसे विशेष कार्यक्रमों के प्रचार का कार्य भी भ्यूरो ने किया । ये कार्यक्रम पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में योजना कमीशन के तत्वावधान में आरम्भ किये गये ।

भ्यूरो का प्रतिरक्षा-विभाग सशस्त्र सेनाओं तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालय के कार्यों के सम्बन्ध में जानकारी देने तथा सशस्त्र सेनाओं के लिए सूचना सेवाओं का संगठन करने का काम करता ।

६०० प्रेस समाचारों के अलावा प्रतिरक्षा-विभाग ने १५० से अधिक सचित्र लेख प्रकाशित किए । सेना दिवस, नौसेना दिवस, वायुसेना दिवस तथा नेशनल फोर्बेड कोर दिवस सम्बन्धी विशेष प्रबन्ध किये गये थे ।

सूचना-चित्रों के निर्माण में प्रतिरक्षा विभाग ने फिल्म डिवीजन की सहायता की ।

प्रतिरक्षा विभाग सचित्र साप्ताहिक 'सैनिक समाचार' के प्रकाशन में तथा आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र से हिन्दुस्तानी में प्रसारित किये जाने वाले दैनिक सेना सम्बन्धी कार्यक्रम की भी व्यवस्था करने में सहायता देता है। 'सैनिक समाचार' नौ भाषाओं में प्रकाशित होता है।

जब कि देशी और विदेशी समाचार-पत्रों ने कोरिया स्थित भारतीय संरक्षक बल के कार्यों में अपनी विलचस्पी दिखाई, तत्स्थ राष्ट्र वापसी कमिशन से सम्बद्ध मुख्य जन सम्पर्क अधिकारी से मिलने वाली रिपोर्टें प्रतिरक्षा विभाग द्वारा प्रकाशित की गई थीं।

प्रकाशन विभाग

प्रकाशन विभाग देश में और विदेश में प्रचार कार्य के लिए पैम्फलेटों और पत्रिकाओं के प्रकाशन, वितरण तथा उनकी बिक्री के लिए उत्तरदायी है। विदेशों में प्रचार-कार्य का उद्देश्य है अन्य देशों में भारत की स्थिति प्रस्तुत करना जिससे उन देशों में भारत की प्रगतियों की प्रगति हो सके और उसकी समस्याओं को ठीक से समझा जा सके। देश में प्रचार-कार्य करने का उद्देश्य है देश तथा सरकार की कार्यवाहियों के विषय में अधिकृत जानकारी देना। यह विभाग प्रचार सम्बन्धी साहित्य के निर्माण के सम्बन्ध में विभिन्न मन्त्रालयों को सहायता देता है। विगत वर्ष में पंचवर्षीय योजना के प्रचार-कार्यक्रम के कारण इस विभाग का उत्तरवाप्तिव बहुत बढ़ गया है। योजना के विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित पैम्फलेट अंग्रेजी और हिन्दी के साथ-साथ अन्य प्रादेशिक भाषाओं में भी निकालने का निर्णय किया गया है। प्रति वर्ष औसतन २४-२४ पुस्तक के ३१८ पैम्फलेट निकाले जायेंगे। १४ भाषाओं में १० पैम्फलेट, नौ भाषाओं में १८ पैम्फलेट और दो भाषाओं में ८ पैम्फलेट निकाले जायेंगे। मार्च १९५३ से अप्रैल १९५४ तक पंचवर्षीय योजना और सामूहिक योजना कार्यक्रम सम्बन्धी ४४ पैम्फलेट निकाले गये। इनके अलावा विभिन्न विषयों पर अंग्रेजी तथा हिन्दी में ३८ पैम्फलेट प्रकाशित किये गये। अप्रैल १९५४ में अंग्रेजी, हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओं के ६१ पैम्फलेट प्रेस में थे।

इस वर्ष अंग्रेजी तथा हिन्दी में क्रमशः 'ए० आई० आर सेलेक्शन्स' तथा 'रेडियो-संग्रह' (जिसका नाम अब 'प्रसारिका' रखा दिया गया है) पत्रिकाओं

का प्रकाशन प्रारम्भ किया गया। यह विभाग केन्द्रीय समाज-कल्याण बोर्ड के मासिक मुखपत्र "समाज-कल्याण" (सोशल वेलफेयर) के प्रकाशन और वितरण का भी काम करता है। इस वर्ष के महत्वपूर्ण प्रकाशनों में 'इण्डिया-ए रेफरेन्स एनुअल, १९५३' का प्रकाशन भी हुआ। यह पुस्तक प्रतिवर्ष प्रकाशित की जायगी और इसके सिधे सामग्री का संकलन सूचना मन्त्रालय का 'रिसर्च एण्ड रेफरेन्स डिवीजन' करता है। 'इण्डिया-ए रेफरेन्स एनुअल, १९५४' का भी प्रकाशन हो चुका है। 'जवाहर लाल नेहरू के भाषण' में १९४६ से १९५३ तक के प्रधानमन्त्री के भाषणों का संग्रह है। "महात्मा गांधी-एन एस्बम" इस वर्ष का एक अन्य महत्वपूर्ण प्रकाशन है जिसमें गांधी जी के जीवन सम्बन्धी लिखों का संग्रह है।

यह विभाग निम्नलिखित पत्रिकाएं प्रकाशित करता रहा—विदेशों में प्रचार के लिए अंग्रेजी की द्विमासिक पत्रिका 'मार्च ऑफ इण्डिया', काश्मीर और उसके निवासी तथा संस्कृति पर अंग्रेजी की मासिक पत्रिका 'काश्मीर', हिन्दी तथा उर्दू की मासिक पत्रिका 'ग्रामकल' जिसका उद्देश्य देश ■ विभिन्न सांस्कृतिक प्रदेशों के बीच समझौता पैदा करना है, बच्चों के लिए हिन्दी की मासिक पत्रिका 'बाल भारती' तथा सामूहिक योजना प्रशासन का मासिक मुखपत्र 'कुलक्षेत्र'।

बिन्की, प्रचार तथा विज्ञापनों के द्वारा प्रकाशनों को लोकप्रिय बनाने के सम्बन्ध में प्रयास किये गये। देश के विभिन्न भागों में एक हजार से अधिक एजेंटों का जाल बिछा हुआ है। रेलवे शताब्दी प्रदर्शनी, कोलम्बो योजना प्रदर्शनी, कल्याणी के कांग्रेस अधिवेशन की प्रदर्शनी, कुम्भ मेले तथा कम लागत के गृह-निर्माण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी तथा अन्य प्रसिद्ध-प्रसिद्ध प्रदर्शनीयों में इन प्रकाशनों की बिन्की तथा प्रदर्शन के आयोजन किये गये। प्रकाशनों को लोकप्रिय बनाने में निवेश स्थित भारतीय राजदूतावासों से भी सहयोग लिया जा रहा है। विचारार्थीन वर्ष में ४१ बाहरी देशों को पत्रिकाएं तथा पैम्फलेट भेजे गये।

फिल्मस डिजीजन

इस डिजीजन ने १९५३-५४ में ४३ सूचना-चित्र प्रसारित किये तथा

साप्ताहिक बर्ष

प्रति सप्ताह एक की गति से न्यूक्लियो तैयार कीं। विदेशों की गैर-व्यापारिक प्रदर्शनियों के लिए प्रत्येक महीने में एक-एक विशेष संग्रह तैयार किया गया। वर्ष भर में क्लिप्स डिबीजन द्वारा तैयार की गई डायग्नोस्टिक फ़िल्में १२ अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्म-महोत्सवों आदि में प्रदर्शित की गईं। फ़िल्म डिबीजन से डायग्नोस्टिक फ़िल्म विदेश स्थित ४७ भारतीय राजदूतावासों को भेजी जाती हैं।

फ़िल्मों की जांच का केन्द्रीय बोर्ड

इस बोर्ड ने २,३६१ फ़िल्मों की जांच की जिनमें से बोर्ड के निर्णय के विरुद्ध आई अपीलों के सम्बन्ध में १६ फ़िल्मों केन्द्रीय सरकार के सुपुर्न की गईं।

रिसर्च एण्ड रेफरेंस डिबीजन

यह डिबीजन मन्त्रालय के अन्य विभागों को विभिन्न विषयों पर शोध सम्बन्धी सामग्री देता है। यह डिबीजन समाचारों का एक विस्तृत सूचनीक तैयार कर रहा है। १९५३ और १९५४ के 'इण्डिया-ए रेफरेंस एनुअल' का संकलन कार्य भी इसी डिबीजन ने किया। जनवरी १९५४ से यह डिबीजन भारतीय तथा विदेशी भाषाओं का पाक्षिक सर्वेक्षण तैयार कर रहा है।

विज्ञापन विभाग

यह विभाग रेखे मन्त्रालय को छोड़ भारत सरकार के अन्य सभी मन्त्रालयों की ओर से विज्ञापन निकलवाने का काम करता है। १९५३-५४ में इस विभाग ने पंचवर्षीय योजना, सामूहिक योजनाओं, पर्यटन, छोटी बचत योजनाओं तथा कम-लागत पर गृह निर्माण सम्बन्धी विज्ञापन निकलवाये।

पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी

संयुक्त प्रचार कार्यक्रम

सितम्बर १९५३ के अन्त में संसद ने पंचवर्षीय योजना और सामूहिक योजनाओं सम्बन्धी प्रचार-कार्य के लिए तथा साथ ही साथ दुनियाधी और समाज शिक्षा ■ लिए ३८ लाख रुपये के एक पूरक अनुदान पर अपनी स्वीकृति दी। देशाती क्षेत्रों में अध्व-बुद्ध प्रचार कार्य के लिए प्रदर्शनी विभाग और

अचार-एककों का निर्माण किया गया और उनको सभी प्रकार की सुविधाएँ भी दी गईं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं की फिल्मों, लोकप्रिय पैम्फलेट, फोल्डर तथा पोस्टर भी आते हैं।

अगस्त १९५३ में जब नई दिल्ली में कोसम्बो योजना सलाहकार समिति की बैठक हुई, तब योजना के प्रचार के लिए प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया। इसके अलावा जयपुर, हैदराबाद, जोधपुर, त्रिवेन्द्रम, शाहजहाँपुर तथा पटिआला में भी योजना सम्बन्धी सामग्री का प्रदर्शन किया गया।

इलाहाबाद में कुछ महीने के अन्तर पर सात फिल्म केन्द्रों में आभयसेन्दरी फिल्मों विकसित हुई तथा आकाशवाणी ■ इलाहाबाद केन्द्र से प्रसारित किये गये विशेष कार्यक्रमों ■ सुनने की सुविधाओं की व्यवस्था की गई।

फिल्म सिबीजन के लिए सात प्रतिरिक्त एककों की स्वीकृति दी जा चुकी है जो प्रति वर्ष दूर फिल्मों संग्रह करेंगे। ये फिल्में अंग्रेजी, हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओं में तैयार की जायेगी।



राज्य



खाद्य और कृषि

मासाम

कृषि विभाग ने फसल, खाद्य, भूमि तथा पौधों विषयक अनेक प्रयोग किये जिनके परिणाम प्रदर्शनों और भावकों द्वारा जनता के सामने रखे गये। विभाग ने बिमोरिया और हुजारी में विकास-केन्द्र भी स्थापित किये। २४० भवनयुक्तों की एक भूमिसेना सब्जियों तथा नहरों के निर्माण के लिए बनायी गई।

धान उगाने की जापानी प्रणाली को प्रदर्शनों द्वारा प्रोत्साहित किया गया। विभागीय कर्मचारियों की टेक्नीकल सहायता की व्यवस्था के साथ-साथ अच्छे बीज, अच्छे पौधे, खाद तथा बीमार भी बिये गये। पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ३४५ लाख रुपये के व्यय से २,२५,००० टन अतिरिक्त अनाज के उत्पादन का जो लक्ष्य बनाया गया था उसके स्थान पर दो वर्षों की अवधि में ७७.६२ लाख रुपये के व्यय से १,५२,७९० टन अतिरिक्त अनाज पैदा किया गया।

बिहार

सन् १९५३ की अन्न स्थिति निम्नलिखित रूप से सुधार की सुचना दे रही थी किन्तु दुर्भाग्य से उत्तरी एवं दक्षिण बिहार के कुछ भागों की बाढ़ों ने फसलों को हानि पहुँचायी। जहाँ धान के बीज बाढ़ द्वारा बह नहीं गये वहाँ बताया जाता है कि पिछले दशक में कमी भी इतनी अच्छी फसल नहीं हुई। फलस्वरूप राकम अर में धान की कीमतें कम रहीं।

कृषि अनुसन्धान का कार्य अधिक तीव्र कर दिया गया और धान तक गेहूँ की भी जातियाँ खोजी गयीं जो बाढ़ की सहन कर सकती हों और साथ ही जलभी पक जतौ हों। जापानी प्रणाली द्वारा धान की खेती का भी प्रदर्शनों द्वारा प्रचार किया गया और देखा गया कि इससे एक एकड़ भूमि में ५० मन तक धान उपजता है।

टेकनीकल शिक्षा प्राप्त किये हुए व्यक्तियों की उत्तरोत्तर आवश्यकता देखकर बिहार कृषि महाविद्यालय में अनेक विद्यार्थियों को भर्ती किया गया। ग्राम सेवकों और सामूहिक विकास योजना खंडों तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षणार्थ चार नये कृषि स्कूल खोले गये।

अधिक एवं सुचारु रूप से सिंचाई की सुविधाएँ दी गयीं। सिंचाई की ९६ मध्यम योजनाएँ और २३७ छोटी योजनाएँ कृषि विभाग द्वारा पूरी की गयीं तथा ५०० नये कुएँ खोदे गये। राजस्व विभाग ने भी १६ लाख रुपये की लागत से १,००० छोटी योजनाएँ पूरी कीं।

सन् १९५३ में सिंचाई की वस बड़ी योजनाएँ तथा २६ नाली और तटीय बांध योजनाएँ पूरी की गयीं। पहले के द्वारा १.११ लाख एकड़ के लिए सिंचाई की सुविधा दी गयी तथा दूसरे के द्वारा १५.८१ लाख एकड़ की लाभ मिली। रामेश्वर सामूहिक योजना खंड के अन्तर्गत मयूरक्षी लेपट बैंक केनाल स्कीम पर ८१.१ लाख रुपये व्यय होने का अनुमान लगाया है जिसमें से ४३ लाख रुपये पश्चिम बंगाल की सरकार देगी। ३५० बिजली के कुएँ लगाने का कार्य प्रगति पर है।

जिबेली नहर के विस्तार के लिए १.१२ करोड़ रुपये का सख्तीया तैयार किया गया है। यह कार्य गंडक योजना के अंतर्गत होगा तथा शीघ्र प्रारम्भ होगा। कोसी बांध पर ३७.५ करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे जिसमें से २ करोड़ रुपये सन् १९५४-५५ में खर्च होंगे।

बम्बई

कृषि विभाग द्वारा उत्तम बीजों के विविध प्रकार तैयार किये गये हैं। पैदावार की वृद्धि के लिए ६३,००० बंगाली मन उत्तम बीज तथा ८,००० टन

‘मिश्र साव सन् १९५४ की फरवरी तक किसानों में वितरित की गयी। गांवों और कस्बों में कम्पोस्ट साव बनाने के तरीकों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

सिंचाई की और अधिक सुविधा हो जा सके इसके लिए ६,००० नये कूपें बनवाये गये तथा १९,००० पुराने कूपों की मरम्मत की गयी। नये कूपों के निर्माण के लिए ८,६२,००० रुपये काज के रूप में बिमा जा चुका है। कूपों में पानी बढ़ाने के लिए खेद करने वाली नदीयों द्वारा उन्हें गहरा किया जा रहा है।

लगभग ३,५०० एकड़ भूमि की तकसवी की जा चुकी है तथा २,५८,००० एकड़ क्षेत्र में साइपाई और लघु बांध बनये गये हैं।

पशु विभाग द्वारा कई गांवों में पशु-चिकित्सालय खोले गये हैं, साथ ही बम्बई पशु-चिकित्सा कालेज का विस्तार किया गया है जिससे अधिक लोगों की शिक्षा दी जा सके। साथ ही सोरा और बैबसीन के लिए एक केन्द्र खोलने की योजना है और एक पशु-प्रजनन केन्द्र भी स्थापित किया जाना है।

समाज का बदतूल धीरे-धीरे कम किया जा रहा है। बाबल की प्राप्ति के कारण पोहे और कुरमरे बनाने वालों पर से नियंत्रण हटा दिया गया है।

मध्य प्रदेश

भारत में बांध की खेती की जापानी प्रणाली मार्च सन्- १९५३ से प्रारम्भ की गयी है और वेरावार में प्रति एकड़ ५८ मन की वृद्धि हुई है। यह संख्या सामान्य उपज से कई गुना है।

५,४०० गांवों की ३१ लाख एकड़ भूमि के ५६ जिलों में ‘अधिक जल उपकारी ग्राम्योत्पन्न’ का प्रदर्शन आयोजित किया गया।

इस वर्ष २२२ नये कूप बने और १३६ की मरम्मत की गयी। अच्छे बीज और साव तथा २५१ रूट वितरित किये गये।

प्रशिक्षण कर्ताओं से विभिन्न कार्य करवाने के लिए ४७ मोवरलियरों तथा ५० कामदारों को पशुशास्त्र की छाठ माह की शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य की चार माह की शिक्षा दी गयी। अचलपुर और केंतल के फार्मों में कृषि सम्बन्धी शिक्षा का आयोजन ३२ स्ट्राक सुपरवाइजरों तथा ३७ स्ट्राकमैनो के लिए किया गया है। राज्य के ट्रैक्टर यूनिट ने अभी तक ४२,७८३ एकड़ की जुताई की है।

खरीफ की फसल (अर्थात् नवम्बर ५३ से १३ अप्रैल ५४ तक) से १,५६,७०० टन चावल की उगाही की गयी जब कि गत वर्ष २,३१,७४२ टन की उगाही हुई थी।

सिंचाई की ६ बड़ी योजनाओं में से पाँच का कार्य गंगुलपाड़ा, गोंदिल, बुकड़ीलोड़ा, सम्पना और सरोबा में प्रारम्भ किया जा चुका है। सिंचाई की सभ्य माध्यमिक योजनाओं में अच्छी प्रगति हुई है तथा ४७ ग्राम बांधों के कार्य पूरे हो चुके हैं।

पशुधन को बढ़ाने के लिये १० नये केन्द्र-ग्राम खोले गये तथा एक कृषि गंधर्वान केन्द्र की स्थापना हुई। सूत की बीमारी से पशुओं को बचावे के लिये सुई लगाने का कार्य बड़े पैमाने पर किया गया। गाँवों में २० नये पशु-चिकित्सालय खोले गये।

मछली-उत्पादन को बढ़ाने के लिए ४० तालाबों में स्वस्थ तथा ताजी मछलियाँ एकत्र की गयीं। एक सुर्गपालन गृह नरगपुर में स्थापित किया गया तथा गाँवों में ३७ छोटे केन्द्र खोले गये। अचलपुर में रई सम्बन्धी शोध-कार्य के लिये एक केन्द्र की स्थापना की गई।

राज्य भर में उपज की वृद्धि के फलस्वरूप धन-स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार हुआ। अर्थात् राज्य के निर्माण से यह आवश्यक हो गया कि चावल तथा धान के क्षेत्रों का पुनर्गठन हो।

किसानों को उत्तम बीज, तथा विकसित औजार वितरित किये गये। फसल

की पशुओं और कीड़ों ॥ बचाने के लिये पीड़ित क्षेत्रों के किसानों को कुत्तों
लागत के ५० प्रतिशत मूल्य में तथा अन्य किसानों को ७५ प्रतिशत मूल्य में
व्याहारां बांध दी गईं। कृषि विभाग के धान सम्बन्धी नये अनुसन्धानों के
अनुसार धान की फौसी वाली भूमि का ६० प्रतिशत भाग अभी तक बोया जा
सुका है। इसमें भी १० से २० प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है।

‘अग्नि कल्प उपग्रामों’ योजना में इस वर्ष ४२४ सिंचाई की छोटी
योजनाएं ४०.४ लाख रुपये की लागत से पूरी होंगी। अभी तक ७७ पूरी हो
चुकी हैं और शेष ३४७ निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। मलमलुभा
बांध तथा सोमर भवानी बांध से सिंचाई के लिए पानी इस वर्ष दिया गया।

गत वर्ष की अपेक्षा संपूर्ण धान क्षेत्र में तथा ज्वार की फसल में १२.५
प्रतिशत तथा २७.७ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जमीनोपवन की जापानी प्रणाली
का १२,८६३ एकड़ में प्रयोग किया गया और उत्पादनक कल प्राप्त हुए हैं।

उड़ीसा

हीराकुड बांध का कार्य योजनानुसार चल रहा है। हीराकुड द्वीप
तथा कलारीकुड द्वीप को मिलाने के लिये एक स्थायी पुल निमित्त हो चुका
है। तटी के बायें बायें दोनों ओर के बांध बन चुके हैं। सन् १९५३ तक हीरा-
कुड बांध योजना में २८ करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं। मधुकुण्ड बांध
का निर्माण लगभग समाप्ति पर है।

भूमि फिर से सुधारी जा रही है। मार्च १९५४ तक १८,००० एकड़
भूमि साफ की जा चुकी है तथा १०,००० भूमि खेती के योग्य बन चुकी है।

सुन्दरगढ़ जिले के करकेला में पाँच लाख टन की शक्ति का लोहे तथा
इस्पात का एक प्लांट लगाया जायगा। हीराकुड बांध के निकट जोड़ा-पूर्व में
कोरो-मैंगनीय का एक प्लांट स्थापित किया गया है।

सरकार ने ४०६ छोटी सिंचाई योजनाओं के लिए १७,८२,७६५ रुपये
अंशुर किये हैं जिसमें अनेक पहाड़ी धाराओं पर बांध बनाने की योजना है।

इनके पूरा हो जाने पर लगभग १,३८,७४२ एकड़ क्षेत्र को सिंचाई संभव हो सकेगी तथा बंजड़ धरती का अधिकांश भाग कृषि के योग्य बनाया जा सकेगा।

राज्य में कृषि के लिये खपया देने वाली ४,८५६ संस्थाएं हैं जो कि किसानों को खपया उपहार देती हैं। ७६ बूझरी ऐसी हैं जो कि किसानों को खपया तो उपहार नहीं देती परन्तु उपज की बिन्धी आदि कई कार्य करती हैं।

राज्य में ५० सहकारी संस्थाएं हैं जो सहकारी कृषि करती हैं, तथा विशेष प्रकार की सहकारी संस्थाएं भी हैं जैसे—गन्ना उद्यमाने वालों की, बासू वालों की, मूंगफली वालों की, तम्बाकू वालों की और जूट वालों की। इनके सदस्यों की संख्या ७१७४ है। उपज की बिन्धी आदि के लिए २० सहकारी संस्थाएं हैं।

मछली उत्पादन के लिए तीन प्रकार की सहकारी संस्थाएं हैं जैसे—(१) बी इनलैंड कोआपरेटिव फिशरीज, (२) बी मेरीन कोआपरेटिव फिशरीज और (३) बी थिस्कोलेक कोआपरेटिव फिशरीज।

पंजाब

कानूनकारों को बेवसल किये जाने से रोकने के लिये सरकार ने अनैक सुविधाएं भी हैं तथा कार्रबाहियां भी की हैं।

व्यापारिक फसल में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। अमेरिकन र्बई वाले क्षेत्रों में सन् १९४७-४८ के ४०,००० एकड़ में २,८०,००० एकड़ की वृद्धि सन् १९४९-५० में हुई। जापानी प्रणाली के अनुसार धान की पैदावार में प्रति एकड़ महत्वपूर्ण प्रगति हुई। यह विचार है कि इस वर्ष १,५०,००० एकड़ भूमि पर इस प्रणाली द्वारा खेती की जाय।

सरकार द्वारा किये गये कर्ज से १,४०० कूएँ खोदे गये। लोगों के द्वारा बिना किसी सहायता के और भी १,५०० कूएँ खोदे गए। कृषि विभाग ने ५०० पम्पिंग सेट वितरित किये तथा ४०० क्यूबों में बोरेिंग की।

राज्य न केवल अन्न में आरम्भनिर्भर हुआ है बल्कि बाहर भी बहुत कुछ भेज सका है। जनवरी-दिसम्बर १९५३ के बीच ३७,३६६ टन गेहूँ, ८१०३ टन जौ, १७३७ टन चना, ८०० टन ज्वार और ६६,४७४ टन चावल दूसरे राज्यों को भेजा गया। अन्न वितरण एवं मूल्यों पर से सब नियंत्रण उठा लिये गये।

उत्तर प्रदेश

अन्न उपाने की आपानी प्रणाली एक वर्ष पूर्व कार्य में लाई गई और ३५,००० एकड़ से ८,६०० टन अतिरिक्त अन्न प्राप्त हुआ।

लगभग ५६० नये बिजली के कूप एवं ४२५ मील लम्बी नहरें बनाई गईं। फ़ास की एक फ़र्म से करार के अनुसार १५० ट्यूब-वेल १९५३ के ऐकनोकर सहयोग प्रशासन कार्यक्रम के अन्तर्गत बनाये गये।

कृषि-विकास योजना के अन्तर्गत गणसभ विस्तार पर ३० राष्ट्रीय विस्तार सेवा विकास संघ शुरू किये गये। प्रत्येक ब्लॉक में १०० गांव हैं जिनकी आबादी लगभग ६६,००० है। यह सेवा उत्तर प्रदेश के ४० ब्लॉकों में फैली हुई है। इस सप्ताह में १६,००० कार्यकर्ताओं के शिक्षण के लिये एक पंचवर्षीय कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है।

राजस्थान के बढ़ते हुए मरुस्थल को रोकने के लिये सीमा पर अन्न उगाये जाने के हेतु १० लाख रुपये व्यय किये जायेंगे। घारे और चरागाहों की स्थिति सुधारने के लिये राज्य में प्रयोग भी किये जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकारकी विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति ६ मार्च १९५४ को प्राप्त हुई। इसके द्वारा न केवल कृषि उत्पादन में ही वृद्धि होगी बल्कि किसानों के भूमि सम्बन्धी पारस्परिक झगड़े भी कम हो जायेंगे।

यह तय हुआ है कि भूतपूर्व जमींदारों को सुधारजे के रूप में हस्तांतर योग्य बांड दिये जायें। जमींदारी उन्मूलन के बाव ३१ मार्च १९५४ को कोई आफ बाईस तोड़ दिया गया।

बाढ़ निरोधक उपाय के रूप में लखनऊ में प्रत्येक वर्ष जुलाई से सितम्बर

सातवीं वर्ष

तत्काल एक केन्द्रीय खेतावली कार्यालय खोला जायेगा। यह कार्यालय बाढ़ नियंत्रण सम्बन्धी सभी निरीमक और सहायता कार्यों के लिये उत्तमवादी होगा।

पश्चिम बंगाल

बंगाल एक जिले से दूसरे जिले में से जाये जाने पर जो रोक लगायी गयी थी वह हटा दी गयी। इसके फलस्वरूप बाढ़ का वितरण उचित रूप से हुआ और मृत्यों में कमी आई। १३ जनवरी १९५४ को मेहूँ पर से नियंत्रण खड़ा लिया गया।

३६६ टन धान के परिष्कृत बीजों के वितरण से २३७६ टन उत्पादन अधिक हुआ। परिष्कृत बीज, संतुलित उर्वरक तथा अन्य खाद के प्रयोग से धान की खेती में भी उन्नति हुई। पटसन की खेती ५,३४,७०० एकड़ भूमि में की गयी और प्रति एकड़ १४,६८,४०० गांठ पटसन पैदा हुआ।

राज्य में लगभग १,१०,२४,३०४ पशु हैं। प्रजनन आदि के लिए हरियाने के साथ प्राप्त किये गये। वेहाली क्षेत्रों में पहली बार कुत्रिन रेतन का प्रयोग किया गया। फल स्वरूप सितम्बर १९५३ तक २२२० गाँवें फलायी गयीं। लगभग ६१,८३६ एकड़ भूमि में धान की खेती की जायगी अणाली अपनायी गयी और ११,७२,००० मन बाढ़ल पैदा हुआ जो कि राज्य के पूर्व-उत्पादन से बढुगा है।

शिक्षा

आसाम

२.८३ करोड़ रुपये में से, जो राज्य की कुल आय है, १६.७ प्रतिशत शिक्षा के लिए रखी गयी है। अजट में भी विश्वविद्यालय तथा माध्यमिक शिक्षा के लिए व्यवस्था की गयी है।

हिन्दी की शिक्षा १३० अन्य हाई स्कूलों तथा मिडिल स्कूलों में आरम्भ की गयी है। कुछ राजकीय हाई स्कूलों में धार्मिकताओं की बोलियों के शिक्षण का भी प्रबन्ध किया गया है। प्राथमिक शिक्षा में सबसे महत्त्वपूर्ण परिवर्तन यह हुआ कि प्राथमिक और जुनियर शिक्षा को मिला दिया गया है।

राज्य में ८४९ समाज शिक्षण केन्द्र हैं। विभिन्न संस्थाओं द्वारा संचालित ये ग्रामीण पुस्तकालय तथा केन्द्र सामाजिक उत्थान तथा मनोरंजन में लगे हैं।

प्रौद्योगिक तथा व्यावसायिक शिक्षा की प्रगति भी संतोषजनक है। जोरहाट का ‘बी प्रिंस आफ वेल्थ’ टेक्नोलॉजिकल स्कूल, इन्जीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के कालेज में परिवर्तित कर दिया जायगा। इस कालेज में तथा भोहाटी के आसाम सिविल इन्जीनियरिंग इन्स्टीट्यूट में नेशनल सर्टिफिकेट-कोर्स जारी किया जायगा।

आसाम के इतिहास और संस्कृत में शोधकार्य ■■■ शिलांग की इतिहास समिति को सन् १९५३ में आर्थिक सहायता दी गयी। आसाम साहित्य सभा को एक ग्रन्थ प्रकाशित करने के लिए आर्थिक सहायता दी गयी है - जिसमें उन ऐतिहासिक लेखों की सूची होगी जो समय समय पर विभिन्न वर्षों में प्रकाशित होते रहे हैं।

बिहार

शिक्षा पर सन् १९५३-५४ में ५ करोड़ रुपये खर्च हुए जब कि सन् १९३८-३९ में ७० लाख रुपये और सन् १९४८ में १.२५ करोड़ रुपये ही खर्च ■■■ थे।

राज्य सरकार ने प्रारम्भिक शिक्षा के प्रसार एवं सुधार के लिए एक योजना तैयार की है और ५१ लाख रुपये से वह सन् १९५३-५४ में कार्यान्वित की जायगी। अभी तक ५,००० नये शिक्षक तथा २५० नूरे समय के लिये समाज शिक्षण निदेशक नियुक्त किये गये हैं।

स्वायत्त शासन कानून में सुधार किया गया है जिसके द्वारा सरकार

प्रारम्भिक शिक्षा पर एवं अधिक नियन्त्रण एक लगेगी।

वर्तमान प्रारम्भिक स्कूल बुनियादी स्कूलों में परिवर्तित कर दिये जायेंगे। ५ लाख रुपये से हाईस्कूलों में व्यवसायों और दस्तकारियों की शिक्षा दी जायगी।

सरकार की इस योजना के अनुरूप कि प्रत्येक जिले में लड़कियों के लिए एक हाई स्कूल तथा प्रत्येक सब डिवीजनल हेडक्वार्टर में लड़कियों के लिए एक मिडिल स्कूल हो, १४ हाई स्कूलों और ३६ मिडिल स्कूलों की स्थापना हो चुकी है।

सुको-बैशाली क्षेत्र में कई सामूहिक केंद्र, बुनियादी स्कूल, ट्रेनिंग स्कूल, पुस्तकालय आदि स्थापित किये जा चुके हैं।

बम्बई

सात से ग्यारह वर्ष तक के बालकों के लिए प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य होने के कारण पहली अप्रैल १९५३ को १४,१०८ प्रारम्भिक स्कूल थे, जिनमें विद्यार्थियों की संख्या १२,५४,०७८ थी। सरकार ने ५०,००,००० रुपये स्कूल भवनों के निर्माणार्थ कर्ज के रूप में स्वीकृत किया। प्रेजिडेंटों के लिये स्वीकृत तीन बुनियादी प्रशिक्षण केंद्रों के पाठ्यक्रम में बुनियादी शिक्षा का प्रशिक्षण भी सम्मिलित है। प्रोबों की निरक्षरता दूर करने के लिए सरकार ने समाज-शिक्षण की एक योजना बनायी है जो तीन प्रादेशिक समाज-शिक्षण समितियों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। हरिजनों के लिए दो सौ समाज शिक्षण केंद्र खोले गये हैं, जिनमें २५,००० रुपये की भाज्यक सामग्री भी सन् १९५३-५४ में दी गयी है। गांवों में वाचनालय खोलने की योजना को भी सरकार ने स्वीकार कर लिया है। वर्तमान वाचनालयों को दी जाने वाली वार्षिक सहायता १८ रुपये से ७५ रुपये कर दी गयी है। सन् १९५३-५४ में ४,००० पुस्तकालयों को सहायता दी गयी।

माध्यमिक स्कूलों का पाठ्यक्रम संशोधित किया गया तथा उन्हें सरकारी सहायता यथावत् मिलती रही। विश्वविद्यालयों की शिक्षार्थ ६६,८२,७००

उपरो की व्यवस्था सन् १९५३-५४ में रखी गयी। शीघ्र कार्य के लिए सुविधाएं बढ़ा दी गयीं।

अनुसूचित जातियों तथा जन जातियों के लिए वे सब सुविधाएं उपलब्ध की गयीं जो कि पिछड़े वर्गों की दी जाती हैं।

टेक्नीकल शिक्षा के लिए गैर-सरकारी संस्थानों को उनके वार्षिक व्यय का ५० प्रतिशत तक सहायता के रूप में दिया गया। गवर्नमेंट एप्रेंटिस स्कीम के अंतर्गत ५५ छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों की ट्रेनिंग के लिए चुना गया। टेक्नीकल संस्थाओं के छात्रों को छात्रवृत्ति तथा दूसरी सुविधाएं भी दी गयीं।

मध्य प्रदेश

सन् १९५३ में प्रारम्भिक शिक्षा पर २०६ लाख रुपये व्यय किये गये। स्कूलों की संख्या १०,९५३ तक पहुँची जिसमें ७३५०५७ विद्यार्थी थे। १,२०६ गांवों में तथा ४६ म्युनिसिपल क्षेत्रों में प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य है। राज्य में ७७ नामल स्कूल हैं जहाँ प्रतिवर्ष १,३६० शिक्षक ट्रेनिंग पाते हैं। ७७ इंडियन मिडिल स्कूलों को सीनियर बेसिक स्कूलों में परिवर्तित किया गया, साथ ही यह भी प्रयास किया जा रहा है कि नामल स्कूलों में बुनियादी शिक्षा की ट्रेनिंग दी जा सके। इंडियन इंग्लिश मिडिल स्कूलों तथा हाई स्कूलों की संख्या ५७५ हो गयी जिसमें २८६ हाई स्कूल हैं तथा १,४७,९८५ छात्र शिक्षा पाते हैं। सन् १९५४ में हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा के लिए २०,१८३ छात्र बैठे। लगभग ३८४ ट्रेण्ड शिक्षक प्रतिवर्ष ट्रेनिंग स्कूलों से पास होते हैं।

प्रधान मंत्री के जन्म-दिन के उपलक्ष्य में मध्यप्रदेश-वासियों ने ८५ स्कूलों के निर्माण का वचन प्रधान मंत्री को दिया। ग्रामीणों ने स्कूल की इमारतों के लिए ६६३ एकड़ भूमि प्रदान की। ३१ मार्च सन् १९५४ को राज्य में ११,३५३ प्रारम्भिक स्कूल थे।

मद्रास

इस वर्ष प्रारम्भिक स्कूलों में १७,३७,८४० छात्र तथा ९,६०,६१५ छात्राएं थीं। राज्य में कुल ६८६ बुनियादी स्कूल हैं जिनमें ५७,२१० छात्र

सातवाँ वर्ष

और ३५,१३६ छात्राएं हैं। छात्रों के लिये राज्य में ८०४ माध्यमिक स्कूल तथा छात्राश्रमों के लिए २०४ स्कूल हैं। सिर्फ इण्डियन सेकेन्डरी स्कूल ही छात्रों के लिए ७७६ हैं और छात्राश्रमों के लिये १७७ हैं जिनमें ३,८४,०३१ छात्र तथा १,०६,०६३ छात्राएं हैं। राज्य की साक्षरता १८.३ प्रतिशत है। दावा है कि शिक्षा पर अवशिष्ट महास राज्य ८५४ लाख रुपयों से भी अधिक व्यय करेगा।

उड़ीसा

इस वर्ष के भीतर ५०० लोअर प्राइमरी स्कूल तथा ६० बेंसिक जूनियर स्कूलों की स्थापना की गयी। ३२ लोअर प्राइमरी स्कूल अपर प्राइमरी स्कूलों में परिणत किये गये। एक शिक्षक वाले प्राइमरी स्कूलों में लगभग ३०० और अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की गयी। इस वर्ष के अन्त तक १२०० नये लोअर प्राइमरी स्कूल शिक्षितों को काम दिखाने वाली योजना के अन्तर्गत खोले गये।

अनिवार्य शिक्षा की योजना राज्य में अल्प पांच स्थानों पर प्रारम्भ की गयी, जैसे प्रथमड़ (नगर) बारीपाड़ा (नगर), बंगुल (नगर) सुन्दर गढ़ (नगर) और अधमलिक घाना। दसवां नये स्कूल खोले गये और २६६ नये शिक्षकों की नियुक्ति की गयी। सात नये एलीमेन्ट्री ट्रेनिंग स्कूल तथा दो चलते-फिरते प्रशिक्षण दल बनाये गये।

पहली मार्च १९५३ से प्रारम्भिक स्कूल के शिक्षकों के वेतन में ४ रुपये की वृद्धि की गयी। सरकार ने यह भी निश्चय किया कि प्रारम्भिक स्कूलों के सभी अध्यापकों को कान्स्टीब्यूटरी प्रोविडेंट फण्ड का लाभ दिया जाय।

जहाँ तक माध्यमिक शिक्षा का प्रश्न है, स्कूलों की संख्या २०० से २०६ हुई। मिडिल इंगलिश स्कूलों की संख्या ५५८ से ५७० हुई। साधारण सरकारी सहायता के अलावा ४.२४ लाख रुपयों की सहायता स्कूल की इमारतों तथा साज-सज्जा के लिए दी गयी।

वैज्ञानिक अनुसन्धान बोर्ड को २६,५६० रुपयों की सहायता दी गयी जिसके द्वारा राज्य के विभिन्न स्तरों द्वारा शोध-कार्य चलता रहे। उच्चशिक्षा

‘क’ भाग

के लिये छात्रवृत्तियों की संख्या ११ से २२ कर दी गयी। ११३६ प्रोक्तों को संसार बनाया गया जो १५० समाज विज्ञान केन्द्रों के प्रयत्नों का फल है।

पंजाब

छात्र और छात्राओं के लिये सन् १९५२ की ४१६१ प्राइमरी स्कूलों की संख्या १९५३ में ५४१६ हो गयी। सन् १९५३ में छात्रों के ३०० प्राइमरी स्कूलों में चार कक्षाओं के बजाय एक कक्षा और बढ़ायी गयी।

सरकार ने कांगड़ा के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को लाहुल और स्पीती में चार प्राइमरी स्कूल खोलने के लिये सहामता दी।

शिक्षितों में बेरोजगारी दूर करने के लिए एक सितक वाले १६०० प्राइमरी स्कूल इस आर्थिक वर्ष में खोले जायेंगे।

बुनियादी स्कूलों में नये कला-कौशल जैसे कुवि, बागवानी, कताई और जुनाई का कार्य प्रारम्भ किये गये हैं। बढ़ती हुई आवश्यकता की पूर्ति के लिए राज्य भर में सात ग्राम-कालीन वृत्ति-केन्द्र स्थापित किये गये हैं।

बंसीगढ़ में एक द्वितीय कालेज खोला गया है। फीस आदि में हरिजन, विछड़े वर्ग के विद्यार्थियों तथा सरायम वैजा जातियों के छात्रों के लिए रिदा-यत हो गयी है।

उत्तर प्रदेश

सरकार ने यह निश्चय किया है कि देहातों के प्राइमरी तथा जूनियर हाईस्कूलों को समाज विस्तार सेवा केन्द्रों में परिवर्तित कर दिया जाय। इन स्कूलों में कुवि अनिवार्य विषय होगा। प्रत्येक स्कूल के साथ एक कुवि-फार्म रहेगा। इस प्रकार ये स्कूल सब लोगों को सामूहिक कार्य की प्रेरणा देकर गांव की भलाई कर सकेंगे।

बेचनागरी सम्मेलन में होने वाले लिपि सम्बन्धी निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की गयी है। प्रकाशकों तथा मुद्रकों से

सालवाँ वर्ष

अनुरोध किया गया है कि वे परिवर्द्धित रूप को स्वीकार करें। निम्नानों एक लेखकों को हिन्दी में अच्छे ग्रन्थ निर्माण करने के लिये प्रोत्साहन के रूप में सरकार ने निर्णय किया है कि महत्वपूर्ण कृतियों को पुरस्कृत किया जाय।

सरकार ने विस्मृष्ट बोंडों की ३२८६००० रुपयों को विशेष अनावर्तक सहायता मंजूर कर दी है ताकि शिक्षकों का बढ़ाया वेतन श्रादि चुकाया जा सके।

पश्चिम बंगाल

स्कूलों के विद्यार्थियों की संख्या अब १५ लाख है। अब तक १४०० शिक्षकों की बुनियादी शिक्षा की ट्रेनिंग हो जा चुकी है। ७६४६० बच्चों से भी अधिक साक्षरता एवं समाज शिक्षण केन्द्रों में उपस्थित होते हैं। ७०० से अधिक केन्द्रों को सरकार चलाती है। निम्नविद्यालयों की तथा टेक्निकल शिक्षा पर सरकार काफी पैसा व्यय करती है।

सरकार ने यह योजना पास कर दी है जिसके अनुसार १०००० प्राइमरी स्कूल खोले जायेंगे। इसे कार्यान्वित करने के लिए २५०० प्राइमरी स्कूल खोले जा रहे हैं।

सार्वजनिक स्वास्थ्य

आसाम

फाला-माजार की रोकथाम तथा बर्बाई के लिये गारो पहाड़ी के फूल-बाड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य चिकित्सालय में १० रोगियों के लिए एक कुटिया बर्बाई जा रही है।

वेहातो में 'हुक बर्ब' को न फेंकने देने के लिए सात बसते-फिरते एकक कार्य करते हैं। जनता के सभी वर्गों से खूब सहयोग मिल रहा है।

स्वायत्त पहाड़ी जिलों, भाषिवासी क्षेत्रों तथा मैदानों में स्वास्थ्य सुधार योजनाओं को विकसित करना सरकार ने स्वीकार कर लिया है।

मौजूदा बवाखानों में सुधार किये जा रहे हैं तथा चलते-फिरते संपूर्ण विकसित बवाखाने प्रचार यूनिटों के साथ व्यवस्थित किये जा रहे हैं।

स्वास्थ्य-सुधार किस प्रकार किया जा सकता है, इस बात का प्रचार अनन्त तक प्रदर्शनों एवं मेलों के माध्यम से किया गया है। मलेरिया विरोधी योजना चलायी गयी तथा बड़े पैमाने पर बी० सी० जी के टीके लगाने का कार्य किया गया। १६२६८२ लोगों की प्रसूता की परीक्षा की गयी और ८६४४३ व्यक्तियों को टीके लगाये गये। देहातों में पांच नये शिक्षा कल्याण-गृह खोले गये। कई नये बाडों के बन जाने से तथा बाहर के लोगों के लिए बवाखाने की नयी हमारत बन जाने से भर्तों को बढ़ावा आवश्यक हो रहा है। इसलिए नई नर्सों को ट्रेनिंग देने की स्कीम बनाई गई है। शिक्षकों तथा साज-सज्जा की व्यवस्था धुनीसेफ करेगा। लोकल बोर्ड के पांच अध्यक्षताओं को नये नये खोजार, साज-सामान देकर उनका प्रातीयकरण किया गया। इसके अलावा वस प्रायुर्वेदीय बवाखाने तथा वस एलोपैथिक डिस्पेन्सरियां सरकारी सहायता से चलायी जा रही हैं।

बिहार

पटना अस्पताल का ‘दि राजेन्द्र सजिकल ब्लॉक’, जिसमें कि २५० पलेंग रहेंगे तथा जिसमें नये से नये सजिकल यूनिट रहेंगे और जो कि पूर्व में अर्द्ध-तीय होगा, लगभग पूरा हो रहा है। पटना में ही खूत की बीमारियों के लिए ५० पलेंगों वाला एक अस्पताल खोला गया है। पटना के शय सन्वाभी प्रदर्शन केन्द्र में दर्जनों को तपेथिक के बारे में जानकारी करायी जाती है। इसकी सीनीटोरियम में ४८ पलेंगों वाला शय का एक विभाग खोला गया। दूंगरी (रांची) स्थित रामकृष्ण मिशन टी० बी० सीनीटोरियम को सरकार ने २.२५ लाख रुपये देना स्वीकार कर लिया है।

कोसी और कपला क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुधार का कार्य उन्नत हुआ है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अस्पतालों को राज्य सरकार ने अपने हाम में से लिया है।

नये अस्पताल तथा स्वास्थ्य-केन्द्र खोले जा रहे हैं। सराय केला और खरसावन के अस्पताल अब बड़े पैमाने के कर दिये गये हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा यूनीस्को की सहायता से कई मातृ-गृहों तथा 'शिशु-गृहों' का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। राष्ट्रीय भलेरिया निरोधक कार्यक्रम कई कन्दूल यूनिटों के साथ शुरू हो गया है। घाट डीमें की प्रति-रिक्त सहायता के साथ बहुदृश्य में बी० सी० जी० के टीके भी लगाये गये हैं। कोढ़ को न बढ़ने देने के लिए पूर्वप्रयत्न किये गये हैं तथा छोटी माता या शूल को शय्य बीमारियों की रोकथाम के लिए भी किये गये प्रयत्न सुचारु रहे हैं।

बम्बई

पूना के अस्पताल में १०० पलंग और बढ़ा दिये गये लेकिन सन् १९५४-५५ में १०० पलंग और भी बढ़ा दिये जायेंगे। पूरे राज्य भर में बी० सी० जी० के टीके लगाये गये हैं। इसके अतिरिक्त पांच डीमें और 'मंजूर करवी' हैं। अस्पतालों तथा सामुदायिक संस्थाओं की सहायता, अनुदान प्राप्ति विधा ला रहा है। दक्षिण भाग में चलती-फिरती प्राग्मेलनिक यूनिट ने सन् १९५४-५५ के बीच अत्यन्त उपयोगी कार्य किये हैं जिसकी प्रानीयों ने बहुत सराहना की है।

पूना और महमदाबाद के मेडिकल कालेजों की इमारतें तैयार हो गई हैं तथा कालेज इन नयी इमारतों में चले गये हैं। सन् १९५४-५५ में इन कालेजों की प्रवेश संख्या १०० तक बढ़ा दी जायगी।

धोंय में १२५ पलंगों वाला शय अस्पताल खोला गया है। जब धन प्राप्त हो सकेगा तो पलंगों की संख्या ३०० कर दी जायगी। शय के दूसरे अस्पताल के लिए स्थान अभी विचारधीन है।

केडगांव में कुष्ठरोगियों की बस्ती की स्थापना के लिए सन् १९५४-५५ के बजट में १४४००० रुपये की व्यवस्था रखी गयी है।

३ जून सन् १९५३ को राज्य-ध्यापी मलेरिया निरोध कार्यक्रम का कार्य प्रारम्भ किया गया। २७००० ग्रामों के लगभग ३५ लाख घरों में दो-दो बार डी० डी० डी० छिड़का गया।

चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य की कुल २३ यूनिटें राज्य में कार्य कर रही हैं। सुझर बेहताओं में ये मातृ-गृह, शिशु-गृह की सेवाएं भी प्रस्तुत करते हैं।

मध्य प्रदेश

नागपुर मेडिकल कॉलेज भवन का उद्घाटन राज्यपति डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद ■ कर-कमलों से २० मार्च १९५३ को हुआ। कॉलेज से संलग्न इस अस्पताल में ६४० पल्लों का प्रभाव है जो कि प्राथमिक प्रकार के वास्तु, रंग तथा साज-सज्जा से युक्त है, साथ ही ‘एन्त-रे’ का बहुत बड़ा रंग भी है।

नागपुर स्थित प्रायुर्वेदीय स्कूल के विकास के साथ एक प्रायुर्वेदीय फार्मसी स्थापित की गयी है और १९१ सरकारी सहायता-प्राप्त तथा १५३ बिना सहायता प्राप्त प्रायुर्वेदीय दवाखाने चालू किये जा चुके हैं। अकोला, निमाड तथा बिलासपुर के अस्पतालों को अब बड़ा कर उनका प्राप्तीयकरण कर दिया गया है।

छिंदवाड़ा में १०० पल्लों का भव्य का एक अस्पताल खोला गया है जिसके ५० पल्ले गरीबों के लिए ही सुरक्षित रखे गये हैं। दुसडाना में २५ पल्लों का भव्य का दूसरा अस्पताल निर्मित हो रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य के मध्य दूसरे अस्पतालों में २१२ पल्लों का प्रभाव और भी किया गया है।

नागपुर, जबलपुर और छिंदवाड़ा की इन तीन बी० सी० जी० की टीमें के अतिरिक्त रायपुर, बिलासपुर और बुरी की टीमें ने भी अत्यन्त उपयोगी कार्य किये। करवरी १९५३ में बी० सी० जी० के डीके लगाने का काम बृहत्-क्रम में प्रारम्भ किया गया।

मद्रास

राष्ट्रीय मलेरिया-निरोध कार्यक्रम के अनुसार राज्य को दो कन्दौल यूनिटों की सहायता मिली। सरकार द्वारा ५४ ऐन्टी फाइलेरिया योजनाओं के लिए भी ग्रांट मिली है।

सामूहिक विकास योजना के कार्यक्रमों के शिक्षण के हेतु एक प्रशिक्ष भारतीय शिक्षण-केन्द्र स्थापित किया गया। उक्त केन्द्र में वेहालों की सफाई तथा ग्राम सेवा की बातों की शिक्षा दी जाती है। इस केन्द्र की स्थापना फोर्ब प्रतिष्ठान की सहायता से हुई है।

म्युनिसिपैलिटी के छाठ क्षेत्रों में जल-वितरण की नयी स्कीमों को कार्यान्वित किया जा रहा है तथा १२ क्षेत्रों में सुधार किये जा रहे हैं। वेहालों में जल-वितरण-कार्य २५०० कूर्ए बनाने से पूरा होगा, और ये कूर्ए आगामी तीन वर्षों में बनाए जाएंगे।

इस वर्ष मद्रास जनरल अस्पताल में अथनी शरीर मनायी। जनरल अस्पताल की वर्तमान चार सर्जिकल एवं मेडिकल यूनिटों की संख्या में एक की और वृद्धि कर दी आगामी।

कैंसर के रोगियों के परीक्षणों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। शय के अस्पताल भी तंजौर जिले के सांगीपती बक्षिण कण्ड के मुडेपोट्टे और मलाबार के पेरीयारम में खोल दिये गये हैं।

मद्रास के सरकारी महिला एवं शिशु अस्पताल का प्रजनन विज्ञान विभाग, स्टेनली मेडिकल कालेज का शरीर रचना-विभाग और जनरल अस्पताल के धीन-व्याधि विभाग के स्तर ऊँचे कर दिये गये हैं जिससे वे स्नातकोत्तर शिक्षण के लिए प्रशिक्ष भारतीय केन्द्र बन सकें। सफाई तथा जन-स्वास्थ्य की उचित शिक्षा दी जा सके इसके लिए मद्रास मेडिकल कालेज में एक नया हाइजीन ब्लॉक खोला गया है। निकट भविष्य में ही मदुराई में भी एक मेडिकल कालेज खोलने का विचार है।

उड़ीसा

मलेरिया निरोध के लिए अत्यन्त सतर्कता बरती गयी और राज्य के मलेरिया क्षेत्रों पर २३३२०० रुपये व्यय किये गये १४०००० रुपये फाइलेरिया के रोगियों पर व्यय किये गये ।

क्षय की रोकथाम के हेतु बी० सी० जी० का कार्य शक किया गया और १९११४२ रुपये व्यय किये गये ।

“कुष्ठमार्गदर्शक योजना” के अन्तर्गत कुष्ठ-सुधार के लिए २२१८८४ रुपये खर्च किये गये ।

सिद्धेश्वर, अस्तुर, बहया, नबुनी और प्रीतिपुर में नये दवाखाने खोले गये । कटक के श्रीराम चौधरी भंज मेडिकल कालेज अस्पताल में १४ पर्जन और बढ़ा दिये गये ।

घेनकमाल की भुवन डिस्पेन्सरी में आठ पर्जन और बढ़ाकर उसे अस्पताल में परिणत कर दिया गया है । भुवनेश्वर में प्रसूतिगृह को बढ़ाकर प्रसूतिगृह एवं शिशु रक्षण केन्द्र कर दिया गया है, तथा कटक जिले के हम्बुपुर में एक नया प्रसूतिगृह खोला गया है ।

कटक के एस० सी० बी० मेडिकल कालेज का स्तर एम० बी० बी० एस० कालेज का कर दिया गया है तथा उसे उत्कल निवचनिकालय तथा मेडिकल कॉलेज आफ इंजिनिरी नाम्यता दे दी है ।

बहुरामपुर के निडवाइकरी ट्रेनिंग स्कूल का स्तर उच्च कर दिया गया है तथा श्रुतियों की संख्या ८ से २० कर दी गयी है ।

बाल्यों की शिक्षण-योजना तथा सरकारी सहायता प्राप्त प्रसूति-गृहों की स्थापना-योजनाएँ स्वीकृत कर ली गयी हैं ।

साल्वो धर्म

अन्ध-रोगियों को ३००० रुपये तक की आर्थिक सहायता दी गयी है।

'अन्धेपन की रोक' पर भावरुणों के लिए सन् १९५३-५४ में १३५० रुपये का वार्षिक व्यय तीन वर्ष तक के लिए स्वीकार किया गया है। ये भावरुण हाई स्कूलों तथा मेडिकल स्कूलों में बिसे आ रहे हैं।

देहात के लिफकों की सहायता से पुरी में ६१० रुपये के व्यय में औषधि-पेट्रिया के पांच केन्द्र स्थापित किये गये हैं।

पंजाब

जुलाई १९५३ में राज्य के १३ जिलों में ६ जिलों में १४ लाख लोगों को मलेरिया से बचाने का आवश्यक कार्य किया गया। इस कार्य की वृद्धि के लिए चालू वर्ष में मलेरिया दूनिवों की संख्या ७ कर दी गयी। १०७६९० लोगों की परीक्षा की गयी तथा ३३६६६ व्यक्तियों को बी० सी० जी० के टोके लगाये गये।

फांगडा जिले में 'गाइटर' की रोकथाम तथा बचाई के लिए 'सायोबाइक साइड्स' का एक बहुत बड़ा कारखाना स्थापित किया गया। विश्व-स्वास्थ्य संगठन तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा भी सहायता प्रदान की जायेगी। नारी स्वास्थ्य निरीक्षिकाओं की कमी को दूर करने के लिए अमृतसर में एक शिक्षण-शाला प्रारम्भ की जा रही है।

सन् १९५३-५४ के बीच अस्पतालों और दवाखानों की संख्या ६११ पहुँच गई तथा पलंगों की संख्या ८३७६। कई अस्पताल आधुनिक किये जा रहे हैं तथा रोपड़, रोहतक, और सोनीपत के अस्पतालों को उच्चस्तरीय कर दिया गया है। दो लाख अतिरिक्त रुपये अस्पतालों की दवाइयों में लिए निर्धारित किये गये हैं।

२० आयुर्वेदीय तथा यूनानी औषधालय खोलने की योजना है तथा रोहतक जिले में एक आयुर्वेदीय महाविद्यालय भी स्थापित किया जायेगा।

कारखाने ■ ३५००० कर्मचारियों को कर्मचारियों की राज्य बीमा-योजना द्वारा लाभ दिया जाता है ।

उत्तर प्रदेश

राज्य सरकार ने देहातों में १ = एलोपैथी तथा १५ आयुर्वेदीय और भूतानी औषधालय खोलने की स्वीकृति दे दी है । बाइयों के प्रशिक्षण ■ लिए ६ केन्द्र स्थापित हो चुके हैं । ६५०० से अधिक गांवों में जिन्की आवादी ६३ लाख से अधिक है, मलेरिया निरोध का कार्य किया गया । प्रयाग के कुष्ठ मेले के अवसर पर, जिसमें कि देश के साफों लोग आये थे, चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्य विभाग की सतर्कता के कारण कोई भी संक्रामक रोग का आक्रमण न हो सका ।

पश्चिम बंगाल

बंगाल में स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक व्यक्ति पर २ रु० २ आ० १० पाई व्यय किया गया, जो कि भारत में सबसे अधिक है ।

राज्य के सब अस्पतालों के पलंगों की संख्या १०३३४ है तथा देहातों में भी दवा-वाक सहायता का प्रबन्ध है । अथ रोगियों के पलंग की १९४० की ६५६ की संख्या सन् १९४४ में २३३० कर दी गयी है । टी० बी० क्लीनिकों की संख्या १५ से २५ कर दी गयी है, प्रसूति के लिए ११०७ पलंगों से बढ़ा कर ३०६३ पलंग कर दिये गये हैं । कुष्ठ और गुप्त रोगों के रोगियों के पलंगों की सन् १९४७ की ७४४ तथा ५० की क्रमशः संख्या को ६३३ और ११० क्रमशः कर दिया गया है ।

मलेरिया निरोध कार्य तथा बी० सी० जी० योजना में संतोषजनक उत्पत्ति हुई है । देहातों में पीने के जल की वितरण-व्यवस्था कर दी गयी है । तथा २७५०६ बिजली के कुएं लगाये गये हैं । स्वास्थ्य सम्बन्धी बहुमुखी कार्य-क्षमता एवं सतर्कता के कारण सन् १९४३ में १०-३ मृत्यु-अनुपात रहा जब कि सन् १९४४ में वह १८.१ था ।

श्रम

आसाम

सन् १९२६ के भारतीय ट्रेड यूनियन कानून के अनुसार राज्य में १६ ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड किये गये तथा स्थायी श्रमिकों के २२ सेट सन् १९४६ के औद्योगिक नियोजन (स्थायी श्रमिक) कानून के अन्तर्गत प्रभावित किये गये। कारखानों के ६५ अगड़े शान्ति के साथ सुलझाये गये। ३२ अगड़े, जे, कि सुलझाये न जा सके, सन् १९४७ में औद्योगिक विवाद कानून के अनुसार निर्मित औद्योगिक श्रमिकों या ट्रिब्यूनलों को सौंपे गये।

चाय-बागानों को बेकारी में उतारना कठिन कार्य था। अन्य हो जाने वाले ६५ चाय बागानों में से ७४ में फिर से काम शुरू हुआ। इस लिए सन् १९४२ के ४८४३३ श्रमिकों में से ३५६८४ को फिर से काम दिया गया। शेष रहे श्रमिकों को या तो दूसरे चायबागानों में काम दिलवाया गया या फिर सड़क बनाने में लगा दिया गया या, दूसरे सार्वजनिक निर्माण-कार्यों में काम दिलवा दिया गया।

श्रमिकों के कल्याण के पश्चात् केन्द्र खोले गये तथा धीरे केन्द्रों की इमारतें लगभग तैयार हो गयी हैं।

औद्योगिक श्रमिक योजना के अन्तर्गत विभिन्न श्रमिक संस्थाओं को ६५००० रुपये कर्ज दिये गये जिसमें श्रमिकों के लिए मकान बनाये जा सकें। अभी तक ३६०९ मकान बन चुके हैं।

बिहार

राज्य के कारखानों की अल्प-स्थिति सन्तोषजनक रही। लीकड़ों अगड़े या तो मध्यस्थता के द्वारा तय किये गये या फिर सरकार द्वारा स्थापित समझौते संगठनों द्वारा मालिकों की बिहार औद्योगिक श्रमिक-योजना के अन्तर्गत कर्ज दिये गये। कर्ज की रकम पर ३ प्रतिशत व्याज लिया जायेगा तथा मूलधन २५

नर्चों में प्राप्त किया जाएगा। अब तक ४० लाख रुपये का कर्ज दिया जा चुका है।

सन् १९५४ में कर्मचारियों की राज्य बीमा योजना शुरू करने का विचार है। एक कारपोरेशन बनाया जाएगा जो कि क्षतिग्रस्त तथा सगातार चलने वाली फैक्ट्रियों में, जहाँ प्रतिदिन औसतम २० या अधिक व्यक्ति काम पर लगाये जाते हैं, काम करने वाले श्रमिकों को चिकित्सा और बीमारी सम्बन्धी सुविधायें, आश्रित सम्बन्धी लाभ, प्रसूति भत्ता और अपंगता के कारण मिलने वाली पैशानों को बिसवाने के लिए उत्तरवादी होगी।

अनुसूचित कारखानों में न्यूनतम वेतन निर्धारित कर दिया गया है। बाहुराज, गया और पटना जिलों में खेतिहर मजदूरों का भी न्यूनतम वेतन निर्धारित हो चुका है।

प्रमाणित मजदूर संघों की संख्या जो सन् १९४९-५० में ६१ थी, बढ़ कर सन् १९५२-५३ में ४१६ हो गयी है। चूंकि किसी विरोधी मजदूर संघ अपने को मजदूरों का प्रतिनिधि कहते हैं, इसलिए राज्य सरकार ने अम सत-हकार बोर्ड की सहमति से ही उनका प्रतिनिधि स्विकार करना तय किया है।

बम्बई

फरवरी १९५४ में समाप्त होने वाले पिछले ११ महीनों में सन् १९५२-१९५३ के मुकाबले में बम्बई, अहमदाबाद, कोलापुर और जलगांव के मजदूरों के जीवन-मापन के स्तर-संक क्रमशः २१, ११, १९ और २७ तक बढ़ गये हैं।

प्रमाणित कारखानों की संख्या ८,८१० है तथा प्रतिदिन कार्य करने वाले श्रमिकों की संख्या औसत ७,२७,६५३ है। सन् १९५३ में लगभग ३०,३६४ दुर्घटनाएँ घटीं।

सन् १९५३ के बम्बई के श्रम-कल्याण विधि कानून के अनुसार बम्बई श्रम कल्याण बोर्ड का निर्माण हुआ तथा राज्य सरकार द्वारा निर्मित सारे सुरक्षा केन्द्र जुलाई १९५३ में उस बोर्ड को सौंप दिये गये ।

ट्रेड-यूनियनों की संख्या १९५३-५४ में ७१९ से बढ़कर ८१२ हो गई है । अप्रैल १९५३ से फरवरी १९५४ के बीच ५२६ अगड़ों का निबटारा या तो बम्बई स्थित औद्योगिक अदालत द्वारा हुआ या फिर औद्योगिक ट्रिब्यूनल के द्वारा ।

सन् १९५३ में मंजूरी भुगतान (बम्बई संशोधन) कानून, बम्बई श्रम कल्याण विधि कानून, और बम्बई औद्योगिक सम्बन्ध (संशोधन) कानून जैसे कुछ महत्वपूर्ण कानून पास किये गये ।

मध्य प्रदेश

सूती मिलों के अधिकों द्वारा सन् १९५०-५१ और १९५१-५२ के लिए बीजल की मांग का मामला पंच-निर्णायक भेजा गया तथा निर्णय अधिकों ■■■ पक्ष में हुआ ।

दूसरे कारखानों में लेकर अफसरों ने ५५ अगड़े सुलझाये तथा ४०० अगड़ों की जाँच की । सन् १९५३-५४ में १७ मजदूर संघ प्रमाणित ■■■ ।

दूकान संस्थान कानून के अन्तर्गत, जो राज्य के २२ नगरों में लागू था, ८,०६६ रेजिस्ट्रेशन और नवीकरण ■■■ । इस वर्ष ४३४ मासिकों पर मुकदमे चलाये गये जिनमें से २६५ को सजा तथा जुर्माना हुआ ।

अनेक कारखानों में सुरक्षा योजना प्रारम्भ की गयी तथा बजनेरा और हिंगमवाट में सुरक्षा केन्द्र खोले गये । नागपुर, जबलपुर और अकोला में राज्य सरकार ने तीन सुरक्षा केन्द्र खोले । अधिकों को श्रम कानून तथा मजदूर संगठन की गतिविधियों से अवगत कराने के लिये सरकार ने नागपुर में एक शिक्षण-केन्द्र प्रारम्भ किया है । ६५ अधिकों में से ६ महिलाएँ भी इस केन्द्र में प्रविष्ट हुई हैं ।

भारत सरकार द्वारा स्वीकृत योजना के अनुरूप ‘राज्य आवास बोर्ड’ अधिकों के लिये जबलपुर में १०० क्वार्टर बन चुके हैं तथा नागपुर में ४५० क्वार्टर पूरे होने की हैं। जबलपुर में ५० क्वार्टरों का निर्माण प्रारम्भ हो चुका है।

मद्रास

अविभाजित मद्रास राज्य में आर्थिक वर्ष के प्रारम्भ में ७,५२९ कारखाने कंठरी कानून के अन्तर्गत आये। अवशिष्ट मद्रास राज्य में मार्च १९५४ में कारखानों की संख्या ६,६०७ थी। सन् १९५३ की जनवरी से अगस्त तक अविभाजित मद्रास सरकार के अन्न विभाग द्वारा ५,७१५ अगड़ों की जांच की गयी। अवशिष्ट मद्रास राज्य द्वारा सन् १९५३ अक्टूबर और नवम्बर में धर्म से १,०६३ पर निरुध्न लिये गये।

अविभाजित मद्रास राज्य में ७२० मजदूर संगठन थे। अवशिष्ट मद्रास राज्य में अन्न संगठनों की कुल संख्या ५५४ है। कर्मचारियों को राज्य बीमा योजना का एक प्रादेशिक कार्यालय कोयम्बटूर में स्थापित कर दिया गया है जो कि अपने आस पास के क्षेत्रों में भी कार्य करता है। शीघ्र उसका कार्य-वृत्त दूसरे कारखानों तक कर दिया जायगा।

उड़ीसा

सन् १९५३ का औद्योगिक विवाद (संशोधन) कानून तथा सन् १९५३ का उड़ीसा प्रसूति सुविधा कानून स्वीकृत हो गये हैं। पहला कानून तो उन अधिकों के लिये है जो या तो काम से हटा या अलग कर दिये जाते हैं, तथा दूसरा महिला अधिकों को प्रसूति भत्ता के देने के लिये है। चावल, धागा, बाल की मिलों, तम्बाकू के निर्यातियों तथा मोटर सवित्तों अधिकों का न्यूनतम वेतन निर्धारित कर दिया गया है।

एक अन्न सहायकार बोर्ड बना दिया गया है जो अन्न सम्बन्धी समस्याओं पर विचार कर सके।

१२ नये मजदूर संगठन प्रमाणित हुए हैं तथा इस प्रकार उनकी कुल -

सातवाँ वर्ष

संख्या ८१ हो गई है। भांडवली, बालासोर, कपता तथा भरमुगुडा में चार कल्याण केन्द्र स्थापित हुए हैं।

सरकारी सहायता प्राप्त छात्रावास योजना के अन्तर्गत राज्यसरकार से सेसर्स उड़ीसा सोमेट लिमिटेड, सेसर्स उड़ीसा टेक्सटाइल मिल लिमिटेड, सेसर्स जयपुर झुगर कम्पनी लिमिटेड और सेसर्स डान एण्ड कम्पनी ने सहायता के लिए प्रार्थना की है।

कुल छः कारखानों ने कर्मचारियों की राज्य बीमा योजना से लाभ उठाया है।

हीराकुड बांध योजना के तैयार हो जाने के बाद प्रवाह की जाती है कि मककुंड पन-बिजली योजना तथा हरकोसा का "हिन्दुस्तान स्टील प्लांट" आदि कई औद्योगिक छोटे-बड़े केन्द्र बनयेंगे।

सन् १९५३-५४ में ४१२ कुर्घटनाएँ हुईं। इनकी जांच पड़ताल हुई तथा भविष्य में इस प्रकार की कुर्घटनाएँ कम हों इसके लिये सतर्कता बरती गयी एवं कार्यवाही भी की गयी। गंभी गडरों, पीकबानों, धौबालनों, भूभामयों, बिजली तथा बीने के जल के वितरण आदि की आवश्यकता पर और जाला गया तथा कुछ विचारों में प्रभावकारी उन्नति हुई।

पंजाब

भूमिकों के लिए एक कमरे वाले मकानों की योजना कार्यान्वित की गयी। समुत्तर में ऐसे २०० मकान निर्मित हुए तथा शीघ्र ही १०० और बनाये जायेंगे। इस योजना के अनुसार जलन्धर में १००, लुधियाने में १२४, बटाला में ५० तथा झरमुल्तापुर में १०० मकान बनेंगे।

औद्योगिक महत्व के अनेक स्थानों पर अन्न विभाग कल्याण केन्द्र चला रहा है। समुत्तर, बटाला, लुधियाना, जलन्धर, झरमुल्ता छाबनी, झरमुल्तापुर और बालमपुर में ये केन्द्र स्थित हैं। भूमिकों को तथा उनके परिवारों को ये कल्याण केन्द्र शिक्षा एवं मनोरंजन दोनों के साधन प्रस्तुत करते हैं।

२६ भाग

पंजाब के साथ बांग्ला तथा चाय फैक्टरियों में काम करने वाले श्रमिकों को भी ये केन्द्र शिक्षा के साधन प्रस्तुत करते हैं।

उत्तर प्रदेश

सूचनात्मक वेतन कानून कृषि सम्बन्धी कार्यों पर लागू किया जायगा तथा उन लोगों तथा फार्मों पर भी जहाँ कम वेतन है और जो फार्म ५० एकड़ के या अधिक के हैं।

कुल २,७७६ मकान श्रमिकों के लिए बनाये गये हैं जिनमें से २,२१६ कानपुर में और ५६० लखनऊ में बने हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा स्थानिक विकास बोर्ड की ओर से कानपुर में २,७५० आवास बनाये जा रहे हैं। ७,४०० आवासों के निर्माण का कार्य शीघ्र प्रारम्भ होगा जिनमें से ३,४०० कानपुर में बनेंगे और शेष आगरा, बनारस, इलाहाबाद, कीर्तिबाबा, मिर्जापुर और सहारनपुर में बनेंगे। कानपुर की रबी बस्ती मकान की बाढ़वी और ५,००० आवास उस स्थान पर बनेंगे।

कर्मचारियों की राक्ष बीमा योजना के अन्तर्गत २,४०० अस्थायी ग्राम्य श्रमिकों के अधिकारपत्र प्राप्त हैं और सन् १९५४ के प्रारम्भिक तीन माहों में २,१०० से अधिक श्रमिकों को पैसा दिया गया। बीमारी को सुविधा सम्बन्ध में ४२,४०० अधिकार पत्रों से भी अधिक प्राप्ति और लगभग १,६४,००० व्ययित व्ययताएँ गयीं।

कानपुर की दो नयी श्रमिक बस्तियों में दो नये कल्याण केन्द्र खोले गये। लखनऊ के ऐशबाग स्थित गवर्नमेंट प्रेस में काम करने वाले ३०० श्रमिकों के लिए एक कल्याण केन्द्र वहाँ भी खोलने का विचार है।

पश्चिम बंगाल

विभिन्न स्थानों पर २७ कल्याणकेन्द्र हैं जो कि श्रमिकों द्वारा प्रस्तुत मनोरंजन में सहायता करते हैं। इनमें १२ केन्द्रों के साथ छोटे अस्पताल व्यवस्था के लिए जुड़े हुए हैं।

सन् १९५२ के कर्मचारियों के प्राविष्टकण्ड कानून तथा सन् १९४७ के कर्मचारियों के राज्य बीमा कानून को कार्यान्वित करने के लिए प्रादेशिक कार्यालय खोले गये हैं ।

उद्योग-धंधे

भासाम

कुटीर और घरेलू उद्योग-धंधों के लिए अलग एक विभाग बना दिया गया है । ५०,००० रुपये तक का अनुदान एवं सहायता उद्योग धंधों के पाँच स्कूलों को दी गई है ताकि वे कारीगरों को काम सिखा सकें । १,२६,६०० रुपये का कर्ज देना स्वीकार कर लिया गया है जिसमें वर्तमान कुटीर-उद्योग-केन्द्रों को उन्नत किया जा सके और कुछ नये केन्द्र स्थापित किये जा सकें । सन् १९५४-५५ में २ लाख रुपये इस प्रकार के कर्ज के लिए सुरक्षित हैं ।

रेलम और करवा उद्योग भासाम के प्रमुख कुटीर उद्योग हैं । सरकार इन दोनों को उन्नत तथा व्यापक करने के लिए कार्य कर रही है । करवा उद्योग में लकड़ और अम की बचत के लिये यंत्रों का प्रयोग कर रही है । इसके शिक्षण तथा उत्पादन की विक्री के लिए भी सहायता दी जा रही है । रेलम के कीड़ों के पराज, रेलम के अमों को सह कामे तथा कलाई के सम्बन्ध में प्रदर्शन किये जा रहे हैं, साथ ही विभाग इसके शिक्षण का भी आयोजन कर रहा है । बीटाबर में 'लेरीकल्चर' के सम्बन्ध में शोध-कार्य के लिए एक केन्द्र खोला गया है जिसकी लागत १,३०,००० रुपये होगी जिसे केन्द्रीय रेलम बोर्ड और राज्य सरकार बराबर-बराबर धन देगी ।

केन्द्रीय रेलम बोर्ड ने विभिन्न योजनाओं के विकास के लिए २,१५,००० रुपये का अतिरिक्त अनुदान देना स्वीकार किया है ।

बिहार

बिहार के कुटीर उद्योग के उत्थान के लिए राज्य सरकार ने एक ध्याये-वायी योजना बनायी है। एक राज्य-वित्त-कारपोरेशन की २ करोड़ रुपये से स्थापना का निर्णय हुआ जिसमें छोटे बड़े उद्योगों की सहायता की जा सके।

कुटीर उद्योगों को कार्य दिया जा सके इसके लिए ४ लाख रुपये स्वीकार किये गये हैं। सरकार ने १ लाख रुपये सहायता के रूप में दिया है।

राज्य में गन्ना बोने वाले चार लाख किसान हैं और वस हजार के लग-भग शक्कर के कारखानों के श्रमिक हैं। गन्ने की किस्म को अच्छा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। गन्ने वाले क्षेत्रों में ३०० विजली के कुएं लगाये जायेंगे जिसमें से १८७ लगा दिये गये हैं। पूसा में शक्कर से सम्बन्धित शोध-कार्य के लिए एक प्रमुख कार्यालय तथा पटना में उप-कार्यालय सरकार द्वारा खोले गये हैं।

गन्ना पैदा करने वालों को उनकी अपनी सहकारी संस्थाओं द्वारा गन्ने की किस्म को अच्छी बनाने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

गन्ने की खेती का क्षेत्रफल सन् १९४६-४७ के ३.९५ लाख एकड़ से बढ़कर सन् १९५२-५३ में ४.०१ लाख एकड़ हो गया। १९४६-४७ में ४०.३६ लाख मन के मुकाबले लगभग ७४.३३ लाख मन धोनी सन् १९५२-५३ में तैयार की गयी।

बम्बई

अगस्त १९५३ से अप्रैल १९५४ तक विभिन्न प्रकार के उद्योग-धंधों को १,२६,००० रुपये कर्ज के रूप में दिये गये। विसम्बर सन् १९५३ में बम्बई राज्य वित्तीय कारपोरेशन की स्थापना के बाद १०,००० रुपये से अधिक की मांग वाले प्रार्थना-पत्र कारपोरेशन के पास भेजे जाते हैं।

सालाई वर्ष

केन्द्रीय स्टीर लरीड संगठन बराबर स्थायी तथा कुटीर उद्योग के भाग की क्य करके प्रोत्साहित करता है ।

जून १९५३ के अन्त तक कुटीर उद्योगों की १,३०७ प्राथमिक सहकारी संस्थाएँ थीं तथा १८ जिला औद्योगिक सहकारी एंजोसियेट्स थे । इन संस्थाओं की सम्मेलन संख्या सन् १९५७ में ४०,०४५ ■ अत्र १,४७, ७०४ हो गयी है ।

मध्य प्रदेश

राज्य की औद्योगिक उन्नति में 'अलारपुर मेयर एण्ड स्ट्रा बोर्ड मिल्स' का २१ नवम्बर १९५३ में खुलना एक महत्वपूर्ण घटना है । मिल की वार्षिक उत्पादन शक्ति ७,५०० टन कापण की है । भारत की सर्वप्रथम जलबारी कापण मिल 'नेपाल' का निर्माण कार्य अब समाप्ति पर है । इसकी उत्पादन-शक्ति १०० टन स्पूक थिन्ट प्रतिदिन होगी ।

मद्रास

मद्रास शहर में तथा उसके पास के क्षेत्र में अनेक उद्योग-यंत्रे धन्य रहे हैं । मोटर और ट्रक निर्माण के लिए दो कारखाने तथा एक कारखाना साइकिलों के लिए मद्रास में स्थापित ■ हैं । लिक्मैसबेली में प्रतिदिन ५ टन कास्टिक सोडा बनाने वाला एक कारखाना खुला है । मद्रास के निकट ही श्रीपी. के लिए भारी मशीनें बनाने तथा सीमेन्ट ग्रानि दूसरे कारखानों के निर्माण के लिए कारखाने खुले हैं ।

वजिरा अरकाट जिले के नेवेली में लिगमाइड पड़ताल योजना में सच्ची सम्मति की है । चतुर्थ त्रिभु कार्यक्रम के अनुसार एक अमेरिकन विशेषज्ञ की सेवाएँ ली गयी हैं ।

कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए निगारे वाली श्रमियों तथा रंगीन साइडों को बनाने का काम एक बम करधों के लिए ही छोड़ दिया गया है । सन् १९५२ की उत्पादन संख्या का ६० प्रतिशत ही भोती बनानेवाली मिल्सों को भोती बनाने ■ लिए रखा गया है । 'हेण्डलूम सेस फण्ड' से ६८,३८, ६७७ रुपये करवा उद्योग के लिए दिया गया है ।

नानुवसन की सरकारी कुर्मेन फैक्टरी में सन् १९५३-५४ में २०,००० पीण्ड विनानाइन सलफेट बनायी गयी थी। कोयम्बटूर जिले के अनमलाइ में भुखरी कुर्मेन फैक्टरी बनायी जा रही है। उसके बन जाने पर राज्य में सलफेट का उत्पादन १ लाख पीण्ड हो जायेगा।

उड़ीसा

सन् १९५३-५४ में स्थापित बृहत् कारखाने में श्री बुर्मा ग्लास वर्क्स लिमिटेड’ उल्लेखनीय है जो कि ७०० टन शीशे के बर्तन और बोतलें बनाती है। ‘कलिंग इयूब्स लिमिटेड’ स्टील पाइप का निर्माण करती है। ‘अम्बपुर मैमनीज सिंडीकेट’ द्वारा एक ‘फ़ेरो मैंगनीज प्लांट’ स्थापित किया जायेगा।

ब्रजराजनगर में ‘दि ओरिएण्ट पेपर मिल्स लिमिटेड’ तथा बालगंगपुर में ‘उड़ीसा सोमेन्ट लिमिटेड’ कारखाने खोलने के प्रयास किये जा रहे हैं।

‘कलिंग इयूब्स लिमिटेड,’ ‘बी डीटागढ़ पेपर मिल्स कम्पनी,’ ‘दि नेशनल फाउण्ड्री एण्ड रोलिंग मिल्स’ आदि बड़े कारखानों में अच्छी प्रगति हुई है।

पहले के देवी राजाओं के शासन काल के कारखाने जो कि सभी बन्द कर दिये गये थे, अब फिर खोले जा रहे हैं। ये ‘भयूरभंज ग्लास वर्क्स लिमिटेड’ और ‘भयूरभंज स्प्रिंग वीविंग मिल्स लिमिटेड’ आदि हैं।

छोटे कुटीर उद्योग-धंधों के विकास के लिए कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना की जा चुकी है। अनेक नयी योजनाएं इन उद्योगों के लिए बनायी गयी हैं जैसे बुनाई, बर्तनगिरी, लुहारी, तासे बनाना, कटलरी का सामान तथा साइकिल ■ पुर्जे आदि। छटाईयां बनाना, कुम्हारों, घमड़े का काम, भधुमक्खी-पालन आदि धंधों के लिए भी योजनाएं बनायी गयी हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा १० लाख रुपये तक की सहायता से कटक स्थित ‘उड़ीसा स्कूल आफ इंजीनियरिंग’ का स्तर उच्च बनाया जाने का विचार है तथा उसमें ‘ग्राल इंडिया सर्टिफिकेट कोर्स’ भी होगा। ४० सरकारी सुविधा प्राप्त तथा २२ सामान्य विद्यार्थी राज्य के बाहर टेक्निक शिक्षण के लिए भेजे गये। २६ विद्यार्थियों को

सप्तवीं वर्ष

विना ध्यान के कर्ज दिया गया जिससे वे भारत में या विदेश में शिथिल होकर भागें।

टेक्नीकल व्यक्तियों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पशु चिकित्सा विभाग के २१ छात्र और कृषि विभाग के ४ छात्र टेक्नीकल शिक्षा के लिए कर्ज के रूप में वृत्तियाँ देकर भेजे गये।

कारखानों को १० लाख रुपये सरकारी सहायता के रूप में दिये गये।

पंजाब

कारखानों की संख्या १,७०० से बढ़कर १,९०० हुई। हिसार में रई की कसाई के लिए बो मिलें तथा करीबाबाद में साइकिलों के लिए एक फैक्टरी के लिए भारत सरकार ने प्रमाणपत्र दे दिये हैं। टेक्नीकल शिक्षण के लिए औद्योगिक स्कूल तथा इंस्टीट्यूट्स खोले गये। सन् १९५३-५४ के बीच कुल ९६५ छात्र और १,१३७ छात्राएँ शिक्षा ले रही हैं, ४३६ ये छात्र इसमें शामिल नहीं हैं जो प्रदर्शन-पार्टियों में हैं।

१६ महत्वपूर्ण स्थानों पर दस्तकारी, घरेलू उद्योग धंध आदि सिखाने वाले केंद्रों में वारंवारियों की कार्य सिखाया जा रहा है। इन केंद्रों में अब तक १,११५ व्यक्तियों ने शिक्षा प्राप्त की। राज्य के १४ कार्ज केंद्रों में १८, ५६, ६८२ रुपये का सामान तैयार किया गया।

१,३७,५०० रुपये कर्ज के रूप में तथा ३८,७९० सरकारी सहायता के रूप में कुडीर तथा करघा उद्योग को दिये गये। सामूहिक विकास योजना के अन्तर्गत ९,२०,००० रुपये कर्ज रूप में दिये गये। करघा उद्योग की समस्याओं से सरकार को अवगत कराने के लिए एक बोर्ड की सभी सभी स्थापना की गयी है।

उत्तर प्रदेश

कुटीर उद्योगों के डाइरेक्टर ने तय किया है कि शिथिल बेकार युवकों को कुडीर उद्योगों के सम्बन्ध में ट्रेनिंग दी जाये और इस सम्बन्ध में कई योजनाएं बनायी हैं। लखनऊ में सिसाई का एक केन्द्र स्थापित किया गया है।

अन्य शिक्षण योजनाएँ लखनऊ के व्यावसायिक संस्थान तथा कानपुर के सरकारी टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट में चल रही हैं।

छोटे कुटीर उद्योगों की सहायता के लिए कम तथा अधिक श्रमिक वाले कर्षे करने के लिए एक औद्योगिक वित्त कारपोरेशन की स्थापना की जायेगी। ५० उत्पादन-केन्द्र खोलने का विचार है जिनमें से ४० नए काम करना शुरू कर दिया है। कुटीर उद्योगों के प्रोत्साहन ■ लिए सहकारी संस्थाएं बनायी जा रही हैं।

कमड़ा कमाले और मृत पशुओं की खाल आदि का उपयोग करने के वर्तमान छः केन्द्रों के अतिरिक्त नौ केन्द्र और खोलने का निर्णय लिया गया है। ये केन्द्र उद्योग का विकास कुटीर उद्योग के रूप में करेंगे।

इस वर्ष के मध्य तक सरकारी सीमेंट फैक्टरी अपना कार्य प्रारम्भ कर देगी।

पहाड़ों में अनेक छोटे-छोटे पन-बिजली केन्द्र खोले जा रहे हैं। टनकपुर और रामनगर में बिजली आ गयी है तथा ज्योलीकोट, गछड़ और बागेश्वर में भी निकट भविष्य में बिजली आ जायेगी।

पश्चिम बंगाल

सन् १९५४ की मार्च तक लगभग १२,००० व्यक्तियों को छाता बनाना, वर्तन बनाना, साबुन बनाना, डेनरी, बुनाई, रेशम उद्योग आदि की शिक्षा दी जा चुकी है। मधुमक्खी पालन, तथा चट्टाई बनाना आदि का काम भी हाथ में लिया गया है।

जून १९५३ में औद्योगिक सहकारी समितियों की संख्या ६०० तथा सदस्य संख्या ७६,७०१ थी। उनको चालू पूंजी २७.६८ लाख रुपये की और माल की बिक्री से उन्हें २१.८ लाख रुपये की प्राप्ति हुई। आठ रेशम पालन केन्द्रों और २३ समितियों में ८०० व्यक्ति कार्य करते हैं।

जनक के मामले में राज्य आत्म-निर्भर हो सके, इसके लिये सरकार

द्वारा कोनवाई के समुद्र-तट पर नमक का बहुत बड़ा कारखाना खोला जाने वाला है ।

पुनर्वास

आसाम

२,४०,००० विस्थापितों में से लगभग १,५५,००० व्यक्तियों को सन् १९५३ के अन्त तक पुनः बसा दिया गया तथा एक लाख के लगभग विस्थापित स्वयं बस गये ।

१५०० के लगभग पीड़ित महिलाओं तथा बच्चों के लासन-पालन का भार स्थायी तौर से सरकार ने अपने कंधों पर ले लिया है । इनके लिए तीन भवन निर्मित किये जाने का विचार है । एक तो मीनाच में तथा दो कछार जिले में । उनकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति की जायेगी जिसमें बच्चों की शिक्षा तथा कला और दस्तकारी का शिक्षण भी है । इसके द्वारा वे स्वावलम्बी होकर आत्म-निर्भर तो हो ही जायेंगे, साथ ही वे समाज के उपयोगी सदस्यों की भाँति भी रह सकेंगे ।

आर्थिक अनुदानों के अलावा छात्रवृत्ति तथा पुस्तकों के लिए भी आर्थिक सहायता दी गई है ।

बाग बागानों की बढ़ती भूमि को सरकार ने ६,००० विस्थापित परिवारों को पुनः बसाने के लिए ले लिया है ।

१,२०० विस्थापित परिवारों के लिए गृह-निर्माण की योजना बस रही है । अगस्त १९५३ से दिसम्बर १९५३ के बीच में १,१७५ किसान परिवारों को तथा १,६५४ गैर किसान परिवारों को कर्ज दिया गया ।

बिहार

राज्य में विस्थापितों की कुल संख्या ८६ हजार है। पश्चिम पाकिस्तान से श्रापे हुए विस्थापितों को पुनः बसा दिया गया है। उन्हें मकानों, गूमटियों तथा बूकानों के साथ कर्ज भी किया गया है।

पूर्वी पाकिस्तान से आए हुए ५०,००० विस्थापितों में से ३८,७०५ पुनः बसा दिये गये हैं। पूर्णिया जिले के १६ ग्रामों में पूर्वो पाकिस्तान से आये विस्थापितों को बसा दिया गया है। रांची और पूर्णिया में विधवाओं, अनाथों तथा अपंगों के लिए आश्रम खोले गये हैं। सन् १९५२-५३ तक पुनर्वास योजना पर २ करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं।

बम्बई

उल्हास नगर, झारवा नगर तथा वालिडवाड़े में विधवाओं, अनाथों एवं अपंगों के लिए आश्रम खोले गये हैं। इनमें रहने वालों को उनकी रुखि एवं गति के अनुसार ही वस्तुकारी का काम सिखाया जायेगा।

राजकीय गृह-निर्माण योजना के कार्य में संतोषजनक प्रगति रही है। सन् १९५२-५३ के अंत तक गृह-निर्माण योजना पर ६.१२ करोड़ रुपये (जिनमें सहकारी संस्थाओं का कर्ज भी सम्मिलित है) व्यय किये जा चुके हैं।

सन् १९५२-५३ के अंत तक कल्याण तथा अहमदाबाद के वस्तुकारी शिक्षण केंद्रों में लगभग ४,००० विस्थापितों को शिक्षण दिया जा चुका है।

खेतिहरों को अस्तियों की योजना के अंतर्गत १,४०० परिवार अभी तक बसाये जा चुके हैं। व्यवसाय या व्यापार के हस्तक्षर विस्थापितों के लिए भारत सरकार ने ७ लाख रुपये कर्ज के रूप में देना स्वीकार कर लिया है।

प्रारम्भिक, माध्यमिक स्कूलों तथा कालेजों में पढ़ने वाले विस्थापित छात्रों को छात्रवृत्ति, आर्थिक अनुदान एवं कर्ज आदि की सहायता की गयी है। सन् १९५३-५४ में यह ६ लाख रुपये की थी।

मध्य-प्रदेश

लगभग ४०६ विस्थापितों को राज्य की सहायता प्राप्त हुई। इस संख्या में विधवाएँ, परिवारहीन स्त्रियाँ तथा उनके बच्चे, अनाथ, नुद्ध आदि हैं।

कटनो, रामपुर, चकराभाटा, और डिंडा में इनके लिए बस्तियाँ बनाने की योजना तैयार हो गयी है। विस्थापितों को दुकानें बनाने के लिए कर्ज दिया गया है साथ ही उन्हें नये मकानों में अस्थायी आवासों में तथा किराये के मकानों में आवास सुविधाएँ दी गयी हैं।

पंजाब

सरकार न उन विस्थापितों के लिए एक योजना अनुमोदन देने के लिए बनायी है जिसकी सम्पत्ति पाकिस्तान में थी।

चंडीगढ़ तथा दूसरे स्थानों पर गृहनिर्माण के लिए सरकार ने ६५ लाख का कर्ज विस्थापितों को देना स्वीकार किया है। कम ब्याज के लोगों को स्थान-स्थान पर सस्ते मकानों की सुविधाएँ मिलें, इसके लिये भी योजना तैयार है। इस प्रकार के २,२०० मकान बन रहे हैं तथा २,००० मकानों की बनाने के लिए स्कीम तैयार हो रही है। लगभग १२,००० मिट्टी की ओपिडियाँ, उनमें रहने वालों को स्थायी रूप से दे दी गयी हैं। रोहतक में एक ब्रमाज मंडी तैयार हो गयी है तथा बजाजकाने का निर्माण शप्त रहा है। अमृतसर, पठानकोट तथा लुधियाने में दुकान के लिए नये-नये स्थान दिये गये हैं।

नीलोसेड़ी की 'पुनर्वास बस्ती' भारत सरकार के हाथों से अब पंजाब सरकार के हाथों में आ गयी है।

भूमि-बाँटने का कार्य पंजाब में पूरा हो गया है तथा प्रमिकाश लोग बस गये हैं।

उत्तर प्रदेश

मैनीताल जिले में खमुर के नई बस्तियों वाले क्षेत्र में पूर्वी पाकिस्तान

से साथे हुए २६७ परिवार इस वर्ष बसाये गये। इन परिवारों को आवास सुविधा, खेती के लिए प्रतिव्यक्ति आठ एकड़ भूमि तथा खेतों के औजार आदि खरीदने के लिए आर्थिक सहायता दी गयी है।

पूर्वी पाकिस्तान से आयी हुई महिलाओं को, जिन्होंने दस्तकारी की शिक्षा प्राप्त की है, पुनः बसाने के लिए इलाहाबाद तथा सखनऊ में दो केन्द्र खोले जाने वाले हैं। देहरादून में “बापू योकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट” को बसाने के लिए भारत सरकार ने १.५० लाख का अनुदान देना स्वीकार कर लिया है।

ग्रामों का अध्ययन जारी रख सकने के लिए अनेक विस्थापित छात्रों को आर्थिक सहायताएँ दी जा रही हैं।

यह भी निश्चय हुआ है कि शरणार्थियों को निष्कान्त बगीचे तथा खेती की धरती उनके दावों को जाँच करने के बाद दे दी जाय। ३०० रुपये या उससे कम के जो कार्य आशुज्य, उद्योग आदि के लिए छोटे शहरी कर्ज योजना के अन्तर्गत दिये गये हैं, या जो अन्य कर्ज भारत में उन विस्थापितों को शिक्षा के लिए दिये गये हैं जिनके कोई भी दावे विस्थापित व्यक्ति (दावे) कानून, १९५० के अन्तर्गत नहीं हैं, उन सभी कर्जों की वापसी रोक दी जायगी।

पश्चिम बंगाल

२५,८५,२७७ शरणार्थियों में से १४,७६,६४० के लगभग दिसम्बर १९५३ तक फिर से बसा दिये गये। शिविरों तथा बस्तियों में शरणार्थियों को कुल संख्या इस प्रकार थी। स्थानान्तरण शिविर २३,६०७, साधारण शिविर २५,८८१ शिविर बस्तियाँ ४,६६७ और काम करने की जगहों के शिविर १०,२१४ इसके अलावा ३४,६०० परिवारहीन महिलाएँ, बच्चे, बूढ़े तथा अपंग स्थायी शिविरों में हैं।

लगभग ६,००५ शरणार्थी परिवार राजकीय भूमि पर बस गये हैं तथा १३,१८७ कृषि भूमि पर और ३८,६११ या तो मंजर या फिर अप्रयुक्त भूमि पर बस गये हैं। अपने मकान बनाने के लिए उन्हें कर्ज तथा इमारतों सामान

दिया गया है। लगभग १५,६७६ शरणार्थी परिवार, जो कि शिल्पियों के थे, गांवों में बसाये गये हैं तथा सरकार ने उन्हें कर्ज देकर पुनः बसने में सहायता की है। ५६,२६१ कृषि-क्षेत्रों तथा ५७,०६० अकृषि-क्षेत्रों पर शरणार्थियों ने या तो मालिकों से सीधा संपर्क स्थापित करके या फिर राजकीय सहायता से अधिकार प्राप्त किया है। शरणार्थियों के लिए सरकार ने ५,६८७ मकान बनाये हैं। अध्ययन की सहायता देने के विचार से सरकार ने कालेजों को ७,३०,६०६ रुपये तथा माध्यमिक स्कूलों को ३३,३८,७१६ रुपये का अनुदान एवं कर्ज दे रखा है। वस्तुकारी का काम तथा टेक्नीकल शिक्षण पुरुषों को दिया जा रहा है तथा महिलाओं को विभिन्न कला और शिल्प में रस किया जा रहा है।

२. 'ख' भाग

खाद्य और कृषि

हैदराबाद

१९५३-५४ में खाद्य की स्थिति अधिक सुधरती गयी। अनाज पर की कंट्रोल हटा लेना संभव रहा और हैदराबाद राज्य पड़ोसी राज्यों को निर्यात के लिए ३५,००० टन ज्वार और ६,००० टन रागी दे सका।

वर्ष की एक महत्वपूर्ण घटना थी, तुंगभद्रा बांध का पूरा हो जाना। इस बांध से ४,५०,००० एकड़ क्षेत्र और १,३५,००० एकड़ भरती और जंगल की सिंचाई के लिये पानी दिया जा सकेगा। बांध पर और नहर के भार-भरपल लोखे १,००,००० किलोवाट अलविद्युत पैदा करने की योजना है।

हाल में एक काश्तकारी कानून बनाया गया है जिससे जमीन जोतने वाले को जमीन की मालिकियत मिल जायगी। इस कानून से किसान को बहुत सी सुविधाएँ और लाभ प्राप्त हुए हैं, जैसे बेंदखली से बचाव, खरीद का अधिकार और समुचित लगान इत्यादि। जपानी ढंग से धान की खेती करने से इस वर्ष उपज में वृद्धि हुई और प्रति एकड़ १०,८७२ पींड धान पैदा हुआ। किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए कर्ज दिये गये हैं। मध्यम वर्ग की सभी सिंचाई योजनाओं में अच्छी प्रगति हुई है।

आधिक सहायता की शर्तों पर किसानों ने राज्य में किसानों की पैदावार में ५,६०,००० टन की वृद्धि कर दिखाई।

जम्मू-काश्मीर

भान की वसुली का तरीका, जो मुजबाना कहलाता था और जिसमें किसान को लगभग सारी पैदावार दे देनी पड़ती थी, मिटा दिया गया है।

भारत सरकार की सहायता से ग्रामाज का समुचित भण्डार तैयार कर दिया गया है, और राज्य सरकार जेती और गहरो के निर्माण को अपने कार्य-काल में सबसे पहला स्थान दे रही है।

मध्य भारत

काको अधिक नयी मशीन तोड़ ली गयी है, कोई ५,००० गेण्ड कुएं बनाने लिए गए हैं और पुराने कुओं को मरम्मत की जा रही है।

धान की जेती का आयाती तरीका अपनाया गया है और जहाँ पहले साधारण रूप से कोई १५ मन प्रति एकड़ धान पैदा होता था, वहाँ एकजगह १९० मन प्रति एकड़ हुआ जो कि एक अभूतपूर्व बात है।

फसलों को कीड़ों और रोगों से बचाने के लिये बका छिड़कने के केन्द्र खोल दिये गये हैं। मक्का, लम्बे देश की कपास, धान और बालों की किस्म सुधारने के लिए पड़ताल की जा रही है।

मालगुजारी की सब जगह एक-सौ व्यवस्था लागू कर दी गई है। जब मध्यभारत राज्य बना था तो पट्टेदारी की व्यवस्था कुछ रैयतवाड़ी और कुछ जमींदारी ढंग की थी। अब जमींदारी और जागीरदारी दोनों ही मिटा दी गयी हैं। जमीन जोतने वालों को पट्टेदारी के पूरे अधिकार दिये जा रहे हैं। मध्यभारत और राजस्थान की सरकारों ने जम्बल नदी का उपयोग करने की एक योजना शुरू कर दी है जिसमें भारत सरकार उनकी सहायता कर रही है। इस पर ४२ करोड़ २० लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है। इससे १२,००,००० एकड़ भूमि सिंचि जा सकेगी और २,००,००० किसानों को पैदा होगी।

‘स’ भाग

कोलार की सोने की खानों के क्षेत्र में और बंगलौर, मैसूर और रावन गिरि पर्वतों में कानून द्वारा जो राक्षस व्यवस्था जारी थी, समाप्त कर दी गयी।

‘अधिक अन्य उपजाओ’ प्रावधानों में २४ अके और १,१५६ छोटे सासाब गहरे किये गये हैं और सुभारे गये हैं।

जापानी डंग से धान की खेती करने वालों को २०,००० टन अनुमतिपत्र सलूकेट इस बात पर बाँटा गया कि कुछ ही समय बाद वे उसका दाम चुका देंगे।

पेप्सू

प्राजा मिलकियत उन्मूलन कानून, पट्टेदारों को मिलकियत देने वाला कानून और पट्टेदारी और खेती की भूमि का कानून १९५३-५४ में लागू हुए। इन कानूनों का उद्देश्य पट्टेदारों की वक्ता सुधारना है। उन्हें बेदखली से बचाया जायगा और जिस जमीन पर वे खेती करते हैं उसे खरीद सकने का अधिकार दिया जायगा। इस नये प्रकबन्धी और भूमि सम्बन्धी कानूनों के कार्यालयों को मिलाकर एक कर दिया गया है जिससे कि कार्य-कुशलता बढ़ जाय।

राजस्थान

पिछले तीन सालों से किसी न किसी क्षेत्र में अभाव का कष्ट पला आ रहा है। इससे सहायता के हिसाब में भारी कर्ज करना पड़ा है।

१९५३-५४ में, सहायता के लिये ४७,८६,००० रुपये देने के अलावा सरकार ने ६३,००,००० रुपये तकावी कर्ज दिया। केन्द्र सरकार ने भी ४७,६३,०००, रुपये कर्ज के और ४,६३,००० रुपये अनुदान के रूप में दिया है।

सौराष्ट्र

भूमि के सम्बन्ध में दो महत्वपूर्ण कानून बनाये गये हैं। पहले कानून श्रेष्ठता की पैदावार बढ़ाने में मदद मिलेगी और दूसरे से अमीन जोतने वाले

को जनसेवक पर स्वामित्व का अधिकार मिल जायगा।

राज्य की १३ सिंचाई योजनाओं में से रंगोला, सूरजवाडी और भीमवाड, विछले साल पूरी हो गयी थीं। बाळू वर्ष में बहारासी और गिर की सिंचाई योजनाएं पूरी कर दी गयीं। सतोई, नालन, पना, और मोज की सिंचाई योजनाओं में बांध बनाये जा चुके हैं और तहरें बनाई जा रही हैं। मध्यम और छोटे दर्जे की २२ सिंचाई योजनाओं पर भी काम शुरू हो गया है।

माल इलाके की पानी पहुँचाने की कई योजनाएं पूरी हो गई हैं और सुभाष पाठन की पीने का साफ पानी पहुँचाने की एक और योजना लागू हो गई है।

तिसवांकुर-कोचीन

केन्द्र द्वारा और अधिक खानस मिलने की वजहसे १९५३-५४ में जनता की और खानस बेना और खानस की ग्राम बाजार दर बढ़ाना सम्भव हो सका है।

जहाँ तक बड़ी-बड़ी सिंचाई-योजनाओं का सवाल है, बलिया की पेरिचनी योजना पूरी हो गई है। अन्य ५ योजनाएं अर्थात् नंदर, कुदुनाच, पोचि, अन्नकामधेरि और बलकुडि भी तत्सोच जतन प्रगति कर रही हैं।

पानी जलीय कर सिंचाई करने के कोई ३७ सेक्टर २४,००० एकड़ की सिंचाई कर रहे हैं। उस १,००,००० एकड़ भूमि में से पानी सिंचालने के लिए जो अभी पड़ी है, मिजली पहुँचाई जा रही है।

जहाँ तक घनी खेती का सवाल है हड़दी, मूंगफली की खली, सुपर फास्फेट, राक फास्फेट इत्यादि प्रभावशाली खादें बढ़ाने की भारी कोशिश की जा रही है। हर साल कोई १६,००० टन खाद, जो ५,००,००० रुपये की होती है, किसानों को फसल की जमानत पर कर्ज के रूप में दी जा रही है। अच्छी तरह खाद देने से धान की पैदावार में १५,००० टन की वृद्धि हुई है।

१९५३-५४ में राज्य भर में प्रचार किया गया कि किसान जान कि खेती का जपानी ढंग अपनाएँ।

शिक्षा

हैदराबाद

पिछले दो वर्षों में ४,२०० प्राथमिक स्कूल खोले गए। विद्यापियों की संख्या में ९ लाख से भी अधिक की वृद्धि हुई है।

२२,००० प्रौढ़ों को शिक्षा देने के लिए बुनियादी शिक्षा के ५०० केंद्र खोले गए हैं।

जम्मू और काश्मीर

सब कक्षाओं में शिक्षा बिना शुल्क के की व्यवस्था कर दी गई है। मजबूत सरकार ने गैर-सरकारी शिक्षालयों के जो अनुदान गंव कर दिए थे, उन्हें फिर जारी कर दिया गया है। जिस विनों अनुदान गंव रहा उन विनों का बकाया अनुदान भी चुकता किया जायगा। अनेक नए गैर सरकारी शिक्षालयों को भी दान दिए गए हैं। लड़कों और लड़कियों के लिए बहुत से स्कूल और इनके अलावा ६ कालेज भी खालू वर्ष में खोले जा रहे हैं। आधुनिक आर्थिक और सामाजिक प्रवृत्तियों को धृष्टि में रख कर सब कक्षाओं में शिक्षा की नए सिरे से व्यवस्था करने के प्रयत्न पर विचार करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई है। जम्मू में स्त्रियों के एक शिक्षालय को सरकार ने अपने अधिकार में लेकर स्त्रियों का जिब्री कालेज बना दिया है।

डोगरी, काश्मीरी और लहासी आदि प्रादेशिक भाषाओं के विकास के उपाय खोजने के लिए समितियाँ बना दी गई हैं ताकि आने वाला प्रारम्भिक शिक्षा विद्याओं की मातृ-भाषा में ही दी जा सके।

सततर्षा वर्ष

कोई २५० प्रारम्भिक स्कूल खोले जा रहे हैं। इनमें अध्यापकों को पहले से ऊँचे वेतन दिए जाएँगे। १९५४-५५ में शिक्षा पर ७० लाख रुपया खर्च किया जाएगा।

मध्य भारत

राज्य में ६०१८ शिक्षालय हैं और सरकार की कुल आयवनी का लगभग छठा हिस्सा शिक्षा पर खर्च किया जाता है। इस वर्ष १५ करोड़ रुपए से ऊपर के बजट में २,४३,५५,२४० रुपया शिक्षा के लिए निर्धारित किया गया है।

घनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा की योजना १० और कस्बों में तथा ६०० से ऊपर गाँवों में भी लागू कर दी गई है। सब प्रारम्भिक स्कूलों को बुनियादी स्कूलों में धीरे-धीरे बदल देने की योजना को भी सरकार कार्य रूप में रही है। कोई ६० प्रारम्भिक स्कूल इस प्रकार बनने भी जा चुके हैं। अध्यापकों को शिक्षाने के लिए ४ बुनियादी ट्रेनिंग स्कूल खोले गए हैं। राज्य के विभिन्न स्कूलों और कालेजों में विद्यार्थियों को सैनिक शिक्षा दी जा रही है।

बच्चों की शिक्षा ■ लिए सौविस्दरी पद्धति के आधार पर २५ शिक्षा भविर खोले गए हैं।

विद्यमान वर्ष ४६० स्कूली इमारतों के निर्माण के लिए सरकार ने ७,८०,००० रुपया वितरित किया।

मंसूर

मंसूर की नयी बंधे शिक्षाने वाली संस्था इस वर्ष से काम करने लगेगी। ग्राम क्षेत्रों में २०० प्रारम्भिक स्कूल और ५० समाज शिक्षा केन्द्र खोले जायेंगे।

दिल्ली जिले के सात ताल्लुके मंसूर राज्य में भित्ता दिए जाने के कारण ४७२ निम्न प्रारम्भिक स्कूल, २६ उच्च प्रारम्भिक स्कूल, १६ हाई स्कूल और ३८ प्रौढ़ साक्षरता स्कूल मंसूर राज्य के शिक्षा विभाग के अधीन आ गए हैं।

मैसूर सुधार समिति की शिफारिश पर निडिल स्कूल और अपर ग्राहमरी
पब्लिक परीक्षाएं समाप्त कर दी गई हैं।

टेक्निकल शिक्षा संचालक का जगह अब स्थापित किया गया है।

वेप्पु

१९५३-५४ में २ अध्यापकों वाले २१४ और १ अध्यापक वाले ६६६
प्रारम्भिक स्कूल खोले गए। प्रारम्भिक स्कूलों की कुल संख्या अब १,८३४ है,
अर्थात् वर्ष के आरम्भ में जितनी थी उससे लगभग दुगुनी। स्कूलों की साज-
सामान और कर्मचर खरीदने के लिए आर्थिक सहायता दी गई है।

भावनों और धुरी के सामूहिक विकास क्षेत्रों में छोटे बुनियादी स्कूल
खोले जा रहे हैं। बुनियादी शिक्षा सीखे हुए अध्यापकों की कमी नाभा में
सरकारी बेसिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुल जाने से दूर हो जायगी ऐसी आशा है।
१५ हाई स्कूलों की प्रतिरिक्त अध्यापकों और कर्मचर की व्यवस्था की गई है,
इन पर ६७,००० खर्च किया जा रहा है।

साम क्षेत्रों में प्रारम्भिक स्कूल खोलने के लिए ६१ इमारतें बनाई गई
हैं। हर इमारत की आधी लागत सरकार ने और आधी गांव वालों ने दी है।

राजस्थान

टेक्निकल और व्यावसायिक शिक्षा देने के लिए इस समय १८ कॉलेज
खोले गए हैं। इनके अलावा कोटा, सवाई-माधोपुर और उदयपुर में तीन कृषि
कक्ष जिन्हें शिक्षा का समुचित साज-सामान है।

सरकार माध्यमिक शिक्षा की अपनी योजनाओं को वास्तव में रही है।
राज्य में सामाजिक और प्रौढ़ शिक्षा का प्रचार किया जा रहा है। राजि-कलाओं
और लघुकलाओं के विभिन्न क्षेत्रों का भी आयोजन हो रहा है।

सौराष्ट्र

शिक्षा के सभी क्षेत्रों में प्रगति हुई है। १९५३-५४ में ४५० प्रारम्भिक

स्कूल खोले गए और ६० नई इमारतें बनाई गईं। माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए ऐसे स्कूल खोले गए हैं जिनमें अनेक प्रकार की शिक्षा दी जाती है। ५०० प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोले गए हैं जिनमें से हर एक में छोटा-सा पुस्तकालय और वाचनालय है।

ऊँचे दर्जे की टेक्नीकल शिक्षा देने के लिए मोरवी इंजीनियरिंग कालेज को डिग्री कालेज बना दिया गया है।

तिरुवांकुर-कोचीन

राज्य में ५१.७९ प्रतिशत साक्षरता है। कुल आबादी में १७ साल से अधिक स्कूल जाने वाले बच्चे हैं। ५ से १० वर्ष की आयु के कुल बच्चों का ६५ प्रतिशत भाग स्कूल में पढ़ता है। कालेजों में विद्यार्थियों की कुल संख्या ९५ हजार है। डाक्टरी, इंजीनियरिंग और अन्य टेक्नीकल शिक्षा के कालेजों को मिलाकर कुल ४५ कालेज, ५५२ हाई स्कूल, ७६९ मिडिल स्कूल ४१३३ प्रारम्भिक स्कूल और कोई १७० विशेष स्कूल हैं। ३६ नए प्रारम्भिक स्कूल, १० मिडिल स्कूल, ६ हाई स्कूल, और दो सम्पादक ट्रेनिंग स्कूल, भी खोले जायेंगे। वर्तमान टेक्नीकल शिक्षालयों में से ४ का केन्द्रीय सरकार की योजना के अनुसार विकास किया जायगा। संविधान के निर्देशक सिद्धांतों को कार्य रूप देने के उद्देश्य से सरकार ने १९५४-५५ के स्कूली वर्ष से मिडिल स्कूल की पहली दो कक्षाओं की फीस माफ कर दी।

समाज शिक्षा में ६० समाज शिक्षा केन्द्र निचमनंतपुरम् के प्रौढ़ शिक्षा ट्रेनिंग केन्द्र से सीजे संचालकों के अधीन उपयोगी काम कर रहे हैं।

लाउडस्पीकर और सिनेमा से शिक्षा देने वाली दो टोलियां बनाई गई हैं जिनमें से एक बलती-फिरती टोली है और दूसरी का कार्यालय ट्रेनिंग केन्द्र में है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य

हैदराबाद

सरकार ने अन्धा-बन्धा के हित की एक योजना मंजूर की है जिस पर ४.५ लाख रुपया सालाना खर्च होने का अनुमान है।

अस्पतालों में तपेविक के मरीजों के लिए यथेष्ट जगह न होने के कारण हैदराबाद और तिकबराबाद के शहरों में यह आन्दोलन चलाया गया है कि मरीजों का इलाज घर पर ही किया जाय।

हैदराबाद सरकार भारत सरकार की राष्ट्रीय मलेरिया-निरोध योजना में भी सक्रिय योग दे रही है।

जम्मू और काश्मीर

राज्य की डाक्टरों-व्यवस्था का बहुत काफी विस्तार किया गया है और प्रवाशों तथा अन्य डाक्टरों सामान के लिए जवाबदा के अनुदान दिए गए हैं। विभिन्न डाक्टरों संस्थाओं में कर्मचारी भी बढ़ा दिए गए हैं। तपेविक के मरीजों के लिए बतोंस में एक चिकित्सालय खोला गया है और जम्मू और श्रीनगर के कुछ अस्पतालों में और अधिक मरीजों के लिए जगह की जा रही है।

ग्यारह दूनानी और आयुर्वेदिक औषधालय खोले गए हैं। श्रीनगर के मुख्य अस्पताल की समीराकबल से कर्णनगर ले जाने के कारण समीराकबल के निवासी डाक्टरों सहायता की सुविधाओं से वंचित हो गये हैं। इसलिए वहीं के पुराने अस्पताल के भवन में एक औषधालय खोल दिया गया है।

स्ट्रैप्टोमाइसिन प्राबि दवाएं खरीदने के लिए सामान्य अनुदानों के प्रतिरक्त ७५,००० रुपये का एक विशेष अनुदान दिया गया है। जी. सी. जी. आन्दोलन तेज किया गया है। ५०,००० से अधिक लोगों का परीक्षण करके-

सालाबाई बर्ब

जगमें से कोई २५,००० को टीका लगाया जा चुका है । डाक्टरों नर्सों और सहायकों को विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है ।

अन्धू में मलेरिया और गुप्त रोगों को फैलने से रोकने के उपाय हो रहे हैं ।

मध्य भारत

राज्य की कुल आबादनी का ६ प्रतिशत से अधिक अंश जनता को डाक्टरों-सुविधा देने पर खर्च हो रहा है । राज्य सरकार डाक्टरों और आरोग्य के शिक्षा में ८० लाख सालाबाई खर्च करती है ।

राज्य में कुल ५६७ डाक्टरों संस्थाएं हैं । उनके अलावा एक औषधालय और बीमार बच्चों के लिए एक अनाथालय है । सभी जिला प्रधान कार्यालयों के अस्पतालों में प्राथमिक साज-सामान है । इनके अलावा राज्य में २५७ आयुर्वेदिक औषधालय हैं । हर ग्राम पंचायत को दवाओं के बक्से दे दिए गए हैं और गांवों में हाट लगने के दिनों पर दवा बांटने का प्रबन्ध कर दिया गया है । अधिकांश गांवों में बी. सी. जी. के टीके लगाए जा चुके हैं । १७ लाख आबादियों का अभी तक परीक्षण हुआ है जिनमें से ५ लाख को टीका लगाया गया है ।

मैसूर

ग्रामसेवकों की सेवा के लिए १३५ आरोग्य इलों का एक जाल बुन दिया गया है । राष्ट्रीय मलेरिया विरोध योजना से, जो दिसम्बर १९५३ में शुरू हुई थी, आशा है कि साढ़े तीन वर्ष के समय में ५० लाख आबादियों को मलेरिया से बचाया जा सकेगा ।

राज्य के चार बी. सी. जी. इलों में १७ सहरों और १,१६७ गांवों में जाकर ३,१८,४५४ आबादियों को टीके लगाए ।

१९५३-५४ में औषधालयों और अस्पतालों की संख्या ४२३ से बढ़ कर ५०२ हो गई । इनमें से ८० प्रतिशत से अधिक ग्राम सेवकों में सेवा कर रहे हैं

और कोई ८० संस्थाओं में औरतों और बच्चों का ही इलाज होता है। १९५४ में ६ प्रौद्योगिक और ६ अस्पताल खोले गए। बंगलौर के पागलों के अस्पताल को मानसिक और स्नायविक रोगों में प्रवेश करने और ग्रेजुएट डाक्टरों को ट्रेनिंग देने के उपयुक्त बना दिया जाया।

पेप्सू

५ नवम्बर १९५३ को राज्य में एक नया डाक्टरों कालेज खोला गया जिसमें ३०० विद्यार्थी हर साल पढ़ सकते हैं।

मलों का एक होस्टल और राजेश्वर अस्पताल बन कर पूरा हो गया है। संगर के मुख्य अस्पताल में तपेदिक के इलाज के लिए २६,००० रुपये मंजूर किया गया है। जालिमों बाबरी के नगरिक अस्पताल का निर्माण पूरा हो चुका है जिस पर ८० हजार रुपये भी लागत आई है। धर्मपुर के तपेदिक अस्पताल और भठिन्डा के नगरिक अस्पताल में नए बार्ड खोल दिए गए हैं।

टापा, गोबिन्द गढ़, नल गढ़, राभीपुर, तालबन्दी, ताबी, कनीना, कुलाना और राजपुरा में जन्मा-बच्चा और शिशु हितकारी केन्द्र भी खोले गए हैं।

सौराष्ट्र

घोरबन्दर और सिन्धी के अस्पतालों में जन्मा-बच्चा विभाग में ११० फ़ार्मों का और प्रबन्ध कर दिया गया। जूनागढ़ में विद्यलेखन करने वाली एक प्रयोग शाला स्थापित की गई है।

धर धर डी. जी. डी. छिड़कने का प्रचार किया गया और मलेरिया निरोधक बनाएँ मुफ्त बाँटी गईं। सौराष्ट्र में बी. सी. जी. के डीके लगाने लगाने वाले तीन दल काम कर रहे हैं और ३,९३,२२२ आदमियों का द्यूबर मुलीन परीक्षण हो चुका है।

घोरबन्दर और सिन्धी में जन्मा-बच्चा हितकारी केन्द्र खोले गए हैं। सन्निधवार के सामूहिक विकास क्षेत्र में ग्रामवासियों के आरोग्य के लिए एक केन्द्र खोला गया है।

गाँवों में, छोटे छोटे रोगों की चुन्नी हुई साप्सुर्वेदिक दवाओं के बक्से बाँटे जा रहे हैं। अब तक ३६६ बक्से बाँटे जा चुके हैं।

एक साप्सुर्वेदिक पुस्तकालय भी खोला गया है।

दूर-दूर के गाँवों में डाक्टरों की सहायता पहुँचाने के लिए एक एक चलते-फिरते डॉकमान का प्रबन्ध किया गया है।

तिरुवांकुर-कोचीन

मलेरिया निरोध संगठन की कार्य कुशलता की बखीलत उन पहाड़ी प्रदेशों में जो अब तक मलेरिया के अर समझे जाते थे, और जहाँ आबादी नहीं थी, गए-गए गाँव बसते जा रहे हैं।

मलेरिया और फाइलेरियासिस को फैलने से रोकने के उपायों पर जोर दिया गया है।

सम के इलाज की बढ़ती माँग को देखते हुए बड़े-बड़े अस्पतालों में तपेदिक के अलग बार्ड खोले जा रहे हैं। हाल ही में एक प्रमुख तपेदिक अस्पताल नियुक्त किया गया है जो तपेदिक में सहायता और उसके नियन्त्रण के सारे काम की देख-भाल करेगा।

बी. सी. जी. का आम्बोलन त्रिचूर जिले में मई १९५३ में पूरा हो गया था। अब वह कोट्टायम और बबीलोन के जिलों में जारी है।

१९५३-५४ में ९० जम्बा-जम्बा और शिशु हितकारी केन्द्र शुरू किए गए जिससे कि कुल केन्द्रों की संख्या २५१ होगी। मेडिकल कालेज जनरल अस्पताल, जिसमें ४५० भरीजों की जगह है, इस वर्ष चालू हो गया।

श्रम

हैदराबाद

राज्य के २४ सहरों में बुकाम-कानून लागू किया जा चुका है। १८५३-५४ में ४० हजार बुकानों का निरीक्षण किया गया, १,०२३ मुकदमे बाहर किए गए और मौकरी से निकाले गए कर्मचारियों को पैन्चुहटी के रूप में ८५,६०० रुपये दिया गया। कई प्रकार के कर्मचारियों और उनके आश्रितों को छोटे-छोटे के और दुर्घटना से मृत्यु के मुआवजे में ३ लाख रुपये चुकता किया गया।

सरकार ने एक न्यूनतम मजदूरी कमेटी बनाई है जो सड़क बनाने वाले, बोड़ी और बटन तैयार करने वाले, चमड़ा साफ करने वाले, और खेती करने वाले मजदूरों के लिए मजदूरी सुझाएगी।

राज्य के १३ अन्य बहुसंख्यक उद्योगों में मजदूरी का सुझाव देने ■ लिए बोर्ड बना दिए गए हैं।

श्रम विभाग ने मालिकों को मजदूरों के हित के कानून मानने पर मजबूर तो किया ही है, साथ-साथ मजदूरों के रहने, बच्चों की शिक्षा और मनोरंजन के सम्बन्ध में जो योजनाएं बनी हैं उनको भी कार्य-कण बना शुरू किया है।

जम्मू-काश्मीर

औद्योगिक मजदूरों की समस्याओं पर विचार करने के लिए एक कमेटी नियुक्त की गई है। मजदूरों को रहने की बेहतर सुविधाएं देने के लिए वर्तमान कानूनों में रियायतें की जायेंगी।

नगर क्षेत्रों में इस बात की पड़ताल की जायगी कि कुल कितने आदमी बेरोजगार हैं और कितने आधे रोजगार से लगे हुए हैं। इसके साथ इस आस-कारों के आधार पर बेरोजगारी दूर करने की योजनाएं बनाई जायेंगी।

मध्य भारत

भारत सरकार ने अम सम्बन्धी जितने कानून निकाले हैं उनमें से लगभग सब मध्य भारत में लागू हो चुके हैं। कुछ उद्योगों में न्यूनतम मजदूरी निश्चित कर दी गई है।

कर्मचारियों का प्राविडेंट फंड कानून लागू कर दिया गया है जिससे कोई ४० हजार मजदूरों का हित होगा। औद्योगिक मजदूरों के लिए मकान बनाने की तीन अलग-अलग योजनाएं हैं। उनमें से दो, जिनमें मध्य भारत के विभिन्न उद्योग क्षेत्रों में १,५५२ मकान बनाने की व्यवस्था है, करीब-करीब पूरी ही हो चुकी हैं। तीसरी को, जिसे हाल में ही भारत सरकार ने संजूर किया है, कार्यान्वित किया जा रहा है।

बार महत्त्वपूर्ण औद्योगिक नगरों में अम हितकारी केन्द्र खोले गये हैं, जिसमें खेल-कूद, डाकघरों सहायता, प्रीव शिक्षा इत्यादि के प्रतिरिक्त मजदूरों में सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यों के लिए सभा-संगठन भी किए जाते हैं। मजदूरों के लिए इन्डोर और एक्सटरनल में जन्मा-बच्चा घर खोले जा रहे हैं जहाँ परिवार-आयोजन के बारे में भी निर्देशन किया जायगा।

मैसूर

मैसूर मजदूर मकान कानून के अधीन जो मजदूर मकान-कारपोरेशन बनाया गया है, वह भारत सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है। औद्योगिक मजदूरों और मध्य वर्ग के लोगों—बोनों के लिए मकानों की व्यवस्था करने ■ वास्ते एक मकान बोर्ड स्थापित किया जायगा।

पेप्सू

पटियाला के फैक्टरी प्रदेश में औद्योगिक मजदूरों के लिए ५० मकान बनाने का विचार है। ३० मकान बन भी चुके हैं। पेप्सू के दो उद्योग शिक्षा केन्द्र फगवाड़ा और नाभा में बने हुए हैं। एक से ११२ और दूसरे में १२८ सीटें हैं।

‘क’ भाग

भान, हाल, घाटे की मिलों में काम करने वालों की स्थूलतम मजदूरी निर्दिष्ट कर दी गई है।

१९५३-५४ में १६ फैक्ट्रियों में कर्मचारियों का प्राबिडेंट फंड लागू कर दिया गया है। इस तक ४,१५१ मजदूरों का इस योजना से हित हुआ है। मासिक और मजदूर दोनों मिलकर महीने में करीब ४१,००० खपा देते हैं।

राजस्थान

३१ शहरों में सप्ताह में एक दिन की छुट्टी अनिवार्य कर दी गई है। मजदूर यूनियन बनाने की प्रोत्साहन दिया जा रहा है और ७७ यूनियनों रजिस्टरशुदा भी हो चुकी हैं। इनके अलावा फैक्टरी कानून के अधीन ४९४ फैक्ट्रियां और रजिस्टरशुदा हुई हैं जिनमें कुल मिलाकर ३३,५५६ मजदूर नौकर हैं।

सौराष्ट्र

राज्य में लगभग ६०० रजिस्टर्ड फैक्ट्रियां हैं। इनमें से ५७५ को लाइसेंस दिए जा चुके हैं। सात प्रकार की अनुसूचित नौकरियों में न्यूनतम मजदूरी निर्दिष्ट कर दी गई है। रजिस्टर्ड मजदूर यूनियनों की कुल संख्या १४० के निकट थी, जिसमें लगभग ३२ हजार मजदूर संवस्य थे। २७ यूनियनों का रजिस्ट्रेशन या तो रद्द कर दिया गया है या वापिस ले लिया गया है। इस केवल ११३ मजदूर यूनियनों हैं और कुल संवस्य संख्या २७,००० है।

राजकोट ■ काम बिलाऊ बपत्तर में नौकरी के इच्छुक ३,००० मजदूरों के नाम दर्ज किए गए हैं।

तिरुवांकुर-कोचीन

समझौता विभाग ने कुल ३,५४० औद्योगिक भगड़ों को हाथ में लिया जिनमें से ३,३०५ निगमों से निगमों लिए गए और ७३ पंकों के सुधुर्ण कर दिए गए।

मालिकों से मजदूरों के लिए आराम घर, भोजन घर, वाचनालय, खेल-

कुद और आस्टरी घासि की मुनिघाएं बिलबाई गई हैं। २५० या अधिक कर्म-
चारियों वाली फैक्ट्रियों में कैंटीन खोलने के सम्बन्ध में जो व्यवस्था है उसको
भी कड़ाई के साथ लागू किया गया है।

मजदूर युनियनों की संख्या ५८१ से बढ़कर ६२६ हो गई है। मगानों
और बोड़ी और फालू के उद्योगों में काम करने वालों के लिए न्यूनतम मजदूरी
निर्धारित कर दी गई है।

उद्योग

हैबराबाद

राज्य में ६ इलेक्ट्रिक केन्द्र खोले गए हैं जो अनेक प्रकार के कारेल उद्योगों
का काम सिकाते हैं और उत्पादन के आधुनिक तरीके बिल्लताते हैं।

कुछ क्षेत्रों में ताँबे की धातु का प्रसा सगाया जा रहा है। सिंगारेनी की
कोयला खदानों पर एक नया बिजलीघर बनाया जा रहा है। इस समय राज्य की
ये खदानें कोई १६ लाख टन कोयला पैदा कर रही हैं। जब बिजलीघर काम
शुरू कर देगा तो उत्पादन २० लाख टन तक पहुँच जायगा।

औद्योगिक हस्त फंड ने स्थानीय उद्योगों और कम्बई की दो कम्पनियों ने
१९१.३६ लाख रुपये के हिस्से ले रखे हैं। अब तक २१३.२६ लाख रुपये
कर्म के रूप में दिया जा चुका है।

१९५३ में ३.५ करोड़ रुपये के मूल्य के खनिज का उत्पादन हुआ।

जम्मू काश्मीर

पर्यटन राज्य के मुख्य उद्योगों में से एक है। सरकार ने यात्रा की और

अधिक सुविधाएं जुटा दी हैं और पहले से अधिक आराम का प्रबंध कर दिया है ताकि बहुत बड़ी संख्या में संलग्नी आयें।

भाषियों और जरूरी सामान का घाना बराबर जारी रखने के उद्देश्य से सरकारी परिवहन विभाग ५०० गाड़ियां चलाता है जिससे लगभग १,५०० आरामियों को काम मिला हुआ है। १९४७ से राज्य के परिवहन उद्योग का ३०० प्रतिशत विकास हुआ है और किराया और भाड़ा बहुत काफी घटा दिया गया है।

काश्मीर सरकार के आर्ट्स एम्प्लॉयमेंट ■ माध्यम से कारीगरों को एकत्र किया गया है। कारीगरों की सहकारी समितियां बनाने की भी प्रोत्साहन दिया गया है। इन समितियों का तैयार किया हुआ साल एम्प्लॉयमेंट अपनी शाखाओं के द्वारा निकालता है जो भारत में कोई ३० जगहों में स्थापित हैं।

सरकार ने पम्पुर में, जो श्रीनगर से घाठ भील पर है, बपतरी, स्टेशनरी, औजार और इमारती सामान को एक नयी फैक्टरी शुरू की है।

लद्दाख की जनता में उद्योग और वाणिज्य का प्रचार करने के उपाय किए जा रहे हैं। साल को बाजार में पहुँचाने की एक संस्था बनाने ■ वास्ते सरकार ने ५,००,००० रुपये का कार्य दिया है जिस पर वह धुव नहीं लेगी। इस संस्था के मुनाफे का ५० प्रतिशत कारीगरों का रहस्य-सङ्गम बेहतर बनाने पर खर्च किया जा रहा है।

मध्य भारत

सरकार घरेलू उद्योगों के विकास पर बहुत जोर दे रही है। एक उद्योग अलाहकार बोर्ड बनाया गया है और १९५३ में सरकार ने विभिन्न घरेलू उद्योगों के विकास के लिए ३५,५०० रुपया कार्य और २९,०३६ रुपया अनुदान के रूप में दिया है।

करघा-वस्त्र उद्योग की रक्षा के लिए सरकार ने चंदेरी, सारंगपुर, महेन्द्रपुर और शाजापुर में बने कपड़े को शुरू में एक वर्ष के लिए बिक्री कर से

सातवाँ वर्ष

छूट दे दी है। सरकार सुनकरों को मशीनों खरीदने के लिए रुपये की मदद भी दे रही है।

ग्रामीणों के विकास में सहायता देने ■ लिए एक ग्राम उद्योग समिति बनाई गई है, जिसे २५ उद्योगों के विकास की क्वातिर ३ लाख रुपया दे दिया गया है।

मैसूर

घरेलू उद्योगों के, विशेष कर खादी और करपा-बस्त उद्योग ■ विकास पर खास ध्यान दिया जा रहा है। इस समय राज्य में घरेलू उद्योगों के ६१ केन्द्र हैं। भारत सरकार ने इन उद्योगों ■ बिस्तार के लिए ५८,५०० रुपया अनुदान के रूप में दिया है। सरकार ने अपनी अधिकांश अकरत के लिए हाथ का बना कपड़ा खरीदने की आज्ञा दी है। सरकार को सेल फंड से १०.१३ लाख रुपया मिला है जो करपा बस्त उद्योग के विकास की योजनाओं पर खर्च किया जायगा। हाथ के बने कपड़े को जिकी कर ■ भी छूट दी जा रही है।

राज्य की औद्योगिक उन्नति के लिए सरकार ने ग्राम औद्योगीकरण योजना राज्य के सब जिलों में लागू करने का निश्चय किया है। १९५४-५५ के बजट में इस योजना के लिए १६ लाख रुपया रख दिया गया है।

पेप्सू

कलाओं और बस्तकारी के विकास के लिए धुरी के सामूहिक विकास कार्य में और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों में कुछ योजनाओं को कार्य रूप दिया जा रहा है जिन पर ५,४०,००० रुपया खर्च होने का अनुमान है। निम्नांकित उद्योगों में गति लाने के लिए भी योजनाएँ बनाई गई हैं: साइकिल के हिस्सों का निर्माण, जूते और चमड़े के अग्न्य सामान, सरल प्रकार के गणित के यंत्र, खेल-कूद की चीजें, शीशे का सामान और तावे, और बड़ईगरी और चमड़े की सफाई।

मालेर कोडला में एक करपा बस्त उद्योग केन्द्र खोला गया है जिनमें बुनाई के नए और अच्छे तरीके बताए जाते हैं और नियमित रूप से ट्रेनिंग दी

जाती हैं। यह ट्रेनिंग लेने के लिए १०४ लोग केन्द्र में शामिल हुए हैं जिनमें से ७२ की ट्रेनिंग पूरी भी हो चुकी है। इन केन्द्रों में अलग-अलग तरह के कपड़ों में,—जैसे पापलोन, दिवाल और कमीज के कपड़े और तीलियाँ—जोस नयी डिजाइनों बिकाली गई हैं।

राजस्थान

मई १९५३ में तवाई माधोपुर के जयपुर उद्योग लिमिटेड ने एक सीमेंट फैक्टरी शुरू की। इस फैक्टरी में हर महीने १० हजार टन सीमेंट तैयार हो सकता है। राज्य में सीमेंट फैक्टरियों की कुल उत्पादन-शक्ति अब ३५,००० टन प्रति मास हो गई है।

बमस्पति तेल के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए तेल और लसी के निर्यात-कर को ५० प्रतिशत घटा दिया गया है।

खादी और ग्राम्य प्रामोद्योगों के विकास को अनेक योजनाएँ चालू हैं। इन उद्योगों में मशीनों और आधुनिक प्रणालियों का भी उपयोग करने का इरादा है।

सौराष्ट्र

राज्य सरकार ने एक औद्योगिक-निरत-कारपोरेशन स्थापित किया है। छोटे कारखानों की जरूरतें सौराष्ट्र का छोटे पैमाने के उद्योगों का बोर्ड पूरा करेगा। यह बोर्ड इसी साल बनाया गया है और इसका काम छोटे उद्योगों के विकास के बारे में सरकार को परामर्श देना भी है।

खादी और ग्रामोद्योगों की देखभाल के लिए सौराष्ट्र खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना की गई है।

छोटे पैमाने के उद्योगों की उन्नति के लिए एक भारी योजना शुरू की गई है जिसके लिए ८,००,००० रुपया अलग रख दिया गया है। सौराष्ट्र करवा बोर्ड इसी वर्ष बनाया गया और करवा पर कपड़ा बुनने का एक आधुनिक केन्द्र भी शुरू किया गया है। छोटे पैमाने के उद्योगों और करवा बुनकरों का

तैयार माल एक एम्पोरियम द्वारा निकाला जायगा जो राजकोट में स्थापित किया जा रहा है।

तिरुवांकुर-कोचीन

उद्योगों के खर्च के लिए पूंजी देने को एक करोड़ रुपये की पूंजी से एक औद्योगिक-वित्त-कारपोरेशन बनाया गया है। पूंजी का ५० प्रतिशत सरकार देगी। कारपोरेशन ने १ दिसम्बर १९५३ को काम शुरू किया और वह अभी तक चार वर्षों भी संजूर कर चुका है जिनकी कुल राशि १२ लाख रुपये है।

अधिकों के हितों की रक्षा ■ लिए सरकार ने कुछ औद्योगिक संस्थाओं की, जो बन्द हो गई थीं, अपने अधिकार में ले लिया है, जैसे त्रिधूर की सोलाराम स्पनिंग और वीथिंग मिल, और मुलकुमलुकावु की महालक्ष्मी काठन मिल लिमिटेड। तिरुवनन्तपुरम् की विट्टेनिधम आक्साइड फैक्टरी में, जहाँ उत्पादन स्थानी रूप से रोक दिया गया था, फिर काम शुरू हो गया है। ताङ्गुडु उद्योग सहकारिता के आधार पर फिर से संगठित किया गया है। इस उद्योग के मजदूरों की दो केन्द्रीय सहकारी संस्थाएं और ५० प्राथमिक संस्थाएं राज्य के विभिन्न भागों में काम कर रही हैं।

इसी प्रकार मारियल-रेला उद्योग भी जिससे तटवर्ती प्रदेशों के कोई ५,००,००० लोगों की रोजगार मिला हुआ है, एक योजना के अधीन विकसित किया जा रहा है जिस पर ६४ लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है। मजदूरों को विधवलियों की उपायों से बचाने के लिए दो केन्द्रीय संस्थाएं और १२० प्राथमिक संस्थाएं बनाई जाएंगी।

कारवा बन्द उद्योग को सहकारिता के आधार पर फिर से संगठित करने की एक योजना तैयार की जा रही है। इस पर इस वर्ष के अन्तर १० लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है।

तेल पेरना, कोरा घास और रेसे से बटाई कुना, मिट्टी के बर्तन बनाना, अधुमक्की घालना इत्यादि अन्य घरेलू उद्योगों को फिर से संगठित करने की योजनाएं भी बनाई जा रही हैं।

पुनर्वास

जम्मू और काश्मीर

काश्मीर कमेटी की सिफारिश के अनुसार कुछ जेजों में विस्थापित लोगों से पुनर्वास करण की वसूलघावी रोक हो गई है। पुंछ में विस्थापित परिवारों को और कर्ज दिए जा रहे हैं जिनकी कुल रकम ४,५०,००० रुपये होगी। विस्थापित व्यक्तियों को मालगुजारी प्रभा करने से भी मुक्त कर दिया गया है।

४,००० परिवारों के लिए एक बस्ती बसाने का विचार है। पुनर्वास की समस्याएँ निबटाने के लिए एक कमेटी बना दी गई है जो सरकार के निर्णयों को कार्यान्वित करेगी।

मध्य भारत

मध्य भारत के ६८,००० विस्थापितों में से अधिकांश फिर से बसा दिए गए हैं। कोई १०,००० लोगों को कर्ज दिया गया है और ३५० परिवारों को बसाने के लिए जमीन दी गई है। खेती के लिए भी कर्ज दिया गया है। उद्योग चले धुक करने के लिए कर्ज के रूप में कुल ६ लाख रुपये बांटा गया है।

इन्दौर, जज्जैन, बालिगर, नीमख, सोरेना, तरगर, मनसर, शिवगढ़ और भानपुरा में विस्थापित व्यक्तियों के लिए अब तक कुल १,४७३ मकान बनाए गए हैं। सरकार ने ७६९ पक्की दुकानें बनवाई हैं और विस्थापित व्यक्तियों ने अपने साधनों से १,२२८ दुकानें बनाई हैं। हरिकर्मों और आदिवासियों के लिए व्यवसाय की शिक्षा देने के केन्द्र खोले गए हैं। बुनाई-कलई, ताड़गुड़ बनाने, बड़ई गिरी और अन्य धर्मों की शिक्षा भी दी जा रही है।

भेंसूर

राज्य में कोई ८,४३६ विस्थापित हैं जिनमें से ७,७८५ बंगनीर में, ५८१ भेंसूर शहर में और बाकी अन्य जिलों में रहते हैं।

लगभग ५५ परिवारों को वान के रूप में सहायता दी जा रही है। हर महीने कुल १,२०० रुपये बांटा जाता है। व्यापार और बुकानवारी में लगे हुए २७७ व्यक्तियों को पुनर्वास के लिए कुल २,७८,८७६ रुपये १२ आने कर्ज के रूप में दिए गए हैं। जय नगर, बंगलौर में विस्थापितों के लिए निर्धारित २०० जमीनों से ५३ पर मकान बन चुके हैं और श्रावित हो चुके हैं। इसके अलावा ५६ परिवारों को मकान बनाने के लिए जमीन दी गई है। विस्थापित विद्यार्थियों को कुल ४६,६४० रुपये पोंच आना की रकम वितरित की जा चुकी है।

राजस्थान

लगभग ३ लाख विस्थापितों को भसाया जा चुका है। इसमें से कोई ८० प्रतिशत गाँवों में जमीन देकर बसाए गए हैं। इनको कुल ६.२८ लाख एकड़ की अधिक उपजाऊ भूमि दी गई है। इसके अलावा पुनर्वास के लिए कर्ज की शक्ल में ४.४५ करोड़ रुपये भी बांटा जा चुका है।

कोई १,०६२ मकान और १,३७५ दुकानें और स्टाल बन कर तैयार हो चुके हैं। ४०० मकान बन रहे हैं। ५५० मकानों और ५४२ दुकानों के मकान बना लिए गए हैं। विस्थापित विद्यार्थियों की शिक्षा सम्बन्धी जरूरतें ख़दार्ता से पूरी की जा रही हैं। विस्थापित विद्यार्थियों के १५७ स्कूलों में ४७५ विस्थापित अभ्यापकों को नियुक्त किया गया है। इन स्कूलों में १३,०८१ विद्यार्थियों को मुफ्त पढ़ाया जाता है। निरक्षित स्त्रियों और बच्चों की सहायता के लिए विशेष ख़पाय किए जा रहे हैं।

विस्थापित लोगों को प्रश्रय देने के लिए जो घर बनाए गए हैं उनमें रहने वालों को सुझावों के दारों का आशिक भुगतान कर दिया गया है। आम नगर में २०८ और राजकोट में ८४ और मकान बनने शुरू हो गए हैं। सरकारी इमारतों और गैर सरकारी मकानों में रहने वाले लोगों को इन मकानों में लाकर भसाया जायगा।

विस्थापित व्यक्तियों को छोटे पैमाने के उद्योग शुरू करने के लिए २,००,००० रुपये कर्ज के रूप में बांटा गया है। जो विस्थापित खेती करने

बालों के रूप में बस गए हैं जन्हें कुल मिलाकर ५० हजार रुपया ख़र्च दिया गया है। विस्थापित विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता देने में ४०,००० रुपया खर्च किया गया है।

अनेक विस्थापित स्त्रियों को नर्सिंग और बाई का काम सिखाया गया है। मोली और बेतूर में विस्थापितों को टेक्नीकल शिक्षा भी दी जा रही है।

३. 'ग' भाग

खाद्य और कृषि

अजमेर

नवम्बर १९५३ में बीबी, मक्का और मिस्रो पर से राशन हटा लिया गया। अजमेर और राजस्थान के बीच अनाज के आने-जाने की अनुमति दे दी गई है ताकि तुले बाजार में काफी अनाज बना रहे।

'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन के अधीन कम्प्रेसर की सहायता से १०५ पुराने कुएं और सात पनघट गहरे किये गये हैं। इसके अलावा ४४२ पुराने कुओं को गहरा करने के लिये १,५६,३७५ रुपये का तत्काली कर्ज-विद्युत गया है। किसानों में करीब ७,४३६ टन कन्वोल्व, करीब १,२४० मन गेहूँ का उम्दा बीज, ३०० मन अन्न बीज, ६९८ मन अमोनियम सल्फेट और ८० मन सुपरफास्फेट बाँटा गया है। इस तरह कृषि उत्पादन काफी बढ़ गया है।

भोपाल

१९५१-५४ में केन्द्रीय ट्रंकटर संगठन ने ४०,०६४ एकड़ जमीन तोड़ी। मशीनी खेतों की खोजत गेहूँ की खोसत प्रति एकड़ उपज ४ मन २२ सेर से बढ़ कर १० मन हो गई। नये तालाबों और कुओं की मदद से १५,६०१ एकड़ भूमि पर सिंचाई होने लगी है। पुराने तालाब और कुएं सुधार किये गये हैं। छोटी नदियों पर बाँध भी बाँधे जा रहे हैं।

कृषि विभाग ने किसानों को १८५ टन रासायनिक खाद और १०४

उन उत्तम बीज दिया है। कम्पोस्ट बनाने का प्रचार करने की योजना भी चालू कर दी गई है।

भोपाल राज्य जागीरदारी उन्मुक्तन कानून पक्ष कर दिया गया है जिसका उद्देश्य किसानों की उन्नति करना है।

मधुबनी के बच्चों को कागज सिक्काने का एक स्कूल खोला गया है। मछली की बिक्री, मछली मारने के लाइसेन्स और मछली मारने के अधिकारी के लीसाबो से १७,६६८ रुपये की आमदनी हुई।

१९५३ का भोपाल पंचायत राज कानून राज्य में १५ अगस्त १९५३ को लागू किया गया, और राज्य में ५३२ गाँव-सभाएं और ४२ ग्वाथ-पंचायतें स्थापित करने की योजना है। इस वर्ष राज्य में चने और ज्वार का उत्पादन १९४९ के १,३४,००० टन उत्पादन से बढ़कर १,६६,००० टन हो गया और राज्य यह दोनों प्रभाव बाहर भेज सकने में सफल रहा।

बिलासपुर

बहुत ही कम पानी बरसने के कारण मक्का, जोकि राज्य की मुख्य फसल है, बहुत कम पैदा हुआ। अभावग्रस्त क्षेत्रों में अटेने के लिये पंजाब से गेहूँ मँगाना पड़ा। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये सामूहिक विकास-कार्य क्षेत्रों में २७० सन सन और फलसरी के बीज की हरी खाद, करीब ५७ सन फलोनि-यन सलफेट और ३७ सुपर फास्फेट बितरण किया गया। खाद बनाने के कोई १० हजार गड़े जोड़े गये हैं और बहुत से गड़े बीड़े किये गये हैं।

ग्राम सेवाओं ने खेती के आधुनिक औजारों का इस्तेमाल करने के तरीकों को सिखाया। ये औजार किसानों को उधार दिये गये हैं ताकि वे इनको जाँच सकें।

टिडिथियों से होने वाले नुकसान को बचाने के लिये दूर-दूर तक दबाये छिड़की गई हैं।

तीन कृषि प्रदर्शिनियाँ और फसल प्रतियोगिताएँ की गईं। धान की खेती के ज़राने तरीके का व्यापक प्रचार किया गया।

कुरु

१९५३ में सेंसर को ७ हजार टन और सालाबार को २०० टन चावल दिया गया। १९५४ में ५० हजार टन चावल अर्थात् पिछले साल से आठ हजार टन अधिक पैदा होने की आशा है। इसलिये राज्य के बाहर कमी वाले प्रदेशों में १४ हजार टन से अधिक चावल भेजने की योजना बनाई गई है।

लगभग ८६० एकड़ पानी भरी जमीन की सिंचाई के लिये ४५ नये तालाब खोदें गये हैं और २६ पुराने तालाब सुधारे गये हैं। २७ बाँधों का निर्माण और सुधार किया गया है और करीब ७५० एकड़ उत्तर खेती-योग्य बनाया गया है।

किसान अब हरी खाद की उपयोगिता समझने लगे हैं। १३ हजार रुपये का खाद मिश्रण और हड्डी का चूरा किसानों को मुफ्त बाँटा गया। सरकार ने अपनी तरफ से पैसे मिलाकर किसानों को सस्ते दामों पर १,१५१ टन खाद और रासायनिक खाद दी है। ■ घास केन्द्रों में धान की खेती के ज़राने तरीके का प्रयोग किया गया है। सरकारी खेती फार्म में तरह-तरह के चारे और अन्य फसलों में प्रयोग किए गए हैं।

दिल्ली

फसल बढ़ाने के लिए मीठा, खाद और रासायनिक खाद किसानों को बाँटी गयी है। हरी खाद का प्रचार करने के लिये बड़ी मात्रा में उचार के बीज बाँटे गये हैं। उत्तम बीजों की कई किस्में भी दी गई हैं। छोटी छोटी बिसरी हुई जमीनों को लगभग ७३ गाँवों में पूरी हो चुकी है और माता है कि १९५५-५६ तक सब गाँवों में पूरी हो जायगी।

खेती के नये और अच्छे तरीकों का प्रचार किया गया है और उनके प्रयोग करके किसानों को दिखाया गया है। मोशन बमारे के लिए लोहा और अस्पात और खेती के लिए औजार मनु-उपयोगी सहकार संस्थाओं के माध्यम से किसानों में बाँटे गये हैं।

खेती के कीड़ों और रोगों के निरोध और नियंत्रण के लिए २.५ लाख रुपया दिया गया है। राज्य सरकार धान क्षेत्रों में सुर्गी पालन के विकास में सहयता देगी। किसानों को उम्दा नस्ल की सुगंधा बीजाणु और मलेरिड ट्रैपिंग भी दी जायगी।

हिमाचल प्रदेश

अगस्त १९५३ में कृषि-विभाग जन-विभाग से अलग कर दिया गया।

टेकनीकल सहायकार सेवा की स्थापना की एक योजना तैयार की गई है, और जनस्पर्ति विज्ञान, कृषि विज्ञान, पौधों के रोगों का विज्ञान, कृषि शास्त्र, भूमि विज्ञान, और रसायन शास्त्र के विभाग खोलने का प्रबन्ध किया जा रहा है। बालू और गेहूं की खेती करने वालों को उम्दा बीज दिए गए हैं और धान बोनेवालों को जापानी तरीका अपनाते पर राखी किया गया है। छाद्यों में कम्पोस्ट बनाने और रासायनिक खाद और हरी खाद इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। भाग लगाने वालों को कृषि विभाग ॥ जगोचों से १६,५६७ फसों के पैक दिए गए हैं और पैकों को कौड़ों से बचाने के उपाय किए जा रहे हैं।

कच्छ

फसल बढ़ाने के लिए किसानों को १० टन सुपर फास्फेट और ४३ टन अमोनियम सल्फेट और नाजरा, उबार और धान के नए और उम्दा किस्म के बीज दिए गए हैं।

जागीरदारों और बड़े किसानों को बढाई के अनाज की जगह अब नगर दिया भी दिया जा सकता है।

१९५३-५४ में बीज, बीजार और बेल खरीदने के लिए किसानों को छोटे-छोटे तक्रावी कर्ज दिए गए जिनकी कुल रकम दस लाख रुपया हुई।

‘अधिक धन्य उपजाओ’ योजना के अधीन ५,६५,००० रुपया सगाकर करीब ६०५ नए कुएं खोले गए। रसालिया, घोड़का, दागला, घनसी, कुम्हा-

रिया, हुब्ले और कल्याणपुर के बांधों पर पानी रोकने और खोसने के बरबादों बनाए जा चुके हैं।

विन्ध्य प्रदेश

भार मए खेती-कार्य स्थापित करने के लिए २ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। हाल ही में एक सिंचाई-विभाग बना दिया गया है जिसका काम सालाब और कुएं खुदवाना है। धान की खेती का जापानी तरीका भी प्रचलित किया जा रहा है और मए और अच्छे प्रकार के औजारों को खेत में इस्तेमाल करके दिखाया जा रहा है। किसानों को बताया जा रहा है कि हर साल खेतों में फसल की अवला-बदली करते रहने से क्या फायदे होते हैं। अच्छी कृषि के बीज, रासायनिक खाद और कम्पोस्ट भी बांटी जा रही है।

सामान्य रूप से राज्य में अपनी ज़रूरत भर का अनाज पैदा हो जाता है, बल्कि धान थोड़ा फालतू हो रहता है। इस वर्ष की पैदावार पहले से भी अधिक रही है और अनाज का दाम आम तौर पर गिर गए हैं। राज्य में अनाज की राशन व्यवस्था लागू नहीं है।

शिच्चा

अजमेर

४० मए बुनियादी स्कूल खोले गए हैं। गांवों के कई प्रारम्भिक स्कूल मिडिल स्कूल, और कई मिडिल स्कूल हाई स्कूल बना दिए गए हैं।

राज्य में कुल मिलाकर १०,२५ प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र हैं।

विस्थापित विद्यार्थियों में सरकारी शिक्षा सुविधा और भूख भण्डार की शकल में २० हजार रुपये की रकम बांटी जा चुकी है। व्यापार-शिक्षा और

‘ग’ भाग

सामाजिक और मनोरंजन सम्बन्धी कामों के लिए १५,००० रुपये की रकम भ्रमण से दी गई है।

अजमेर के सावित्री गार्ल्स कालेज में नेशनल केबेट कोर की एक टुकड़ी लड़कियों ■ लिए बनाई गई है। सहायक केबेट कोर की भी चार जगह स्थापना हुई है।

भोपाल

१६५२-५४ में एक हाई स्कूल और २० प्राथमिक स्कूल खोले गए। ग्राम क्षेत्रों में २ छोटे बुनियादी स्कूल भी खोले गए। गांधी नगर में एक बुनियादी ट्रेनिंग कालेज खोला गया है और २६ अध्यापकों को उसमें बुनियादी शिक्षा की ट्रेनिंग दी जा रही है।

ग्राम क्षेत्रों के सब हाई और मिडिल स्कूलों में कृषि को पाठ्य-क्रम में शामिल कर दिया गया है। भोपाल शहर के कैम्ब्रिज स्कूल को हाई स्कूल बनाकर माध्यमिक शिक्षा के केन्द्रीय बोर्ड से संयुक्त कर दिया गया है।

हरिजन विद्यार्थियों के हित के लिए ५० हजार रुपये रखा गया है और अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के सर्व विद्यार्थियों को माध्य-पुस्तकों और शिक्षक-पढ़ने की अन्य सामग्री मुफ्त दी गई है।

भोपाल में १० और सेहोर में ५ समाज-शिक्षा-केन्द्र खोले गए हैं।

बिलासपुर

कुल विद्यालयों की संख्या अब ५० हो गई है जिनमें २५० अध्यापक और ७ हजार विद्यार्थी हैं। विकास योजनाओं सहित शिक्षा की मद में इस वर्ष लगभग ६५,००० रुपये के कार्य का अनुमान है। प्रारम्भिक स्कूलों की संख्या ३० से बढ़ाकर ३४ कर दी गयी है। ४ प्राथमिक स्कूल मिडिल स्कूल बना दिए गए हैं। स्कूलों के लिए १२ हजारसें जतना की मदद से बनाई गई है। बिलासपुर शहर का मिडिल स्कूल बड़ा बुनियादी स्कूल कर दिया गया है। बुनियादी ट्रेनिंग कालेज में ४० अध्यापकों को तैयार भी किया जा चुका है।

सालर्था वर्ष

राज्य में एक जनता कालेज और ११ प्रौढ़ केन्द्र हैं जिनमें ६ सामुहिक विकास कार्य क्रम के अधीन स्थापित किए गए हैं। इन केन्द्रों में रेडियो, रंस के संपन्न और छात्र जल्दारी चीजें मौजूब हैं। हर केन्द्र में एक छोटा-सा पुस्तकालय भी है।

कुर्ग

सरकार ने जिला बोर्ड के सब स्कूलों की अपने अधिकार में लेकर अध्यापकों के वेतन सरकारी वेतन-प्रणाली के अनुसार कर दिए हैं। सहायक केडेट कोर नामक एक युवक हितकारी आम्बोलन सब सरकारी हाई स्कूलों में शुरू कर दिया गया है। स्कूलों की नयी इमारतें बनाने और मिडिल और प्रारम्भिक स्कूलों में स्थान बढ़ाने के लिए ३-३५ लाख रुपया संभूर किया गया है। हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए हाथ का काम सिक्काने का कार्यक्रम जारी है और विद्यार्थियों ने बहुत-सा उपयोगी काम भी कर डाला है। समाज-विकास-केन्द्रों में पुस्तकालयों का प्रबन्ध कर दिया गया है और शिक्षात्मक फिल्में भी दिखाई जा रही हैं।

विल्ली

१९५३-५४ में माध्यम-प्राप्त स्कूलों की संख्या ७५५ हो गयी; १९५२-५३ में यह संख्या ७२५ थी। इसलिये २३,८७६ विद्यार्थियों ■ लिए शिक्षा की सुविधाएँ और बढ़ाया गई।

ग्राम क्षेत्रों में प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य कर दी गयी है। गांव के सब बच्चों की प्रारम्भिक शिक्षा मुफ्त देने के उद्देश्य से १२ छोटे बुनियादी स्कूल बना दिए गये हैं। १२ सेजुएट अध्यापकों को शामिल मिस्तिया में बड़े बुनियादी पाठ्यक्रम बढ़ाने की शिक्षा लेने भेजा गया है।

१९५३-५४ में "अपना देश देखो" नामक भ्रमण कार्य-क्रम बनाया गया। कोई ६०० विद्यार्थियों ने एक स्पेशल रेल गाड़ी से वाणिज्य और इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों की यात्रा की। विद्यार्थियों ने कोई ३,००० मील की सैर की।

अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को उच्च माध्यमिक शिक्षा तक की शिक्षा अब मुफ्त दी जाती है। अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को कोई १,१३,००० रुपया भत्ता अनुदान बांटा गया है और विस्थापित विद्यार्थियों को कुल ४,६५,००० रुपया आर्थिक सहायता के रूप में दिया गया है। समाज सेवा के जनता कलेज में विशेष पाठ्य क्रम शुरू किए गए हैं जैसे प्लास्टिक और कंपोज का काम, बड़ईमोरो, फेरी, पशु-पालन और साबुन बनाना। क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग के लिए ३ केंद्रों का आयोजन किया गया। "हमारा गाहर", "हमारा गांव" और "समाज शिक्षा संदेश" नामक तीन पत्रिकाएँ प्रकाशित हो रहे हैं।

हिमालय प्रदेश

मिडिल स्कूलों को हाई स्कूल, और लोअर मिडिल स्कूलों को मिडिल स्कूल बना दिया गया है। नए प्रारम्भिक दुनियादी स्कूल भी खोले गये हैं।

समाज शिक्षा की एक विशाल योजना भी तैयार की जा रही है।

१९५३ में हिमालय प्रदेश मनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा बिल पास किया गया।

कच्छ

१९५३ की जून में 'भक्त' में एक इंटरमीडिएट कालेज खोला गया जिसमें अन्य विषयों के साथ विज्ञान की भी शिक्षा दी जा रही है। ग्राम स्तरों में ५ नए प्रारम्भिक स्कूल खोले गये हैं और स्कूलों की ५ नयी इमारतें बन रही हैं। मुख्य तालुका शहरों में समाज और प्रौढ़ शिक्षा-केन्द्र खोले गए हैं। गांवों में समाज शिक्षा देने के लिए सामूहिक केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। १९५३-५४ में ६ अभ्यासकों को दुनियादी शिक्षा की ट्रेनिंग देने के लिए बम्बई राज्य भेजा गया। ६६ विद्यार्थियों को देश में और जगह ऊँची शिक्षा ग्रहण करने के लिए छात्रवृत्ति दी गई। जिन केंद्रों में हिन्दी पढ़ाई जाती है उन्हें कुल २,५०० रुपया दिया गया। शिक्षितों में बेरोजगारी कम करने के लिए २० नए प्रारम्भिक स्कूल खोले जा रहे हैं और १० प्रारम्भिक स्कूलों का दर्जा बढ़ाया जा रहा है।

विन्ध्य प्रदेश

१९५३-५४ में प्रारम्भिक स्कूलों की संख्या २,१६३ हो गयी। १९५२-५३ में यह संख्या १,८५८ थी। भरम्मत के लिए ७५ हजार रुपये सालाना की जो व्यवस्था है उसके अतिरिक्त इस वर्ष नयी इमारतों पर २० हजार रुपये खर्च किया जा रहा है।

१९५३-५४ में ८ जिलों के प्रधान कार्यालयों में एक २ बुनियादी स्कूल और कुण्डेश्वर में एक बुनियादी ट्रेनिंग कालेज खोला गया। १३७ हिन्दी मिडिल स्कूलों को अंगरेजी मिडिल स्कूल बना दिया गया है।

समाज शिक्षा की योजना को जो राज्य के पंचवर्षीय आयोजन का अंग है, कार्य-रूप दिया जा रहा है। समाज शिक्षा के लिए लाउडस्पीकर और फ्लिमेना से लैस एक गाड़ी उपयोगी कार्य कर रही है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य

अजमेर

विजय नगर के मधुदा स्टेट औषधालय और किंग जार्ज पंचम मेमोरियल जलवा-बलवा अस्पताल को सरकार ने ले लिया है। राज्य के आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक औषधालयों को ५,००० रुपये अनुदान के रूप में दिया गया है।

बीबर में एक मलेरिया निरोध केन्द्र खोला गया है। बी० सी० जी० टीका आन्दोलन, जो १९५२ में बड़े पैमाने पर शुरू किया गया था, अच्छी प्रगति कर रहा है। जनवरी १९५४ तक २३८,७३५ व्यक्तियों का दूधरकुलिन परीक्षण हो चुका था।

परिवार आयोजन के सम्बन्ध में सत्ताह देने का प्रयत्न जार्ज पंचम

‘ग’ भाग

अमेरिकियल जलवा-बच्छा अस्पताल में स्मृतिपल औषधालय में और औरतों के मिशन अस्पताल अजमेर में किया गया है।

भोपाल

१९५३-५४ में बरेली का औषधालय, अस्पताल बना दिया गया जिसमें २० मरीजों की जगह है। सेहोर जिले के बोरहा में एक नया एलोपैथिक औषधालय खोला गया।

गान्धी नेत्र अस्पताल अलीगढ़ की चलती किरती टुकड़ी के सहयोग से स्वास्थ्य विभाग ने भोपाल शहर में भौखों के इलाज के लिए एक कैंम्प का आयोजन किया।

ईबगाह पहाड़ी पर एक सुसम्पन्न अंग अस्पताल बनाया गया है जिसमें १५२ मरीजों की जगह है।

राज्य के लगभग सब ऐसे शहरों और गांवों में, जहाँ की आबादी १,००० या अधिक है, बी० सी० जो० के टीके लगाने वाली टीसी जा चुकी है। मलेरिया दूर करने का एक संगठित आन्दोलन सारे राज्य में शुरू किया गया और १,१६४ गांवों में बी० सी० टी० छिड़की गई। गांव वालों को पैलूडिन की टिकिया भी बांटी गई।

४ चलते किरते औषधालयों ने राज्य में जगह-जगह घाकर गांवों में आबकारी सहायता पहुँचाई।

बिलासपुर

राज्य में मलेरिया का निरोध जोरों के साथ किया जा रहा है। घरों में बी० सी० टी० छिड़की जा रही है, मलेरियोस टिकिया भी बांटी जा रही हैं। कुम्हों और तालाबों में कीड़े मारने वाली दवा डाली गई है और सफाई का आम प्रचार किया जा रहा है।

सातवाँ वर्ष

१९५३-५४ में राज्य में जच्चा-बच्चा और शिशु-हित के दो और केन्द्र खोले गए ।

कुर्ग

डाक्टरों विभाग, जो कुर्ग जिला बोर्ड के अधीन था, अब राज्य सरकार में लिया है । फलतः बाइयों, नर्सों और अन्य कर्मचारियों की तनकाहें ऊँचे स्तर में आ गई हैं । राज्य के बजट में ३१ हजार रुपये को और व्यवस्था की गई है जो डाक्टरों विभाग पथ्य और औषधि पर खर्च करेगा । सोह्रे के सर्वेक्षण करीबों के लिए ७,००० रुपये और साज सामान भंगाने के लिये भी ७,००० रुपये मंजूर कर दिये गये हैं ।

नवम्बर १९५६ में राज्य में बड़े पैमाने पर बी० सी० जी० के डीके लगाना शुरू किया गया । २२ स्कूलों में बच्चों का निरीक्षण किया गया, इनमें से ६,०२६ को डीके लगाए जा चुके हैं और बाकी के लगाए जा रहे हैं ।

दिल्ली

हिन्दू राज अस्पताल को इस वर्ष आम अस्पताल बना दिया जायगा जिसमें १०० मरीजों की जगह होगी । एस्० जे० अथ अस्पताल में १२० रोगियों की जगह और की गयी है : सीने की शल्य-चिकित्सा का एक विभाग भी जोड़ा गया है जिसके पास आपरेशन का विशेष कमरा और आपरेशन के बाद के उपयोग के लिए कमरे तथा एक्स-रे मंच भी है । छूत की बीमारियों के अस्पताल में एक को संजिला बाई बढ़ा दिया गया है जिसमें ४६ रोगियों की जगह है ।

शाहजहाँ औषधालय को शाहजहाँ म्युनिसिपैलिटी में ले लिया गया है । बहुत सा नया साज सामान भंगया गया है और विचार है कि उसे शीघ्र ही ऐसा अस्पताल बना दिया जाय जिसमें ५० रोगियों की जगह हो ।

विलिंगडन अस्पताल और सरसिंग होम, जो अभी तक नयी दिल्ली म्युनिसिपल कमिटी के अधीन था, अब केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण में हो गया है । विस्त्रावितों के लिए पाँचवाँ आरोग्य केन्द्र पटेल नगर में खोला गया है ।

न' भाग

- छठा मोदी नगर में बन रहा है। दिल्ली के निर्जन क्षेत्रों में आरोग्य का प्रबन्ध प्रस्था करने के लिए कमलानगर, रोशनारारोड, अन्धा मुगत, आनन्द पर्वत, भाषानगर और संतनगर में ६ सेविका केन्द्र खोले गए हैं।

अभी तक १० लाख आयुधियों का क्षम परीक्षण करके २ लाख को बी० सी० जी० का टीका लगाया जा चुका है।

दिल्ली के नगर क्षेत्र के मलेरिया ग्रस्त भाग और लगभग सब गांवों और बस्तियों में डी० डी० टी० छिड़क कर उन्हें कीटाणुनाशित कर दिया गया है।

१९५३-५४ में कोठला मुबारकपुर और मसकागंज में जप्पा-बप्पा और विशु हित का एक-एक केन्द्र खोला गया।

१०० रुपयों से कम वेतन पाने वालों के जप्पों के लिए नर्सरी स्कूल भी खोले गए हैं।

कर्मचारियों की सरकारी बीमा योजना के अधीन बीमा कराने वालों की संख्या, जो १९५२ में ३१ हजार थी, वितम्बर १९५३ में ६६,६२५ हो गयी। बीमा कराए हुए कर्मचारियों की जरूरतों के लिए घूरे समय के भाड और आंशिक समय के ११ औषधालय खोले गए हैं।

हिमाचल प्रदेश

अमृतपुर के निकट मंदीधर में एक क्षय अस्पताल खोला गया है जिसमें ३५ रोगियों की जगह है। महात्मा, मंत्री, कम्मा और सिरमूर के जिलों में एक-एक आयुर्वेदिक और एक-एक एसीवैधिक औषधालय का आयोजन किया गया है। शिमले के हिमाचल प्रदेश अस्पताल में २५ रोगियों की जगह और की गयी है। इस अस्पताल में कोई ६० हजार रुपये की लागत से एक शक्तिशाली एक्स-रे यंत्र लगाया गया है। डाक्टर नियम से गांवों में जा जाकर इलाज करने के अलावा आरोग्य के बारे में सलाह भी देते रहते हैं। पंचवर्षीय आयोजन के अधीन डाक्टरों और आरोग्य की योजनाओं को संतोषजनक रूप से

सातवाँ वर्ष

कार्यान्वित किया जा रहा है। इन पर १८,०६,००० रुपये खर्च होने का अनुमान है।

कोष्ठ और कुत्ते काटे के इलाज की शिक्षा प्राप्त करने के लिए डाक्टरों और पारोम्य विभाग के अनेक कर्मचारियों को भेजा गया है। इसके अलावा आयुर्वेद और एस० बी० सी० एस० पाठ्य क्रम की शिक्षा ■ लिए ९ छात्र चुनिये भी बी गये हैं।

मलेरिया वाले सब प्रवेष्टों में जी० डी० टी० छिड़की जा रही है। मलेरिया को बचा भी मुफ्त बांटी जा रही है। कुल मिलाकर ६४,३७२ घरों में बचा छिड़की गयी है और ८,१६४ रोगियों का उनके घर पर ही इलाज किया गया है।

मंडी और चम्बा जिलों में बड़े पैमाने पर बी० सी० जी० के टीके लगाए गए हैं और मंडी और चम्बा के शहरों में बड़े पैमाने पर एकत-रे किया गया है।

सुन्दर नगर, चम्बा, तिस्ता और जवाग में जल्वा-जल्वा और शिशु हित के भार केन्द्र खोले गए हैं। गर्भवती स्त्रियों को मछली का तेल, अनेक विटामिनों से युक्त द्रवियाँ और अलनिया दूध इत्यादि बांटा जाता है।

कच्छ

दुधई के एक ग्राम औषधालय और नकतराना ताल्लुके में एक जलता-फिरता औषधालय शुरू किया गया है। भुज में एक ग्राम अस्पताल और मांडवी में एक नेत्र-अस्पताल बनाने के लिए ४ लाख रुपये बतल दिये गये हैं। इनका चलना जल्दी ही शुरू होगा। अंजार में ५ लाख रुपये की एक इमारत अस्पताल के लिए अधिकारियों को बतल दी जा रही है।

राष्ट्रीय मलेरिया निरोध योजना के अर्धीन मलेरिया का रोकने के अनेक प्रकार के उपाय किए गए हैं। १९५३-५४ में राज्य में अस्पतालों की संख्या बढ़ाकर ७५ की गई और उनकी उन्नति के लिए इस वर्ष बी लाख रुपये खर्च

किया गया। एक में ईल चिकित्सा विभाग भी खोला गया। वर्ष भर में चलते-फिरते अस्पतालियों ने दूर-दूर के गांवों में डाक्टरों सहायता पहुँचायी और भले-रिया रोकने की वकालत की। बड़े पैमाने पर बी० सी० जी० के टीके लगाए जा रहे हैं। नती और बाहियों को कमी पूरी करने के लिए रोवा के जी० एम० अस्पताल में ट्रेनिंग की व्यवस्था की गयी है।

श्रम

अजमेर

उम सब अनुसूचित औद्योगिक कार्यालयों में, जहाँ एक हजार या अधिक श्रमिक काम करते हैं, न्यूनतम मजदूरी निर्दिष्ट कर दी गयी है। जघोंगों को कच्चा भात बिजाने और मशीनों लाने-लेजाने में श्रम विभाग सहायता देता रहा है।

४ कपड़ा मिलों और बी भोजा बनिमाल आदि के कारखानों में कर्मचारियों की प्रोबिडेन्ड फंड की योजना लागू कर दी गयी है। १९५३ में हर महीने औसतन ५,४०० कर्मचारियों ने इस योजना से सीधे लाभ उठाया है।

भोपाल

१९५३-५४ में औद्योगिक अवास्त ने मालिकों और मजदूरों के ९ भागड़े निबटाए। इनके अलावा ४५० से अधिक अन्य भागड़े भी निबत्तापूर्वक निबटा लिए गए।

९ मजदूर युनियनों और रजिस्टर्ड की गई हैं जिनसे मजदूर युनियनों की कुल संख्या २१ हो गयी है।

साप्ताहिक छुट्टी कानून एक नवम्बर १९५३ से भोपाल शहर में लागू हो गया है।

कुर्ग

काफ़ी और इलायची बगानों में काम करने वाले और खेती करने वाले मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी निश्चित कर दी गयी है। कुर्ग न्यूनतम मजदूरी नियम भी तैयार कर लिए गए हैं।

कुल मिलाकर ३०७ भगदे औद्योगिक अवास्त के सुपुर्द किए गए। इनमें से १२७ मित्रतापूर्वक निष्ठा लिए गए, ६२ रह कर दिए गए और ३१ बाधित से लिए गए।

अस और समाज हित के कामों पर कोई ३० हजार रुपया खर्च हुआ।

दिल्ली

कुल १९१ औद्योगिक भगदों और १,१०२ शिकायतों को मित्रता से निबटारा गया। इनके फंसलों के अनुसार मालिकों को मजदूरों की बकाया मजदूरी चुकाने में ४५,५५५ रुपया देना पड़ा है।

न्यूनतम मजदूरी कानून लोहे की चीजें डालने, कारखानों (मशीन की श्रुक्त सहित प्रथम उसके बिना), मोटर गाड़ियों के कारखानों, छायाखानों और वायु के बर्तन बनाने वाले कारखानों पर भी लागू कर दिया गया है। इनमें के पहले तीन में न्यूनतम मजदूरी निश्चित कर २५ से ५ हजार से अधिक मजदूरों का हित हुआ है।

जहाँ जहाँ सम्भव हो सका है, मालिकों से मजदूरों के लिये फौजिन, सपोरेशन और सबकासा-ग्रहण करने की सुविधाओं का प्रबन्ध कराया गया है। नवम्बर १९५३ में सरकार ने सक्जीमण्डी जेम्स में एक हितकारी केन्द्र खोला जिसमें पुस्तकालय, भाषामालय और खेल-कूद की सुविधाएँ हैं और जो साक्षरता की कक्षाएँ भी चलाता है।

सरकारी सहायता-प्राप्त औद्योगिक मकान योजना के अधीन सरकार ने औद्योगिक कर्मचारियों के लिये १,२७६ मकान बनाने का निश्चय किया है।

२५ नये यूनिपन रजिस्टर्ड किए गए हैं। भाग १९५३ में सब यूनिपनों में विलाकर २,००,२६६ सदस्य थे।

फैक्टरी कानून के अधीन रजिस्टर्ड फैक्टरियों की संख्या जो १९४७ में २८१ थी, १९५३ में ६२५ हो गयी। इस कानून की आरोग्य, सफाई और अन्य हितकारी विषयों की व्यवस्थाओं के उचित पालन के लिए एक फाक्टरी निरीक्षक का पद बनाया गया है।

कच्छ

अनहित सम्बन्धी भारत सरकार ■ सब कानून, जिसमें १९४५ का फैक्टरी कानून, १९४७ का न्यूनतम मजदूरी कानून, १९४७ का औद्योगिक संघर्ष कानून और १९३६ का मजदूरी अवधारी कानून, कच्छ में भी लागू कर दिया गया है।

विन्ध्य प्रदेश

औद्योगिक कर्मचारियों को अपने मजदूर यूनिपन बनाने की सुविधा दी गयी है। सब अनुसूचित गौहरियों में न्यूनतम मजदूरी भी निर्दिष्ट कर दी गयी है।

फैक्टरी मजदूरों की सुविधा और हित के लिए १९४५ का फैक्टरी कानून और १९४२ के बी० पी० फैक्टरी नियम लागू कर दिये गये हैं। १९४७ के औद्योगिक संघर्ष कानून के अधीन भगड़ों को मित्रता से निबटाने के लिए समझौते के उपाय अपनाए गए हैं।

उद्योग

अजमेर

राज्य राज्यों की प्रेरणा यहाँ औद्योगिक कच्चे माल की कमी है और

औद्योगिक माल के लिए सुविकसित स्थानीय बाजार भी नहीं है, इसके कारण जहाँ औद्योगिक काम-काज की गुंजाइश काफी कम है। फिर भी नए उद्योग खोलने की संभावना का पता लगाने के लिए एक औद्योगिक सलाहकार समिति बनाई गयी है। इस समिति ने एक प्रश्नभासा तैयार करके आवश्यक जानकारी जुटाना शुरू कर दिया है। राज्य सरकार ने आर्थिक जाँच पड़ताल का भी एक बोर्ड बनाया है जो राज्य की आर्थिक सामर्थ्य का पता लगायगा।

भोपाल

१९५३-५४ में भोपाल शहर, सेहोर, और पड़ोसी क्षेत्रों में निवासियों की उपयोगी काम-काज जैसे बुनाई, बर्तनीगिरी और बढ़ईगिरी सिखाने के लिए कई केंद्र खोले गये।

भोपाल के गांधी आश्रम में एक ग्रामोद्योग शिक्षा केंद्र खोला गया। इसका उद्देश्य गांववालों को तरह तरह के कपड़े, बिशेष कर खादी की बुनाई सिखाकर गाँवों की प्रगति-व्यवस्था की उन्नति करना है।

ग्रामोद्योगों में लगे हुए व्यक्तियों और सहकारी संस्थाओं को २,००० रुपया कर्ज के रूप में दिया गया।

मकख अनुदान, भीखार और साज-सामान के रूप में ६,४५५ रुपया और भी बाँटा गया है।

भोपाल शहर में एक एम्प्लॉयमेंट खोला गया जिसमें सरकारी शिक्षा केंद्रों की बनी हुई जाँच विकसित और बेचने के लिए रखी जाती है।

प्रभिल भारत वस्तुकारी बोर्ड ने राज्य की ४२ वस्तुकारियों के विकास की एक योजना बनाई है, जिसमें मिट्टी ■ बर्तन, घटाई और खिलौने बनाने के धंधों को महत्व का स्थान दिया गया है। इन वस्तुकारियों के कारीगरों की सहकारी संस्थाएं बनायी जायेंगी।

विलासपुर

साप्ताहिक विकास कार्यक्रम के अग्रणी घुमरवीं और सदर सहसील विकास समितियों में ५ घंटे फिरेट ट्रेनिंग केन्द्र छोले जायेंगे को लकड़ों के काम, बर्फी-गिरी, बुनाई, जमड़े के काम और लुहारगिरी की शिक्षा देंगे।

कुरंग

राज्य के महत्वपूर्ण घरेलू उद्योगों में अधुमक्खी पालन, कपड़ा बुनना मिट्टी के बर्तन बनाना और मुर्गी पालन आते हैं। इनमें से लगभग सब स्थानीय बाजार में ही अपना भाग बेचते हैं और केवल ग्राह्य ही ऐसा भाग है जो राज्य सरकार बड़ी मात्रा में बाहर भेजती है। राज्य में मिल सकने वाले कच्चे भाग का विस्तार पूर्वक पता लगाकर राज्य के उद्योग सलाहकार बोर्ड में कई घरेलू उद्योगों का तुरन्त विकास करने की सिफारिश की है।

इनमें मिट्टी के बर्तन बनाना, कपड़ा बुनना, मछली मारना, कलों का रस निकालना और मुर्गी इत्यादि तथा अधुमक्खी और रेशम के कीड़े पालना महत्वपूर्ण हैं। कुरंग के करया बस्म सलाहकार बोर्ड ने राज्य में करया बस्म उद्योग की उन्नति के लिए जो योजना बनायी है उसमें कहा गया है कि बिनाई के और स्कूल छोले जायें और बुनकरों को अपना धंधा अजाने के लिए जितना प्रोत्साहन चाहिए दिया जाय।

विरली

१९५३-५४ में राज्य में ७५ नयी उत्पादन संस्थाएं बनीं जिसका श्रेय उद्योग विभाग से तुरन्त और समय पर प्राप्त सहायता को है। उद्योग विभाग ने इन संस्थाओं को वेश में से और वेश के बाहर से कच्चा भाग प्राप्त करने में मदद दी, शिल्प विधि और वाणिज्य सम्बन्धी मामलों में निःशुल्क सलाह दी और बिजली और परिवहन की सुविधाओं के अतिरिक्त आर्थिक सहायता का भी प्रबन्ध किया।

सादी उद्योग की उन्नति के लिए सादी और ग्राम उद्योग सहकारी समिति लिमिटेड को ३२,००० रुपये का अनुदान दिया गया। हरिजन लड़कों

को धरेलू उद्योग सिलाने के लिए हरिजन सेवक संघ को ५,००० रुपये की मदद दी गयी। १९५३-५४ में संघ ने क्लिन्नोत्तर बनाने का एक विभाग खोला।

उद्योग सलाहकार बोर्ड ने राज्य में एक औद्योगिक वित्त कारपोरेशन बनाने की एक योजना स्वीकार की है। बोर्ड ने राज्य में बेरोजगारी की समस्या अच्छी तरह समझ ली है और शीघ्र ही वह कई प्रकार के उपाय करने वाला है।

साथ और डाट निरीक्षण विभाग ने राज्य में जगह-जगह प्रचलित बद-चारों और नपनों की जांच-पड़ताल करने और उन पर ठप्पे लगाने का बड़ा उठाया और बेईमानी रोकने के लिए तथा अपराधियों को पकड़ने के लिए छाये मारे।

१९५३-५४ में भारतीय कम्पनी कानून के अधीन ११६ नई कम्पनियाँ रजिस्टर्ड की गईं जिनमें ३ विदेशी कम्पनियाँ भी हैं। १९६२ के भारतीय साक्षीकारी कानून के अधीन ६०० नयी फर्म स्वीकृत की गयीं।

हिमाचल प्रदेश

● ऊन की कलई और बुनाई सिलाने और साथ ही साथ भात तैयार करने के लिए चम्बा, मंडी, रियूर और सुन्धर नगर (जिला मंडी) तथा चीनी (जिला महासू) में नए केन्द्र खोले गए हैं। इसी प्रकार चमड़ा कमाने और चमड़े का सामान बनाने के लिए चम्बा और पौडा (जिला सिरमूर) में, भात के बर्तन बनाने के लिए सोलन (जिला महासू) में, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए पीड़ा (जिला सिरमूर) में, दोकरियाँ बुनने के लिए नाहन (जिला सिरमूर) में, और स्लेटें बनाने के लिए मंडी में तथा दियासलाई और दियासलाई की डिब्बियाँ बनाने के लिए जोगेन्द्र नगर (जिला मंडी) में नए केन्द्र खोले गए हैं।

मंडी, सिरमूर और चम्बा जिलों में सहस्रत के पेड़ लगाने के लिए नए

कगोथे बनाए गए। उद्योग विभाग ने भंडी जिले में रेशम निहालने और रेशमी कपड़ा बनाने का भी काम शुरू किया है।

नाहन में हिमाचल रेखिन और तारपीन फैक्टरी ने १,१३,००० मन रेखिन साफ किया है, उसने ७७,२०० मन रेखिन और १,५४,००० गैलन तारपीन भी तैयार किया है जिसका मूल्य लगभग २४,७०,००० रुपये आंका जाता है। घरेलू और छोटे पैमाने के उद्योग शुरू करने को प्रोत्साहन देने के लिए योग्य लोगों को १,३२,००० रुपये कर्ज के रूप में बांटा जा चुका है।

कच्छ

कांडला, जखार, मुन्हा और कोटेसर के चारों तमक कारखाने बराबर उन्नति कर रहे हैं। घरेलू उद्योगों के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार ने अपनी तरफ से २०,००० रुपये की सहायता मंजूर की है जो राज्य सरकार द्वारा कर्ज के रूप में बांटी जायगी। राज्य में घरेलू उद्योगों के विकास के तरीके और साधन जुटाने के लिए एक घरेलू उद्योग बोर्ड स्थापित किया गया है। मछली उद्योग के संगठन और उन्नति के उपाय लीजें जा रहे हैं; मछली उद्योग राज्य में बहुत सी आयबनी और रोजगार का साधन है।

बिन्ध्य प्रदेश

राज्य की धर्म-व्यवस्था का मूल आधार जाले है जिनसे १२ महत्त्वपूर्ण अनिज प्राप्त होते हैं।

पुनर्वास

अजमेर

१९५१-५४ में विस्थापितों को १९,३५० रुपये छोटे-छोटे कर्जों के रूप में बांटा गया। १९६ विधवाओं, २५१ बूढ़ों को गुजारा भत्ता भी दिया गया है।

सातवाँ वर्ष

अजमेर में १९५० में जो विषयाध्ययन ट्रेनिंग केन्द्र खोला गया था वह सिलाई, कढ़ाई और कालोन बुनने की शिक्षा बराबर देता आ रहा है। व्यावर के व्यवसाय-शिक्षा केन्द्र में भी कताई और सिलाई सिखाई जाती रहते हैं। सीलने वाली को १२ रुपये महीना छात्र वृत्ति दी जाती है। १९५३ के अन्त में ४३ विपन्न विस्थापित स्त्रियाँ यह धन्धे सीख रही थीं।

विस्थापित हरिजनों के लिये १९५३ के अन्त में अजमेर में एक कामरे वाले १६० और व्यावर में १३६ मकान बनाए जा रहे थे।

भोपाल

बैरागढ़ में विस्थापित व्यक्तियों की बस्ती बन कर तैयार है। जो लोग कोई काम अच्छा सीख चुके हैं उन्हें अपनी मर्जी का काम चुनकर करने के लिए कर्जा दिया गया है। बैरागढ़ में विस्थापित व्यक्तियों को मकान और भुक्तान बनाने के लिए भी कर्ज दिया गया है। २,००० विस्थापित विद्यार्थियों को १५,००० रुपये अनुदान और छात्रवृत्ति का रूप में बाँटा गया है।

बिलासपुर

भाकड़ा मंगल अलगाव बन जाने पर जिन लोगों की जमीन पिर जायी, उनको फिर से बसाने के लिए प्रयत्न किया जाने लगा है।

कच्छ

गाँधी काम के आश्रम में जो विस्थापित वृद्धों के लिये बना है, १९५३ के अन्त में २६३ आवसी रह रहे थे। इस आश्रम पर वर्ग में तीन लाख रुपये खर्च होता है। विस्थापितों को उद्योग और खेती के लिए छोटे-छोटे कर्ज दिए गए हैं।

विन्ध्य प्रदेश

पश्चिम पाकिस्तान से आये हुए विस्थापित विद्यार्थियों और शिक्षार्थियों को आर्थिक सहायता देने के लिए भारत सरकार ने १०,००० रुपये मंजूर

किया है। गुजारा और विवाह अलावा तथा पुनर्वासि अनुदान के रूप में बाँटे जाने के लिए २३ लाख रुपये दिया गया है। विस्थापित व्यक्तियों के लिए एक कमरे वाले ६१० मकान बनाने की मंजूरी दे दी गयी है और काम शुरू भी हो गया है।



Catalogued

CATALOGUED

CENTRAL ARCHAEOLOGICAL LIBRARY,
NEW DELHI
Borrowers record.

Catalogue No.310.58/Ind/M.I.B.-
3651

India. Ministry of
& Broadcasting.



CATALOGUED.

देश-विदेश

की

लोक-कथायें

इस संग्रह में देश-विदेश को चुनी हुई सोलह लोक-कथाओं को
स्थान दिया गया है। पुस्तक में ५० से ऊपर चित्र और ७४ पृष्ठ
हैं। इसका आकार एक बड़ा ही आकर्षक तथा तिरंगा है। इतना
सब हो

"A book that is shut is but a block"

CENTRAL ARCHAEOLOGICAL LIBRARY
GOVT. OF INDIA
Department of Archaeology
NEW DELHI.

Please help us to keep the book
open and moving.

अथवा

पब्लिकेशन्स डिवीजन, ओल्ड सेक्रेटेरियेट
दिल्ली को लिखें

स्वाधीनता

और

उसके बाद

जवाहरलाल नेहरू के भाषण

(१९४६-१९४६)

इस संग्रह में हमारे प्रधानमन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू के लगभग ६० महत्वपूर्ण भाषण संग्रहीत हैं। ये भाषण १९४६ से १९४८ तक विरोध-विक्रम समूहों पर विरोध सभा में। स्वाधीनता, महात्मा गांधी, राजन्यायिकता, कांग्रेस, हुंदराबाद, विद्या, उद्योग, भारत की वैदेशिक नीति, भारत और राष्ट्रमंडल, भारत और विश्व आदि विषयों के प्रतिरिक्त कई फुटकर विषयों पर भी भाषण हैं। जो व्यक्ति मात्र के भारत या भारत सरकार पर कुछ भी जानना चाहता है वह इन भाषणों को पढ़े बिना काम नहीं चला सकता। नैतिक मूल्यों के लिए हमारे प्रधानमन्त्री का भाषण, उनकी सरलता, निष्कपकता तथा स्वभावगत सचाई के कारण इन भाषणों को स्वाधीनता साहित्य का महत्व प्राप्त हुआ है। केवल सामयिक विषयों पर सामयिक रीतिनी की दृष्टि से ही नहीं बल्कि सभी दृष्टियों से ये भाषण वैश्वव्यापी और पार्वतीय हैं।

पृष्ठ संख्या डिमाई ४४५, सुन्दर कलापूर्ण
बाकी मूल्य ५) डाक व्यय १)

प्राप्ति स्थान :

पब्लिकेशन्स डिवीजन,

ओल्ड सेक्रेटरीट,

दिल्ली-८